



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072020-220579
CG-DL-E-19072020-220579

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 18, 2020/आषाढ़ 27, 1942

No. 168]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 18, 2020/ASHADHA 27, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2020

मामला सं. (एसजी) 01/2020

विषय : भारत में “सोलर सेल चाहे उसे “माड्यूल अथवा पैनल में असेम्बल किया हुआ हो अथवा नहीं” के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच – अंतिम जांच परिणाम – सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 और सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आंकलन) नियमावली, 1997 – के अंतर्गत कार्यवाही के संबंध में।

फा.सं.22/1/2020-डीजीटीआर.—

(क) परिचय

1. दिनांक 15 जनवरी, 2020 का एक आवेदन मेरे समक्ष तीन भारतीय उत्पादकों अर्थात् (i) मै. मुन्द्रा सोलर पीवी लिमिटेड, अदानी हाउस, मीठा खाली 6 रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009, गुजरात; (ii) मै. जुपिटर सोलर पॉवर लिमिटेड, काथा गांव, डाकघर बादी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश 173205; और (iii) मै. जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड, काथा गांव, डाकघर बादी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश - 173205 की ओर से इंडियन सोलर मैन्यूफ़क्चरर्स एसोसिएशन (आईएसएमए) द्वारा सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आंकलन) नियमावली, 1997 (इसके पश्चात् “नियमावली” के रूप में भी संदर्भित) के नियम 18 के अंतर्गत भारत में “सोलर सेल चाहे उसे “माड्यूल अथवा पैनल में असेम्बल किया हुआ हो अथवा नहीं”

(इसके पश्चात इसे “विचाराधीन उत्पाद” या “पीयूसी” के रूप में भी संदर्भित) के आयातों के विरुद्ध मौजूदा रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाए जाने की मांग करते हुए दायर किया गया था।

2. विचाराधीन उत्पादन पर मौजूदा रक्षोपाय शुल्क पीयूसी के बढ़े हुए आयातों के कारण हुई गंभीर क्षति से घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत में **“सोलर सेल चाहे उसे “माड्यूल अथवा पैनल में असेम्बल किया हुआ हो अथवा नहीं” के आयातों पर** प्रथम वर्ष के दौरान 25 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से, अगले छह महीने के दौरान 20 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से और अगले छह महीने के दौरान 15 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 16 जुलाई, 2018 को इस नियमावली के नियम 11 (1) के अंतर्गत महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा जारी किए गए अंतिम जांच परिणामों तथा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों के अनुसरण में लगाया गया था। उक्त जांच परिणाम के आधार पर तथा इस नियमावली के नियम 12 और 14 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 8ख की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने दिनांक 30 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. 01/2018- सीमा शुल्क (एसजी) के माध्यम से निम्नलिखित दर पर रक्षोपाय शुल्क भारत में आयात किए जाने पर उक्त सीमा प्रशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप शीर्षक सं. 8541.40.11 के अंतर्गत आने वाले “सोलर सेल चाहे उसे “माड्यूल अथवा पैनल में असेम्बल किया हुआ हो अथवा नहीं” पर लगाया।
 - (i) जब 30 जुलाई, 2018 से 29 जुलाई, 2019 (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) के दौरान आयात किए जाने पर भुगतान योग्य 25 प्रतिशत यथामूल्य जिसमें पाटनरोधी शुल्क घटाया गया हो, यदि कोई हो;
 - (ii) जब 30 जुलाई, 2019 से 29 जनवरी, 2020 (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) के दौरान आयात किए जाने पर भुगतान योग्य 20 प्रतिशत यथामूल्य जिसमें पाटनरोधी शुल्क घटाया गया हो, यदि कोई हो; और
 - (iii) जब 30 जनवरी, 2020 से 29 जुलाई, 2020 (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) के दौरान आयात किए जाने पर भुगतान योग्य 15 प्रतिशत यथामूल्य जिसमें पाटनरोधी शुल्क घटाया गया हो, यदि कोई हो;
3. इसके अलावा, उक्त अधिसूचना के द्वारा सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख की उप धारा (6) के नियम (क) के अंतर्गत चीन और मलेशिया को छोड़कर अधिसूचित विकासशील देशों से पीयूसी के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से छूट दी गई।
4. सीमा प्रशुल्क शीर्षक के 8541 4011 - “सोलर सेल चाहे उसे “माड्यूल अथवा पैनल में असेम्बल किया हुआ हो अथवा नहीं” को निम्नलिखित दो शीर्षकों में वित्त अधिनियम 2020 (सं. 2020 का 12) की धारा 117(बी) के साथ उसकी अनुसूची III की प्रविष्टि सं. 2 के साथ पठित को दिनांक 01.02.2020 से विभाजित किया गया है:

8541 4011- सोलर सेल असेम्बल न किया हुआ

8541 4012- सोलर सेल जिसे माड्यूल में असेम्बल किया गया हो अथवा पैनल में बनाया गया हो
5. दिनांक 2 फरवरी, 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 1/2020-सीमा शुल्क (एसजी) के माध्यम से यहां ऊपर में उल्लेख किए गए दो नए प्रशुल्क शीर्षकों को दिनांक 30 जुलाई, 2018 की पूर्व की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 1/2018-सीमा शुल्क (एसजी) में एकमात्र प्रशुल्क शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।
6. इस प्रकार से मौजूदा रक्षोपाय शुल्क सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के अध्याय 85 की प्रशुल्क शीर्षक 85414011 और/अथवा 85414012 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने योग्य “सोलर सेल चाहे उसे “माड्यूल अथवा पैनल में असेम्बल किया हुआ हो अथवा नहीं” पर लागू किया जाता है। हालांकि सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से दिनांक 16 जुलाई, 2018 की अंतिम जांच परिणामों में यथा उल्लिखित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
7. उल्लिखित आवेदन जिसका संदर्भ उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में लिया गया है, के आधार पर और गंभीर क्षति के साक्ष्य के संबंध में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य तथा यह कि घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है, के आधार पर अपने आप को संतुष्ट करने पर, महानिदेशक ने दिनांक 3 मार्च, 2020 की जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस (एनओआई) सं. 22/1/2020-डीजीटीआर के माध्यम से पीयूसी पर रक्षोपाय

शुल्क को लगातार लगाए जाने की आवश्यकता की जांच करने के लिए इस नियमावली के नियम 18 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 8 ख के अनुसार एक समीक्षा जांच शुरू की।

8. उक्त नियमावली के नियम 6 के उप नियम (2) और (3) के साथ पठित नियम 18 के अनुसार, जांच की शुरुआत संबंधी दिनांक 3.03.2020 के नोटिस की एक प्रति और दिनांक 15.1.2010 के आवेदन के अगोपनीय पाठ(एनसीवी) की एक प्रति जिसे घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने केन्द्र सरकार, प्रमुख निर्यातक देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से और उक्त आवेदन में उल्लिखित हितबद्ध पक्षकारों को अग्रेषित किया गया था। इसके अलावा, इस नियमावली के नियम 6(4) के अंतर्गत यथानिर्धारित हितबद्ध पक्षकारों से सूचना की मांग करने वाली एक प्रश्नावली इस अनुरोध के साथ ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को अग्रेषित किया गया था कि वे जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के जारी होने के तिथि से 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोणों से अवगत कराएं।
9. जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के उत्तर में, या तो हितबद्ध पक्षकारों के रूप में विचार करने के लिए अनुरोध अथवा लिखित अभ्यावेदन निम्नलिखित पक्षकारों से प्राप्त हुए थे:

1.	मै. इंडियन सोलर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
2.	मै. जुपिटर सोलर पावर लिमिटेड
3.	मै. जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड
4.	मै. मुन्द्रा सोलर पीवी लिमिटेड
5.	इंडोनेशियन एम्बेसी
6.	मलेशिया की सरकार
7.	चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलैक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमई)
8.	मै. एसीएमई सोलर होलिंग्स लिमिटेड
9.	मै. सोलर पावर डवलपर्स एसोसिएशन
10.	मै. कैनेडियन सोलरमैनुफैक्चरिंग (थाइलैंड) कं., लि.,
11.	मै. आल इंडिया सोलर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
12.	मै. शापूरजी पालोंजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी प्रा. लि.
13.	मै. अजुरे पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
14.	काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर
15.	मै. आरईसी सोलर प्रा. लि., सिंगापुर
16.	मै. विक्रम सोलर लि.
17.	ताइपेई इकनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर
18.	मै. सुझोउ तालेसन सोलर टेक्नोलॉजिस कं., लि.
19.	मै. एसबी एनर्जी प्रा. लि.
20.	मै. जीआरटी ज्वैलर्स (इंडिया) प्रा. लि.
21.	मै. एकमे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्रा. लि.
22.	मै. एएमपी एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
23.	मै. अवादा अनंतपुरमु सोलर प्राइवेट
24.	मै. आयाना एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

25.	मै. एमवी फोटोवोल्टाइक पावर प्राइवेट लिमिटेड
26.	मै. गोलडी सोलर प्राइवेट लिमिटेड
27.	मै. टेपसोल फोटोवोल्टाइक पावर वेंचर्स प्राइवेट
28.	मै. नार्थ इंडिया मॉड्युल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एनआईएमएमए)
29.	मै. इन्सोलेशन एनर्जी प्रा. लिमिटेड (एनआईएमएमए के बिहाफ पर)
30.	मै.मै. पतंजलि रेनेवेबल एनर्जी प्रा. लि.
31.	मै. रिन्यूजेज इंडिया प्रा. लि.
32.	मै. वेबसोल एनर्जी सिस्टम लि.
33.	मै. विराज सोलर महाराष्ट्र प्रा. लि.

10. प्राधिकारी ने डीजीटीआर की वेबसाइट पर हितबद्ध पक्षकारों की सूची आमंत्रित की।
11. सभी अगोपनीय पाठ (एनसीवी) की प्रस्तुति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहुंच को आसान बनाने के लिए, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को कोविड-19 संकट के कारण सार्वजनिक फाइल तक पहुंच बनाने में उनके द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए ई-मेल के माध्यम से एक दूसरे के साथ अपने एनसीवी अनुरोधों का आदान-प्रदान करने की सलाह दी।
12. एक मौखिक सुनवाई 3 जुलाई, 2020 को आयोजित की गई थी। इस नियमावली के नियम 6 के उप नियम (6) के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से प्रस्तुत किए गए विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करें। किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए लिखित अनुरोधों की प्रति सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को एक दूसरे के लिए उपलब्ध कराई गई थी जैसाकि मौखिक सुनवाई में सलाह दी गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों के प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी दिया गया था।
13. सार्वजनिक सुनवाई के अनुसरण में अथवा अन्य प्रकार से, सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की उपयुक्त रूप से जांच की गई है और उनका समाधान संगत पैराओं के अंतर्गत किया गया है। चूंकि अन्य मुद्दे दोहराए गए हैं अतः उनका सामूहिक रूप से समाधान संगत पैराओं में किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का सत्यान डेस्क अध्ययन के द्वारा उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया।

(ख) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

14. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का सारांश नीचे दिया गया है:
 - i) निर्यातक देशों की सरकारें
15. इंडोनेशिया, मलेशिया और ताइवान की सरकारों ने महानिदेशक(रक्षोपाय) से अपने दृष्टिकोण अवगत कराए।
16. मौखिक सुनवाई के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए लिखित अनुरोधों में, इंडोनेशिया ने यह तर्क दिया कि (क) आयातों में वृद्धि और अप्रत्याशित घटनाक्रम को भी समीक्षा में देखे जाने की आवश्यकता है (ख) इंडोनेशिया को मूल जांच में रक्षोपाय शुल्क को लागू किए जाने से बाहर रखा गया था क्योंकि इंडोनेशिया से आयात भारत में कुल आयातों का 3 प्रतिशत से कम था और उसे बाद की किसी समीक्षा के अंतर्गत वैसा ही रहना चाहिए और (ग) इंडोनेशिया से वर्तमान आयात 3 प्रतिशत की न्यूनतम स्तर से कम होना जारी है और तदनुसार इंडोनेशिया से आयातों पर कोई रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
17. मौखिक सुनवाई के लिए दायर लिखित अनुरोधों में, मलेशिया सरकार ने प्रस्तुत किया कि (ए) विचाराधीन उत्पाद के आयात ने जुलाई 2018 में सुरक्षा शुल्क लगाने के पद को काफी कम कर दिया है और मलेशिया को अनुच्छेद 9 (1) के अनुसार बाहर रखा जाना चाहिए सुरक्षा, और (ख) समझौते के अनुच्छेद 12 (2) के अनुसार सुरक्षा पर

समझौते, एक उपाय के विस्तार के मामले में, सबूत है कि संबंधित घरेलू उद्योग को समायोजित कर रहा है, को भी सुरक्षा उपायों पर समिति को प्रदान किया जाएगा। मलेशिया ने सुरक्षा उपाय के लागू होने के बाद घरेलू उद्योग के समायोजन योजना के विकास के इच्छुक पक्ष को सूचित करने का सुझाव दिया।

18. ताईवान ने मौखिक सुनवाई के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए अपने लिखित अनुरोधों में निम्नलिखित मुद्दों को उठाया:

- (i) रक्षोपाय संबंधी करार का अनुच्छेद 8 निर्यातक देशों को गैट 1994 के अंतर्गत काफी हद तक समतुल्य रियायतों अथवा अन्य दायित्वों को स्थगित रखने का अधिकार देता है यदि रक्षोपाय शुल्क की अवधि 3 वर्ष से अधिक हो।
- (ii) इस याचिका में उपलब्ध कराई गई सूचना अन्य चार वर्षों की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क विस्तार किए जाने के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे का समर्थन नहीं करता है।
- (iii) इस करार के अनुच्छेद 2.1 में यह प्रावधान है कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए, घरेलू उत्पादन के सापेक्ष अथवा स्वतंत्र रूप में आयातों में वृद्धि होनी चाहिए। भारत में कुल आयात 2017-18 में 9,790 मेगा वाट से घटकर 2019-20 में 8,754 मेगा वाट (वार्षिकीकृत) हो गया है।
- (iv) ताईवान से आयात 2017-18 में 393 मेगा वाट से घटकर 2019-20 में 24 मेगावाट हो गया है। कुल आयातों में ताईवान का हिस्सा 2019-20 में लगभग 0.28 प्रतिशत है।
- (v) घरेलू उद्योग के घटकों में से एक घटक विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है। प्राधिकारी ने मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों में स्पष्ट रूप से यह देखा था कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई को रक्षोपाय जांच के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के भाग के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग के रूप में आवेदकों का आधार और गंभीर क्षति के दावे का आंकलन केवल घरेलू उद्योग के शेष दो घटकों के आधार पर किया जाना चाहिए।
- (vi) संशोधित समायोजन योजना पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि घरेलू उद्योग ने मूल जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए समायोजन योजना की अपनी पूर्ति और अनुपालन के संबंध में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। यदि 25 से 15 प्रतिशत के बीच में रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना घरेलू उद्योग को अपनी मूल समायोजन योजना को कार्यान्वित करने की अनुमति नहीं देता है, इस संबंध में कोई निश्चितता नहीं है कि संशोधित समायोजन योजना तब कार्यान्वित की जाएगी जब 15 प्रतिशत से कम रक्षोपाय शुल्क लागू रहेगा।
- (vii) घरेलू उद्योग की याचिका में जांच की अवधि के दौरान बाजार हिस्सा, उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग, घरेलू बिक्री आदि में उपलब्ध कराई गई सूचना पर्याप्त सुधार को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति का नहीं हो रही है।
- (viii) भारत के संघीय बजट 2020-21 के अनुसार, हम नोट करते हैं कि भारत ने सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में “सोलर सेल, असेम्बल नहीं किया हुआ” के लिए प्रशुल्क मद 8541.4011 और “सोलर सेल मॉड्यूल में असेम्बल किया हुआ और पैनलों में तैयार किया हुआ” के लिए प्रशुल्क मद 8541.4012 बनाते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव किया है और यह कि 20 प्रतिशत के प्रशुल्क दर को 2 फरवरी, 2020 से लागू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। हमारी चिंता यह है कि भारत द्वारा इन उत्पादों पर बढ़ाए गए प्रशुल्क विश्व व्यापार संगठन में भारत की शून्य प्रतिबद्धता से अधिक हो गया है।

ii) निर्यातक देशों से निर्यातक अथवा व्यापार अथवा व्यापार संघ

19. निर्यातक देशों से निम्नलिखित निर्यातक और व्यापार अथवा व्यापार संघों ने इस समीक्षा में अनुरोध किए हैं:

- (i) आरईसी सोलर प्रा. लि. (“आरईसी सोलर”)
- (ii) कैनेडियन सोलर मैनुफैक्चरिंग (थाइलैंड) कं. लि. (“कैनेडियन सोलर”)
- (iii) चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमई)

20. आरईसी सोलर द्वारा जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के उत्तर में और मौखिक सुनवाई में किया गया अनुरोध:

- (i) इस नियमावली के नियम 18 के अनुसार, नियम 5,6,7 और 11 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित समीक्षा जांच पर लागू होते हैं। तदनुसार किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए समीक्षा आवेदन को बड़े हुए आयातों, गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे, बड़े हुए आयातों और कथित गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध और आयात प्रतिस्पर्धा के प्रति समारात्मक समायोजन करने के लिए किए जा रहे प्रयासों अथवा किए जाने की योजना वाले प्रयासों अथवा दोनों प्रयासों के संबंध में विवरण के बारे में पर्याप्त साक्ष्य के द्वारा सिद्ध की जानी होती है। जांच की शुरुआत का अनुपालन नियम 5 के अंतर्गत अपेक्षाओं से नहीं किया जाता है।
- (ii) यदि घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग की याचिका के साथ प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था तब इसका यह आशय होता है कि माननीय महानिदेश द्वारा जांच किए गए आवेदन में समायोजन की योजना शामिल नहीं थी। इस प्रकार से, यदि इस वर्तमान समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए आवेदन में संशोधित समायोजन योजना शामिल नहीं थी तब इस प्रकार से माननीय महानिदेशक ने भारतीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत इस अपेक्षा का पालन नहीं किया है।
- (iii) आवेदक दो कारणों से – (क) जेआईएल विचाराधीन उत्पाद का एक “उत्पादक” नहीं है क्योंकि यह केवल पुनः उद्देश्य करने और वृद्धि जॉब कार्य करता है (ख) घरेलू उद्योग जैसाकि पहचान किया गया है, घरेलू उद्योग के क्षेत्र के भीतर जेआईएल को शामिल करते हुए अथवा उसके बिना कुल घरेलू उत्पादन के बड़े हिस्से का प्रतिनिधिक नहीं है, “घरेलू उद्योग” के रूप में विचार किए जाने के लिए मानदंडों को पूरा नहीं करता है।
- (iv) अल्फा उत्पाद का डिजाइन सिंगापुर द्वारा तथा यूरोप सहित अन्य क्षेत्राधिकारों में सरकारों के द्वारा जारी किए गए डिजाइन पेटेंट के अंतर्गत किया जाता है। भारत में उनके द्वारा बनाए गए डिजाइन अनुप्रयोग लंबित हैं। पेटेंट किए हुए डिजाइन के उपयोग के कारण, यह उत्पाद – (i) प्रोपराइटरी उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, उत्कृष्ट गुणवत्ता, स्थान कार्यक्षम, और अपेक्षाकृत अधिक पर्यावरण अनुकूल होता है (ii) भारतीय बाजार में अपेक्षाकृत अधिक कीमत इसे प्राप्त होती है और (iii) यह भारत में निर्मित वस्तुओं के अनुरूप सभी अर्थों में न तो सदृश्य और न ही एक जैसा होता है। अल्फा उत्पाद को पीयूसी के कार्यक्षेत्र के बाहर रखा जाएगा क्योंकि इसका पेटेंट किया गया है और इस प्रकार से बाहर रखना चीन जन.गण., जापान, कोरिया, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान (चीनी ताइपेई), थाईलैंड और यूएसए के दिनांक 24 नवंबर, 2009 के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की जांच में भारतीय प्राधिकारी के निर्णय जहां स्टेनलेस स्टील के कुछ पेटेंट किए गए ग्रेडों को बाहर रखा गया था, के अनुरूप होगा।
- (v) नियम 2(ड.) में दो परिस्थितियों के लिए प्रावधान है जिसमें किसी उत्पाद को “समान वस्तु” के रूप में घोषित किया जा सकता है। अनेक मामलों में विश्व व्यापार संगठनों के पैनलों और अपीलीय निकाय में “समानता” जैसे जापान – एल्कोहालिक बिबिरेज और कनाडा – पीरियोडिल्स का परीक्षण का सहारा लिया है। विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय ने सीमा कर समायोजन संबंधी कार्यशील पक्षकार की रिपोर्ट 1970 में उल्लिखित मूल दृष्टिकोण का समर्थन किया है। दिनांक 8 दिसंबर, 2009 की हॉट रोल्ड कॉयल्स/शीट/स्ट्रिप्स के आयात के विरुद्ध रक्षोपाय जांच के अंतिम जांच परिणामों में महानिदेशक (रक्षोपाय शुल्क) द्वारा जैसा कि देखा गया है, इन उत्पादों की समानता का आंकलन भौतिक विशेषताओं, अंतिम उपयोग, निर्माण की प्रक्रिया और कीमत संबंध पर विचार करने के बाद किया जाएगा।
- (vi) वर्तमान समीक्षा जांच में आयात की मात्राओं में किसी वृद्धि अथवा कमी का निर्धारण करने के लिए आधार वर्ष मूल जांच के साथ अतिव्याप्त नहीं होना चाहिए। हालांकि, इसे वर्तमान मामले में भी अपनाया नहीं गया है जहां सभी आंकड़ों के विश्लेषण और अनुमानों के लिए आधार वर्ष के रूप में 2016-17 को लिया गया है।

- (vii) केवल छह महीने के आयात आंकड़े वर्ष 2019-20 के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार के आयात आंकड़ों को वर्ष 2019-20 के लिए आयात संबंधी मात्रा को तय करने के लिए “वार्षिकीकृत” नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार का वार्षिकीकरण विश्व व्यापार संगठन के डीएसबी के द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार और संगत प्रावधानों के अंतर्गत यथा अपेक्षित वास्तविक आयातों का साक्ष्य नहीं होगा।
- (viii) आयातों में मामूली वृद्धि के आधार पर ही बढ़े हुए आयातों का सकारात्मक निर्धारण करना पर्याप्त नहीं होगा। यद्यपि आयातों की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान मामूली वृद्धि हुई है फिर भी यह वृद्धि गंभीर क्षति के लिए तीव्र, अचानक अथवा पर्याप्त नहीं है जैसाकि डब्ल्यूटीओ/डएस-121 अर्जेन्टीना-फुटवियर (ईसी) में डब्ल्यूटीओ डीएसबी अपीलिय निकाय द्वारा व्याख्या की गई है।
- (ix) ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि यदि मार्च, 2020 के आयात संबंधी आंकड़ों पर विचार किया जाए तब पीयूसी का आयात वास्तव में बढ़ने के बजाय 2018-19 से एक प्रतिशत तक कम हुआ है जैसाकि घरेलू उद्योग द्वारा वार्षिकीकृत आंकड़ों के आधार पर दावा किया गया है।
- (x) रक्षोपाय जांच में क्षति का निर्धारण उस आधार पर नहीं किया जा सकता है जिस आधार पर पाटनरोधी अथवा प्रति संतुलनकारी शुल्क जांच में किया जाता है। और यह कि इसका विश्लेषण निश्चित रूप से उच्चतर मानदंड पर किया जाना चाहिए। “गंभीर क्षति” पारिभाषिक शब्दावली को भी परिभाषित रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4.12(क) में किया गया है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अत्यधिक सुधार किया है। उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, उत्पादकता आदि में वृद्धि हुई है। प्रतिवादी का यह दावा है कि घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का उपयोग तथा उत्पादन में वृद्धि करने में सक्षम रहा है लेकिन कहीं भी इसने यह दर्शाया नहीं है कि घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री के संबंध में आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है।
- (xi) रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4.2(ख) में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि बढ़े हुए आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए “बढ़े हुए आयातों को उत्तरदायी नहीं माना जाएगा”। घरेलू कीमतों में इसी गिरावट का कारण वैश्विक स्तर पर विचाराधीन उत्पाद की गिरती हुई कीमतों और न कि भारत में विचाराधीन उत्पादों के आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन, यदि कोई हो, को बढ़े हुए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। कुछ कारक जो बढ़े हुए आयातों और कथित गंभीर क्षति और उसके खतरे के बीच कारणात्मक संबंध के न होने को दर्शाता है, मांग और आपूर्ति में अंतर, भारतीय सौर निर्माण उद्योग की अन्तर्निहित कमियां, गंभीर क्षति के न होने तथा आयातों में वृद्धि को दर्शाने में अपर्याप्तता है।
- (xii) घरेलू उद्योग की क्षमता के उपयोग में 2016-17 में 44 प्रतिशत से 2019-20 के दौरान 75 प्रतिशत (वार्षिकीकृत) तक वृद्धि हुई है जो 70 प्रतिशत तक समतुल्य वृद्धि है। उसी प्रकार से घरेलू उद्योग के घरेलू उत्पादन में 2016-17 में 100 सूचकांक-मेगावाट अंक से 2019-20 के दौरान 171 सूचकांक-मेगावाट अंक (वार्षिकीकृत) तक वृद्धि हुई है जो 71 प्रतिशत तक समतुल्य वृद्धि है। घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बिक्री में मात्रा के मामले में 2016-17 में 100 सूचकांक-मेगावाट से 2019-20 में 166 सूचकांक-मेगावाट(वार्षिकीकृत) तक वृद्धि हुई है। यह कहना सही नहीं है कि घरेलू बिक्री में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट हुई है।
- (xiii) घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा सर्वाधिक हाल की अवधि में तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। यह भी अवश्य नोट किया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2018-19 में 60 सूचकांक प्रतिशत अंकों से 2019-20 में 124 सूचकांक प्रतिशत अंकों (वार्षिकीकृत) तक वृद्धि हुई है जो उस वर्ष में 64 प्रतिशत तक समतुल्य वृद्धि है जबकि आयातों के बाजार हिस्से में वास्तविक रूप में उसी अवधि के दौरान 3 सूचकांक प्रतिशत अंकों तक गिरावट देखी है।
- (xiv) घरेलू उद्योग को कीमत में कटौती की गणना करने में एमएसपीएल को शामिल नहीं करना चाहिए। इस याचिका में दी गई कटौती सही नहीं है और उसकी गणना फिर से की जानी चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी

को वर्तमान जांच में उचित विश्लेषण के उद्देश्य से शीघ्रातिशीघ्र संशोधित आंकड़े फिर से प्रस्तुत करने के लिए घरेलू उद्योग को निदेश देना चाहिए।

- (xv) कीमत में कटौती की गणना एमएसपीएल अर्थात् विशेष आर्थिक क्षेत्र के एकक सहित घरेलू उत्पादकों द्वारा वसूली जाने वाली औसत कीमतों के आधार पर की जाती है। कीमत में कटौती की गणना करने में, विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सोलर सेल के लिए कीमत में कटौती 2016-17 में 55-65 प्रतिशत से घटकर जांच की अवधि के दौरान 0-10 प्रतिशत तक हो गई है। उसी प्रकार से, सोलर मोड्यूल के लिए कीमत में कटौती 2017-18 में 35-45 प्रतिशत से घटकर जांच की अवधि के दौरान 5-15 प्रतिशत तक हो गई है।
- (xvi) कुछ कारक जो बढ़े हुए आयातों और कथित गंभीर क्षति तथा उसके खतरे के बीच कारणात्मक संबंध में विच्छेद को दर्शाते हैं, उनकी सूची नीचे दिए गए अनुसार है:
- क. मांग और आपूर्ति में अंतर
- ख. भारतीय सौर निर्माण उद्योग में अंतर्निहित करना
- ग. बढ़े हुए आयातों को दर्शाने में अपर्याप्तता
- घ. कथित गंभीर क्षति का ना होना
- (xvii) भारतीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 18 में घरेलू उद्योग से यह अपेक्षित है कि वे माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सकारात्मक रूप से समायोजन करें और निर्दिष्ट प्राधिकारी रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाए जाने के लिए सिफारिश करें। घरेलू उद्योग को जुलाई, 2018 से शुल्क संरक्षण मिल रहा है और उसने अभी तक समायोजन योजना के अनुसार सकारात्मक रूप से समायोजन करने के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किए हैं। घरेलू उद्योग ने पीईआरसी प्रौद्योगिकी अथवा द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी परियोजना जो एक अन्य कदम था जिसका वे शुल्क संरक्षण प्राप्त करते समय उठाना चाहते थे, के उपयोग पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। घरेलू उद्योग ने सकारात्मक समायोजन के संबंध में दस्तावेज संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके अलावा, प्रश्नावली के उत्तर के साथ उपलब्ध कराई गई संशोधित समायोजन योजना अस्पष्ट और अत्यधिक गोपनीय है। घरेलू उद्योग को कम से कम मूल रक्षोपाय जांच के दौरान उपलब्ध कराई गई समायोजन योजना तथा वर्तमान समीक्षा जांच में उपलब्ध कराई गई समायोजन योजना के बीच तुलना का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराना चाहिए था।
- (xviii) घरेलू उद्योग ने इस तथ्य का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि इस प्रकार से विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाए जाने का प्रतिकूल प्रभाव उपभोक्ताओं/प्रयोक्ता उद्योग पर पड़ेगा और भारत में प्रयोक्ता उद्योग/उपभोक्ता अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।
- (xix) रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना जन हित में नहीं है। वैश्विक स्तर पर तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि प्रयोक्ता उद्योग घरेलू उद्योग से अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप विचाराधीन उत्पाद प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, प्रयोक्ता उद्योग के पास विदेशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। चूंकि उनकी परियोजनाओं को घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता न होने के कारण बंद किया जा सकता है अतः इस प्रकार से शुल्कों को लगातार लगाए जाने से आयात वित्तीय रूप से गैर-अर्थक्षम बन जाएगा। यह भारत में प्रयोक्ता उद्योग के हित को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा।
- (xx) शुल्क को लगातार लगाए जाने से आयातों के लिए व्यापार संबंधी अवरोध उत्पन्न होगा जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा एकाधिकार बन जाएगा और इसके फलस्वरूप डाउन स्ट्रीम उद्योगों जो देश में सामूहिक रूप से बहुत अधिक मात्रा में रोजगार देते हैं, को क्षति होगी। यदि इस शुल्क को हटा लिया जाता है तब उनके पास और अधिक रोजगार उत्पन्न करने की विशाल संभावना है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 दिसंबर, 2017 को एक अवधारणा नोट

जारी किया गया था जिसमें इसने इस बात का उल्लेख किया; “प्रति वर्ष वर्तमान अधिकतम सोलर सेल निर्माण क्षमता 20 गीगा वाट अर्थात् 15 प्रतिशत की औसत आवश्यकता के विरुद्ध लगभग 3 गीगा वाट ही है। शेष क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदा जाना होता है”। भारत में विचाराधीन उत्पादों के आयातों में वृद्धि के लिए घरेलू आपूर्ति की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारतीय सौर निर्माता अप्रचलित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते रहे हैं और वे घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बहुत अधिक अपर्याप्त है।

- (xxi) हालांकि भारतीय निर्माताओं के पास एक समन्वित उत्पादन चेन का आधार है। इसके फलस्वरूप उनमें अन्तर्निहित कमियां हैं जिसके कारण वे वैश्विक कंपनियों के विरुद्ध अप्रतिस्पर्धी हो गये हैं।
- (xxii) घरेलू उद्योग ने एक वर्ष में 0.05 प्रतिशत की मामूली दर से इस शुल्क को उदार बनाने का प्रस्ताव किया है जो अपने आप में यह दर्शाता है कि यह सकारात्मक रूप से समायोजित करने के लिए इच्छुक नहीं है। इस कमी की विषमता को देखते हुए इतनी कम उदारीकरण के बारे में किसी रक्षोपाय जांच में नहीं सुना गया है। मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों में भी, माननीय प्राधिकारी ने तीन चरणों में 5 प्रतिशत कटौती की सिफारिश की है।
- (xxiii) भारत की सरकार का विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर 20 प्रतिशत तक मूल सीमा शुल्क (“बीसीडी”) तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह 15 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क के मौजूदा अधिरोपण की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक होगी और यह 14.95 प्रतिशत शुल्क के अतिरिक्त है जिसका घरेलू उद्योग में समीक्षा में अनुरोध किया है। बीसीडी में वृद्धि के योग के साथ घरेलू उद्योग अब अपने हितों की रक्षा करने के लिए रक्षोपाय शुल्क की आवश्यकता नहीं है। बीसीडी में वृद्धि के अलावा रक्षोपाय शुल्क के फलस्वरूप समग्र प्रयोक्ता उद्योग जो पहले से आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है पर अपरिवर्तनीय नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- (xxiv) 2019-20 के दौरान, भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों का 94 प्रतिशत तीन देशों – चीन जन.गण-75 प्रतिशत, थाईलैंड – 10.2 प्रतिशत और वियतनाम – 9.4 प्रतिशत से हुआ। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात न केवल चीन जन.गण, थाईलैंड और वियतनाम से बहुत अधिक मात्रा में भारत में हो रहा है बल्कि वियतनाम और थाईलैंड से आयात कीमत में भी जांच की समग्र अवधि के दौरान सतत रूप से कमी आई है। जहां घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापार कार्य-पद्धति जैसे कम कीमत पर आयातों से हानि हो रही है, यह उपचार पाटनरोधी प्रावधानों के अंतर्गत और न कि रक्षोपाय प्रावधानों के अंतर्गत है।

21. जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के उत्तर में और अपने लिखित अनुरोधों में तथा कनाडा के सोलर द्वारा की गई मौखिक सुनवाई में निम्नलिखित अनुरोध किए गए:

- (i) थाईलैंड से आयातों की मात्रा को इस याचिका में बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। थाईलैंड से आयात उस स्थिति में 3 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं जब घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार आयात की मात्रा पर विचार कुल आयातों की मात्रा और थाईलैंड से आयातों की मात्रा का आंकलन करने के लिए किया जाता है। वे वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 अर्थात् जांच की अवधि के प्रथम दो वर्षों में तीन प्रतिशत से कम थे। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसमें यह प्रावधान हो कि प्राधिकारी को जांच की अवधि में पिछले 18 महीने की अवधि पर विश्वास करना चाहिए।
- (ii) नियम 18 (1)(i) में उन देशों पर नए सिरे से रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का प्रावधान नहीं है जो मूल रूप से रक्षोपाय शुल्क के अधिधीन नहीं थे। तदनुसार, मूल जांच के अनुसरण में रक्षोपाय शुल्क के क्षेत्र से बाहर किए गए विकासशील देशों को समीक्षा के अनुसरण में शामिल नहीं किया जा सकता है।
- (iii) यदि इस तरह के विस्तार की आवश्यकता वाली कोई असाधारण परिस्थितियां न हों तब रक्षोपाय शुल्क का विस्तार सामान्य रूप से समीक्षा में नहीं किया जाना चाहिए।
- (iv) यदि ऐसे विस्तार की आवश्यकता वाली असाधारण परिस्थितियां न हों तब रक्षोपाय शुल्क का विस्तार सामान्य रूप से समीक्षा में नहीं किया जाना चाहिए। अन्य अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क के विस्तार के फलस्वरूप रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 8 के अनुसार भारत और निर्यातक विश्व व्यापार संगठन

देशों के बीच गैट 1994 के अंतर्गत मौजूदा रियायतों और अन्य दायित्वों के पर्याप्त रूप से समतुल्य स्तर को स्थगित करना पड़ेगा।

- (v) मूल जांच में प्राधिकारी ने आई टी करार ("आईटीए-1") के अनुसरण में पीयूसी के आयातों पर 0 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क के बाध्यकारी प्रशुल्क रियायत पर विश्वास किया। एचएस कोड 8541 4011 और 8541 4012 के अंतर्गत प्रशुल्क दर को पहले ही 1 फरवरी, 2020 से वित्त अधिनियम, 2020 के माध्यम से 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार से अब यह आशा है कि वे सोलर सेल और मॉड्यूल के आयात पर सीमा शुल्क की दर में इस वृद्धि को लगाने के लिए अपने निर्णय की घोषणा करें। यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या आईटीए-1 भारत की स्वतंत्र कार्यवाही को रोकता है और इसे सोलर सेल और मॉड्यूल के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने से रोकता है। किसी भी मामले में यह सुनिश्चित करना कि भारत विश्व व्यापार संगठन के विरोधी रवैये को सूचित नहीं करता है, रक्षोपाय शुल्क और सीमा शुल्क दोनों नहीं लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या 20 प्रतिशत की मूल सीमा शुल्क उसी प्रकार से लगाई गई है जिस प्रकार से सीमा प्रशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उस पर विचार किया गया है, घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण मिलेगा और 15 प्रतिशत की अतिरिक्त रक्षोपाय शुल्क की कोई आवश्यकता नहीं है।
- (vi) सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल की अलग अलग भौतिक विशेषताएं, अलग अलग उपयोग, अलग अलग कीमत निर्धारण और अलग अलग उत्पादन की प्रक्रिया है और इन्हें वर्तमान रक्षोपाय समीक्षा में घरेलू उद्योग के आधार का निर्धारण करने के उद्देश्य से पृथक् रूप से माना जाना चाहिए। प्राधिकारी को इस बात का आकलन अवश्य करना चाहिए कि क्या इन याचिकाकर्ताओं द्वारा संबद्ध वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है जैसाकि पाटनरोधी जांचों में प्राधिकारी द्वारा (क) चीन जन.गण से फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नकल्स तथा (ख) चीन और मेक्सिको से पेंसिलिन – जी और 6एपीए के संबंध में किया गया है।
- (vii) सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल के आधार का आकलन पृथक् रूप से किया जाना चाहिए। सोलर सेल की उनकी उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए, अनेक अलग-अलग पीवी सेल को बंद, वाटरप्रूफ पैकेज में एक साथ अंतर-संयोजन किया जाता है जिसे मॉड्यूल कहा जाता है। सोलर मॉड्यूल का अलग अलग स्वतंत्र उत्पादक है जो सोलर सेल के उत्पादक नहीं हैं। इन मॉड्यूल उत्पादकों के उत्पादन को इन घरेलू उत्पादन से अलग नहीं रखा जा सकता है। सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल के कुल भारतीय उत्पादन पर इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग का हिस्सा कुल उत्पादन में बड़ा हिस्सा होता अथवा नहीं। यदि वैसा किया जाता है तब यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित करेगा कि घरेलू उद्योग के पास सोलर मॉड्यूल के लिए पर्याप्त आधार नहीं है क्योंकि भारत में कुल मॉड्यूल उत्पादन में इन याचिकाकर्ताओं का हिस्सा बहुत कम है और यह बहुत बड़ा हिस्सा नहीं माना जाएगा।
- (viii) दिनांक 6 सितंबर, 1997 के व्यापार नोटिस एसजी/टीएन/1/97 में आवेदन का प्रपत्र तथा आवेदन में दिए जाने वाले आंकड़ों का प्रपत्र दिया गया है। हालांकि याचिकाकर्ताओं कंपनियों ने अनेक आर्थिक मानदंडों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता का दावा किया है जो गंभीर क्षति के आकलन के लिए संगत नहीं है और डीजीटीआर द्वारा जारी किए गए दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुरोधों की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है जिसमें इस याचिका के गोपनीय और अगोपनीय पाठ में सूचना के प्रकटन के लिए दिशा-निर्देश दिया गया है। घरेलू उद्योग ने व्यापार नोटिस का उल्लंघन करते हुए ऐसी अत्यधिक गोपनीयता के लिए किसी सही कारण को भी नहीं दर्शाया है। याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका के परिशिष्ट 10 पर गोपनीयता के दावे को खारिज कर दिया जाएगा।
- (ix) विश्व व्यापार संगठन के रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.2, करार के अनुच्छेद 2.1 और इस नियमावली के नियम 18 के संबंध में रक्षोपाय शुल्क तभी लगाया अथवा इसका विस्तार किया जा सकता है जब संबद्ध उत्पाद के "आयातों में वृद्धि" हो। केवल छह माह के आयात आंकड़े उपलब्ध हैं। इस प्रकार के आयात आंकड़ों को वर्ष 2019-20 के लिए आयात संबंधी मात्रा तय करने के लिए "वार्षिकीकृत" नहीं किया जा

सकता है क्योंकि इस प्रकार का वार्षिकीकरण सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख(1), विश्व व्यापार संगठन के रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 और रक्षोपाय की नियमावली के नियम 11 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित वास्तविक आयातों का साक्ष्य नहीं होगा। लौह और इस्पात उत्पादों के आयातों पर कुछ उपायों के मामले में भारत में विश्व व्यापार के पैनेल ने यह नोट किया कि पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए वस्तुपरक आंकड़े पिछले दो वर्षों की तुलना में प्रवृत्ति के आकलन के लिए अपेक्षित है।

- (x) भारत में पीएक्स-13 अथवा 6पीपीडी (रबड़ केमिकल) की रक्षोपाय समीक्षा तथा भारत में फिनोल की रक्षोपाय समीक्षा में महानिदेशक रक्षोपाय ने इस बात की जांच की कि क्या आयातों में अथवा न कि भारत में वृद्धि हुई है। इस प्रकार से इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयातों में वृद्धि की आवश्यकता रक्षोपाय समीक्षा पर भी लागू है।
- (xi) वर्तमान रक्षोपाय समीक्षा में, घरेलू उद्योग को यह दर्शाना चाहिए कि 2017-18 के बाद के प्रवर्ती वर्षों अर्थात् 2018-19 और वर्ष 2019-20 में आयातों में लगातार वृद्धि हुई है। हालांकि, आयात संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि इस अवधि में आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। आयातों में वृद्धि बिल्कुल हाल का, अचानक, तीव्र और अधिक होना चाहिए था जिससे कि “गंभीर क्षति” उत्पन्न हो अथवा होने का खतरा हो।
- (xii) आयातों में वृद्धि को 2016-17 के आधार वर्ष की तुलना में नहीं देखा जाना चाहिए। इस याचिका में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार हाल की अवधि में आयातों में उस स्थिति में गिरावट हुई है जब 2017-18 को आधार वर्ष के रूप में माना गया हो।
- (xiii) चीन जन.गण से आयातों में रक्षोपाय शुल्क को 25 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक क्रमिक कटौती के बावजूद पिछले दो वर्षों के दौरान रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की अवधि के दौरान वृद्धि नहीं हुई है। इस प्रकार से यह आशंका कि यदि रक्षोपाय शुल्क को 29 जुलाई, 2020 के बाद आगे शून्य प्रतिशत तक कम कर दिया जाता है तब इसके परिणामस्वरूप चीन जन.गण से आयातों में वृद्धि होगी, का कोई आधार नहीं है।
- (xiv) याचिकाकर्ता कंपनियों को रक्षोपाय संबंधी करार अनुच्छेद 4.1(ग) तथा इस अधिनियम की धारा 8ख(6)(ख) के संबंध में घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि उनका सामूहिक उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा नहीं होता है।
- (xv) इसके अलावा, यह याचिका निम्नलिखित को प्रकट नहीं करता है:
 - (क) सेल और माड्यूल की याचिकाकर्ता कंपनियों का कुल उत्पादन
 - (ख) सेल और माड्यूल का कुल भारतीय उत्पादन
 - (ग) सेल और माड्यूल में कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता कंपनियों का प्रतिशत हिस्सा
 - (घ) दो याचिकाकर्ता कंपनियों जिनका डीटीए में इकाइयां हैं सेल और माड्यूल में प्रतिशत हिस्सा (विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों के उत्पादन को अलग करने के बाद)।
- (xvi) घरेलू उद्योग ने कुल भारतीय उत्पादन और जांच की अवधि के दौरान इसके कुल उत्पादन का समस्त आंकड़ों को प्रकट नहीं किया है। कुल भारतीय उत्पादन गोपनीय नहीं हो सकता है क्योंकि यह सूचना विशेष रूप से घरेलू उद्योग से संबंधित नहीं है। इस सूचना के प्रकटन नहीं किए जाने पर, कोई प्रभावी प्रति उत्तर अनुरोध अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस दावे के उत्तर में नहीं किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग का समग्र जांच की अवधि के दौरान कुल भारतीय उत्पादन में 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा था। यदि याचिकाकर्ता कंपनियां सूचना प्रकट करने के लिए इच्छुक नहीं हो तब प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे रक्षोपाय नियमावली के नियम 7(3) के संबंध में इस प्रकार की सूचना को अस्वीकार कर दें।
- (xvii) प्राधिकारी को इस बात का भी सत्यापन करना चाहिए कि क्या डीटीए में स्थित दो याचिकाकर्ता कंपनियों की क्षमता अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 के दौरान कुल भारतीय उत्पादन में 55-60 प्रतिशत हिस्सा होगा। क्योंकि उनकी मिश्रित क्षमता केवल 390 मेगा वाट है।

- (xviii) जुपिटर इंटरनेशनल लि. मूल जांच में याचिकाकर्ता कंपनी नहीं थी। यह याचिका “(i) मूल जांच में जुपिटर इंटरनेशनल लि. को शामिल न किए जाने का कारण (ii) वर्तमान समीक्षा जांच में जुपिटर इंटरनेशनल लि. को शामिल किए जाने का कारण (iii) जांच की अवधि के दौरान जुपिटर इंटरनेशनल लि. की स्वतंत्र क्षमता, उत्पादन और बिक्री (iv) जुपिटर इंटरनेशनल लि. द्वारा संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन को आरंभ करने की तिथि के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।
- (xix) विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाईयों में स्थित याचिकाकर्ताओं को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उनका प्राथमिक लक्ष्य निर्यात बाजार की मांग को पूरा करना है। इलैक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स मामले में महानिदेशक रक्षोपाय के दिनांक 27 सितंबर, 2012 के अंतिम जांच परिणामों जहां डब्ल्यू एस आई इंडस्ट्रीज (विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित) को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से बाहर रखा गया था, विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है, जैसाकि डीजीटीआर द्वारा जारी किए गए पाटनरोधी मामलों के लिए प्रचालन कार्य-पद्धति मैनुअल में उल्लेख किया गया है।
- (xx) यदि मुन्द्रा सोलन पीवी लिमिटेड को घरेलू उद्योग क्षेत्र से बाहर किया जाता है तब, घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत में काफी हद तक कमी आएगी।
- (xxi) घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन नहीं कर रहा है। इन्डोसोलर लि. अब चालू नहीं रह गया है और यह दिवालियापन की प्रक्रिया का सामना कर रहा है तथा दस और कंपनियां भी इस अवधि के दौरान बंद हो गई हैं। रक्षोपाय शुल्क घरेलू उद्योग को सकारात्मक रूप से समायोजित करने की अनुमति नहीं दे रहा है और इस कारण से रक्षोपाय शुल्क का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- (xxii) इस याचिका में न दी गई परंतु प्रत्येक याचिकाकर्ता कंपनी के प्रश्नावली के उत्तर में दी गई संशोधित समायोजन योजना को गोपनीय के रूप में माना गया है। याचिकाकर्ता कंपनियों ने उसका अगोपनीय सारांश भी उपलब्ध नहीं कराया है।
- (xxiii) रक्षोपाय नियमावली के नियम 17 में नियमित अंतरालों पर शुल्क के प्रगामी उदारीकरण का प्रावधान है। नियमित अंतरालों पर रक्षोपाय शुल्क के उदारीकरण की आवश्यकता एक प्रतिकात्मक आवश्यकता नहीं है और इसे केवल प्रत्येक वर्ष के अंत में 0.05 प्रतिशत तक रक्षोपाय शुल्क कम करते हुए पूरा किया नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के शुल्क के कम उदारीकरण के लिए अनुरोध यह दर्शाता है कि रक्षोपाय शुल्क को जारी रखा जाना अपेक्षित नहीं है क्योंकि यह समायोजन को आसान बनाने के लिए उपयोगी नहीं होगा।
- (xxiv) रक्षोपाय निमावली के नियम 18 में यह अपेक्षित है कि रक्षोपाय शुल्क को गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। याचिकाकर्ता कंपनियों को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति का खतरा नहीं हो रहा है। डब्ल्यू टी/डीएस 178-यूएस-लैम्ब में अपीलीय निकाय के निर्णय के संबंध में, गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति का खतरा होने को आसानी से नहीं माना जा सकता है। प्राधिकारी को अपने आप को घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों के मूल्यांकन के आधार पर संतुष्ट करना चाहिए कि घरेलू उद्योग को हो रही क्षति “गंभीर” प्रकृति की है।
- (xxv) घरेलू उत्पादक जो बाजार हिस्से में गिरावट का अनुभव नहीं कर रहे हैं को इस आवेदन में घरेलू उद्योग के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। याचिकाकर्ता कंपनियों के बाजार हिस्से में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तुओं अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में काफी हद तक कमी आई है। वास्तविक क्षति का वस्तुपरक आंकलन अन्य भारतीय उत्पादकों जो बाजार हिस्से में गिरावट का अनुभव कर रहे हैं, के कार्य-निष्पादन की जांच किए बिना नहीं की जा सकती है।
- (xxvi) आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की क्षमता, बिक्री और उत्पादन में जांच की अवधि में बहुत अधिक सुधार हुआ है। यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को कर्मचारी और प्रतिदिन उत्पादकता के मामले में कोई क्षति नहीं उठानी पड़ी है। दोनों मानदंडों में अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है। इस कारण से घरेलू

उद्योग को बिल्कुल क्षति नहीं हुई है, समग्र हानि की प्रकृति जिसे गंभीर क्षति के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, में क्षति की बात छोड़ ही दी जाए।

- (xxvii) कीमत में कटौती का निर्धारण रक्षोपाय शुल्क को जोड़ने के बाद किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, कीमत में कटौती का रुझान यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योगक द्वारा आयातों और लाभ/हानि जिसका अनुभव किया गया है, द्वारा कीमत में कटौती के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। 2016-17 में, घरेलू उद्योग लाभ अर्जित कर रहा था, वर्ष 2017-18 में, हालांकि घरेलू उद्योग द्वारा आधार वर्ष से 41 सूचकांकों तक कम की गई कीमत में कटौती के कारण हानि होना शुरू हो गया। वर्ष 2018-19 में, कीमत में कटौती सेल और मॉड्यूल दोनों के लिए न्यूनतम थी हालांकि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई हानि अधिकतम थी।
- (xxviii) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि के दौरान लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। आयातों का बाजार हिस्सा स्थिर रहा है और इसके कारण जांच की अवधि के दौरान इसमें केवल 2 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।
- (xxix) रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 पर घरेलू उद्योग की निर्भरता यह तर्क देने के लिए है कि विकासशील देशों को किसी समीक्षा के अनुसरण में शुल्क लगाए जाने के क्षेत्र के भीतर शामिल नहीं किया जा सकता है, सही नहीं है क्योंकि यदि विकासशील देशों से आयातों को अलग करने की समीक्षा आवधिक आधार पर की जानी अपेक्षित थी, रक्षोपाय करार इस प्रकार के उद्देश्य के लिए समीक्षा तंत्र उपलब्ध कराया होता। यदि विकासशील देशों को रक्षोपाय शुल्क के दो वर्षों के बाद शुल्क के क्षेत्र में शामिल किया जाता है तब एक असंबद्ध कार्य-पद्धति सृजित हो जाएगी जिसके फलस्वरूप अनुमान लगाना कठिन होगा।
- (xxx) फिनोल रक्षोपाय जांच घरेलू उद्योग के तर्क का समर्थन नहीं करता है क्योंकि उक्त उत्पाद पर शुरू किए गए समीक्षा कार्यवाही में, एसजीडी अन्य विकासशील देशों पर लागू नहीं किया गया था जिन्हें मूल शुल्क के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था। एक तीसरी समीक्षा जांच इस बात का आंकलन करने के उद्देश्य से प्रथम समीक्षा के समाप्त होने के बाद किया गया था कि क्या अन्य देशों से फिनोल के आयात में वृद्धि हुई थी।
- (xxxi) घरेलू उद्योग ने गलत तरीके से घरेलू उद्योग के बचे रहने के साथ रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने को समतुल्य माना है। भारत में अन्य मॉड्यूल उत्पादकों (i) पतंजलि नवीकरणीय ऊर्जा प्रा. (ii) गोल्डी सोलर प्रा. लि. ने विशेष रूप से सोलर सेल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने पर आपत्ति की है। उन्होंने उल्लेख किया है कि स्वदेशी सेल निर्माण मुश्किल से 3 गीगा वाट है जो मॉड्यूल निर्माताओं की आवश्यकता का केवल 25 प्रतिशत होता है। दोनों कंपनियों ने सोलर सेल के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का विस्तार किए जाने के विरुद्ध विरोध किया है क्योंकि सोलर मॉड्यूल का निर्माण आयातों पर निर्भर करता है। यदि घरेलू उद्योग का यह दावा कि आयातों में कटौती सामान्य तौर पर जनहित में है, को स्वीकार कर लिया जाता है तब इसका अभिप्राय यह होगा कि रक्षोपाय शुल्क भारत में सभी आयातों पर लगाया जाना चाहिए जिसके लिए भारत में घरेलू उत्पादक है। जनहित की आवश्यकता की जांच विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में और न कि भारत में आयातों की तुलना में सामान्य रूप से की जानी है।
- (xxxii) एसजीडी को जारी रखने के फलस्वरूप छह वर्षों की कुल अवधि के लिए इसे लगाना होगा। भारत में पिछले 25 वर्षों में किसी उत्पाद पर छह वर्षों की लगातार अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया है।
22. मै. सीसीसीएमई द्वारा जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के उत्तर में और अपने लिखित अनुरोधों में तथा मौखिक सुनवाई में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- (i) प्राधिकारी ने केवल दो कंपनियों अर्थात् जुपिटर इंटरनेशनल लि. और जुपिटर सोलर पावर लिमिटेड को ही घरेलू उद्योग के क्षेत्र के लिए माना है और मुन्द्रा सोलर प्राइवेट लि.(विशेष आर्थिक क्षेत्र) को बाहर रखा है। हालांकि जेआईएल और जेएसपीएल के क्रियाकलापों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। चूंकि जेएसपीएल, जेआईएल के आदेशों के अनुसार संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने वाला एकमात्र जॉब वर्कर है, उसे घरेलू उद्योग के भाग के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह एक नया घटनाक्रम है जिसे मौखिक सुनवाई के समय तक याचिकाकर्ताओं द्वारा छुपा लिया गया था।
- (ii) विशेष आर्थिक क्षेत्र की ईकाई पर घरेलू उद्योग के भाग के रूप में फिर से विचार करने के लिए याचिकाकर्ताओं का अनुरोध सही नहीं है क्योंकि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 53 में यह प्रावधान है कि एक

विशेष आर्थिक क्षेत्र को अधिकृत क्रियाकलापों के उद्देश्य से भारत के सीमा शुल्क प्रक्षेत्र के बाहर एक प्रक्षेत्र माना गया है। इसके अलावा, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम की धारा 30(क) में यह प्रावधान है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र से डीटीए तक हटाई गई किसी वस्तु पर रक्षोपाय शुल्कों सहित सीमा शुल्क जहां भी ऐसी वस्तुओं पर लागू हो, तब वसूला जाएगा जब उसका आयात किया जाएगा जो निर्यातोन्मुख इकाईयों पर भी लागू एक शर्त है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित याचिकाकर्ताओं और निर्यातोन्मुख एककों में याचिकाकर्ताओं को घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि वे विभिन्न प्रोत्साहनों और लाभों जो उन्हें मिलता है, के कारण अलग वाणिज्यिक स्थिति पर नहीं हैं। इस कारण से विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों पर घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के द्वारा प्रभाव नहीं पड़ता है और तदनुसार घरेलू उद्योग में विशेष आर्थिक क्षेत्र के एककों को शामिल करने के लिए कोई कारण नहीं है।

- (iii) कुछ उत्पादों जिसमें भारतीय घरेलू उद्योग का उत्पादन करने की बिल्कुल नहीं अथवा अपर्याप्त क्षमता है अर्थात् महीन फिल्म उत्पाद, मोनो क्रिस्टलिन सोलर उत्पाद और सोलर सेल को संबद्ध वस्तुओं के क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए।
- (iv) सोलर सेल मॉड्यूल के लिए कच्चा माल है। कई अन्य मालों और अतिरिक्त उत्पादन प्रक्रियाओं की आवश्यकता सोलर सेल से मॉड्यूल का निर्माण करने के लिए होती है। इस कारण से वे अलग-अलग उत्पाद हैं जिनकी आवश्यकता विभिन्न प्रकार के ग्राहकों द्वारा महसूस की जाती है। इन तथ्यों पर विचार करते हुए, सोलर मॉड्यूल को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए।
- (v) मै. जुपिटर सोलर पॉवर लिमिटेड और मै. जुपिटर इंटरनेशनल लि. द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत किया गया संशोधित समायोजन योजनाएं अपर्याप्त और अनुपयुक्त हैं। पैथेलिक एनहाइड्राइड (पैन), पीब-13 अथवा 6पीपीडी (रबड़ केमिकल्स), 400 सीरीज के स्टेनलेस स्टील का कोल्ड रोलड फ्लैट प्रोडक्ट, भारत में अनराउट एल्युमिनियम का अलॉयड इनगोट्स नहीं, लचीला स्लैब स्टॉक पोलियोले (एफएसपी) के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच में, महानिदेशक ने उस स्थिति में एसजीडी लगाने से इंकार किया है जब घरेलू उद्योग समायोजन योजना के संबंध में दस्तावेज और उसके समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया। याचिकाकर्ता ने केवल लागतों में कमी का दावा किया लेकिन उन कदमों के बारे में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जो उन्होंने समायोजन करने के लिए उठाया है और यह कि क्या जिन कदमों को उन्होंने उठाया है और लागत में कटौती के बीच कोई संबंध है। प्रश्नावली के उत्तर में भी, उनके समायोजन का ब्यौरा बहुत संक्षिप्त है।
- (vi) घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित समायोजन योजना में, निर्माण की लागत ने नीचे की ओर की प्रवृत्ति दर्शाई है। इसे मुख्य कच्चा माल अर्थात् सिलिकॉन वेफर्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम होती कीमतों द्वारा आगे बढ़ाया गया है। उत्पादन की लागत में कटौती, वैश्विक स्तर पर कच्चे माल की कीमतों में कटौती के कारण समायोजन योजना के सकारात्मक कार्यान्वयन को नहीं ठहराया जा सकता है।
- (vii) यह दावा कि समायोजन योजना रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए आवश्यक नहीं है, सही नहीं है क्योंकि सीमा प्रशुल्क का नियम 5(2)(ख) जो आवश्यक परिवर्तनों सहित रक्षोपाय समीक्षाओं पर लागू है, में समायोजन योजना को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
- (viii) रक्षोपाय को तभी अपनाया जा सकता है जब बड़े हुए आयातों के कारण गंभीर क्षति होने का साक्ष्य हो और इस प्रकार की वृद्धि गैट के अनुच्छेद XIX:1(क) के अनुसार प्रत्याशित घटनाक्रमों तथा अर्जेन्टीना – फुटवियर (ईसी) पर अपीलिय निकाय द्वारा पुष्टि किए गए अनुसार परिणामके रूप में ही हुआ होगा। भावी आवेदकों के लिए प्रश्नावली का प्रपत्र उनसे यह अपेक्षा करता है कि वे अप्रत्याशित घटनाक्रम जिसे आवेदक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है, के मौजूद होने के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराएं। चीन जन.गण से भारत में 304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के हॉट रोलड फ्लैट उत्पादों के मामले में जारी किए गए अंतिम जांच परिणामों और यूएस – लैम्ब पर विश्वास किया गया जिसमें यह माना गया था कि अप्रत्याशित घटनाक्रमों के न होने पर एसजीडी नहीं लगाया जा सकता।
- (ix) चीन जन.गण से आयातों में वृद्धि का कारण कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है बल्कि भारत सरकार का ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का संबंध करने की परिकल्पना है जिसके फलस्वरूप सोलर सेल और मॉड्यूल के लिए मांग में वृद्धि हुई है। मांग और आपूर्ति में अंतर को चीन जन.गण और अन्य देशों से पर्याप्त घरेलू आपूर्ति के न होने पर

आयातों के द्वारा भरा जाना होगा। घरेलू उद्योग ने केवल यह तर्क दिया कि शुल्क को लगाया जाना अप्रत्याशित है परंतु इस बात की उपेक्षा की कि इस प्रकार के घटनाक्रमों और आयातों में वृद्धि के बीच कारणात्मक संबंध में आवश्यक है। भारतीय बाजार एक मुक्त एवं मांग उन्मुक्त बाजार है इसलिए आयातों में वृद्धि अन्य देशों द्वारा व्यापार उपचार उपायों को लगाने के बजाय मांग में वृद्धि के द्वारा होती है। अत्यधिक क्षमताओं को गैट के अनुच्छेद XIX के अभिप्राय से अप्रत्याशित घटनाक्रम के रूप में नहीं देखा जा सकता है। 2005 के स्तरों से सीओ2 के उत्सर्जन में 33-35 प्रतिशत तक कमी आने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, भारत का लक्ष्य 2022 तक 100 गीगा वाट सौर उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य है और इसे अप्रत्याशित भी नहीं माना जा सकता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय करार के अंतर्गत प्रतिबद्धताएं अप्रत्याशित हो सकती हैं परंतु यह तथ्य कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और उसके कारण प्रभाव पड़ सकता है और संगत बाजार में बदलाव आ सकता है, वास्तव में प्रत्याशित है।

- (x) वह उद्देश्य जिसके लिए याचिकाकर्ता शुल्क को जारी रखने का अनुरोध करते हैं क्षति का उपचार करने के लिए नहीं बल्कि बाजार में अपने एकाधिकार अथवा दबदबा वाली स्थिति बनाए रखने के लिए अवैध तरीकों से अन्यायोचित व्यापार संरक्षण प्राप्त करना है। घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है। आयातों को आपूर्ति और मांग में अंतर को दूर करने के लिए किया जाना है। एसजीडी लगाए जाने के नकारात्मक प्रभाव में निम्नलिखित शामिल रहेगा: (1) भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार संबंध (2) भारत में विभिन्न डाउनस्ट्रीम उद्योग और उपभोक्ता (3) सोलर सेल उद्योग का स्वस्थ विकास तथा इसके कारण बहुत व्यापक स्तर पर वर्तमान सरकार द्वारा आरंभ की गई ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव भी पड़ेगा। मिथाइल एसिटोएसिटेट के संबंध में अंतिम जांच परिणामों में, महानिदेशक रक्षोपाय ने एसजीडी लगाए जाने की सिफारिश नहीं की थी क्योंकि घरेलू उद्योग यह दर्शाने के लिए सक्षम नहीं था कि उक्त उत्पाद पर एसजीडी लगाना जनहित में था।
- (xi) आरंभिक स्तर पर, याचिकाकर्ता ने 2012 में एडीडी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सोलर सेल के आयातों पर शुल्क की सिफारिश की। हालांकि कोई भी एडीडी इस प्रकार की सिफारिशों के अनुसरण में नहीं लगाया गया था क्योंकि घरेलू सौर क्षमता हरित ऊर्जा के स्रोतों से बिजली के उत्पादन के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। बाद में, 2017 में, याचिकाकर्ताओं ने फिर से पाटनरोधी शुल्क की मांग की परंतु उस जांच को बाद में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए “अतार्किक और अन्यायोचित आधारों” के कारण याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर समाप्त कर दिया गया था।
- (xii) सेल का निर्माण करने के साथ जुड़ी हुई अत्यधिक लागत की मांग घरेलू उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक निर्माता के अनुसार, 100 मेगा वाट सेल निर्माण करने की सुविधा के लिए भूमि और अवसंरचना की लागतों को छोड़कर 800 मिलियन रुपए (10.53 मिलियन डॉलर) का निवेश आवश्यक है। हालांकि 100 मेगा वाट सेल की सुविधा विशेष रूप से चीन की सेल से आयात किए गए सेल की कीमतों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए वही किफायती उत्पादन नहीं होगा। 500 मेगा वाट की आदर्शतम क्षमता वही है, जो लाभप्रद होगा जिसके लिए 4 बिलियन रुपया (52.63 मिलियन डॉलर) के निवेश की जरूरत है। यद्यपि घरेलू निर्माता निवेश करने का निर्णय तो लेते ही हैं फिर भी मांग की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि सरकारी नीतियां बिना अधिक सूचना के अक्सर बदल जाती हैं। जब घरेलू उद्योग की निर्माण क्षमता डीसीआर श्रेणी के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए अपेक्षित स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अतः आयातों पर शुल्क लगाना अथवा उसे नियंत्रित करना अस्पष्ट/बेतुका है जिसका प्रभाव समग्र उद्योग पर पड़ेगा।
- (xiii) संबद्ध वस्तुओं के आयातों में विगत हाल में स्वतंत्र रूप में अथवा सापेक्ष रूप में कोई उछाल नहीं देखा गया है। हालांकि, 2016 से जांच की अवधि तक भारत में आयातों की वृद्धि का कारण आयातों का अचानक उछाल नहीं है बल्कि डाउनस्ट्रीम उद्योग के विकास के बाद भारतीय बाजार में विकास की मांग है।
- (xiv) घरेलू उद्योग की बिक्री बहुत अधिक विकास के साथ सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष 2016-17 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। क्षमता क्षति की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहती है। हालांकि, उत्पादन में 2019-20 के दौरान तेजी से वृद्धि हुई है। बिक्री की लागत में कमी आई है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है। तदनुसार आधार वर्ष की तुलना किए जाने पर जांच की अवधि के दौरान क्षमता के उपयोग में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार से संबद्ध देशों से आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

- (xv) इस नियमावली का नियम 5(2)(ख) में यह उल्लेख है कि इस आवेदन का समर्थन किए गए प्रयासों अथवा किए जाने वाले प्रयासों अथवा आयात प्रतिस्पर्धा का समायोजन करने के लिए विवरण द्वारा किया जाएगा। चूंकि वर्तमान जांच मार्च, 2020 को आरंभ की गई थी। अतः 2019-20 के लिए प्रस्तावित समायोजन योजना निष्फल हो जाती है। सही माइने में, घरेलू उद्योग चार वर्षों के लिए रक्षोपाय शुल्क सभी मर्दों पर लगाया जाना चाहता है परंतु 2020 के बाद अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने की इसकी कोई योजना नहीं है।

III) भारत में आयातक और व्यापार अथवा व्यापार संघ

23. भारत के निम्नलिखित आयातकों और व्यापार अथवा व्यापार संघों ने इस समीक्षा में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किया:

- (i) सोलर पॉवर डवलपर्स एसोसिएशन (“एसपीडीए”)
- (ii) शापूरजी पालोंजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कं. लि. (“शापूरजी”)
- (iii) विक्रम सोलर लिमिटेड (“विक्रम”)
- (iv) पतंजलि रेनेवेबल एनर्जी प्रा. लि. (“पतंजलि”)
- (v) गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड (“गोल्डी”)
- (vi) रिन्यूजिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (“रिन्यूजिज”)

24. एसपीडीए ने जांच की प्रक्रिया के दौरान कैनेडियन सोलर थाइलैंड द्वारा किए गए अनुरोधों को दोहराया है और उसका उल्लेख प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए फिर से नहीं किया गया है। केवल उन तर्कों जिन्हें विशेष रूप से एसपीडीए द्वारा उठाया गया है और कैनेडियन सोलर के अनुरोधों में उसका उल्लेख नहीं पाया गया है, उसे फिर से नीचे प्रस्तुत किया गया है:

- (i) एमएनआरई ने एलएमएम सूची-I (सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए) और एएलएमएम सूची-II (सोलर पीवी सेल के लिए) में बीआईएस मानकों का अनुपालन करते हुए सोलर पीवी सेल और मॉड्यूल के मॉडलों और निर्मातों का सूचीयन का प्रावधान करते हुए सोलरपीवी सेल और मॉड्यूल के लिए मॉडल और निर्माता (एलएमएम) की अनुमोदित सूची के संबंध में दिनांक 2.1.2019 का आदेश जारी किया था। इस सूची को 30 सितंबर, 2020 को प्रकाशित किया जाना निर्धारित है। इस कारण से महानिदेशक से अनुरोध किया जाता है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या याचिकाकर्ता कंपनियों ने विश्वसनीयता और संगठना सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता प्राप्त करने हेतु सकारात्मक रूप से समायोजन किया है और वह उस सूची में शामिल किए जाने के योग्य है।
- (ii) चीन जन.गण से आयातों में 25 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक रक्षोपाय शुल्क की क्रमिक कटौती के बावजूद रक्षोपाय शुल्क को लागू करने की अवधि के दौरान वृद्धि नहीं हुई है। इस प्रकार से यह आशंका कि 29 जुलाई, 2020 के बाद रक्षोपाय शुल्क में 0 प्रतिशत तक कटौती के फलस्वरूप चीन जन.गण. से आयातों में वृद्धि होगी, का आधार नहीं है।
- (iii) इसके अलावा, यूरोपीय यूनियन ने 3 सितंबर, 2018 से चीन के विरुद्ध सोलर सेल और मॉड्यूल पर पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों को वापस ले लिया और इसके फलस्वरूप चीन से यूरोपीय संघ में निर्यातों में वृद्धि हुई है और चीन जन.गण. के निर्यातों में भारत के हिस्से में 29.6 प्रतिशत से 7.3 प्रतिशत तक का अनुपातिक रूप से गिरावट आई है। इस प्रकार से यदि रक्षोपाय शुल्क को वापस ले लिया जाता है तब चीन को भारत में अपने निर्यात बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- (iv) इंडोसोलर लि. और विचाराधीन उत्पाद के दस अन्य घरेलू उत्पादक ने प्रचालन बंद कर दिया है अथवा दिवालियापन की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। इस कारण से घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजित नहीं कर रहा है जिससे कि विस्तार की आवश्यकता पड़े।

- (v) पिछले चार वर्षों की जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत में गिरावट पर निर्भरता सरल और भ्रामक है।
- (vi) घरेलू उद्योग तर्कसंगत रूप से यह दावा नहीं कर सकता है कि विकसित देशों जैसे यूरोपीय यूनियन देश, ताईवान, सिंगापुर सहित सभी देश और थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि जैसे अन्य छोटे छोटे विकसित देश भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सस्ती और अनुचित कीमतों पर कर रहे हैं तथा उस स्थिति में भी घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रहे हैं जब घरेलू उद्योग ने पिछले दो वर्षों में सकारात्मक समायोजन के प्रति पर्याप्त कदम उठाया है।

25. शापूरजी द्वारा जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के उत्तर में और अपने लिखित अनुरोधों में तथा मौखिक सुनवाई में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) समीक्षा आवेदक यह सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि नियम 18(2) में उल्लिखित उन शर्तों को पूरा कर लिया गया है जिसे कि दो वर्ष की अवधि से आगे (जुलाई 2018 से जुलाई 2020 तक) रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाया जाना आवश्यक हो।
- (ii) वर्तमान समीक्षा जांच विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क को पूर्व में लगाए जाने की वैधता को चुनौती देते हुए जो माननीय मद्रास हाइकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, कंपनी द्वारा फाइल की गई रिट याचिका के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
- (iii) समीक्षा आवेदक रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 18 के साथ पठित धारा 8ख के संबंध में “घरेलू उद्योग” के रूप में योग्य नहीं हैं और उन्हें विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना जारी रखने के लिए समीक्षा आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। समीक्षा आवेदकों के पास घरेलू संस्थापिक क्षमता का एक बहुत छोटा हिस्सा है जो उन्हें घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने से अयोग्य ठहराता है और उन्हें समीक्षा आवेदन दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- (iv) विचाराधीन उत्पाद के आयात में कोई वृद्धि नहीं हुई है इस बात का आकलन कि क्या आयातों में कोई वृद्धि हुई है अथवा नहीं उन वर्षों के दौरान आयात संबंधी मात्राओं का विश्लेषण किया जाना चाहिए जिसमें रक्षोपाय शुल्क लगाया गया है अर्थात् 2018-19 और 2019-20 और उसके साथ रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के तत्काल पूर्व के वर्ष अर्थात् 2017-18 का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए जिसे दिनांक 16.7.2018 के जांच परिणामों में अंतिम वर्ष के रूप में माना जाएगा। ऐसे वर्ष (2017-18) के पूर्व किसी वर्ष से आयात संबंधी मात्राओं की तुलना करने का आशय यह होगा कि करार, सीपीए अथवा रक्षोपाय नियमावली में मूल जांच की जांच के अधीन अवधि के प्रथम वर्ष में आयातों की तुलना में आयात के कम होने तक जोकि यह मामला नहीं है, रक्षोपाय शुल्क लगाने की परिकल्पना है। स्वतंत्र रूप में और सापेक्ष रूप में (घरेलू बिक्री की तुलना में) आयातों का आकलन यह दर्शाता है कि उसमें वृद्धि नहीं हुई है।
- (v) इस बात का कोई आकलन कि क्या घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है, पर आवश्यक रूप से विचार किया जाना चाहिए, न केवल सोलर सेल पर बल्कि सोलर मॉड्यूल/पैनलों पर भी जो विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा है, सकारात्मक शुल्क का प्रभाव और उसका आयात रक्षोपाय शुल्क के अध्येधीन रहा है।
- (vi) यह दर्शाने का कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उद्योग रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए सही तरीके समायोजित कर रहा है। समायोजन योजना के संबंध में घरेलू उद्योग ने अगले तीन वर्षों के लिए भावी कार्य-निष्पादन नीचे दिए गए अनुसार उपलब्ध कराया है:
 - i. यदि बेहतर नकद प्रवाह प्राप्त हो तब कच्चे माल की दीर्घावधि खरीद, दर और मात्रा में छूट।
 - ii. क्षमता का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग जिसके फलस्वरूप बेहतर परिवर्तन लागत होती हो।
 - iii. अर्थ निर्धारित और निर्धारित लागतों का बेहतर विभाजन।
 - iv. बेहतर क्रेडिट रेटिंग उधार की लागत को कम करेगा और ऋण की बेहतर सर्विसिंग करेगा।

- v. बैकवर्ड एकीकरण के प्रति प्रयास और एक समग्र कार्य-प्रणाली विकसित करना।
- vi. प्रौद्योगिकी का विकास एवं आर एंड डी।
- (vii) समीक्षा आवेदकों ने केवल यह दर्शाया है कि उन्होंने लागत में कमी (कच्चे माल की, परिवर्तन लागत निर्धारित लागत) प्राप्त किया है। इसके अलावा, समीक्षा आवेदकों ने यह दर्शाने के लिए कोई आंकड़े नहीं दिए हैं अथवा कोई दावा नहीं किया है कि घरेलू उद्योग ने अन्य कार्य-निष्पादन (समायोजन योजना में) प्राप्त किया है अथवा उसे पूरा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाया है। घरेलू उद्योग यह दावा नहीं कर सकता है कि यह रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए यह दर्शाने के लिए सूचना/आंकड़े उपलब्ध कराए बिना सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है कि उपर्युक्त समायोजन योजना को पूरा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। इस प्रकार की सूचना/आंकड़ों को उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में, समीक्षा आवेदकों का दावा झूठा है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- (viii) घरेलू उद्योग का तथा विचाराधीन उत्पाद के अन्य घरेलू निर्माताओं का आवश्यक आर्थिक आंकड़ा अस्पष्ट है जिसमें समीक्षा आवेदन का उपर्युक्त रूप से उत्तर देना कठिन बना दिया है। यह खाली औपचारिकता वाला उत्तर है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से पूर्व की अवधि अर्थात् 30 जुलाई, 2018 से पूर्व की अवधि के लिए आर्थिक आंकड़े पर समीक्षा आवेदन में गलत तरीके से विचार किया गया है। सकल आंकड़े सूचीबद्ध आंकड़ों के बजाय दिया जाना चाहिए था।
- (ix) घरेलू उद्योग किसी गंभीर क्षति का सामना नहीं कर रहा है जो रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाया जाना आवश्यक बनाएगा। आयातों में स्वतंत्र वृद्धि नहीं हुई है। सापेक्ष रूप में भी जब आयातों की मात्रा की तुलना घरेलू बिक्री से की जाती है तब यह देखा गया है कि आयात और घरेलू बिक्री दोनों में मात्रा संबंधी परिवर्तन मांग/खपत पर आधारित है। मात्रा और घरेलू बिक्री दोनों में गिरावट आई जब खपत में गिरावट आई थी। हालांकि, 2019-20 में जब खपत और मांग अधिक थी तब घरेलू बिक्री आयातों की तुलना में 101 प्रतिशत की बिक्री में वृद्धि के साथ पूर्व स्थिति में आ गई जिसमें केवल 9.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी। 2018 में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद, घरेलू बिक्री का बाजार हिस्सा आयातों के लिए उसी अवधि के बास्ते बाजार हिस्से में केवल 0.99 प्रतिशत वृद्धि के साथ तुलना किए जाने पर घरेलू उद्योग के लिए 2017-18 से 2019-20 तक बाजार हिस्से में लगभग 40.9 प्रतिशत वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बढ़ रहा है। घरेलू बिक्री (मेगावाट में) स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि जबकि 2018-20 में गिरावट आई थी (खपत में कमी के कारण) बिक्री का वही स्तर पिछले वर्ष 2018-19 से 130.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2019-20 में फिर तेजी से बढ़ गया। इस कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि आयातों का घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2018-19 जब खपत/मांग कम थी, को छोड़कर, उत्पादन की मात्रा और क्षमता के उपयोग में इस प्रकार की मांग को पूरा करने के लिए वृद्धिक रूप से बढ़ोतरी हुई है। यह दर्शाता है कि आयातों का इस प्रकार के संकेतकों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।
- (x) यह तथ्य कि संस्थापित क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है, आयातों के कारण नहीं बल्कि अन्य आर्थिक कारकों को छोड़कर हुई है जो घरेलू उद्योग को परेशानी में डालता है।
- (xi) लाभ और हानि के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 2019-20 में घरेलू उत्पादकों ने वर्ष 2018-19 के दौरान उठाई गई हानि से बहुत अधिक सुधार (91.1 प्रतिशत की सीमा तक) कर लिया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इन आयातों का घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
- (xii) कुछ अन्य संगत आर्थिक कारकों जैसे माल भंडार, कर्मचारियों की संख्या और प्रति कर्मचारी उत्पादकता के संबंध में आंकड़ों की भी तुलना की गई है। कर्मचारी की संख्या में कटौती/अवरोद्धता इस तथ्य के कारण हुई है कि सोलर सेल का निर्माण पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकीय उन्नति के साथ स्वचालित हो गई है। वर्ष 2019-20 में प्रति कर्मचारी उच्च उत्पादकता घरेलू उद्योग के घनात्मक विकास का द्योतक है जिसे आयातों के कारण गंभीर क्षति नहीं हुई है।

- (xiii) कीमत में कटौती के लिए पद्धति(जिसे क्षति का मुख्य स्रोत माना जाता है) उपलब्ध नहीं कराया गया है। जुपिटर इंटरनेशनल और जुपिटर सोलर पावर लिमिटेड के लिए मिश्रित संस्थापित क्षमता प्रत्येक कंपनी के लिए अलग-अलग संस्थापित क्षमताओं को उपलब्ध कराए बिना दिया गया है।
- (xiv) समीक्षा आवेदकों ने वर्ष-वार क्षति रहित कीमत (और कम कीमत पर बिक्री का आधार) बिंदु का निर्धारण उसके लिए किसी पद्धति/आधार उपलब्ध कराए बिना और समीक्षा आवेदक के दावे का खंडन करने के लिए कंपनी के लिए इसे असंभव बनाते हुए उसी स्पष्ट, संदिग्ध और समझ में न आने योग्य आंकड़ों की तुलना में सूचीबद्ध रूप में आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।
- (xv) घरेलू उत्पादकों ने सोलर सेल की लागत में काफी हद तक कटौती करने में सफल हुआ है और साथ ही साथ वे अपनी हानि को कम करने सहित उनके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार लाने में सफल हुआ है। ऐसे परिदृश्य में जहां घरेलू उद्योग उस समय वित्तीय रूप से सुधार कर रहा है जब समीक्षा आवेदक कीमत में कटौती का आरोप लगा रहे हैं, यह दर्शाता है कि घरेलू उत्पादकों को निःसंदेह रूप से प्रतिस्पर्धा देखते हुए आयातों की अपेक्षाकृत कम पहुंच मूल्य एकमात्र मानदंड है जो घरेलू उद्योग के प्रतिकूल है और वह क्षति का दावा करने के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।
- (xvi) कोई भी क्षति यदि थोड़ा भी हो तब वह उन आर्थिक कारकों के कारण हुआ है जिसका विचाराधीन उत्पाद के आयात से कोई लेना-देना नहीं है जो उस स्थिति में भी जारी रहेगा जब रक्षोपाय शुल्क को लगाया जाना जारी रखा जाएगा।
- (xvii) रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से प्रतिस्पर्धी असुविधा होने पर घरेलू उद्योग के लिए निहित कारण को समाप्त करने में बहुत कम सहयोग मिलेगा और मांग एवं दृश्यता से संबंधित समस्याएं बनी रहेगी। जबकि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से भारतीय निर्माताओं के लिए इकाई लागतों में कमी आएगी और नकदी के प्रवाह में सुधार आएगा परंतु इस प्रकार के लाभ का प्रभाव अस्थायी ही होगा। कुछ प्रमुख कारक जो घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धी असुविधा के लिए जिम्मेदार हैं स्पष्ट रूप से दर्शा रहे हैं कि क्षति, यदि कोई हो, इस प्रकार के कारकों के कारण हुई है (और न कि आयातों में उछाल के कारण) और उन्हें यहां नीचे दिया गया है:

- क. वित्त की अपेक्षाकृत अधिक लागत
- ख. उच्चतर बिजली कीमतें
- ग. अपेक्षाकृत कम किफायती उत्पादन
- घ. वर्टिकल इंटीग्रेशन की कमी
- ङ. संस्थापित क्षमता में वृद्धि का अभाव
- च. घरेलू उद्योग का क्षमता से कम उपयोग: आगे बढ़ाने में
- छ. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद पर आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद पर भरोसा नहीं किया जा सकता

- (xviii) रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाए जाने से जनहित में बाधा पहुंचेगी। इस संबंध में निम्नलिखित पर विचार कि जा सकता है:

- i. इसके फलस्वरूप विचाराधीन उत्पाद के आयातों में और आगे कमी आएगी (जो सोलर पावर परियोजनाओं का आवश्यक भाग होता है, और उसके द्वारा भारत के लिए 100 गीगा वाट सोलर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का के इस सम्मेलन के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव हो जाएगा।
- ii. रक्षोपाय शुल्क लगाने के कारण माँड्यूल की लागत में वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप बाद में परियोजना की लागत और बिजली प्रशुल्क की लागतों में वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप अवार्ड की गई परियोजनाएं और निविदाओं को रद्द करने में विलंब हुआ क्योंकि डवलपर ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

(एमएनआरई) द्वारा सिफारिश की गई प्रशुल्क की उच्चतम सीमा की व्यवहार्यता के बारे में संदेह व्यक्त किया है।

- iii. प्रशुल्क में वृद्धि के फलस्वरूप लगभग 5 गीगा वाट की अवार्ड की गई परियोजना क्षमता को रद्द करना पड़ा जो सरकार की 100 गीगा वाट सोलर बिजली क्षमता संस्थापित करने के लक्ष्य के लिए झटका था।
 - iv. परियोजना परिणामी अर्थात् सोलर विद्युत परियोजनाएं अधिक सघन हैं और प्रति मेगा वाट लगभग 3.45 मेगा (यूटिलिटी) और 24.72 (रूफटॉप) प्रत्यक्ष पूर्णकालिक समतुल्य जॉब उपलब्ध कराता है। सोलर विद्युत परियोजनाओं में निरस्तीकरण/विलंब के फलस्वरूप रोजगार की विशाल संभावना में कटौती हुई।
 - v. अतिरिक्त सुरक्षोपाय शुल्क लागत की वसूली और परियोजनाओं को रद्द करने से संबंधित समस्याएं जिनके फलस्वरूप अनिश्चितता पैदा हुई और निवेशक की धारणा को चोट पहुंची।
 - vi. आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(सी) का उल्लंघन होगा जिसमें राज्य से यह अपेक्षित है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि की शर्तों के लिए सम्मान बढ़ाने के लिए प्रयास करे।
 - vii. रक्षोपाय शुल्क लगाने के कारण स्वतंत्र मॉड्यूल निर्माताओं जिन्हें कच्चे माल की लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ा है क्योंकि वे आयात किए गए सोलर सेल पर अधिकांशतः निर्भर हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
 - viii. घरेलू रूप से उत्पादित सोलर सेल में से निर्मित घरेलू स्तर पर सोलर मॉड्यूल खरीदने के बजाय सोलर विद्युत डवलपर ने अपने लेन-देन को इस तरीके से संरचित किया ताकि जब रक्षोपाय शुल्क की दर न्यूनतम थी तब आयात किए गए सोलर सेल (जो अपेक्षाकृत सस्ता और गुणवत्ता में बेहतर था) से बनाए गए मॉड्यूल की अधिकांश राशि प्राप्त कर सके। सोलर सेल के घरेलू उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए रक्षोपाय शुल्क का अभीष्ट प्रभाव सीमित था।
 - ix. चीन की सरकार ने 2018 में सब्सिडी प्रदान करने की प्रणाली को बदलने का निर्णय लिया और सोलर परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोली की प्रणाली लागू की जिसके फलस्वरूप सोलर परियोजनाओं का विकास चीन में सीमित हो जाएगा। इसके फलस्वरूप चीन में घरेलू सोलर सेल के निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा है और उसके कारण कीमतों में बहुत अधिक गिरावट आई जिसके पास चीन की मांग पर अधिकांश रूप से निर्भर विशाल क्षमता है। ऐसी कीमतों को आयातों में भी दर्शाया गया है तथा यदि रक्षोपाय शुल्क को लगाया जाना जारी रखा जाता है तब भी आगे किसी कटौती की संभावना नहीं है – विशेषकर चूंकि यह अपेक्षाकृत कम दर पर ही लगाया जाएगा (पूर्व में लगाए गए शुल्क से कम)।
 - x. इस कारक के साथ-साथ कि रक्षोपाय शुल्क का परियोजना के निरस्तीकरण/विलंब के कारण सामान्य तौर पर सोलर उद्योग के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है अतः शुल्कों में वृद्धि आदि से आगे घरेलू उद्योग में निवेश प्रोत्साहित होगा और इसके परिणामस्वरूप जो आरंभ में उद्देश्य निर्धारित किया गया था उसका पूर्ण रूप से उल्टा प्रभाव पड़ेगा।
- (xix) घरेलू उद्योग का सकारात्मक रूप से समायोजन करने का कोई उद्देश्य/क्षमता नहीं है। यह स्पष्ट है क्योंकि उन्होंने प्रत्येक वर्ष के अंत में केवल 0.05 प्रतिशत के उदारीकरण का प्रस्ताव किया है जिसके माध्यम से हुए लम्बी समय अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क का अधिकतम संरक्षण प्राप्त करने में सक्षम हो सके।
- (xx) यदि घरेलू उद्योग का आरोप यह है कि पाटन के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होती है और उन्हें एक पृथक पाटनरोधी जांच का सहारा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कर, घरेलू उद्योग यह आरोप लगा नहीं सकते कि यह रक्षोपाय जांच के अंतर्गत एक आधार है।
26. मै. विक्रम द्वारा जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के उत्तर में अनुरोध और अपने लिखित अनुरोधों में और मौखिक सुनवाई में किया गया अनुरोध नीचे दिया गया है:

- (i) महानिदेशक(रक्षोपाय) को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख (6) के साथ पठित विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों के अंतर्गत, सोलर सेल चाहे उसे मॉड्यूल में अथवा पैनलों में असम्बल किया गया हो अथवा नहीं पर लगाया गया रक्षोपाय शुल्क विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों से डीटीए को सोलर सेल और/अथवा मॉड्यूल की स्वीकृति पर भुगतान योग्य नहीं होगा।
- (ii) यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों से डीटीए तक स्वीकृति रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के अध्यक्षीन हो तब विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों डीटीए इकाइयों की तुलना में मुश्किल में होगी और एसईजेड इकाइयों का अप्राकृतिक मृत्यु होगी और हजारों लोगों को अपना रोजगार खोना पड़ेगा।
- (iii) इससे स्वदेशी स्तर पर निर्माण किए गए सेल और मॉड्यूल का उत्पादन करने के लिए देश की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वीएसएल जो विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर कार्य करता है, के पीवी सेल और मॉड्यूल सहित पीवी सेल और मॉड्यूल निर्माताओं द्वारा किया गया समग्र निवेश निष्क्रिय हो जाएगा।
- (iv) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 की धारा 30 और सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख(6) के प्रावधानों के बीच व्याख्या संबंधी मुद्दे का निपटारा किए बिना अथवा अन्य प्रकार से विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को छूट दिए बिना रक्षोपाय शुल्क लगाना उत्पादों के विरुद्ध होगा और इससे शुल्क लगाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। रक्षोपाय शुल्क से विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को छूट दिए बिना रक्षोपाय शुल्क लगाने के कारण विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों को अपूर्णनीय क्षति होगी और इस प्रकार से घरेलू उद्योग को संपूर्ण रूप में समुचित रक्षोपाय संरक्षण नहीं मिलेगा।

27. मै. पतंजलि द्वारा जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के उत्तर में अनुरोध और अपने लिखित अनुरोधों में और मौखिक सुनवाई में किया गया अनुरोध नीचे दिया गया है:

- (i) सरकार को एक अन्य 3-4 वर्ष के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का विस्तार करना चाहिए लेकिन यह केवल मॉड्यूल के आयात पर होना चाहिए न कि सेल पर।
- (ii) स्वदेशी सेल निर्माता मुश्किल से 3 गीगा वाट है (स्वदेशी मॉड्यूल निर्माण का 25 प्रतिशत)। इसलिए अधिकांश मॉड्यूल निर्माताओं को रक्षोपाय शुल्क का भुगतान करने के बाद चीन का सेल आयात करना होता है और यह स्वदेशी मॉड्यूल की लागत को बढ़ा देता है और वह चीन के मॉड्यूल से अधिक महंगा हो जाता है।
- (iii) जब तक भारत के पास मॉड्यूल निर्माताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सेल निर्माण क्षमता है, एसजीडी को सेल पर जारी नहीं रखा जाना चाहिए ताकि स्वदेशी मॉड्यूल को कम किया जा सके।

28. मै. गोल्डी द्वारा जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के उत्तर में अनुरोध और अपने लिखित अनुरोधों में और मौखिक सुनवाई में किया गया अनुरोध नीचे दिया गया है:

- (i) सरकार को एक अन्य 3-4 वर्ष के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का विस्तार करना चाहिए लेकिन यह केवल मॉड्यूल के आयात पर होना चाहिए न कि सेल पर।
- (ii) भारतीय निर्माता आगे सेल के उत्पादन में निवेश के साथ अपनी निर्माण क्षमताओं का काफी हद तक विस्तार करने के लिए उत्सुक है। हालांकि अपेक्षाकृत कम सेल के उत्पादन की क्षमता और अधिक मांग के कारण, अधिकांश मॉड्यूल निर्माताओं को सेल का आयात करना होता है और एसजीडी का भुगतान करना जरूरी होता है और इससे स्वदेशी मॉड्यूल की लागत में वृद्धि हो सकती है।
- (iii) जब तक भारत के पास मॉड्यूल निर्माताओं की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है, एसजीडी को सेल के आयात पर जारी नहीं रखा जाना चाहिए ताकि स्वदेशी मॉड्यूल की लागत को कम किया जा सके।

29. मै. रिन्यूसिस द्वारा जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के उत्तर में अनुरोध और अपने लिखित अनुरोधों में और मौखिक सुनवाई में किया गया अनुरोध नीचे दिया गया है:

- (i) विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों के लिए सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8(6)(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग का गठन करने के उद्देश्य से किसी वस्तु के घरेलू उत्पादकों के रूप में विचार किए जाने के लिए कोई रोक नहीं है।
- (ii) डीटीए को विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्वीकृतियों पर सीमा शुल्क नहीं लगता है क्योंकि भारत ने आईटीए:1 का हस्ताक्षरकर्ता होने के अनुसरण में विचाराधीन उत्पाद के लिए अपनी सीमा शुल्क हटाकर “शून्य” कर दिया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित उत्पादकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के लिए डीटीए स्वीकृति पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों का यह दायित्व होता है कि वे सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) बनाए रखें। चूंकि डीटीए में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री पर विचार सकारात्मक एनएफई की गणना करने के उद्देश्य की जाती है अतः विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों को डीटीए में उसकी बिक्री करना जारी रखने में कोई बाधा नहीं है और सकारात्मक एनएफई बनाए रखने के उद्देश्य से भी निर्यात करने में कोई मजबूरी नहीं है।
- (iii) कोई लदान नहीं है और वास्तव में एक विशिष्ट प्रावधान है जो इस प्रकार की विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों के द्वारा डीटीए में बिक्री को आसान बनाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों के द्वारा इस प्रकार की डीटीए की बिक्री घरेलू बाजार में डीटीए पर आधारित संबद्ध वस्तुओं के अन्य निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा करता है। इस कारण से विशेष आर्थिक क्षेत्र की ये इकाईयां संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादक भी हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयां डीटीए में सतत रूप से संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करती रही है कि वे डीटीए में संबद्ध वस्तुओं की स्वीकृति देते समय सीमा शुल्क के अधिधीन नहीं हैं यूंकि सीमा शुल्क विचाराधीन उत्पाद पर “शून्य” है।
- (iv) इस तथ्य को देखते हुए कि कोई सीमा शुल्क डीटीए की स्वीकृति पर लगाने योग्य नहीं है, संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाली विशेष क्षेत्र की ये इकाईयां संबद्ध वस्तुओं के अन्य घरेलू उत्पादकों के समतुल्य है।
- (v) विद्वान महानिदेशक का अनराउट एल्युमिनियम के मामले में निष्कर्ष कानून पर ध्यान दिए बिना और मौन दोनों हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर बनाम सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लि. और एएनआर [(1991) 4 एससीसी 139] के मामले में स्पष्ट रूप से यह माना है कि वह उस मामले जो कानून पर ध्यान दिए बिना और मौन दोनों हैं, के संबंध में निर्णय एक बाध्यकारी पूर्व उदाहरण नहीं है और इसे बाद के मामले के बारे में निर्णय लेते समय विचार किए जाने से उपेक्षा नहीं की जा सकती है।
- (vi) उपर्युक्त कारणों से, पूर्व के अंतिम जांच परिणाम पर फिर से विचार किया जाएगा और विशेष आर्थिक क्षेत्रों को घरेलू उद्योग के एक अभिन्न हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा और इस प्रकार से विशेष आर्थिक क्षेत्र से डीटीए को आपूर्ति को रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से रोका जाएगा।

(iv) आवेदक घरेलू उद्योग – इंडियन सोलर मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन ("घरेलू उद्योग" अथवा "डीआई")

30. जांच की शुरुआत की सूचना के उत्तर में और अपने लिखित अनुरोधों तथा घरेलू उद्योग द्वारा की गई मौखिक सुनवाई में अनुरोध:

- (i) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सोलर सेल चाहे वे मॉड्यूलों अथवा पैनलों में असेंबलड हैं अथवा नहीं" है। व्यावहारिक प्रयोग के लिए, सोलर सेलों को पैक किया जाता है और असेंबली में जोड़ा जाता है तथा सोलर सेलों की इस असेंबली को सोलर पैनल अथवा सोलर मॉड्यूल कहा जाता है। सोलर पैनल में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वांछित आउटपुट वाट प्राप्त करने के लिए सीरीज को और/अथवा वांछित करंट क्षमता प्रदान करने के लिए पैनल में किया जाता है। वित्त अधिनियम, 2020 की तीसरी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 2(ii) तथा दिनांक 02 फरवरी, 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 1/2020-सीमा शुल्क (एसजी) के मद्देनजर विद्यमान रक्षोपाय अर्थात् 15 प्रतिशत शुल्क सीमा प्रशुल्क शीर्ष 85414011 और 85414012 के

तहत वर्गीकरणीय "सोलर सेल चाहे वे मॉड्यूलों अथवा पैनलों में असेंबलड हैं अथवा नहीं" पर लागू है। तथापि, प्रशुल्क शीर्ष केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह आयातित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। अकेले उत्पाद का विवरण रक्षोपायों को लागू करने के प्रयोजन के लिए निपटान योग्य होना चाहिए।

- (ii) विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण दो प्रमुख प्रौद्योगिकियों (1) क्रिस्टलीन सिलिकॉन (सी-एसआई) आधारित सोलर सेल टेक्नोलॉजी, जो सिलिकॉन जल आधारित प्रौद्योगिकी के रूप में भी जानी जाती है, और (2) थिन फिल्म टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किया जा रहा है। सी-एसआई प्रौद्योगिकी एन-टाइप और पी-टाइप सिलिकॉन का प्रयोग कर सकती है तथा मोनो क्रिस्टलीन और मल्टी क्रिस्टलीन सिलिकॉन सामग्री का भी प्रयोग कर सकती है। थिन फिल्म प्रौद्योगिकी अमॉर्फस सिलिकॉन, कैडमियम टेलुरियम (सीडीटीई) अथवा सेमी कंडक्टर सामग्री के रूप में कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनियम का प्रयोग कर सकती है। सी-एसआई प्रौद्योगिकी और थिन फिल्म प्रौद्योगिकी, दोनों पर आधारित सोलर सेलों का भारत में आयात किया जाता है।
- (iii) आवेदक केवल सी-एसआई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले न कि थिन फिल्म प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले सोलर सेलों/मॉड्यूलों/पैनलों का विनिर्माण करते हैं। ये उत्पाद सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों में व्यापार संबंधी मंत्रालयी घोषणा के संलग्नक क, भाग 1 के अंतर्गत शामिल हैं जो आम तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटीए-1) के रूप में जाने जाते हैं। चूंकि भारत आईटीए-1 पर हस्ताक्षरकर्ता है, अतः आयातित उत्पाद आधारभूत सीमा शुल्कों से छूटशुदा हैं। संगत प्रशुल्क शीर्ष सेलों, मॉड्यूलों और थिन फिल्म मॉड्यूलों को एक उत्पाद के रूप में अभिज्ञात करता है और इन तीनों प्रकारों अर्थात् सी-एसआई सेलों, सी-एसआई सोलर मॉड्यूलों/पैनलों और थिन फिल्म मॉड्यूलों/पैनलों पर लागू है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से नए, चिल्ड अथवा फ्रोजन लैम्ब मीट के आयातों संबंधी यूएस – रक्षोपाय में अपीलीय निकाय द्वारा माने गए अनुसार "समान वस्तु का क्षेत्र" निर्धारित करते समय उत्पादों की पहचान तथा उनके "समान अथवा सीधे प्रतिस्पर्द्धी" संबंध पर जोर दिया जाना चाहिए न कि इन प्रक्रियाओं पर जिनसे वे उत्पाद उत्पादित किए जाते हैं।
- (iv) दोनों प्रकार के सोलर सेलों के बीच किसी वास्तविक अंतर के अभाव में, सी-एसआई प्रौद्योगिकी उत्पादों तथा थिन फिल्म प्रौद्योगिकी उत्पादों के बीच भिन्नता निकालने के किसी प्रयास से "समान अथवा सीधे ही प्रतिस्पर्द्धी उत्पाद" को परिभाषित करना नहीं होगा बल्कि उस समान अथवा सीधे ही प्रतिस्पर्द्धी उत्पाद का भाग होगा। यह दृष्टिकोण एओएस के अंतर्गत समान अथवा सीधे ही प्रतिस्पर्द्धी उत्पाद के निर्धारण के अनुरूप नहीं है तथा डोमोनिकन रिपब्लिक – रक्षोपायों में डब्ल्यूटीओ पैनलों को भी दोहराया गया है।
- (v) प्रकार्य एवं अंतिम प्रयोग के संवर्ग में विनिर्मित दोनों सोलर सेलों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है क्योंकि सी-एसआई तथा थिन फिल्म प्रौद्योगिकियों दोनों पर आधारित सोलर सेलों का प्रयोग फोटोवोल्टेक प्रक्रिया अपनाकर बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। तदनुसार, आयातित उत्पादों के संबंध में "सीधे ही प्रतिस्पर्द्धी/प्रतिस्थापनीय उत्पाद" के निर्धारण के लिए दोनों प्रकार के सोलर सेलों के बीच अंतर निकालने के लिए कोई आधार न होने पर विचाराधीन उत्पाद को "सोलर सेल चाहे वे मॉड्यूलों अथवा पैनलों में असेंबलड हैं अथवा नहीं" के रूप में सही निर्धारित किया गया है।
- (vi) यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई जांचों में थिन फिल्म प्रौद्योगिकी उत्पादों को जांचाधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया था। तथापि, कनाडा ने इसे क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया था। थिन फिल्म को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल करना और/अथवा हटाना प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर मामला दर मामला निर्धारण है। भारत में वर्तमान मामले में आने वाले तथ्य थिन फिल्मों को जांचाधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल करना अनिवार्य बनाते हैं अन्यथा पूरे कार्य के रक्षोपाय शुल्क की प्रवंचना हो सकती है क्योंकि आयातक शुल्कों से बचने के लिए आसानी से थिन फिल्मों में जा सकते हैं। "थिन फिल्म मॉड्यूलों" का आयात भी उसी शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है और सोलर सेलों/मॉड्यूलों जैसे आधारभूत सीमा शुल्क से छूटशुदा हैं।
- (vii) प्रथम पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम में थिन फिल्मों को सी-एसआई प्रौद्योगिकी से बनाए गए सोलर मॉड्यूलों की समान वस्तु माना गया था और निम्नलिखित कारणों से विचाराधीन उत्पाद में शामिल किया गया था जो कि इस समीक्षा पर भी लागू हैं:

- क. प्रौद्योगिकी में अंतर किसी भी प्रौद्योगिकी के माध्यम से सोलर पैनलों के अंतिम प्रयोगों को नहीं बदलता अथवा उसमें बाधा नहीं डालता;
 - ख. यहां तक कि यद्यपि प्रौद्योगिकी भिन्न है, तथापि दोनों प्रौद्योगिकी में अपनाया गया सिद्धांत समान अर्थात् सनलाइट को बिजली में बदलने के लिए फोटोवोल्टेक प्रक्रिया है;
 - ग. यहां तक कि यद्यपि आधारभूत कच्ची सामग्री भिन्न है, तथापि दोनों प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत प्रवृत्त कच्ची सामग्री की तकनीकी विशेषता फोटोवोल्टेक प्रौद्योगिकी के अनुरूप होने के गुणों वाली है;
 - घ. क्रिस्टलीन सोलर सेल सेमी कंडक्टर पी-एन जंक्शन डायोड होते हैं जो रोशनी को बिजली में परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार, थिन फिल्म आधारित सोलर सेल भी सेमी कंडक्टर पी-एन जंक्शन डायोड हैं और रोशनी को बिजली में परिवर्तित करते हैं।
 - ङ. दोनों प्रौद्योगिकियों के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा है क्योंकि दोनों प्रौद्योगिकियों के उत्पाद सोलर लाइट से विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं और विकासकर्ता आरंभिक स्तर पर अपनी विद्युत परियोजनाओं के लिए किसी भी प्रौद्योगिकी को चुन सकते हैं और उसके बाद अलग-अलग लाइनों में साथ-साथ प्रयोग कर सकते हैं।
 - च. दोनों सामान दोनों प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत अंतिम प्रयोक्ता को मॉड्यूल अथवा पैनल के रूप में दिए जा सकते हैं।
 - छ. लागत/कीमत भी वाट प्रति यूनिट, सेल/मॉड्यूलों की दक्षता जैसे कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती है और क्रिस्टलीन तथा थिन फिल्म उत्पादों के बीच बाजार परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा भी सामान्यतः दोनों प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत इन्हीं कारकों के आधार पर होती है।
 - ज. सभी प्रौद्योगिकियों के सोलर सेल सामान्य प्रशुल्क शीर्ष में सामान्य सीमा शुल्क वर्गीकरण प्रशुल्क शीर्ष 8541 40 11 के अंतर्गत वर्गीकृत थे। 01.02.2020 से संशोधन के बाद भी थिन फिल्म मॉड्यूल प्रशुल्क शीर्ष 8541 40 12 के अंतर्गत शामिल हैं जिसमें सी-एसआई सोलर सेलों से बने सेलों वाले मॉड्यूल भी शामिल हैं।
 - झ. एक प्रौद्योगिकी के उत्पाद, जो दूसरी प्रौद्योगिकी के उत्पाद में प्रकार्यात्मक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, पर रक्षोपाय शुल्क लगाना निरर्थक होगा क्योंकि जिस उत्पाद पर शुल्क नहीं है, वह बाजार में दूसरे का स्थान ले सकता है।
 - ञ. डिस्कॉमों और सोलर पावर विकासकर्ताओं के बीच विद्युत क्रय करार सोलर पावर संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रौद्योगिकियों के बीच अंतर नहीं करता।
- (viii) प्रशुल्क शीर्ष 85414011 (असेंबल न किए गए सोलर सेल) और प्रशुल्क शीर्ष 85414012 (मॉड्यूलों में असेंबल किए गए अथवा पैनलों में बनाए गए सोलर सेल) में विभाजित किए जा रहे प्रशुल्क शीर्ष 85414011 के बावजूद सेल और मॉड्यूल एक उत्पाद के रूप में माने जाने योग्य है। सोलर सेल तथा एक उत्पाद से मॉड्यूलों में व्यवस्थित किए गए सोलर सेल इस कारण विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कि सोलर मॉड्यूल कुछ नहीं है बल्कि सोलर सेलों की असेंबली है जो पैक किए जाते हैं तथा व्यावहारिक प्रयोग के लिए असेंबली में जोड़े जाते हैं। यूएस में सोलर सेलों के आयात संबंधी सुरक्षा जांच में यूएसआईटीसी के जांच परिणाम में सीएसपीवी सेलों, चाहे वे आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह से अन्य उत्पादों में असेंबल किए गए हों अथवा नहीं, जो सभी रूपों वाले एकल घरेलू उत्पाद पर विचार किया गया था। यूएसआईटीसी ने पाया कि यद्यपि सीएसपीवी मॉड्यूल सीएसपीवी सेलों के "समान" नहीं है, तथापि वे रक्षोपाय संविधि के अभिप्राय से "सीधे ही प्रतिस्पर्द्धी" हैं। चूंकि, सीएसपीवी सेल सीएसपीवी मॉड्यूल के आधारभूत तथ्य हैं, अतः सेल और मॉड्यूल, दोनों में समान प्राथमिक भौतिक गुणधर्म हैं। सीएसपीवी सेलों की विशेषताएं, जो उन्हें सनलाइट से बिजली में परिवर्तित करने में सक्षम बनाती हैं, मॉड्यूल असेंबली प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होते हैं बल्कि सीएसपीवी सोलर प्रणालियों में मॉड्यूल का एक अनिवार्य प्रकार्य है। इसी प्रकार, सीएसपीवी मॉड्यूल, सीएसपीवी सेलों को शामिल किए बिना सनलाइट को बिजली में परिवर्तित करने का अपना इच्छित कार्य नहीं कर सकते। सीएसपीवी सेलों से सीएसपीवी मॉड्यूलों का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाएं प्रौद्योगिकिय रूप से अत्याधुनिक, सीएसपीवी सेलों का विनिर्माण करने की अपेक्षा अधिक श्रमसाध्य हैं और

उत्पाद में मूल्यवर्धन करते हैं, परंतु वे परिवर्तन की अपेक्षा सीएसपीवी सेलों का आधारभूत कार्य बढ़ाते हैं जो कि सनलाइट को बिजली में परिवर्तित करना है। सीएसपीवी सेल और सीएसपीवी मॉड्यूल दोनों फोटोवोल्टेक सोलर प्रणालियों में एकीकृत किए जाते हैं जो आवासीय, वाणिज्यिक और यूटिलिटी अनुप्रयोगों के लिए सनलाइट को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। सीएसपीवी सेलों का परिष्कृत सीएसपीवी मॉड्यूलों की कुल लागत का काफी भाग होता है तथा सेलों की कीमतें सामान्यतः जांच की अवधि के दौरान मॉड्यूल की कीमतों से सह-संबंध रखती हैं। इन कारणों से एक घरेलू उत्पाद को परिभाषित किया गया था जिसमें सीएसपीवी सेल और सीएसपीवी मॉड्यूल दोनों शामिल थे।

- (ix) मलेशिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के धारा 9क के अंतर्गत पाटनरोधी जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सोलर सेलों तथा मॉड्यूलों पर 22.05.2014 के अंतिम जांच परिणाम में लगभग समान कारणों से एक ही उत्पाद होने पर विचार किया था।
- (x) आरईसी सोलर को भारत में कोई पैकेड प्रदान नहीं किया गया है और इसका साक्ष्य देने में विफल रहे हैं कि भारतीय क्रेता अंतिम प्रयोगों के लिए घरेलू रूप से उत्पादित सामानों का प्रयोग नहीं कर सकते तथा नहीं करते जिसके लिए वे आरईसी के पेटेंट शुदा उत्पादों का प्रयोग करते हैं। कई इंजीनियरी उत्पादों के पेटेंट होते तथा वे व्यापार उपचार जांचों के अध्यक्षीन भी होते क्योंकि वे बड़े हुए आयातों/पाटन/सब्सिडीकरण की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं जिनसे आयातक देश में घरेलू उद्योग को क्षति होती है।
- (xi) भारत में कई मामलों में व्यापार उपचार उपायों में पेटेंट शुदा उत्पादों को रखा है। 400 सीरीज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच (23 मार्च, 2015 के अंतिम जांच परिणाम) में उल्लेख किया, जहां एक समान स्थिति में रक्षोपाय महानिदेशक ने क्षेत्र से उत्पाद को हटाने के लिए दावे को रद्द किया है। चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमलेस ट्यूब, पाइपों और लौह, अलॉय और नॉन-अलॉय स्टील के खोखले प्रोफाइल (कास्ट आयरन तथा स्टीनलेस स्टील को छोड़कर), चाहे वे गर्म परिष्कृत अथवा कोल्ड रोल्ड अथवा 355.6 एमएम या 14" ओडी से अनधिक बाहरी डायमीटर के कोल्ड रोल्ड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम में दिनांक 09 दिसंबर, 2016 को प्राधिकारी ने माना है कि पेटेंट शुदा सामान और अन्य सब-कैटेगिरी को तब तक विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता जब तक वे घरेलू समान सामानों के तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इस प्रकार हटाए जाने से प्रवंचना होगी।
- (xii) चीन जन. गण., जापान, कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान (चीनी तैपई), थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम, जिन पर आरईसी सोलर पीटीई लि. द्वारा विश्वास किया गया था, इन तथ्यों पर लागू नहीं है और इस कारण वर्तमान मामले की परिस्थितियों में कि यद्यपि पेटेंट का आवेदन भारत में किया गया है, उक्त पेटेंट अभी प्रदान नहीं किया गया है।
- (xiii) यह अनुरोध करने के अलावा कि एल्फा उत्पाद उच्च गुणवत्ता का है, स्थल दक्ष है, स्वामित्व वाली उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है जो तथाकथित रूप से घरेलू उद्योग की कीमतों से उच्चतर कीमतों होने के नाते अपनी कीमतों में बढ़ता है, यह आरईसी सोलर पीटीई लि. का मामला नहीं बना है कि उनका उत्पाद सीधी प्रतिस्पर्धा में नहीं है और उसी अंतिम प्रयोग के लिए घरेलू समान उत्पाद से वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है। आरईसी सोलर पीटीई लि. ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जो यह दर्शाए कि प्रयोक्ताओं ने फोटोवोल्टेक प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन को छोड़कर अन्य प्रयोग के लिए उनके उत्पादों का प्रयोग किया है।
- (xiv) उत्पाद क्षेत्र का निर्धारण करने में आयातित वस्तु की सीधे प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति के साथ घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु की समान अथवा सीधे ही प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति पर जोर होना चाहिए। विभिन्न प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पादित अनेक किस्मों के सोलर सेल दक्षता, कीमत, भौतिक विशेषताओं और समान आकार तथा भार आदि के संदर्भ में अलग-अलग होते हैं। इन अंतरों से केवल कीमत और दक्षता में ट्रेड ऑफ होता है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा आयात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद का अंतिम प्रयोग समान अर्थात् फोटोवोल्टेक प्रभाव के माध्यम से उत्पादन के लिए रहता है।

- (xv) मैसर्स सीसीसीएमई ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि इन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके विचाराधीन उत्पाद, जिनका उत्पादन डीटीए यूनिटों द्वारा किया जाता है, इन यूनिटों द्वारा उत्पादित वस्तु से प्रतिस्पर्द्धा नहीं करते।
- (xvi) याचिकाकर्ताओं का सामूहिक उत्पादन भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है और इस प्रकार, कुल भारतीय उत्पादन में उनका प्रमुख अनुपात है तथा इसीलिए भारत में समान वस्तु के घरेलू उद्योग हैं।
- (xvii) मूल जांच में महानिदेशक ने यह माना कि एसईजेड में स्थित उत्पादकों को घरेलू उत्पादक नहीं माना जा सकता। महानिदेशक को निम्नलिखित कारणों से एसईजेड यूनिट को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में न मानने के अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए:

क. धारा 53 में यह अधिदेशित है कि एसईजेड पर सीमित प्रयोजन अर्थात् प्राधिकृत प्रचालन करने के प्रयोजन के लिए भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र के बाहर होने पर विचार किया जाएगा। यद्यपि कोई एसईजेड भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर होने के लिए एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान की गई सीमा तक भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर माना जाता है, तथापि वह भारत के सीमा क्षेत्र का पूरी तरह से अभिन्न अंग है और कानून तथा विनियमों के अधीन है।

ख. यह पाया जाता है कि एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत "आयात" का अर्थ भारत से बाहर के स्थान के एसईजेड यूनिट द्वारा सामान अथवा सेवाएं प्राप्त कर लेते हैं जबकि "निर्यात" का अर्थ डीटीए से किसी एसईजेड यूनिट को सामानों की आपूर्ति करने से है। एसईजेड यूनिटों द्वारा डीटीए मंजूरी पर भारत में "आयात" तथा एसईजेड से "निर्यात" नहीं माना जाता है।

ग. यद्यपि एसईजेड से डीटीए में हटाए गए सामान पर उस समय ऐसे सामानों पर लगाए जाने योग्य सीमा शुल्क में लगाए जाते हैं जब धारा 30 के मद्देनजर भारत में आयात किए जाएं, तथापि यह नोट किया जाए कि भारतीय निर्यातों में इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माने गए अनुसार उसे "आयात" नहीं माना जाता है।

घ. एसईजेड से डीटीए में सामानों की मंजूरीयों को भी "निर्यात" नहीं माना जाता है। इसकी अपेक्षा डीटीए की एसईजेड यूनिटों में बिक्री को शुल्क वापसी, डीईपीबी लाभ आदि जैसे वास्तविक निर्यातों के मामलों के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनिट/विकासकर्ता को लाभ उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत निर्यात माना जाना होता है। तथापि, दो अन्य देयताएं निर्यात शुल्क लगाए जाने जैसी भारत से बाहर के क्षेत्र को डीटीए से वास्तविक निर्यात करने से प्रभावित नहीं होती है, वे नहीं लगती हैं।

ङ. एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसार दी गई विशेष छूटों तथा निष्कासनों को छोड़कर, एसईजेड द्वारा डीटीए बिक्रियां डीटीए में उत्पादित सामानों पर लगाए जाने वाले उन्हीं शुल्कों के अधीन हैं, जैसे आयातों के मामले में असमान केंद्रीय बिक्री कर। अतः एसईजेड में स्थित यूनिटों को भारत से बाहर स्थित नहीं माना जा सकता और वे निरंतर भारत के अभिन्न अंग हैं। महानिदेशक से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार एसईजेड यूनिटों को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए क्योंकि वह भारत में किसी भी अन्य यूनिट को उपलब्ध है।

च. एसईजेड से डीटीए को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री पर रक्षोपाय शुल्क नहीं लगेगा, जैसा कि एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 8ख(2क) और धारा 30 को संयुक्त रूप से पढ़ने से स्पष्ट है।

छ. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबंधित धारा 9क, प्रतिकारी शुल्क के संबंध में धारा 9 और रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से संबंधित धारा 8ख किसी अनिश्चित शर्त का उल्लेख नहीं करते कि वे भारत में वस्तु के आयातों पर लागू हैं।

ज. यदि कोई वस्तु भारत में आयात नहीं की जाती तो उपर्युक्त कोई भी शुल्क देय नहीं है। इस संबंध में, यद्यपि मान्य प्रावधान द्वारा एक कानूनी धारणा बनाई जाती है जिससे एसईजेड को भारत के सीमा

शुल्क क्षेत्र से बाहर माना जाए तो भारत में किसी भी विद्यमान कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एसईजेड में विनिर्मित सामान आयात के रूप में डीटीए को मंजूरी की मान्यता देता हो।

- झ. एसईजेड में विनिर्मित सामान डीटीए को मंजूरी भारत के क्षेत्र में आयात नहीं बनता जो कि एस्सार स्टील बनाम भारत संघ [2010 जीएलएच (1) 52], इंडिया एक्सपोर्ट्स बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य [(2012) 47 वीएसटी 126], श्री डी. वी. सराधी प्रबंधक-प्रशासन के प्रतिनिधित्व में तिरुपति उद्योग लिमिटेड बनाम भारत संघ (यूओआई), सचिव, वित्त मंत्रालय एवं अन्य के माध्यम से [2011 (272) ईएलटी 209(ए.पी.)] सहित कई निर्णयों में भी दोहराया गया है।
- ञ. आयात की वस्तुस्थिति के बिना, कोई पाटनरोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क, रक्षोपाय शुल्क नहीं हो सकता।
- ट. धारा 30 में उल्लिखित डीटीए मंजूरी के दौरान पाटनरोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने के उल्लेख का अर्थ यह है कि परिष्कृत उत्पाद पर प्रयुक्त इनपुट (उस स्थिति में जब विशिष्ट देशों से आयातित इनपुट पर पाटनरोधी शुल्क अथवा प्रतिकारी शुल्क अथवा रक्षोपाय शुल्क लगता हो) के मूल्य पर देय शुल्क है न कि परिष्कृत उत्पाद पर ही।
- ठ. यही सिद्धांत किसी उस समान वस्तु के विरुद्ध उठाए गए रक्षोपाय शुल्कों पर भी लागू है जिसका विनिर्माण एसईजेड में किया जाता है और डीटीए में मंजूर किया जाता है। यह सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(2क) के लिए भी सिद्ध है।
- ड. डीटीए की धारा 8ख(2क) के साथ पठित एसईजेड अधिनियम की धारा 30 इसे स्पष्ट करती है कि रक्षोपाय शुल्क परिष्कृत उत्पादों में प्रयुक्त इनपुट पर ही देय होता है न कि एसईजेड में विनिर्मित परिष्कृत उत्पाद पर और डीटीए में मंजूर किया जाता है।
- ढ. एसईजेड यूनिटों को समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों के रूप में माने जाने अथवा घरेलू उद्योग के भाग के रूप में माने जाने से नहीं रोका जा सकता। रक्षोपाय कानून के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख की उप-धारा (6) के खंड (ख) घरेलू उद्योग को परिभाषित करता है।
- ण. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 22.05.2014 के अंतिम जांच परिणाम में मलेशिया, चीन जन. गण., चीनी तैपई और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोलर सेल, चाहे आंशिक रूप से असेंबल किए गए हों अथवा पूर्णतः मॉड्यूलों या पैनलों में अथवा ग्लास पर अथवा कुछ अन्य उपयुक्त उपकरणों पर असेंबल किए गए हों अथवा न किए गए हों, के आयातों पर पूर्व पाटनरोधी जांच में समान वस्तु के घरेलू उद्योग के भाग के रूप में विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने वाली एसईजेड यूनिट पर विचार किया है। इस प्रकार, जहां तक पाटनरोधी प्रक्रियाओं का संबंध है, विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने वाली यूनिटों को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) तथा सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क, दोनों के तहत समान वस्तु का घरेलू उद्योग माना जाता है।
- त. रक्षोपाय कानून तथा पाटनरोधी कानून, दोनों में प्रावधान यह निर्धारित नहीं करते कि केवल डीटीए में स्थित समान वस्तु के उत्पादकों को घरेलू उद्योग के रूप में माना जाएगा अथवा उस मामले में एसईजेड में उत्पादित समान वस्तु तथा घरेलू खपत के लिए डीटीए में मंजूर की गई समान वस्तु को समान वस्तु के घरेलू उत्पादन के रूप में नहीं माना जाना होता है। एसईजेड में समान वस्तु के उत्पादकों को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में माना जाना अपेक्षित होता है क्योंकि एसईजेड में स्थित समान वस्तु के उत्पादक किसी सीमा से अथवा भारत के घरेलू बाजार में बिक्री करने में कोई बाधा नहीं होती।
- थ. एसईजेड द्वारा सामानों की डीटीए मंजूरी आयात किए जाने पर उन पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के भुगतान के लिए देय होते हैं। तथापि, पूर्व पाटनरोधी जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम में नोट किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद, जो सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की सीमा प्रशुल्क मद 85414011 में आता है, भारत का आयात प्रशुल्क "निःशुल्क" है और इसीलिए उसका विनिर्माण करने वाली एसईजेड यूनिटों द्वारा डीटीए मंजूरी पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है। एसईजेड यूनिटों का भी सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा ("एनएसई") बनाए रखने का दायित्व है जो नियम 53 के तहत

निर्धारित परिकलन के सिद्धांत के मद्देनजर उनके द्वारा उत्पादित सामानों के निर्यात के लिए एसईजेड यूनिटों पर और दायित्व लगाता है।

- द. इस प्रकार, बिक्री की मात्रा के संबंध में एक सीमा है जो घरेलू बाजार में खपत के लिए डीटीए में एसईजेड यूनिट द्वारा की जा सकती है। तथापि, वर्तमान मामले के तथ्यों में विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने वाली एसईजेड यूनिटों द्वारा डीटीए मंजूरीयां भी एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 53(क)(1) के मद्देनजर सकारात्मक एनएसई को पूरा करने के प्रति मानी जाती हैं। एसईजेड में आधारित विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों पर सकारात्मक एनएसई बनाए रखने के प्रयोजन के लिए सामानों का निर्यात करने की कोई मजबूरी नहीं है और न ही उसे डीटीए में देखने के लिए कोई प्रतिबंध अथवा सीमा है क्योंकि सकारात्मक एनएसई डीटीए बिक्री के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि प्रशुल्क शीर्ष "निःशुल्क" है, अतः एसईजेड से मंजूर विचाराधीन उत्पाद पर कोई सीमा शुल्क देय नहीं है। यह इसे पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि एसईजेड यूनिटें विचाराधीन उत्पाद के घरेलू बाजार में बिना किसी प्रतिबंध अथवा प्रतिस्पर्द्धा के घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की बिक्री कर रहे हैं।
- ध. सैचुरेटेड फैट्री एल्कोहॉल के आयातों के संबंध में, रक्षोपाय जांच में प्राधिकारी ने मैसर्स वीवीएफ लिमिटेड, एक 100 प्रतिशत ईओयू को घरेलू उद्योग माना था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 100 प्रतिशत ईओयू को घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल करने के लिए नियमित रूप से पात्र भी माना है। उदाहरण के लिए, 100 प्रतिशत ईओयू को (क) चीन जन. गण. और स्विट्जरलैंड से डीपीपी रेड 254, (ख) चीन जन. गण. और स्विट्जरलैंड से विटामिन-ए पामीटेड के संबंध में पाटनरोधी जांचों में घरेलू उद्योग का भाग होना माना गया है।
- न. यह नोट किया जाता है कि एसईजेड के समान 100 प्रतिशत ईओयू को भी एफटीपी 2015-20 के पैरा 9.16 (जो एफटीपी 2009-14 के समान हैं) के अनुसार डीटीए के बाहर माना जाता है। 100 प्रतिशत ईओयू और एसईजेड, दोनों समान रूप से स्थित हैं क्योंकि उन्हें डीटीए में नहीं माना जाता है तथा डीटीए में उनकी बिक्री सकारात्मक एनएसई बनाए रखने पर आकस्मिक है। अतः जो परीक्षण घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल किए जाने के लिए 100 प्रतिशत ईओयू की पात्रता मापने के लिए लागू हैं, वे एसईजेड यूनिटों की पात्रता का परीक्षण करने के लिए भी लागू होने चाहिए।
- प. वर्तमान मामले के तथ्यों में यह देखा जाता है कि चूंकि एसईजेड यूनिटें घरेलू बिक्री के माध्यम से सकारात्मक एनएसई हासिल कर सकती हैं, अतः बिक्री की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा न ही निर्यात के लिए कोई मजबूरी है। डीटीए में समान वस्तु की बिक्री पर कोई प्रतिबंध न होने वाली एसईजेड यूनिटों को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(6)(ख) के तहत घरेलू उद्योग का भाग माना जाना अपेक्षित है।
- फ. अतः महानिदेशक मैसर्स मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड की एसईजेड यूनिट को भारत में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण करने वाले घरेलू उद्योग के भाग के रूप में मानेंगे और वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए उसके आंकड़ों पर विचार करेंगे।
- ब. इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर और अनरॉट एल्युमीनियम से संबंधित रक्षोपाय अंतिम जांच परिणाम में एसईजेड यूनिटों को इस कारण घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना गया था कि एसईजेड यूनिटें निर्यात के प्रयोजन के लिए एसईजेड में स्थापित की गई थीं, प्रश्रुगत एसईजेड यूनिट द्वारा मंजूरीयां सीमा शुल्क के अध्यक्षीन थीं और डीटीए से एसईजेड यूनिट को सामानों की आपूर्ति करना निर्यात माना गया था। यह तर्क गलत है और संगत कानूनी प्रावधानों की त्रुटिपूर्ण समझ पर आधारित है। यह निर्णय भी अरुचिकर है क्योंकि उन्होंने इलाहाबाद, गुजरात और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों के बाध्यकारी निर्णयों पर विचार नहीं किया।

(xviii) यह मानते हुए कि एसईजेड यूनिटों को घरेलू उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता और यह कि मूल जांच में किए गए निर्णय को अपनाते हुए डीटीए यूनिटों तक ही घरेलू उद्योग का क्षेत्र प्रतिबंधित था,

- वे आवेदक डीटीए यूनिटों अर्थात् जुपिटर इंटरनेशनल लि. ("जेआईएल") और जुपिटर सोलर पावर लि. ("जेएसपीएल") का घरेलू उत्पादन में (एसईजेड यूनिटों को अलग करने के बाद) प्रमुख अनुपात है।
- (xix) उन घरेलू उत्पादकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिन्होंने घरेलू उद्योग के रूप में निर्णायक समीक्षा में भाग लेने से मूल जांच में भाग नहीं लिया था। धारा 8ख(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक परिभाषा के अनुसार "घरेलू उद्योग" का अर्थ भारत में समान वस्तु अथवा सीधे ही प्रतिस्पर्धी वस्तु के समग्र रूप में उत्पादकों से है अथवा जिनका समान वस्तु के सामूहिक उत्पादन अथवा भारत में सीधे ही प्रतिस्पर्धी वस्तु का भारत में उपर्युक्त वस्तु के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि केवल वे घरेलू उत्पादक जिन्होंने मूल जांच के दौरान उपाय लगाए जाने के लिए भाग लिया था, निर्णायक समीक्षा में भी घरेलू उद्योग के रूप में लिए जाने हैं।
- (xx) हितबद्ध पक्षकार भी यह दर्शाने में असमर्थ हैं कि एसईजेड को घरेलू उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा रखा गया तर्क गलत है और उन्होंने केवल पूर्व अंतिम जांच परिणामों पर विश्वास किया है जिन्हें विशिष्ट किया गया था तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित कानून तथा संविधि की अज्ञानता में अरुचिकर होना दर्शाया गया था। प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं की डीजीटीआर की नियम पुस्तिका पर किया गया विश्वास हितबद्ध पक्षकारों का विरोध करने के लिए कोई सहायक नहीं हो सकता क्योंकि वे माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित इस मुद्दे के संबंध में बाध्यकारी पूर्ण उदाहरणों को नकार नहीं सकते।
- (xxi) धारा 8ख में केवल यह उल्लेख है कि जो घरेलू उत्पादक जांच में भाग लें, उनकी समान अथवा सीधे ही प्रतिस्पर्धी वस्तु का सामूहिक उत्पादन घरेलू उद्योग माने जाने के लिए उपर्युक्त वस्तु के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। यहां तक कि यदि एमएसपीवीएल को घरेलू उद्योग की परिधि में न माना जाए, तो जेआईएल और जेएसपीएल का संयुक्त उत्पादन डीटीए में समान वस्तु के उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।
- (xxii) संबद्ध सामानों की संस्थापित क्षमता घरेलू उद्योग का आधार निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए असंगत है और केवल संगत मानदंड वास्तविक उत्पादन है।
- (xxiii) आयातित सोलर सेलों से उत्पादित सोलर मॉड्यूल भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन के प्रयोजन के लिए नहीं माने जा सकते। यहां तक कि घरेलू रूप से उत्पादित सोलर सेलों से उत्पादित सोलर मॉड्यूल संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन का परिकलन करने के लिए नहीं माने जा सकते क्योंकि इससे समान वस्तु के कुल उत्पादन की दोहरी गणना होगी। यह इसलिए है क्योंकि घरेलू रूप से उत्पादित सोलर सेलों की गणना सोलर सेल विनिर्माताओं द्वारा पहले उत्पादन के समय की जाएगी और उसके बाद घरेलू मॉड्यूल विनिर्माताओं द्वारा मॉड्यूलों में व्यवस्थित किए जाने के समय की जाएगी। इससे भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का परिकलन करने के लिए उन सोलर सेलों को दो बार परिकलन करना होगा और इसीलिए अनुमति नहीं दी जा सकती।
- (xxiv) जांच की अवधि के दौरान जुपिटर इंटरनेशनल लि. की एकल क्षमता, उत्पादन, बिक्री के संबंध में, उसका उत्पादन शुरू होने की तारीख, जुपिटर सोलर पावर लि. और जुपिटर इंटरनेशनल लि. के बीच संबंध की वास्तविक स्वीकृति और इन दो कंपनियों के बीच संबद्ध सामानों की बिक्री और/अथवा खरीद लेन-देन के संबंध में सूचना एलडी को दी गई है, महानिदेशक रक्षोपाय को याचिका में तथा जुपिटर सोलर पावर लि. और जुपिटर इंटरनेशनल लि. द्वारा दायर घरेलू उत्पादकों के प्रश्नावली के उत्तर के गोपनीय रूपांतर में दी गई है।
- (xxv) डीजीटीआर की व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन परिपाटियों की नियम पुस्तिका में पैरा 17.12 में यह उल्लेख है कि जब तक आवेदकों का निर्णायक समीक्षा जांच में कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है, आवेदकों का मूल जांच में वही होना आवश्यक नहीं है।
- (xxvi) धारा 8ख में यह प्रावधान नहीं है कि रक्षोपायों के द्वारा संरक्षण की मांग करने वाले घरेलू उत्पादकों का प्रमुख हिस्से के रूप में माने जा सकने से पूर्व न्यूनतम प्रतिशत होना चाहिए। इसकी अपेक्षा संविधि में यह निर्धारित है कि उनका भारत में उपर्युक्त वस्तु के कुल उत्पादन में प्रमुख हिस्सा होना चाहिए।

- (xxvii) इस मुद्दे के संबंध में कि "प्रमुख हिस्सा" क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कतिपय ऑटोमोबाइल पर चीन – पाटनरोधी एवं प्रतिकारी शुल्क के मामले में विवाद निपटान समझ के तहत गठित डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय के समक्ष आया जिसमें यह माना गया था कि आवेदकों का घरेलू उद्योग माने जाने के लिए घरेलू उत्पादन में पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण, गंभीर और काफी हिस्सा होना चाहिए।
- (xxviii) डब्ल्यूटीओ पैनेल की उपर्युक्त टिप्पणियों में सीमा शुल्क आयुक्त, बेंगलुरु बनाम जी. एम. एक्सपोर्ट्स [(2016) 1 एससीसी 91] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर निर्णायक मार्गदर्शन का प्रावधान है जिसमें उन वीडियो का अभिप्राय सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत उल्लिखित हैं, जो रक्षोपाय करार की प्रकृति में बहुपक्षीय करार पर हस्ताक्षरकर्ता होने के परिणामस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसरण में अधिनियमित किए गए हैं।
- (xxix) सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(6) में प्रयुक्त भाषा जो डब्ल्यूटीओ के तहत भारत के दायित्वों को शामिल करने वाली भारतीय विधि में घरेलू उद्योग का परिभाषा खंड है, भी प्रमुख हिस्से की अपेक्षा "द" प्रमुख हिस्से की अपेक्षा "एक" प्रमुख हिस्सा उल्लिखित करती है जो उनके घरेलू उद्योग माने जाने के लिए पात्र होने से पूर्व कुल घरेलू उत्पादन में न्यूनतम 50 प्रतिशत तक घरेलू उत्पादकों को प्रतिबंधित न करने के कानून का आशय स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है।
- (xxx) वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए माने गए डीटीए में याचिकाकर्ताओं के घरेलू उत्पादन में हिस्से के संबंध में प्रतिवादी अंतिम जांच परिणामों में रिकार्ड किए गए तथ्य यह दर्शाते हैं कि उनका वर्तमान समीक्षा में मानी गई जांच की अवधि की दौरान कुल घरेलू उत्पादन में 30-35 प्रतिशत से कम हिस्सा नहीं था और सबसे हाल की अवधि के दौरान 55-60 प्रतिशत से अधिक नहीं था।
- (xxxi) डीटीए में आधारित वर्तमान याचिकाकर्ता पर्याप्त रूप से लंबी अवधि तक विद्यमान रहे हैं और उन्होंने बड़े हुए आयात के विध्वंस को देखा है जिससे गंभीर क्षति हुई है और वे आपातकालीन उपायों का सहारा लेने के लिए मजबूर हुए। अतः आवेदक, चाहे एसईजेड यूनिटें सहित हों अथवा उनसे अलग हों, को समान तथा सीधे ही प्रतिस्पर्धी वस्तु के घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने योग्य हैं क्योंकि उनके लिए परिकलित उत्पादन की प्रतिशतता इन उत्पादन के महत्वपूर्ण, गंभीर अथवा पर्याप्त अनुपात के रूप में योग्य बनने के लिए पर्याप्त रूप से अधिक है।
- (xxxii) जेआईएल केवल वृद्धिकारक कार्य नहीं करता बल्कि उसने जांच की अवधि के दौरान सीधे ही प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादन किया है। उसने कार्य आधार पर जेएसपीएल के माध्यम से सीधे ही प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादन भी किया है। अतः जेआईएल के क्रियाकलाप केवल वृद्धिकारक कार्य नहीं हैं।
- (xxxiii) आयातों में वृद्धि निर्धारित समीक्षा में एक अपेक्षा नहीं है। यह तथ्य कि नियम 5, 6, 7 और 11 संशोधित रूप में किसी निर्णायक समीक्षा में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होते हैं, समीक्षा के प्रयोजन के संदर्भ में देखा जाना है जो कि रक्षोपाय नियमावली के नियम 18 तथा सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(4) दोनों में उल्लिखित है। **रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.2 के अनुसार**, अनुच्छेद 2, 3, 4 और 5 में निर्धारित समीक्षा करने के लिए प्रक्रिया ही लागू होगी। इन प्रावधानों में प्रक्रियागत पहलुओं के अलावा, आरंभिक तौर पर शुल्क लगाए जाने के लिए आयातों में वृद्धि की आवश्यकता लागू नहीं होती। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने *संत गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ, वित्त मंत्रालय और अन्य* के मामले में माना है कि भारत जिस करार पर हस्ताक्षर करता है और जिसके अनुसरण में इस संबंध में नगर पालिका कानून में लागू किया गया है तथा कानून का प्रयोजन भारतीय कानून का निर्वचन करते समय मार्गदर्शी दल होना चाहिए।
- (xxxiv) प्रश्नगत उपाय 30 जुलाई, 2018 से प्रभावी हुआ। उपाय लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए उपाय लगाए जाने के पूर्व विद्यमान स्थिति के साथ उसकी तुलना की जानी है। उपाय लगाए जाने के पूर्व और उसके बाद के बीच सक्षम तुलना के प्रयोजन के लिए ही 2016-17 और 2017-18 के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।

- (xxxv) घरेलू उद्योग ने अक्तूबर, 2019 से फरवरी, 2020 के महीनों के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े भी प्राप्त किए हैं और 3 जुलाई, 2020 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के अनुसरण में घरेलू उद्योग द्वारा दायर लिखित अनुरोधों में अगोपनीय सार भी दिया गया है तथा हितबद्ध पक्षकारों को उन पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
- (xxxvi) शुल्क 30 जुलाई, 2018 से लागू किए गए थे। शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप, आयात मात्रा 2018-19 के दौरान 8,010 मेगावाट तक कम हो गई। परंतु आयातों में यह गिरावट बहुत कम समय तक रही क्योंकि आयातों ने पुनः बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाई है।
- (xxxvii) यह मानते हुए कि आयातों में वृद्धि आवश्यक है, 2018-19 और 2019-20 के 3 तदनुसूची तिमाहियों की जांच से यह देखा जा सकता है कि आयातों पर 2019-20 में प्रभाव पड़ा। रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बावजूद, संबद्ध सामानों की आयात मात्रा पूर्व के स्तरों पर वापस नहीं गई और अब भी भारत में बढ़े हुए स्तरों पर आ रही है।
- (xxxviii) यह नोट करना व्यावहारिक है कि यद्यपि आयातों की मात्रा 2018-19 में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के अनुसरण में अनुभव की गई मात्रा में थोड़ी सी गिरावट को छोड़कर बढ़ी है, तथापि विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतें निरंतर गिरावट पर रही हैं। रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बावजूद, संबद्ध सामानों की आयात मात्रा पूर्व के स्तरों पर वापस नहीं गई है और अब भी भारत में बढ़े हुए स्तरों पर आ रही है।
- (xxxix) रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के उत्तर में, आयात कीमतें और नीचे गई हैं जिनसे रक्षोपाय शुल्क का अपेक्षित प्रभाव कम हुआ है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि आयातों की मात्रा इस तथ्य के साथ कि रक्षोपाय शुल्क 01.08.2019 से 20 प्रतिशत तक और 02.01.2020 से 15 प्रतिशत तक कम किया गया था, 2019-20 में आयात कीमतों में तेज गिरावट के साथ बढ़ी है। आयात कीमतें माह दर माह आधार पर प्रमुख रूप से कम हुई हैं। अप्रैल, 2018 और फरवरी, 2020 के बीच सेल की आयात कीमतों में 50 प्रतिशत तक और मॉड्यूल में 30 प्रतिशत तक गिरावट आई।
- (xi) यद्यपि चीन जन. गण. से आयात मात्रा रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद कम हुई, तथापि वह भारत को विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा निर्यातक बना रहा।
- (xli) यूरोपीय संघ के 03 सितंबर, 2018 से चीन के विरुद्ध सोलर सेलों और मॉड्यूलों पर पाटनरोधी एवं प्रतिकारी शुल्क वापस लिए जाने के बाद चीन से यूरोपीय संघ को निर्यात 2017 में 5.36 प्रतिशत से बढ़कर 2019 (1एच) में 25.7 प्रतिशत तक हो गए और चीन जन. गण. के निर्यातों में भारत का हिस्सा आनुपातिक रूप से 29.6 प्रतिशत से घटकर 7.3 प्रतिशत हो गया जो भारत द्वारा रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के अनुरूप है। यह तथ्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि यूरोपीय संघ द्वारा शुल्क समाप्त किए जाने से यहां चीन से निर्यातों में वृद्धि हुई है जबकि भारत वाला शुल्क लगाए जाने से वहां चीन जन. गण. से निर्यातों में कमी हुई है। यदि चीन से आयातों पर रक्षोपाय शुल्क हटाया जाता है तो चीन भारत को बढ़ी हुई मात्रा में सामानों का पुनः निर्यात शुरू कर देगा। अतः हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि चीन के लिए भारत को उसके निर्यात बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सहज ज्ञान विरोधी है।
- (xlii) थाइलैंड और वियतनाम को चीन से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात भारत द्वारा रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद बढ़े हैं जो कि वर्तमान में लागू हैं। उसके बाद थाइलैंड और वियतनाम से भारत को विचाराधीन उत्पाद के आयातों में तदनुसूची वृद्धि देखी गई है।
- (xliii) अब थाइलैंड और वियतनाम से आयात हाल की अवधि अर्थात् 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) में भारत को विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों में क्रमशः लगभग 12.46 प्रतिशत तथा 11.7 प्रतिशत है, जबकि 2017-18 में कुल आयात अधिक होने के बावजूद रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से पूर्व वे केवल 0.26 प्रतिशत एवं 0.70 प्रतिशत थे। रक्षोपाय शुल्क लगाना थाइलैंड और वियतनाम के लिए बढ़ाया जाएगा क्योंकि उन्होंने विकासशील देशों के लिए 3 प्रतिशत की शुरुआती अपेक्षा से अधिक बढ़ाया है।
- (xliv) रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 में यह प्रावधान है कि रक्षोपाय किसी विकासशील देश सदस्य के मूल के उत्पाद के विरुद्ध तब तक लागू नहीं होंगे जब तक आयातक सदस्य ने संबंधित उत्पाद के आयात पर उसका

हिस्सा 3 प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाता। "जब तक" पदबंध का प्रयोग रक्षोपाय के अनुप्रयोग पर प्रतिबंध सिद्ध करता है, उस समय तक लागू होगा जब तक आयात मात्रा 3 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर में रहती है। न्यूनतम स्तर के पार होने पर रक्षोपाय के लिए आवेदन करने हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है।

- (xiv) फिनोल पर रक्षोपाय के 11 दिसंबर, 2001 की समीक्षा में अंतिम जांच परिणाम द्वारा मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर को समीक्षा के अनुसरण में उपाय के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया था, यद्यपि इन देशों को मूल उपाय के समय शामिल नहीं किया गया था। इसी प्रकार, एसीटोन के आयात पर रक्षोपाय शुल्क की समीक्षा में 4 फरवरी, 2002 के अंतिम जांच परिणाम द्वारा दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर को समीक्षा के अनुसरण में रक्षोपाय शुल्क के क्षेत्र में शामिल किया गया था। यद्यपि उन्हें मूल रूप से शुल्क लगाए जाने के समय उपाय के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था।
- (xlv) इस्पात उत्पाद के संबंध में यूरोपीय संघ द्वारा की गई रक्षोपायों की समीक्षा में जिन विकासशील देशों को मूल रूप से शुल्क लगाए जाने के क्षेत्राधिकार से अलग किया गया था, उन्हें इस उपाय की समीक्षा के अनुसरण में उसकी परिधि में शामिल किया गया था। यूरोपीय संघ द्वारा दूसरी समीक्षा जांच भी की गई थी और जिन विकासशील देशों को पहली समीक्षा के अनुसरण में अलग किया गया था, उन्हें उसकी परिधि में शामिल किया गया था। अतः अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने भी उस समीक्षा के अनुसरण में विकासशील देशों पर रक्षोपाय बढ़ा दिए हैं जब ये देश में समीक्षा की हाल की अवधि में न्यूनतम स्तर से अधिक हुए हैं।
- (xlvii) यह निर्धारण कि क्या विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों में इंडोनेशिया का हिस्सा सबसे हाल की अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि वह न्यूनतम है तो क्या उसे अलग किया जा सकता है।
- (xlviii) मैसर्स कनाडियन सोलर थाइलैंड ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में दिए गए अनुसार कुल मात्रा की तुलना की है जो मापन की विभिन्न यूनिटों का योग है। इन सभी यूनिटों का कुल योग आयातों की मात्रा का कोई सार्थक संकेत नहीं दे सकता। मापन की विभिन्न यूनिटों को विश्लेषण के प्रयोजन के लिए एक यूनिट में परिवर्तित किया जाना चाहिए। संबंधित उत्पाद के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट वाट है जिसका प्रयोग प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में भी किया गया है। वाट के परिवर्तन पर थाइलैंड से आयात सबसे हाल की अवधि के दौरान 12.46 प्रतिशत है।
- (xlix) समीक्षा का प्रयोजन यह मूल्यांकन करना है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति रोकने अथवा गंभीर क्षति का उपाय करने के लिए रक्षोपाय अपेक्षित है। अतः यदि आयातों की मात्रा उन अन्य विकसित देशों से बड़ी है जिन्हें मूल जांच के अनुसरण में उपाय के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था तो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति नहीं रोकी जा सकती अथवा उसका उपचार नहीं किया जा सकता, यदि जो विकसित देश 3 प्रतिशत की शुरुआत से आगे बढ़ गए हैं, उन्हें उस उपाय के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है, उसे जारी रखा जा रहा है।
- (i) आर्थिक मानदंडों अर्थात् उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा तथा समायोजन योजना, जो कि नियम 7 के अनुरूप व्यापार संवेदी तथा गोपनीय है, जैसे आर्थिक मानदंडों के आंकड़ों के संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है। सूचना की उपयुक्त समझ सुकर बनाने के लिए उसके स्थान पर पर्याप्त अगोपनीय सार प्रदान किया गया है, केवल जहां सूचना सार के लिए उपयुक्त नहीं थी, वहां पूर्ण गोपनीयता का दावा किया गया है। घरेलू उद्योग ने 6 सितंबर, 1997 की व्यापार सूचना एसजी/टीएन/1/97 की अपेक्षाओं को पूरा किया है और संगत आर्थिक मानदंडों के संबंध में सूचीबद्ध आंकड़े दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने 6 सितंबर, 1997 की व्यापार सूचना एसजी/टीएन/1/97 में दिए गए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार गोपनीय रूपांतर में अपने आर्थिक मानदंडों के संबंध में भी पूरी सूचना दी है।
- (ii) यद्यपि 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10 रक्षोपाय प्रक्रिया पर लागू नहीं है, तथापि याचिकाकर्ताओं ने उसमें दी गई गोपनीयता का दावा करने के लिए अपेक्षाओं को पूरा किया है।
- (iii) जेआईएल और जेएसपीएल संबद्ध कंपनियां हैं क्योंकि जेएसपीएल, जेआईएल की एक सहायक कंपनी है। अतः यह कहा जा सकता है कि दो कंपनी समूह हैं जिन्होंने वर्तमान आवेदन पत्र दायर किया है, यथा जुपिटर और एमएसपीवीएल। अतः यदि यह मानते हुए व्यापार सूचना के अनुसार वास्तविक सूचना प्रकट की जाती है कि

दो से अधिक घरेलू उत्पादक हैं तो फिर इससे अन्य आवेदक समूह कंपनी को गोपनीय सूचना प्रकट होगी। परिणामस्वरूप, गोपनीयता का प्रयोजन बेकार हो जाएगा। जेआईएल और जेएसपीएल के लिए संयुक्त आंकड़े घरेलू उद्योग की याचिका में उस भाग में दिए गए हैं, जिसमें डीटीए में वर्णित उद्योग का निष्पादन दिया गया है।

- (liii) याचिकाकर्ताओं ने आवेदन पत्र के भाग 5 में क्षति संबंधी मानदंडों से संबंधित सभी सूचीबद्ध आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।
- (liv) इसके अतिरिक्त, जेएसपीएल और जेआईएल की संयुक्त स्थापित क्षमता इस कारण उनकी अलग-अलग संस्थापित क्षमताओं के बिना दी गई है कि जेएसपीएल ने कार्य आधार पर सबसे हाल की अवधि के दौरान जेआईएल के लिए विचाराधीन उत्पाद उत्पादित किया है और इसीलिए उनकी संयुक्त क्षमता उनकी अलग-अलग क्षमताओं के बिना संगत बन जाती है।
- (lv) हितबद्ध पक्षकारों पर अपने आप डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े प्राप्त करने और उन आंकड़ों के संबंध में अनुरोध करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये आंकड़े मौखिक सुनवाई से केवल दो दिन पूर्व प्राप्त किए गए थे और सुनवाई से एक दिन पहले छांटे गए थे। अतः अगोपनीय सार बताने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों का सार घरेलू उद्योग द्वारा लिखित अनुरोधों में बता दिया गया है। घरेलू उद्योग सार्वजनिक फाइल में कच्चे तथा छांटे न गए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों को बताने से प्रतिबंधित है क्योंकि वे 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10 के अनुसार गोपनीय है। अतः हितबद्ध पक्षकारों को अपने आप छांटे न गए तथा डीजीसीआईएंडएस के कच्चे आंकड़ों को लेना होता है जिसके लिए प्रक्रिया उपर्युक्त व्यापार सूचना में निर्धारित है।
- (lvi) वर्तमान जांच में एसईजेड में तीन आवेदक हैं जिनमें एसईजेड में एक है जिसे पूर्व जांच में अलग किया गया था। अतः जैसा कि संधारणा थी कि एसईजेड यूनिट अलग कर दी जाएगी, एसईजेड और डीटीए यूनिटों, दोनों के लिए संयुक्त तथा डीटीए यूनिटों तथा एसईजेड यूनिटों के लिए अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं।
- (lvii) चूंकि जेएसपीएल ने केवल एक कार्य आधार पर उत्पादन किया है, अतः वास्तविक उत्पादन एवं अन्य संबंधित आंकड़े प्रकट नहीं किए जा सकते क्योंकि जेएसपीएल और जेआईएल के वास्तविक आंकड़े उसी आधार पर सुनिश्चित किए जा सकते हैं। ये आंकड़े दर्शाए नहीं गए हैं क्योंकि वे यदि प्रकट किए जाते हैं तो व्यापार संवेदी सूचना और याचिकाकर्ताओं के हितों के पूर्वाग्रही हैं। घरेलू उद्योग द्वारा जांच के पूर्व और बाद में उसके निष्पादन की उपयुक्त समझ की तुलना के लिए वर्ष 2016 से आगे घरेलू उद्योग के निष्पादन मानदंडों के प्रकृति विश्लेषण के रूप में नियम 7(2) के अनुरूप अगोपनीय सार दिया गया है।
- (lviii) न तो सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और न ही उसके तहत बनाई गई नियमावली एलडी. महानिदेशक रक्षोपाय पर यह विश्लेषण करने का दायित्व लगाती है कि क्या बड़े हुए आयात समीक्षा जांच में अप्रत्याशित विकासों के परिणाम थे। चूंकि अप्रत्याशित विकास और दायित्वों का प्रभाव पहले ही कारणों के रूप में निर्धारित किए गए थे, जिनसे आयातों में वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप जिनसे रक्षोपाय लगाना आवश्यक हो गया, यह अपेक्षित नहीं है कि उन्हीं अप्रत्याशित विकास तथा दायित्वों के प्रभावों, जिनसे आयातों में वृद्धि हुई, की समीक्षा में पुनः जांच की जाए, न ही उपाय लगाए जाने के बाद, परंतु उसकी समीक्षा के पूर्व, मध्यवर्ती अवधि में आयातों में वृद्धि होने के लिए अप्रत्याशित विकास और दायित्वों के प्रभाव (जो उनके समान नहीं हैं जिन्हें मूल उपाय के दौरान मापा गया था) के लिए संभव नहीं है। मूल जांच के दौरान, महानिदेशक ने निर्धारित किया कि आयातों में वृद्धि भारत में समान तथा सीधे ही प्रतिस्पर्धी वस्तु के घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति के लिए सीधे ही उत्तरदायी थी।
- (lix) यदि घरेलू उद्योग ने आयात प्रतिस्पर्धी को समायोजित करने के लिए उपाय किए हैं तो यह मापने के लिए पैमाने है कि क्या रक्षोपाय शुल्क जारी रखा जाना चाहिए अथवा इस मूल्यांकन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति में इस सीमा तक सुधार हुआ है कि आयात प्रतिस्पर्धी का मुकाबला करने के लिए जारी रहने के बावजूद उसे बार-बार होने वाली गंभीर क्षति का कोई खतरा नहीं है।

- (ix) प्रमुख महत्व की बात यह है कि क्या विचाराधीन उत्पाद काफी मात्रा में अब भी आयात किया जा रहा है, क्या इतनी बड़ी मात्रा से घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हो रही है, क्या घरेलू उद्योग में संस्थापित क्षमता विचाराधीन उत्पाद के सतत काफी आयात के कारण बाजार में पर्याप्त मांग के बावजूद घरेलू उद्योग में संस्थापित क्षमता का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया है, क्या घरेलू उद्योग बाजार में उत्पाद बेचने में समर्थ है अथवा क्या आयात आने के कारण उसकी असमर्थता से मालसूची में वृद्धि हुई है।
- (ixi) उपाय लगाए जाने से पूर्व की अवधि के संदर्भ में उपाय लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग की स्थिति की तुलना के संदर्भ में ही उपाय लगाए जाने से पूर्व के आंकड़ों पर विचार किया जा रहा है।
- (ixii) याचिका का संशोधित वृत्तांत प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कानून में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है तथा दूसरे, याचिकाकर्ताओं के आवेदक में डीटीए यूनिटों के लिए दिये गये विवरणात्मक वृत्तांत में भी डीटीए में आधारित घरेलू उद्योग की यूनिटों के संयुक्त ब्यौरे दिए गए हैं।
- (ixiii) एक रेंज के रूप में घरेलू उत्पादन में घरेलू उद्योग का हिस्सा सभी हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया है।
- (ixiv) यद्यपि मांग 2016-17 से 2019-20 (क) तक 35 प्रतिशत तक बढ़ी, तथापि आयातों का प्रभावी बाजार हिस्सा बना रहा। घरेलू उद्योग ने भी उसी अवधि में आंशिक रूप से *** प्रतिशत तक बाजार हिस्सा प्राप्त किया जो यह सिद्ध करता है कि वह सकारात्मक दिशा में बाजार में समायोजन कर रहा है। तथापि, अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा आधा हुआ है जो इस तथ्य को सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग को समग्र रूप से अब भी गंभीर क्षति हो रही है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वास्तविक वृद्धि केवल *** प्रतिशत है जो नगण्य है। भारत में सभी घरेलू उत्पादकों का समग्र बाजार हिस्सा 2016-17 में *** प्रतिशत से गिरकर अप्रैल, 2019 – सितंबर, 2019 में *** प्रतिशत हो गया।
- (ixv) घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में रक्षोपाय शुल्कों के संरक्षण के परिणामस्वरूप और उसकी समायोजन योजना के कार्यान्वयन के कारण वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उत्पादकों की समग्र स्थिति टूटने की स्थिति में है क्योंकि डीटीए में स्थित अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री तेजी से कम हुई है।
- (ixvi) क्षमता उपयोग में सुधार उपाय लगाए जाने का और घरेलू उद्योग के अपने समायोजन मूल्यों के कार्यान्वयन के माध्यम से अपनी बिक्री लागत कम करने में समर्थ होने के कारण सीधा परिणाम है। तथापि, यह मानते हुए कि रक्षोपाय शुल्क का संरक्षण पिछले दो वर्षों के लिए लागू रहा है और भारत में विचाराधीन उत्पाद की भारी मांग, घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता इन आयातों से प्रतिस्पर्धा के कारण कम उपयोग में रहीं जो कीमतों में कमी कर रहे हैं। घरेलू उद्योग अपने पूरे उत्पादन की बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है जिससे मालसूची में वृद्धि हुई है। रक्षोपाय शुल्क के संरक्षण के बिना आयात कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती करेंगे और उसके उत्पाद की बिक्री की क्षमता में बाधा डालेंगे। इससे मालसूची बढ़ेगी तथा उत्पादन सुविधाएं बेकार होंगी और इस दिशा में प्राप्त किए गए लाभ समाप्त हो जाएंगे।
- (ixvii) प्रति कर्मचारी उत्पादकता में काफी सुधार हुआ है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी समायोजन योजना के अनुसार अपनी दक्षता में सुधार किया है।
- (ixviii) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2018-19 में अत्यधिक नकारात्मक थी। तथापि, बिक्री लागत में काफी कमी के साथ बड़े हुए उत्पादन और बिक्री से घरेलू उद्योग 2018-19 में अपनी हानियों को कम करने में सक्षम रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता नकारात्मक रही और उसकी टूटने की स्थिति बनी हुई है।
- (ixix) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क के संबंध में कि वर्तमान याचिका में दर्शाई गई लाभप्रदता 2017-18 में मूल जांच में दर्शाई गई लाभप्रदता से भिन्न है, मूल जांच में पांच आवेदक थे, यथा – (i) मैसर्स मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड, (ii) मैसर्स इंडोसोलर लिमिटेड, (iii) मैसर्स जुपिटर सोलर पावर लिमिटेड, (iv) मैसर्स वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, और (v) मैसर्स हेलियोस फोटो वोल्टेक लिमिटेड जबकि वर्तमान जांच में केवल (i) मैसर्स मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड, (ii), मैसर्स जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड और (iii) मैसर्स जुपिटर सोलर पावर लिमिटेड। अतः यह स्पष्ट भी है कि लाभप्रदता के मानदंडों सहित निष्पादन मानदंड समान नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, वर्तमान आवेदक के लिए 2017-18 के दौरान लाभों की इक्विटी मूल जांच की स्थिति की

तुलना करने पर, जिसने नकारात्मक लाभप्रदता दर्शाई, संगत नहीं है क्योंकि बढ़े हुए आयातों से भी गंभीर क्षति के परिणामस्वरूप लाभप्रदता पर प्रभाव आवेदकों के दोनों सेटों के लिए समान प्रवृत्ति दर्शाता है। यद्यपि मूल जांच में आवेदकों की लाभप्रदता 2016-17 में -22 से तेजी से घटकर 2017-18 में -107 हो गई। तथापि, वर्तमान आवेदकों की लाभप्रदता भी 100 से घटकर 22 हो गई। यद्यपि अब भी मुश्किल से ही लाभप्रद है, अतः घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़े विश्वसनीय हैं क्योंकि बढ़े हुए आयातों के प्रतिकूल प्रभाव की घटना आवेदकों के दोनों सेटों से सह-संबंध बनाती है।

- (lxx) यद्यपि मालसूची स्तरों में 2018-19 में सुधार हुआ, तथापि मालसूची स्तर में फिर से पर्याप्त मांग की मौजूदगी के बावजूद सबसे हाल की अवधि में काफी उछाल आया।
- (lxxi) अप्रैल, 2019 – सितंबर, 2019 के दौरान अत्यधिक सस्ती कीमतों पर विशेष रूप से वियतनाम और थाइलैंड से आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग की घरेलू बाजार में अपने उत्पाद को बेचने की क्षमता प्रभावित हुई है जिससे मालसूची इकट्ठी हो गई।
- (lxxii) रक्षोपाय शुल्क शामिल किए बिना आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों की कटौती करते रहते हैं। रक्षोपाय शुल्क के बिना घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति भारी मात्रा तक होगी और उत्पादन, बिक्री, उत्पादकता एवं लाभप्रदता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार का सफाया हो जाएगा क्योंकि प्रयोक्ता बड़ चढ़कर वापस सस्ते आयातों में जाएंगे।
- (lxxiii) निर्णायक समीक्षाओं में आयातों की कीमतों की जांच यह मापने के लिए रक्षोपाय शुल्कों के साथ की जाएगी कि क्या यदि रक्षोपाय शुल्क बंद किया जाता है तो क्या कीमत कटौती के कारण बार-बार गंभीर क्षति होने की संभावना है।
- (lxxiv) थाइलैंड और वियतनाम से आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लागू नहीं हैं, जिनका अप्रैल, 2019 – सितंबर, 2019 के दौरान भारत में सभी आयातों का लगभग 24 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, थाइलैंड और वियतनाम से आयातों का पहुँच मूल्य बहुत कम है। रक्षोपाय शुल्क लगाए बिना भारत में आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के काफी भाग से घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण एवं ह्रास जारी है, विषय अपनी बिक्री कीमतें तदनुसार रखनी होती हैं।
- (lxxv) कीमत कटौती के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण तथा ह्रास हुआ, जिससे घरेलू उद्योग द्वारा कीमतों को और कम करना पड़ा।
- (lxxvi) इससे यद्यपि कीमत कटौती का मार्जिन कीमत न्यूनीकरण प्रभावों के परिणामस्वरूप कम हुआ, तथापि घरेलू उद्योग की हानियां बढ़ गईं क्योंकि उसे विचाराधीन उत्पाद की बिक्री अलाभप्रद कीमतों पर करनी पड़ी।
- (lxxvii) आवेदकों के पास अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाएं हैं और वे नवीनतम प्रौद्योगिकियों के सोलर सेल उत्पादित करने में सक्षम हैं। कई मामलों में घरेलू रूप से उत्पादित सोलर सेलों की दक्षता आयातित सोलर सेलों से कहीं अधिक है।
- (lxxviii) दक्षता क्षति का कारण नहीं है। घरेलू रूप से उत्पादित सोलर सेलों के लिए बाजार है और घरेलू उत्पादक अपना उत्पादन बेचने में समर्थ हैं। तथापि, घरेलू उत्पादकों को कीमत के संदर्भ में आयातित सामानों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। चूंकि आयात भारतीय बाजार में बहुत ही कम कीमतों पर आ रहे हैं, अतः घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हो रही है।
- (lxxix) आयातित सामान अप्रैल-सितंबर, 2019 के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती करते रहे। कीमत कटौती की कम प्रतिशतता केवल इस कारण है कि घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को कम करके आयातों से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। घरेलू उत्पादक आयात कीमतों के समान कीमतें रखने के लिए मजबूर हैं। अन्यथा उन्हें ऑर्डर नहीं मिलेंगे।
- (lxxx) कम कीमत पर बिक्री आयातों से हुई क्षति की मात्रा के अधिक उपयुक्त मानदंड होंगे तथा घरेलू समान वस्तुओं के लिए लाभप्रद कीमतें वसूल करने से घरेलू उद्योग को रोक रही है।
- (lxxxi) रक्षोपाय लगाए जाने के बाद सतत गंभीर क्षति के अन्य कोई ज्ञात कारण नहीं हैं।

- (lxxxii) धारा 8ख(4) के अंतर्गत सांविधिक निर्धारण के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए गंभीर क्षति झेलना जारी रखना आवश्यक नहीं है और घरेलू उद्योग के लिए यह दर्शाना पर्याप्त है कि उसने उसको हुई गंभीर क्षति को समायोजित करने के लिए उपाय किए हैं और यह दर्शाने पर कि यह गंभीर क्षति वह होगी।
- (lxxxiii) 2016-17 और 2017-18 को इस कारण शामिल किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व और बाद में घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण रक्षोपाय लगाए जाने के पूर्व और बाद की उनकी स्थिति को समझना सुकर बनाने के लिए किया जा सकता है।
- (lxxxiv) हितबद्ध पक्षकारों को साथ-साथ अनुमोदन करने तथा विरोध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती अर्थात् पहला तर्क कि घरेलू उद्योग गंभीर क्षति में सकारात्मक रूप से समायोजन नहीं कर रहा है और उसी स्वर में यह भी तर्क देते हैं कि घरेलू उद्योग को अब कोई क्षति नहीं हो रही है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति में मूल जांच के दौरान की स्थिति से सुधार हुआ है। इंडोसोलर सहित 11 घरेलू उत्पादकों से उनकी बंदी के कारण किसी अन्य कारण के बिना गैर-प्रचालनात्मक होने पर इस तथ्य का स्पष्ट साक्ष्य है कि कम कीमत वाले आयातों की मौजूदगी से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति जारी रही है। अतः यह अनुरोध है कि शुल्क लगाए जाने का विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों के विरोधीभासी अनुरोध स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करते हैं कि आयातों के कारण गंभीर क्षति अब भी मौजूद है और यह कि घरेलू उद्योग ने आयात प्रतिस्पर्धा में सकारात्मक रूप से समायोजन किया है क्योंकि वह उस गंभीर क्षति की मात्रा को कम करने में सक्षम रहा है जो उसे काफी मात्रा तक मूल जांच के दौरान हो रही थी।
- (lxxxv) यह तथ्य कि घरेलू उद्योग की उत्पादन सुविधाओं का मांग-आपूर्ति अंतराल के बावजूद अब भी पूर्णतः उपयोग किया जाना है, इस तथ्य को सिद्ध करता है कि आयात घरेलू बाजार में की गई प्रतिस्पर्धी वस्तु को बेचने से उनकी कीमतों की कटौती पर रोक रहे हैं।
- (lxxxvi) इस दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद घटिया है अथवा उस मामले में उधारदाताओं ने उन परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए इंकार कर दिया है जो इस कारण घरेलू रूप से उत्पादित विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग करने का विचार करते हैं कि घरेलू रूप से उत्पादित सेल घटिया गुणवत्ता के हैं।
- (lxxxvii) आवेदक शुल्क लगाए जाने के बाद कुछ निष्पादन मानदंडों में सुधार स्वीकार करते हैं, परंतु घरेलू उद्योग की स्थिति वित्तीय रूप से जोखिम तथा टूटने की स्थिति में बनी हुई है। यद्यपि उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा बढ़ा है, तथापि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता रक्षोपाय शुल्क आदि लगाए बिना भारत में आ रहे आयातों की काफी मात्रा से सतत कीमत प्रभाव के कारण नकारात्मक बनी हुई है।
- (lxxxviii) खड़े एकीकरण, संस्थापित क्षमता में वृद्धि तथा बढ़ते हुए आर्थिक पैमाने का अभाव, घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले कारकों के रूप में उल्लिखित किए गए हैं, जो उसकी समायोजन योजना का भाग बनते हैं और इसके ब्यौरे आवेदकों द्वारा दायर घरेलू उत्पादकों की प्रश्नावली के उत्तर में भी दिए गए हैं।
- (lxxxix) जहां तक निविदाओं की मौसमी प्रकृति के कारण कम क्षमता उपयोग से संबंधित आरोप का संबंध है, घरेलू उद्योग ने 2016-17 से 2019-20 तक के अपने आंकड़े दिए हैं जो यह दर्शाते हैं कि बढ़ाई गई समयावधि में भी घरेलू उद्योग की क्षमता का मांग में काफी वृद्धि के बावजूद कम उपयोग रहा है। अतः मौसमी होने के नाते निविदाओं के कारण किसी क्षति का बढ़ाई गई अवधि से विरोधाभास है जिसमें घरेलू उद्योग के निष्पादन को मापा गया है।
- (xc) घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले अन्य विभिन्न कारक, जो मैसर्स शपूर्जी पल्लोंजी द्वारा उल्लिखित किए गए हैं, वास्तविक आंकड़े अथवा साक्ष्य से समर्थित नहीं हैं और केवल अनुमान और कल्पना के आधार पर हैं। ऐसे दावों का आधार सत्यापित करने के लिए न तो उल्लेख और न ही स्रोत प्रदान किया गया है।
- (xci) घरेलू उत्पादकों को बाजार स्थिति में समायोजन करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। ये परिस्थितियां निरंतर शुल्क लगाने को आवश्यक बनाती हैं ताकि घरेलू उद्योग स्थिरता प्राप्त कर सके और स्वयं को बाजार में स्थापित कर सके।

- (xcii) घरेलू उद्योग को कम आयात कीमतों के दबाव को दूर करने के लिए रक्षोपाय शुल्क का संरक्षण और उससे अपनी समायोजन योजना कार्यान्वित करने में सक्षम होने के लिए लाभप्रदता प्रदान करने की आवश्यकता है।
- (xciii) आयात मांग के 90 प्रतिशत से अधिक की पूर्ति करते हैं और उन्होंने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेशों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
- (xciv) अनुच्छेद 5.1 रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के संदर्भ में समायोजन योजनाओं पर विचार करने का दायित्व नहीं लगाता, जैसा कि कोरिया-डेयरी में डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट में पाया गया है। रक्षोपाय लगाने का प्रयोजन घरेलू उद्योग को आयात प्रतिस्पर्धा में समायोजित होने के लिए पर्याप्त समय देना है और शुल्क लगाए जाने के संरक्षण के लिए पात्र होने हेतु समायोजन योजना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग को दायित्व नहीं देता।
- (xcv) इसकी अपेक्षा, शुल्क के प्रगामी उदारीकरण के संबंध में समायोजन का प्रश्न संगत हो जाता है जिसे जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा आयात प्रतिस्पर्धा में समायोजन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अपेक्षित समय की जांच के आधार पर निर्धारित किया जाना होता है।
- (xcvi) चूंकि रक्षोपाय शुल्क लगाने की स्थिति घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति रोकना तथा उसका उपचार करने के लिए है, अतः आयात प्रतिस्पर्धा में सकारात्मक रूप से उद्योग के समायोजन करने का साक्ष्य घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार तथा इस बात की जांच कि क्या मूल जांच के दौरान प्रस्तावित समायोजन योजना का अपेक्षित प्रभाव उपयुक्त मात्रा तक प्राप्त कर लिया गया है। इस संबंध में, मूल जांच के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित समायोजन योजना के अपेक्षित प्रभाव से कम कीमत वाले आयातों के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए बिक्री लागतों में कमी हुई थी।
- (xcvii) याचिकाकर्ताओं ने कई कदम उठाकर भारत से बाहर के निर्यातकों के साथ लागत प्रतिस्पर्धी बनने के लिए अपनी लागत में कमी करने की योजना बनाई। इन कदमों में (i) यथापेक्षित दीर्घावधि भारी संविदाओं में प्रवेश कर कच्ची सामग्री की लागत कम करने की दृष्टि से कच्ची सामग्री के विद्यमान आपूर्तिकर्ताओं के साथ पुनः वार्ता करना, (ii) आधारभूत कच्ची सामग्री से वेफर्स और इंगट के विनिर्माण के लिए संयंत्र स्थापित कर पिछड़े एकीकरण और मितव्ययिता महसूस करने में सहायता के लिए परियोजनाएं, (iii) जिनके पास केवल सेल बनाने के लिए सुविधाएं हैं, उनके द्वारा मॉड्यूलों का विनिर्माण करने के लिए सुविधाएं स्थापित कर अग्रवर्ती एकीकरण हेतु परियोजनाएं शुरू करना, (iv) ईआरपी प्रौद्योगिकी अथवा बाइफेसियल प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर तकनीकी रूप से बेहतर उत्पादों के लिए जहां भी संभव हो, परियोजनाएं शुरू करना, (v) लगाए गए रक्षोपाय शुल्क की मात्रा के आधार पर क्षमता का उपयोग बढ़ाकर प्राथमिक रूप से परिवर्तन लागत कम करना जिससे बाजार में अपेक्षित परिवर्तन होंगे, (vi) वित्तपोषण लागत कम करना क्योंकि किसी संगत समय में उधार की लागत काफी थी और नियोजित पूंजी पर आय पर उसका काफी प्रभाव था, शामिल हैं।
- (xcviii) डेढ़ वर्ष के अंतर्गत, घरेलू उत्पादकों ने ***-*** सेंट/वाट की लागत कटौती हासिल की है। घरेलू उद्योग ने *** सेंट/वाट की भारित औसत लागत कटौती हासिल की। ये आवेदकों की संबंधित घरेलू उत्पादकों की प्रश्नावली के उत्तरों में ब्यौरे में दर्शाए गए हैं।
- (xcix) इसे समायोजन करने वाले घरेलू उद्योग के साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए। तथापि, आयातों की कीमतों में सतत गिरावट के कारण वर्तमान समीक्षा आवश्यक हो गई है क्योंकि घरेलू उद्योग को पुनः प्रतिस्पर्धी बनने के लिए और अधिक लागत बचत हासिल करनी है और इस दिशा में एक संशोधित समायोजन योजना दी गई है। जहां तक घरेलू उद्योग के बदले हुए संघटकों का संबंध है, यह अनुरोध है कि संगत मानदंड यह है कि क्या समान तथा सीधे ही प्रतिस्पर्धी वस्तु का घरेलू उद्योग समायोजन कर रहा है। यहां तक कि जिन उत्पादकों ने मूल जांच के दौरान भाग नहीं लिया था, समीक्षा में भाग लेते हैं, यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि ये घरेलू उत्पादक जो नए हैं, भी रक्षोपाय शुल्क द्वारा दिए गए संरक्षण के परिणामस्वरूप सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहे हैं।
- (c) समायोजन योजना के ब्यौरे प्रकृति में गोपनीय हैं क्योंकि यह व्यापार संवेदी सूचना है और उसका पर्याप्त अगोपनीय सार, जो उठाए जाने के लिए मांग किए गए कदमों की पर्याप्त समझ के लिए अनुमति देता है, आवेदकों के एनसीवी घरेलू उत्पादकों की प्रश्नावली के उत्तर के अनुबंध 4 में प्रकट किए गए हैं।

- (ci) मैसर्स कनाडियन सोलर थाइलैंड का यह दावा कि याचिकाकर्ता कंपनियों ने दावा नहीं किया है कि उन्होंने छः कदम वाली समायोजन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं, गलत है और रिकार्ड में सामग्री के विरुद्ध है क्योंकि प्रत्येक आवेदक ने अपने संबंधित घरेलू उत्पादकों की प्रभावली के उत्तर के अनुबंध 4 में मूल जांच के अनुसरण में सितंबर, 2019 तक प्राप्त कटौती के साथ अपनी संशोधित समायोजन योजना दी है।
- (cii) यद्यपि घरेलू उद्योग आयात प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वयं ही सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है, तथापि आयात कीमतों में निरंतर तेजी से गिरावट आती रही है जो घरेलू उद्योग को निरंतर गंभीर क्षति पहुँचा रही है। अतः घरेलू उद्योग को बढ़ते हुए आयातों से हुई अपनी टूटती हुई वित्तीय स्थिति से उबरने के लिए स्वयं को सही स्थिति में लाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है।
- (ciii) एक संशोधित समायोजन योजना तैयार की गई है और प्रत्येक याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा अपने विशेष तथ्यों और लागत ढाँचे को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक को दे दी गई है।
- (civ) यह समायोजन योजना मूल जांच के दौरान पूर्व में दी गई योजना के अनुरूप है, परंतु प्राप्त किए जाने के लिए मांग किए गए अन्य उपायों तथा कीमत कटौती में आयात कीमतों में और अधिक गिरावट के मद्देनजर संशोधन किया गया है।
- (cv) हितबद्ध पक्षकार यह मानने में विफल रहे हैं कि रक्षोपाय शुल्क की मांग मूल जांच के दौरान 4 वर्षों की अवधि के लिए की गई थी और उन्होंने उपर्युक्त समय सीमा के अनुसार समायोजन योजना प्रस्तुत कर दी थी। अतः यह तथ्य कि संशोधित समायोजन योजना कुल मिलाकर पूर्व समायोजन योजना के अनुसार है, केवल तार्किक है और इन हितबद्ध पक्षकारों के लिए कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
- (cvi) वर्तमान समायोजन योजना ने पर्याप्त लागत कटौतियाँ स्पष्ट रूप से प्राप्त कर ली हैं जबकि नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने एवं उन्हें अपनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास में से कुछ कदम अभी हासिल किए जाने हैं क्योंकि घरेलू उद्योग को उन कीमतों पर आयातों में वृद्धि के कारण हानियाँ हो रही हैं जो और कम हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, समायोजन योजना के निमित्त कदम जो अतिरिक्त लागत बचत हासिल करने के लिए काफी सीमा तक पहले ही सफल रही हैं, व्यवहार्य योजना है।
- (cvii) इस तर्क के संबंध में कि बिक्री लागत में कमी सिलिकॉन वेफर्स की कीमतों में गिरावट के कारण है, बिक्री लागत में गिरावट समायोजन योजना के माध्यम से प्राप्त कम लागत बचतों के परिणामस्वरूप थी। अन्यथा घरेलू उद्योग आयात कीमतों और घरेलू एनएसआर के बीच खाई को कम करने में सक्षम नहीं होता जो मूल जांच के अनुसरण में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के पूर्व थी, यदि अंतर्राष्ट्रीय रूप से कीमतों के लिए निर्धारक कारक केवल कच्ची सामग्री की कीमत थी। यदि कच्ची सामग्री कीमत के लिए एक मात्र निर्धारक कारक था, तो आयातों और एनएसआर के बीच अंतर रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से पूर्व और उसके बाद समान रहता।
- (cviii) इंडोसोलर का दिवालियापन इस तथ्य के कारण हो सकता है कि यद्यपि मूल अंतिम जांच परिणाम में महानिदेशक के दिनांक 05.01.2018 के प्राथमिक जांच परिणाम में इस जांच परिणाम पर 70 प्रतिशत अनंतिम रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की गई थी कि सौर ऊर्जा विकासकर्ता अर्थात् मैसर्स शपूर्जी पल्लोंजी द्वारा शुरू किए गए विवाद में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश के कारण रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए नाजुक परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिसके परिणामस्वरूप 16.04.2018 तक अनंतिम शुल्क लगाए जाने पर स्थगन आदेश हुआ। परिणामस्वरूप, अंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की सिफारिश और परिणामस्वरूप शुल्क लगाए जाने की अधिसूचना के बावजूद 2018 की रिट याचिका 12817 में मैसर्स एसीएमई सोलर होल्लिंग द्वारा प्राप्त स्थगन के कारण शुल्क लगाए जाने को प्रभावी नहीं किया जा सकता। जिस याचिका के फलस्वरूप अनुदेश संख्या 12/2018 जारी हुए जिसमें माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक विचाराधीन उत्पाद की मंजूरी के समय रक्षोपाय शुल्क के भुगतान पर जोर न देने का निर्णय लिया गया था। यह स्थगन आदेश अंतिम रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2018 की एसएलपी (सी) 24009-10 में दिनांक 10.09.2018 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था। रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने में लंबे विलंब के कारण रक्षोपाय नियमावली के नियम 9 के तहत महानिदेशक द्वारा पहले ही निर्धारित किए जाने के बावजूद कि महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जहां अनंतिम शुल्क लगाए जाने में विलंब से क्षति

होगी जिसे 05.01.2018 से ठीक करना कठिन होगा, रक्षोपाय शुल्क एसपीडीए सदस्यों द्वारा विवाद के कारण नहीं लगाया जा सका। परिणामस्वरूप, चूंकि कोई अनंतिम रक्षोपाय शुल्क प्राथमिक जांच परिणामों पर स्थगन के कारण नहीं लगाया जा सका, अतः रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने में विलंब का अपरिहार्य परिणाम यह था कि इंडोसोलर को मूल जांच होने तक के दौरान निरंतर क्षति होती रही और उसके बाद भी अपने प्रचालनों को मुक्ति देने में सक्षम होने की स्थिति से और अपनी समायोजन योजना कार्यान्वित करने की स्थिति से बाहर हो गया। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से पूर्व अन्य घरेलू उत्पादकों को भी गंभीर क्षति अतः गंभीर सिद्ध हुई और इसीलिए यही इस तथ्य को बल देता है कि रक्षोपाय शुल्क जारी रखना आवश्यक है। अतः यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि रक्षोपाय शुल्क के उपायों को रद्द करना, जिसे घरेलू उद्योग के सभी आर्थिक मानदंडों में सुधार से उनकी दक्षता प्रदर्शित की है, घरेलू उद्योग को पुनः क्षति पहुँचाएगा जिससे उभरना कठिन हो जाएगा।

- (cix) चूंकि भारत का लक्ष्य पेरिस करार के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को हासिल करने के लिए 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का है जिस करार में वर्ष 2022 तक 33-35 प्रतिशत कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन कम करने की मांग है, घरेलू उद्योग ने विस्तारित हो रही संस्थापित क्षमता में काफी निवेश किया है। तथापि, विद्यमान आयात कीमतों से आयातित विचाराधीन उत्पाद आएंगे जो पूरे गृह बाजार को ले लेंगे तथा इस प्रक्रिया में घरेलू उद्योग को नष्ट कर देंगे।
- (cx) रक्षोपाय शुल्क जारी रखने से मितव्ययिता हासिल कर सतत निवेश, पूंजी व्यय विस्तार और लागत में कमी के लिए एक प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
- (cxi) रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना जारी रखना व्यापक सार्वजनिक हित में भी है और रक्षोपाय शुल्क न लगाना भारत के सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा क्योंकि स्थानीय विनिर्माण बंद हो जाएंगे और 11,000 करोड़ रुपये के निवेश का दिवाला निकल जाएगा तथा भारी बेरोजगारी होगी। घरेलू उद्योग पर सतत आयातों के प्रभाव कई घरेलू उत्पादकों की बंदी से स्पर्श गोचर है। भारत सरकार की पहले से ही विद्यमान तिरछी आयात निर्भरता काफी बढ़ना जारी रहेगी क्योंकि भारत चीन का शीर्ष निर्यात लक्ष्य है जो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक था और चीन से आयात केवल रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद भी कुछ सीमा तक कम हुए।
- (cxii) यह मानते हुए कि घरेलू सेल विनिर्माताओं के सामने उनकी मौजूदगी का आसन्न खतरा है, अतः रक्षोपाय शुल्क जारी न रखने से घरेलू सेल विनिर्माण आधार का पूर्णतः उन्मूलन हो जाएगा और सोलर मॉड्यूल विनिर्माता मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए आयातित सोलर सेलों पर पूर्णतः निर्भर हो जाएंगे। मॉड्यूलों में व्यवस्थित सोलर सेलों की पहुँच कीमतों में गिरावट केवल सोलर सेलों की अपेक्षा काफी अधिक रही है। भारत में घरेलू सेल विनिर्माण प्रचालनों को पूर्णतः बंद करने पर मॉडल विनिर्माता निर्यातकों की पूरी दया पर हो जाएंगे जो फिर कीमतें बताने की स्थिति में होंगे और मॉड्यूल विनिर्माताओं को अप्रतिस्पर्धी बनाते हुए सोलर सेलों की कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं। इसका सोलर मॉड्यूलों जैसे – ईवीए शीट्स और सोलर ग्लास के लिए उपस्करों का विनिर्माण करने में शामिल ऊपरी स्तर के और निचले स्तर के अन्य उद्योगों पर प्रपाती प्रभाव पड़ेगा तथा भारत की सौर उपस्कर विनिर्माण क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट करेगा।
- (cxiii) जब घरेलू उद्योग रक्षोपाय शुल्क के संरक्षण में सकारात्मक रूप से समायोजन करता रहा है तो घरेलू उद्योग का संरक्षण न करना माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान के विरुद्ध होगा।
- (cxiv) यद्यपि एमएनआरई द्वारा दिनांक 22.07.2019 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, तथापि उसके तहत परिकल्पित परियोजनाएं अभी शुरू होनी हैं और उसके परिणामस्वरूप कोई मूर्त लाभ होंगे। चूंकि घरेलू उत्पादकों को कुसुम कार्यक्रम से अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, अतः रक्षोपाय शुल्क का संरक्षण अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादक पूरे घरेलू बाजार को आपूर्ति भी करना चाहते हैं। रक्षोपाय लगाने से यह सुनिश्चित होगा कि घरेलू उद्योग पूरे घरेलू बाजार को आपूर्ति कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं और बने रहने के लिए कुसुम कार्यक्रम पर पूर्णतः निर्भर नहीं होंगे।

- (cxv) चूंकि भारत ने आईटीए-1 के तहत प्रतिबद्धताएं की हैं, अतः बढ़े हुए बीसीडी से रुका हुआ है। जैसे ही प्रभावी दर जीरो होती है तो इस तथ्य कि बीसीडी 20 प्रतिशत तक बढ़ गया है, का कोई परिणाम नहीं है। एसजीडी और बीसीडी साथ-साथ लगाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- (cxvi) एसजीडी केवल एक प्रशुल्क उपाय है और इसीलिए आयातों के माध्यम से मांग-आपूर्ति का घाटा पूरा करने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के इन आयातों को रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बावजूद समाप्त नहीं किया गया है जो स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि मांग-आपूर्ति अंतराल आयातों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। रक्षोपाय शुल्क केवल कीमतें बढ़ाते हैं और केवल आयात को प्रतिबंधित नहीं करते जो कि मात्रात्मक उपायों के असमान हैं।
- (cxvii) सार्वजनिक हित में प्रश्रुत उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं से तत्काल हित ही शामिल नहीं हैं। दीर्घावधि सार्वजनिक हित केवल तभी पूरा होगा जब भारतीय विद्युत क्षेत्र अपने भीतर से अपने पूंजी उपस्करों की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हों और आयातों पर निर्भर न हों।
- (cxviii) रक्षोपाय शुल्क का प्रयोजन घरेलू उद्योग को बड़ी हुई आयात प्रतिस्पर्धा के कारण ही गंभीर क्षति से बचाना और उसका उपचार करना है। क्या उपाय कानूनी विवाद के आशय तथा प्रयोजन पर विचार करके निर्धारित किए जाने वाले सार्वजनिक हित में हैं जिसके तहत उपर्युक्त निवारण किया जा रहा है। यदि रक्षोपाय शुल्क उपर्युक्त उद्देश्य को हासिल करने में सक्षम है तो शुल्क लगाए जाने पर जनहित में होने के रूप में विचार किया जाना चाहिए।
- (cxix) इस तर्क के संबंध में कि पीईआरसी और बायफेसियल जैसे प्रौद्योगिकिय रूप से उन्नत सोलर सेल केवल एमएसपीवीएल द्वारा उत्पादित किए जाते हैं जिसे अलग कर दिया गया है, मैसर्स एमएसपीवीएल घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने योग्य है। उसके द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद के भेद घरेलू उद्योग की प्रौद्योगिकिय क्षमताओं का बहुत ज्यादा परिणाम हैं। यदि केवल बिक्री यूनिटों पर विचार किया जाता है क्योंकि जेएसपीएल और जेआईएल, एमएसपीवीएल से पुरानी यूनिटें थीं जिसने 2017 में अपना उत्पादन आरंभ किया, अतः नई प्रौद्योगिकियों से उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए और अनुसंधान तथा विकास और कैपेक्स में निवेश करने के लिए लाभप्रद होने वाले उद्यम की आवश्यकता है। बड़ी हुई आयात प्रतिस्पर्धा को देखते हुए जेआईएल और जेएसपीएल की लाभप्रदता गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी, जिसने उन्हें इस संबंध में कदम उठाने से रोका। रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने और वित्तीय स्थिति में सुधार के बावजूद घरेलू उद्योग को अभी पुनः लाभप्रद होना है और इसीलिए वह अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने तथा नई प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग ने अपनी समायोजन योजना को महसूस करने के निमित्त ठोस कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसका अधिकतर भाग कार्यान्वित किया जा रहा है। घरेलू उद्योग के रक्षोपाय शुल्क की सहायता से पुनः लाभप्रद हो जाने पर वह इस दिशा में आगे निवेश करने में सक्षम होगा। अतः रक्षोपाय शुल्क का संरक्षण बढ़ाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की निरंतर कटौती कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की क्षमता पर उसके उत्पादन को उचित कीमत पर बेचने के संबंध में आसन्न दबाव डाल रहे हैं।
- (cxx) मिथाइल एसोसिएट पर विश्वास गलत रखा गया है क्योंकि रक्षोपाय शुल्क उपर्युक्त मामले में जनहित में नहीं पाया गया था क्योंकि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद को छोड़कर अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए अपनी उत्पादन सुविधाओं का प्रयोग किया था और आयात प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप बाजार हिस्से की हानि का दावा किया था। इसके अतिरिक्त, इसे जनहित में नहीं पाया गया था क्योंकि निचले स्तर के उद्योग पर प्रभाव के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया था, कीमत कटौती भी नकारात्मक थी जिससे आयातित सामान घरेलू रूप से उत्पादित विचाराधीन उत्पाद से अधिक महंगे हो जाएंगे और अनुचित बाजार स्थिति बनेगी। अंतिम रूप से कोई गंभीर क्षति तथा खतरा अथवा यहां तक कि उसका खतरा घरेलू उद्योग को नहीं पाया गया था। वर्तमान मामले में, मूल जांच के अनुसरण में गंभीर क्षति पहले ही निर्धारित कर दी गई थी। तथापि, सीसीसीएमई यह मानने में विफल रहे हैं कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग ने साक्ष्य दिया है कि केंद्र सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रभावित विद्युत विकासकर्ताओं के हितों का संतुलन बनाने के लिए कदम उठाए हैं जो उन्होंने दिनांक 02.04.2018 की अधिसूचना फा. सं. 283/3/2018-ग्रिड

सोलर द्वारा पास-श्रु सुविधा अधिसूचित करके किया है जिसमें करारों के "कानून में परिवर्तन" खंड संबंधी स्पष्टीकरण दिया गया है। उसके बाद, विद्युत मंत्रालय ने भी आयातित सोलर सेलों और मॉड्यूलों पर दिए गए रक्षोपाय शुल्क के पास-श्रु की अनुमति देने के लिए 27.08.2018 को सीईआरसी को निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसरण में, कुछ सौर विद्युत विकासकर्ताओं को भी आयातित विचाराधीन उत्पाद पर उनके द्वारा वहन किए गए अतिरिक्त रक्षोपाय शुल्क के पास-श्रु की अनुमति दी गई है तथा उसका साक्ष्य याचिकाकर्ताओं के लिखित अनुरोध में प्रदर्श 389 के रूप में संलग्न था। अतः, केंद्र सरकार ने सौर विद्युत विकासकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं।

- (cxxi) अंतिम उपभोक्ता पर प्रभाव के संबंध में, घरेलू उद्योग ने मूल जांच के दौरान अपने अनुरोधों में विद्युत की कीमतों पर 95 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क का प्रभाव बताया था और इस पर महानिदेशक द्वारा ध्यान दिया गया था जिन्होंने निर्धारित किया कि वास्तविक प्रभाव घरेलू उद्योग द्वारा सुझाए गए तथा विरोधी पक्षकारों द्वारा सुझाए गए प्रभावों के बीच में सही होगा। उसके बाद, महानिदेशक ने 25 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की थी जिसे अंतिम उपभोक्ता पर प्रभाव पर विचार करने के बाद जनहित में पाया गया था। वर्तमान मामले में प्रार्थित रक्षोपाय शुल्क मूल जांच से काफी कम है।
- (cxxii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद लागू बीआईएस मानदंडों का पालन करता है। सोलर फोटोवोल्टेक, सिस्टम, डिवाइसेस और कम्पोनेंट्स गुड्स (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकताएं) आदेश, 2017 उन फोटोवोल्टेक सेलों के विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण पर रोक लगाता है जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं हैं। यदि आवेदकों द्वारा लागू बीआईएस मानदंडों के अनुरूप न होने वाला एक उत्पाद बेचा गया तो वह विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण, भंडारण अथवा बिक्री नहीं कर पाते।
- (cxxiii) मैसर्स एसपीडीए और मैसर्स कनाडियन सोलर थाइलैंड ने भारत में सीधे ही प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादन करने वाले कई घरेलू उत्पादकों की बंदी के तथ्य का उल्लेख किया है। अतः, व्यापार उपचार उपायों का अनुचित लाभ लेने का प्रश्न ही नहीं उठता और उनके जारी रहने का एक स्पष्ट मामला बन जाता है।
- (cxxiv) रक्षोपाय शुल्कों, जो अंतरिम उपाय हैं, में घरेलू उद्योगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने पर उनके उद्योग में उनकी स्थिति बनाए रखने के लिए प्रावधान है।
- (cxxv) मूल जांच के अनुसरण में दिए गए रक्षोपाय शुल्क का स्तर समायोजन योजना पूरी तरह से कार्यान्वित करने का वांछित उद्देश्य हासिल करने हेतु घरेलू उद्योग के लिए आवश्यक पूर्ण संरक्षण प्रदान नहीं करता। चूंकि रक्षोपाय शुल्क पहले ही बहुत कम है, अतः प्रार्थित उदारीकरण का स्तर बहुत कम है ताकि घरेलू उद्योग वर्तमान समीक्षा में योजना बनाई गई संशोधित लागत बचतें हासिल कर सके।
- (cxxvi) यूक्रेन – कुछ पैसेंजर कारों पर निश्चयात्मक रक्षोपाय में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय की रिपोर्ट पर यह तर्क देने के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता, शुल्क का उदारीकरण नियमित अंतरालों पर शुल्क में काफी कमी लाने के आशय से है क्योंकि अपीलीय निकाय ने केवल यह माना है कि शुल्क का धीरे-धीरे उदारीकरण में विलंब नहीं किया जा सकता और किसी बाद की तारीख को नहीं रखा जा सकता तथा उसे नियमित अंतरालों पर उदारीकृत किया जाना है। यह कहीं भी नहीं पाया गया है कि उदारीकरण की मात्रा काफी होनी चाहिए, न ही नियमित अंतरालों पर उदारीकरण की न्यूनतम सीमा अपेक्षित है।
- (cxxvii) शुल्क लगाए जाने की अवधि तथा कटौती की मात्रा घरेलू उद्योग के सकारात्मक समायोजन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक सीमा पर निर्भर करती है।
- (cxxviii) मैसर्स एमएसपीवीएल को हटाना रक्षोपाय शुल्क का 25 प्रतिशत में संशोधन करके कम करने का कारण नहीं था, मूल जांच के दौरान क्षति मार्जिन सिफारिश किए गए रक्षोपाय शुल्क की राशि से अधिक था और मूल जांच के रिकार्ड से इसका सत्यापन किया जा सकता है।

(ग) महानिदेशालय (रक्षोपाय) की जांच एवं जांच परिणाम

31. (क) घरेलू उद्योग द्वारा इस याचिका में दी गई सूचना, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई अतिरिक्त सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया विभिन्न अनुरोध और अन्य प्राथमिक एवं गौण उपलब्ध रिकार्डों तथा

(ख) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और साक्ष्य का उस सीमा तक सत्यापन जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया, के आधार पर, मैंने उसकी जांच की है और अपना अंतिम जांच परिणाम नीचे दिए गए अनुसार रिकॉर्ड किया है :

(i) **लागू कानूनी प्रावधान**

32. सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8 ख (4) के प्रथम परंतुक में यह प्रावधान है कि यदि केन्द्र सरकार का यह मत हो कि घरेलू उद्योग ने इस प्रकार की क्षति अथवा उसके खतरे के लिए समायोजित करने हेतु कदम उठाए हैं और यह आवश्यक है कि रक्षोपाय शुल्क को लगाया जाना जारी रहना चाहिए, यह ऐसे अधिरोपण की अवधि का विस्तार कर सकता है। दूसरे परंतुक में यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी स्थिति में रक्षोपाय शुल्क को उस तिथि से जिस तिथि को इस प्रकार का शुल्क सबसे पहले लगाया गया था, 10 वर्षों की अवधि से आगे लगाया जाना जारी रखना चाहिए।

33. इस नियमावली का नियम 18 में निम्नानुसार उल्लेख है :-

(i) महानिदेशक समय समय पर रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे और यदि वे संतुष्ट हों, तब उन्हें प्राप्त सूचना के आधार पर इसे इस प्रकार से जारी रखेंगे कि :

(i) रक्षोपाय शुल्क गंभीर क्षति को रोकने अथवा इसका उपचार करने के लिए आवश्यक है और यदि ऐसा कोई साक्ष्य हो कि यह उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजित कर रहा है, तब यह केन्द्र सरकार को शुल्क को लगातार लगाए रखने के लिए सिफारिश करेगा ;

(ii) इस प्रकार के शुल्क को लगातार लगाए रखने, केन्द्र सरकार को इसे वापस लिए जाने की सिफारिश करने का कोई औचित्य नहीं है।

बशर्ते कि यहां रक्षोपाय शुल्क को लगाए जाने की अवधि तीन वर्ष से अधिक होती हो, वहां महानिदेशक इस प्रकार के अधिरोपण की मध्य अवधि के बाद इस स्थिति की समीक्षा करेंगे और यदि उपयुक्त हो तो शुल्क के उदारीकरण में वृद्धि के लिए अथवा इस प्रकार के रक्षोपाय शुल्क को वापस लिए जाने के लिए सिफारिश करेंगे।

(2) उप नियम (1) के अंतर्गत शुरू की गई किसी समीक्षा को इस प्रकार की समीक्षा की शुरुआत की तिथि से अधिकतम 8 महीने तक अथवा ऐसी विस्तारित अवधि जिसे केन्द्र सरकार अनुमति दे, के भीतर समाप्त किया जाएगा।

(3) नियम 5, 6, 7 और 11 के प्रावधान समीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

34. इस नियमावली के नियम 4(5) में महानिदेशक रक्षोपाय को यह कार्य सौंपा गया है कि वे रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करें। उपर्युक्त प्रावधानों का अवलोकन यह दर्शाता है कि समीक्षा में, महानिदेशक (रक्षोपाय) से यह अपेक्षित है कि वे साक्ष्य की जांच करें और उसका निर्धारण करें कि:

(क) यह आवश्यक है कि रक्षोपाय शुल्क को गंभीर क्षति से रोकने अथवा इसका उपचार करने के लिए लगाया जाना जारी रखना चाहिए।

(ख) यह कि घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है अर्थात् क्या घरेलू उद्योग ने इस प्रकार की क्षति अथवा इसके खतरे के लिए समायोजन करने हेतु कदम उठाए हैं।

35. यह जांच उक्त नियमावली के अनुसार की गई है और अंतिम जांच परिणामों को इस अधिसूचना के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया है।

(ii) **विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)**

36. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद को नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित किया गया था :

“सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क शीर्ष 8541 और प्रशुल्क मद 85414011 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य “सोलर सैल जिसका मॉड्यूल अथवा पैनलों में असेंबल किया गया हो अथवा नहीं”। सोलर सैल को बाजार की भाषा में फोटोवोल्टेयिक सैल के रूप में भी जाना जाता है। फोटोवोल्टेयिक प्रौद्योगिकी आणविक स्तर पर

शुल्क के प्रकाश को बिजली में सीधे परिवर्तन को सक्षम बनाता है और सोलर सैल ठोस अवस्था का विद्युतीय उपकरण है जो फोटो वोल्टेयिक प्रभाव के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिणत करता है। व्यावहारिक उपयोग से सोलर सैल की पैकेजिंग की जाती है और इसे एक असेंबली से जोड़ा जाता है और सोलर सैल की इस प्रकार की असेंबली को सोलर पैनल अथवा सोलर मॉड्यूल के रूप में संदर्भित किया जाता है। विद्युतीय संयोजन सोलर सैल में क्रम में किया जाता है ताकि अपेक्षित वर्तमान क्षमता उपलब्ध कराने के लिए इच्छित उत्पादन वाटेज और/ अथवा समांतर में प्राप्त किया जा सके।”

37. जैसा कि पूर्व में नोट किया गया है, सीमा प्रशुल्क शीर्षक “8541 4011- चाहे उसे मॉड्यूल में असेंबल किया गया हो अथवा नहीं” को 01.02. 2020 से उसकी अनुसूची III की प्रविष्टि सं. 2 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का सं. 12) की धारा 117 (ख) के माध्यम से निम्नलिखित दो शीर्षकों में विभाजित किया गया है :

8541 4011- सोलर सैल असेंबल नहीं किया हुआ

8541 4012- सोलर सैल मॉड्यूल में असेंबल किया हुआ अथवा पैनल में बनाया हुआ।

38. दिनांक 02 फरवरी, 2020 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 1/2020-सीमाशुल्क (रक्षोपाय) के माध्यम से इसमें ऊपर में उल्लिखित दो नए प्रशुल्क शीर्षकों को दिनांक 30 जुलाई, 2018 की पूर्व की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 1/2018-सीमाशुल्क (रक्षोपाय) में एक प्रशुल्क शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।
39. इस प्रकार, मौजूदा रक्षोपाय शुल्क सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 के अध्याय 85 के प्रशुल्क शीर्षक 85414011 और/अथवा 85414012 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य “सोलर सैल” चाहे उसके मॉड्यूल अथवा पैनलों में असेंबल किया गया हो अथवा नहीं” पर लागू होता है। हालांकि सीमाशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं होता है।
40. इस समीक्षा का विरोध करने वाले विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि सोलर सैल और सोलर मॉड्यूल को एक नहीं माना जा सकता है और यह कि घरेलू उद्योग के पास प्रौद्योगिकी, बायफेसियल एन टाइप सोलर सैलों, 5 और 6 बस बार उच्च क्षमता वाले सोलर सैल और मोनोक्रिस्टलाइन प्रौद्योगिकी के आधार पर थिन फिल्म प्रौद्योगिकी और “पी ई आर सी” (फैसीवेटेड एनीटर रियर फिल्म) नहीं है और इस कारण से विचाराधीन उत्पाद को केवल ऐसे उत्पादों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिसके लिए घरेलू उद्योग के पास उत्पादन की क्षमता है अथवा इसने वास्तव में उत्पादन किया है।
41. इसके अलावा, आर ई सी सोलर पी पी ई लि. ने यह दावा किया है कि उनके अल्फा उत्पाद को यूरोप सहित सिंगापुर और अन्य प्रक्षेत्रों द्वारा डिजायन पेटेंट दिया गया है और यह कि इसके डिजायन का उपयोग भी भारत में लंबित है। आर ई सी सोलर का यह दावा है कि उनका अल्फा उत्पाद (i) प्रोपाइटरि एडवांस टैक्नोलॉजी का उपयोग करता है, उत्कृष्ट क्वालिटी, स्थान कार्यक्षम और अधिक पर्यावरण अनुकूल है (ii) भारतीय बाजार में यह अपेक्षाकृत अधिक कीमत प्राप्त करता है और (iii) यह भारत में निर्मित वस्तुओं से सभी अर्थों में न तो सदृश और न ही समान है। वे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अपने अल्फा उत्पाद को बाहर रखने की मांग करते हैं क्योंकि उनके पास इसके लिए कुछ डिजायन पेटेंट है और उन्होंने इस उद्देश्य से दिनांक 24 नवंबर, 2009 का चीन जन गण, जापान, कोरिया, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान (चीनी ताइपेयी), थाइलैंड और यू एस ए से स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोलड फ्लैट प्रोडक्ट्स के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की जांच में की गई टिप्पणियों पर विश्वास किया है।
42. इस पहलू की ध्यानपूर्वक जांच करने पर मैं नोट करता हूं कि विभिन्न प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकारों के सोलर सैल कार्यक्षमता, भौतिक विशेषताओं जैसे आकार और वजन आदि तथा कीमत के मामले में अलग-अलग हैं। यद्यपि इस अंतर के कारण कीमत और कार्य क्षमता, विचाराधीन उत्पाद का अंतिम उपयोग के मामले में व्यापार केवल बिजली का उत्पादन करने के लिए है। वहां तक चीन जन गण, जापान, कोरिया, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान (चीनी ताइपेयी), थाइलैंड और यू एस ए से स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोलड फ्लैट उत्पादों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणामों पर निर्भरता का प्रश्न है, मैंने नोट किया है कि विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों जिसका घरेलू उद्योग उत्पादन नहीं कर रहा था, को बाहर रखा गया था क्योंकि ये ग्रेड विशिष्ट अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों के लिए अपेक्षित थे जिसे घरेलू उद्योग द्वारा

उत्पादित समान वस्तु द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका। वर्तमान मामले में, यह अनुरोध करते हुए कि अल्फा उत्पाद उत्कृष्ट कोटि, स्थान कार्यक्षम का है, और यह प्रोपराइटरी एडवांस प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और यह अपेक्षाकृत अधिक पर्यावरण अनुकूल है, यह हितबद्ध पक्षकारों के मामले में नहीं रहा है कि उनका उत्पाद घरेलू समान उत्पाद द्वारा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन के योग्य नहीं है और उससे इसकी सीधी प्रतिस्पर्धा नहीं है।

43. चीन जन.गण. से लोहा, एलाय अथवा गैर-अलाय स्टील का सीमलैस ब्लूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में दिनांक 9 दिसंबर, 2016 के अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी ने यह माना था कि पेटेंड की गई वस्तुओं और अन्य उप श्रेणी को तब तक विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता है, जब तक वे घरेलू समान वस्तुओं से तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन के लायक न हो जाएं और इस प्रकार उन वस्तुओं को बाहर करने के फलस्वरूप प्रवंचना होगी।
44. रक्षोपाय शुल्क नियमावली (सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997- दिनांक 29.07.1997 की अधिसूचना सं. 35/97-एन टी-सीमाशुल्क) (इसके पश्चात रक्षोपाय नियमावली के रूप में भी जाना जाता है) में किसी घरेलू उत्पादक को “भारत में समान वस्तु का एक उत्पादक अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तु अथवा व्यापार अथवा व्यापार संघ, जिसके अधिकांश सदस्यगण भारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के समान वस्तु का उत्पादन अथवा व्यापार करते हैं” और “समान वस्तु आ आशय उस वस्तु से है जो सभी अर्थों में जांच के अधीन वस्तु के अतिरिक्त अथवा समान हो” के रूप में परिभाषित “समान वस्तु” के रूप में घरेलू उत्पादक को मानते हैं। विचाराधीन उत्पाद अथवा फोटोवोल्टयी प्रभाव के द्वारा सूरज के प्रकाश को सीधे बिजली में परिणत करने के सामान्य एवं अतिव्याप्त अनुप्रयोग यह सिद्ध करते हैं कि आयात किए गए और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध वस्तु प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी हैं। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण ही कीमत और कार्यक्षमता के मामले में व्यापार होता है। इस कारण से जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में किए गए उल्लेख के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, इन मुद्दों का समाधान भी मूल जांच परिणाम में किया गया था और इस कारण से मुझे विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों अथवा रूपों को बाहर रखने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों में कोई दम नजर नहीं आता है और मैं मूल जांच में था विचारित तथा उल्लिखित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को बनाए रखता हूं और उसकी पुष्टि करता हूं।
45. सीमा प्रशुल्क शीर्षकों में परिवर्तन पर विचार करते हुए विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

“सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क शीर्ष 85414011 और प्रशुल्क मद 85414012 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य “सोलर सैल जिसका मॉड्यूल अथवा पैनलों में असेंबल किया गया हो अथवा नहीं”। सोलर सैल को बाजार की भाषा में फोटोवोल्टेयिक सैल के रूप में भी जाना जाता है। फोटोवोल्टेयिक प्रौद्योगिकी आणविक स्तर पर शुल्क के प्रकाश को बिजली में सीधे परिवर्तन को सक्षम बनाता है और सोलर सैल ठोस अवस्था का विद्युतीय उपकरण है जो फोटो वोल्टेयिक प्रभाव के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिणत करता है। व्यावहारिक उपयोग से सोलर सैल की पैकेजिंग की जाती है और इसे एक असेंबली से जोड़ा जाता है और सोलर सैल की इस प्रकार की असेंबली को सोलर पैनल अथवा सोलर मॉड्यूल के रूप में संदर्भित किया जाता है। विद्युतीय संयोजन सोलर सैल में क्रम में किया जाता है ताकि अपेक्षित वर्तमान क्षमता उपलब्ध कराने के लिए इच्छित उत्पादन वाटेज और/ अथवा समांतर में प्राप्त किया जा सके।

हलांकि सीमाशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।”

(क) घरेलू उद्योग (डी आई) का क्षेत्र एवं आधार

46. सीमाप्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख की उपधारा (6) के उपबंध (ख) में घरेलू उद्योग (इसके पश्चात डीआई के रूप में भी संदर्भित) नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित किया गया है:

(ख) “घरेलू उद्योग” का अभिप्राय उन उत्पादकों से है -

(i) जो भारत में संपूर्ण रूप में समान वस्तु अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादन करते हों अथवा ; अथवा

(ii) जिनका समान वस्तु का सामूहिक उत्पादन अथवा भारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का उत्पादन होता हो, वह भारत में उक्त वस्तुओं के कुल उत्पादक का अधिकांश हिस्सा होता है ;

47. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में, दिनांक 16.07.2018 का अंतिम मूल जांच परिणाम और दिनांक 3.3.2020 की जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस को पहले ही स्पष्ट किया गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयां घरेलू उद्योग के क्षेत्र से बाहर हैं। इस समीक्षा में घरेलू उद्योग का क्षेत्र डीटीए में इकाइयों तक भी सीमित है।

48. यह समीक्षा आवेदन (i) मै. मुद्रा सोलर पीवी लिमिटेड, अदानी हाउस (एस ई जैड); (ii) जुपीटर सोलर पावर लिमिटेड (डी टी ए), (iii) मै. जुपीटर इंटरनेशनल लिमिटेड (डी टी ए) की ओर से आई एस एम ए द्वारा दायर किया गया है। डी जी टी आर में इस मामले में घरेलू उद्योग को केवल दो डीटीए इकाइयों अर्थात् मै. जुपीटर सोलर पावर लिमिटेड और मै. जुपीटर इंटरनेशनल लिमिटेड को दिनांक 16.07.2018 की मूल जांच परिणामों के अनुसार सीमित किया है। जेआईएल और जेएसपीएल के उत्पादन के संबंध में महानिदेशक ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला :

- i. जेआईएल और जेएसपीएल डी टी ए इकाइयां हैं और वे एक ही समूह से संबंधित हैं। जेएसपीएल, जेआईएल की एक सहायक कंपनी है।
- ii. जेएसपीएल मूल जांच में आवेदक नहीं था। जेएसपीएल स्वयं के बल पर 2016-17 और 2017-18 के दौरान उत्पादन कर रहा था। जेएसपीएल को 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान जॉब कार्य आधार पर जेआईएल द्वारा उत्पादन किए गए सोलर सैल भी प्राप्त हुए। मार्च, 2019 से जेएसपीएल ने अपने बल पर उत्पादन नहीं किया था बल्कि जेआईएल के लिए जॉब कार्य आधार पर ही उत्पादन किया था। जेआईएल स्वयं के बल पर उत्पादन कर रहा है और इसे जेएसपीएल के माध्यम से जॉब कार्य आधार पर उत्पादन भी करवा रहा है।
- iii. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि जेएसपीएल ने केवल वृद्धिगत जॉब कार्य किया है। हालांकि यह देखा गया है कि जे एस पी एल ने उत्पादन संबंधी सभी क्रियाकलापों को निष्पादित किया है, क्योंकि इसमें जेआईएल द्वारा आपूर्ति किए गए वेफरों से सोलर सैल का उत्पादन किया है। यह भी पाया गया है कि जेआईएल ने स्वयं के बल पर सोलर सैल का उत्पादन किया है और उसके साथ ही जॉब कार्य के आधार पर जेएसपीएल द्वारा उसका उत्पादन भी करवाया है।

दो डी टी ए इकाइयां विचाराधीन उत्पाद का भारत में कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा (50 प्रतिशत से अधिक) होता है। गणना के उद्देश्य से, विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा उत्पादन के हिस्से को ऊपर में किए गए उल्लेख के अनुसार बाहर रखा गया है।

(घ) जांच की अवधि

49. जांच की शुरुआत के समय, वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पी ओ आई) को 1 अप्रैल, 2016-31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017- 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018- 31 मार्च, 2019 और 1 अप्रैल, 2019 – 30 सितंबर, 2019 के रूप में माना गया था। उक्त अवधि को बाजार परिस्थितियों और अन्य कारकों जो रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाए रखने की आवश्यकता का पता लगाने के लिए संगत है, पर विचार करने के लिए बहुत अधिक लंबी मानी गई थी।

(ङ) सूचना का स्रोत

50. जांच की शुरुआत के समय घरेलू उद्योग ने 2014-15 से 2019-20 (सितंबर, 2019 तक) की अवधि के लिए वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), वाणिज्य विभाग, से विचाराधीन उत्पाद के लिए लेनदेनवार आत संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए थे और जांच की शुरुआत के समय विश्लेषण के

लिए उस पर विचार किया गया था। घरेलू उद्योग ने बाद में फरवरी, 2020 तक के डी जी सी आई एंड एस के आयात संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। जांच की अवधि के बाद के आयात संबंधी आंकड़ों पर भी विचार 1 अक्टूबर, 2019 से 28 फरवरी, 2020 तक किया गया है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त आंकड़ों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणिक वित्तीय अभिलेखों का संदर्भ लेकर डेस्क अध्ययन के आधार पर किया गया है।

(च) गोपनीयता और प्रस्तुत की गई सूचना

51. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में गोपनीय आधार पर कुछ सूचना उपलब्ध कराई हैं और अनुरोध किया है कि इसे गोपनीय के रूप में माना जाए। घरेलू उद्योग ने फा. सं. डी-22011/75/2009 के अंतर्गत महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा जारी किए गए दिनांक 21.12.2009 के व्यापार नोटिस के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत यथाअपेक्षित अपने आवेदन का अगोपनीय पाठ (एन सी वी) भी उपलब्ध कराया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने इस सूचना की गोपनीयता के अपने दावे का औचित्य बताते हुए कारण प्रस्तुत किए हैं।
52. उक्त नियमावली के नियम 7 के संबंध में, आवेदक सूचना, जो गोपनीय प्रवृत्ति की है, को प्रकट नहीं करने का विकल्प ले सकते हैं और उसका अगोपनीय सार उपलब्ध करा सकते हैं। घरेलू उद्योग ने सूचना की गोपनीयता का दावा करने के लिए कारण प्रस्तुत किए हैं और गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय सार प्रस्तुत किया है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि डी जी टी आर द्वारा जारी किए गए दिनांक 7 सितंबर, 2018 के व्यापार नोटिस सं. 10/2018 के अनुबंध-1 में याचिका का गोपनीय और अगोपनीय पाठ में सूचना के प्रकटन के लिए इन दिशानिर्देशों को घरेलू उद्योग द्वारा याचिका दायर करते समय पालन नहीं किया गया है।
53. घरेलू उद्योग का इस प्रकार के दावे के लिए दिए गए कारणों के साथ गोपनीयता के संबंध में दावे पर विचार नियम 7 की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है। आवेदक ने स्थापित कार्य पद्धति के अनुसार आवेदन का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है जिसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करा दिया गया था।

छ. आयात की प्रकृति और मात्रा

54. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 5 में यह अपेक्षित है कि जांच की किसी शुरुआत के लिए, महानिदेशक को आयातों में विधि अवश्य मिलनी चाहिए। विशेष रूप से उपबंध 5(3) में यह अपेक्षित है कि महानिदेशक अब तक उप नियम (1) के अंतर्गत किए गए आवेदन के अनुसरण में किसी जांच की शुरुआत नहीं करेगा जब तक कि वह आवेदन में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के समुचित और प्रतीक होने की जांच नहीं कर लेता है और अपने आप को संतोष नहीं कर लेता है कि बड़े हुए आयातों के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य है। चूंकि आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है अतः रक्षोपाय शुल्क लगाने को कोई आधार नहीं है।
55. मैं यह देखता हूं कि बड़े हुए आयातों का मानदंड समीक्षा में लागू नहीं होगा क्योंकि समीक्षा का उद्देश्य नियम 18 के अनुसार इस बात का आकलन करने के लिए है कि क्या रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाया जाना गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने के लिए आवश्यक है और इस तथ्य का साक्ष्य है कि घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है।
56. आयातों की मात्रा की जांच पहले से लागू रक्षोपाय शुल्क के प्रभार को ध्यान में रखकर किया जाना आवश्यक है और यह कि यदि रक्षोपाय शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो क्या आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी रहेगा। इस संबंध में यह भी नोट किया जाना है कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद भी संबद्ध वस्तुओं की आयात संबंधी मात्रा शुल्क के स्तर तक वापस नहीं गई है लेकिन भारत में अब भी बड़े हुए स्तरों पर हो रही है। 2017-18 में वास्तविक आयात 9790 मे.वा. थी जो 2018-19 में 8010 मे.वा. और 2019-20 में 8545 मे.वा. रही थी। (वास्तविक आंकड़ों को फरवरी, 2010 तक माना गया है)।
57. आयात 2016-17 में 6375 मे.वा. था और यह 2017-18 में बढ़कर 9790 मे.वा. हो गया। इन शुल्कों को 30 जुलाई, 2018 से लागू किया गया था। शुल्कों के लगाए जाने के परिणामस्वरूप, आयात की मात्रा 2018-19 के दौरान घटकर 8010 मे.वा. हो गया है। लेकिन आयातों में यह गिरावट क्षणिक थी क्योंकि सबसे हाल की अवधि

अर्थात् 2019-20 के लिए आयात संबंधी मात्रा (वार्षिकीकृत- वार्षिक आंकड़ा सितं., 2019 तक) 8754 मे.वा. था।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (वार्षिकीकृत)	अप्रैल 19 – सितं. 19
सैल्स	मे.वा.	785	1,280	2,024	2,588	1,294
मॉड्यूलस	मे.वा.	5,590	8,510	5,986	6,167	3,083
कुल आयात	मे.वा.	6,375	9,790	8,010	8,754	4,377
प्रवृत्ति	मे.वा.	100	154	126	137	

58. यह नोट किया जाता है कि यदि क्षति की अवधि की अवधि के आधार वर्ष पर भी विचार किया जाता है तब आयात गिरकर 2379 मे.वा. हो गया है। अर्थात् 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 4377 मे.वा. का आयात वित्तीय वर्ष 2019 की प्रथम छमाही के दौरान किया गया और वह वित्तीय वर्ष 2017-18 की समान अवधि के दौरान आयात किए गए 4917 मे.वा. से कम था। जबकि, वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली छमाही के दौरान कोई रक्षोपाय शुल्क नहीं था, अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान आयात 1 अप्रैल से 29 जुलाई, 2019 तक 25 प्रतिशत के रक्षोपाय शुल्क के अधीन थी। इस कारण से आयात की मात्रा में 2018-19 में 1780 मे.वा. तक कमी आई। हालांकि 30 जुलाई, 2019 से 20 प्रतिशत तक रक्षोपाय शुल्क के उदारीकरण के साथ आयातों में फिर से ऊपर की ओर की प्रवृत्ति को दर्शाया है और 2019-20 (वार्षिकीकृत) में 744 मे.वा. वार्षिकीकृत तक वृद्धि हुई है अर्थात् इसमें 9 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

59. यह भी नोट करना संगत है कि भारत में थाइलैंड और वियतनाम से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि देखी गई है जो अब सबसे हाल की अवधि अर्थात् 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) में भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों में क्रमशः लगभग 12.46 प्रतिशत और 11.7 प्रतिशत होता है जबकि ये कुल आयातों के अधिक होने के बावजूद 2017-18 में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के पूर्व केवल 0.26 प्रतिशत और 0.70 प्रतिशत था। इसके अलावा थाइलैंड और वियतनाम से आयातों की कीमतों में भी बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है और वे चीन जन गण से आयातों की कीमतों की तुलना में बहुत कम है जो नीचे दर्शाए गए अनुसार रु./वाट में आयात कीमत की तुलना में वर्तमान में 15 प्रतिशत की दर से रक्षोपाय शुल्क के अधीन भी है।

		2017-18	2018-19	2019-20 (अप्रैल – सितंबर)	2019-20 (वार्षिकीकृत)
चीन जन गण	रु./वाट	21.76	17.49	15.58	15.58
थाइलैंड	रु./वाट	18.53	9.33	10.58	10.58
वियतनाम सामाज्यिक गण.	रु./वाट	10.59	12.87	11.13	11.13

60. वास्तव में थाइलैंड और वियतनाम से आयात की कीमतों के कारण रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद भी घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होती रही है।

(छ) अप्रत्याशित घटनाक्रम और दायित्वों का प्रभाव

61. घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए समीक्षा का विरोध करने वाले कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि समीक्षा के मामले में भी, यदि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले बड़े हुए आयातों का साक्ष्य हो, तब रक्षोपाय शुल्क जारी रखा जा सकता और आयातों में इस प्रकार की वृद्धि प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट) के अनुच्छेद XIX: 1 (क) में दिए गए अनुसार अप्रत्याशित घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप हुआ होगा। इस संबंध में, इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि अप्रत्याशित घटनाक्रमों अथवा दायित्वों के

प्रभाव के संबंध में कोई सूचना घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन करते समय दायर नहीं की गई है। इस संबंध में मैं यह देखता हूँ कि अप्रत्याशित घटनाक्रम और दायित्वों का प्रभाव केवल मूल शुल्क के समय रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए आवश्यक पूर्व शर्त है क्योंकि यह देखा गया है कि आयातों में वृद्धि आवश्यक मानदंड नहीं है क्योंकि इस नियमावली में दो मुद्दे अर्थात् क्या रक्षोपाय शुल्क गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने के लिए आवश्यक है और इस तथ्य का साक्ष्य है कि घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है कि जांच की जानी अपेक्षित है। इस कारण से न तो आयातों में वृद्धि रक्षोपाय शुल्क के लिए रखे जाने हेतु एक आवश्यक पूर्ण शर्त है और न ही आयातों में इस प्रकार की वृद्धि अप्रत्याशित घटनाक्रमों द्वारा अथवा दायित्वों के प्रभाव के कारण हुआ है जो केवल मूल शुल्क को लगाए जाने का औचित्य ठहराने के लिए आवश्यकता है।

62. यह दोहराया गया है कि मूल अंतिम जांच परिणामों में किए गए निर्धारण में यह देखा गया था कि जांच में संगत क्षति की अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि अप्रत्याशित घटनाक्रमों और भारत द्वारा गैट के अंतर्गत पूरे किए गए दायित्वों के प्रभावों का एक परिणाम था। मैं यह नहीं मानता हूँ कि यह अपेक्षित है कि वर्तमान समीक्षा में इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जाए।

ज. गंभीर क्षति और / अथवा गंभीर क्षति का खतरा

63. निर्धारण के लिए अगला मामला यह है कि क्या रक्षोपाय शुल्क का विस्तार आवश्यक है और क्या विचाराधीन उत्पाद से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को समान और प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों से गंभीर क्षति होना अथवा गंभीर क्षति को रोकने या उसका उपचार करने के लिए जारी रहा है जिसके फलस्वरूप शुल्कों को जारी नहीं रखने का परिणाम हो सकता है। विचाराधीन उत्पाद का घरेलू उत्पाद के क्षति की जांच में विभिन्न मानदंडों जैसे घरेलू उद्योग की बिक्री, उत्पादन, क्षमता का उपयोग, आयातों की तुलना में बाजार हिस्सा जिसका नीचे अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया है, की जांच शामिल है।

- (i) **घरेलू बाजार का हिस्सा:** यह देखा जा सकता है कि जबकि मांग 2016-17 से 2019-20 (वार्षिकीकृत) तक 34 प्रतिशत तक बढ़ी, आयातों का अपना प्रमुख बाजार हिस्सा बना रहा। घरेलू उद्योग ने यह देखते हुए कि यह सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है, आंशिक रूप से 1.1 प्रतिशत तक उसकी अवधि में बाजार हिस्से को भी प्राप्त किया।

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (वार्षिकीकृत)	अप्रैल 19 - सितं. 19
आयात	% (सूचीबद्ध)	100	101	105	102	102
घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बिक्री	% (सूचीबद्ध)	100	88	60	124	124
अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा घरेलू बिक्री	% (सूचीबद्ध)	100	84	36	49	49
मांग/खपत	मे.वा. (सूचीबद्ध)	100	152	120	134	67

- (ii) **उत्पादन और बिक्री :** घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री तथा विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों को दर्शाने वाली निम्न तालिका से यह नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में रक्षोपाय शुल्कों के संरक्षण के परिणामस्वरूप और इसके समायोजन योजना के कार्यान्वयन के कारण वृद्धि हुई है, हालांकि घरेलू उत्पादकों की समग्र स्थिति अस्थिर बनी हुई है क्योंकि विशेष आर्थिक क्षेत्र को छोड़कर अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री में गिरावट आई है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (A)	अप्रैल 19 – सितं. 19
कुल आयात	मे.वा.	6,375	9,790	8,010	8,754	4,377
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मे.वा. (सूचीबद्ध)	100	129	64	170	85
घरेलू उद्योग की बिक्री	मे.वा. (सूचीबद्ध)	100	134	72	166	83
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मे.वा. (सूचीबद्ध)	100	128	43	66	33

- (iii) **क्षमता का उपयोग** : घरेलू उद्योग के क्षमता के उपयोग में 2016-17 में 44 प्रतिशत से 2019-20 (वार्षिकीकृत) में 75 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। हालांकि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि रक्षोपाय शुल्क का संरक्षण पिछले दो वर्षों में लागू रहा है और भारत में विचाराधीन उत्पाद की बहुत अधिक मांग रही है, घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता का आयातों से प्रतिस्पर्धा के कारण कम उपयोग होना जारी है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (A)	अप्रैल 19 – सितं. 19
संस्थापित क्षमता	मे .वा. (सूचीबद्ध)	100	100	100	100	50
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मे .वा. (सूचीबद्ध)	100	129	64	170	85
क्षमता उपयोग	%	44%	57%	28%	75%	75%

- (iv) **रोजगार और उत्पादकता** : घरेलू उद्योग द्वारा त्वरित सृजित रोजगार में क्षति के विश्लेषण की अवधि के दौरान गिरावट आई है

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (A)	अप्रैल 19 – सितं. 19
कर्मचारियों की सं.	सं. (सूचीबद्ध)	100	96	69	69	69
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मे .वा. (सूचीबद्ध)	100	135	94	249	125

- (v). हालांकि प्रति कर्मचारी उत्पादकता में काफी हद तक सुधार आयात है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी समायोजन योजना के अनुसार अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाया है।

- (vi) **लाभ/हानि** : यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2018-19 में नकारात्मक हो गई। हालांकि बड़े हुए उत्पादन और बिक्री के साथ-साथ बिक्री की लागत में कमी के कारण घरेलू उद्योग 2018-19 में अपने घाटे को कम करने में सक्षम हो पाया है। हालांकि यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता

नकारात्मक रह जाती है और इसकी स्थिति अस्थिर है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (A)	अप्रैल 19 – सितं. 19
लाभ/हानि	रू./वाट (सूचीबद्ध)	100	22	(204)	(18)	(18)
घरेलू बिक्री कीमत	रू./वाट (सूचीबद्ध)	100	78	40	37	37
बिक्री की लागत	रू./वाट (सूचीबद्ध)	100	90	95	49	49

(vii) मालसूची : यद्यपि मालसूची के स्तरों में 2018-19 में सुधार हुआ फिर भी वह नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए अनुसार सबसे अधिक हाल की अवधि अर्थात् 2019-20 (वार्षिकीकृत) में तेजी से वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (A)	अप्रैल 19 – सितं. 19
मालसूची	मे.वा. (सूचीबद्ध)	100	120	11	272	141

(viii.) कीमत में कटौती : यह देखा जा सकता है कि रक्षोपाय शुल्क को शामिल किए बिना, आयातों की कामतों के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में कटौती होना जारी है और इसे गंभीर क्षति हो रहा है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	अप्रैल 19 – सितं. 19
आयातों का पहुंच मूल्य					
सोलर सैल	रू./वाट	15.42	13.68	8.95	8.76
सोलर मॉड्यूल	रू./वाट	29.20	22.56	19.10	16.80
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति					
सोलर सैल	रू./वाट (सूचीबद्ध)	100	78	39	37
सोलर मॉड्यूल	रू./वाट (सूचीबद्ध)		100	61	57
कीमत कटौती					
सोलर सैल	रू./वाट (सूचीबद्ध)	100	59	6	4
सोलर मॉड्यूल	रू./वाट (सूचीबद्ध)		100	4	15
कीमत कटौती (%)					
सोलर सैल	% रेंज	55-65	35-45	5-15	0-10
सोलर मॉड्यूल	% रेंज		35-45	0-10	5-15

कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने कीमत में कटौती का विश्लेषण के संबंध में यह उल्लेख करते हुए आपत्ति उठायी है कि कीमत में कटौती का विश्लेषण विचाराधीन उत्पाद की पहुंच मूल्य में रक्षोपाय शुल्क को जोड़े जाने के बाद किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि चूंकि यह क्षति के फिर से होने को रोकने के लिए रक्षोपाय शुल्क का विस्तार किए जाने की जांच करने के लिए एक समीक्षा है अतः पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

झ. पीओआई पद की प्रवृत्ति

64. 2019-20 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान, आयातों में 2018-19 की पहली तीन तिमाहियों की तुलना में 33% वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, आयात की मात्रा में वृद्धि को भी आयात की कीमतों में कमी के साथ जोड़ दिया गया था। पीओआई

पद की अवधि सहित जांच की अवधि के दौरान आयात का मूल्य और प्रति इकाई मूल्य निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	अप्रैल-सितं. 2019	अप्रैल, 19 से फर.-20	2019-20 (वार्षिकीकृत)
सैल्स	लाख रुपए में	121,126	175,202	181,155	113,301	207,785	226,675
सैल्स	रु./वाट	15.42	13.68	8.95	8.76	7.91	7.91
मॉड्यूल्स	लाख रुपए में	1,632,107	1,920,223	1,143,368	517,875	849,750	927,000
मॉड्यूल्स	रु./वाट	29.2	22.56	19.1	16.8	16.32	16.32
कुल	लाख रुपए में	1,753,233	2,095,425	1,324,523	631,176	1,057,535	1,153,675
कुल	रु./वाट	31.29	34.10	27.50	21.40	16.54	14.42

65. वर्ष 20-16-17 के दौरान प्रति वाट भारित औसत आयात मूल्य 27.5 रु. से घटकर वर्ष 2019-20 के दौरान 13.5 रु. हो गयी है। पिछले कुछ महीनों के दौरान आयात की कीमतों की मासिक प्रवृत्ति में गिरावट प्रदर्शित हुई है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

	सैल्स	मॉड्यूल्स		सैल्स	मॉड्यूल्स
वि.व. 2018-19	8.95	19.10	वि.व. 2019-20	7.91	16.32
2018-04	12.08	22.40	2019-04	8.61	17.36
2018-05	11.96	23.26	2019-05	8.92	16.00
2018-06	9.73	22.61	2019-06	9.04	16.29
2018-07	8.50	21.83	2019-07	9.03	15.97
2018-08	8.26	20.93	2019-08	8.70	17.76
2018-09	8.06	20.02	2019-09	8.25	16.82
2018-10	8.07	19.75	2019-10	8.30	15.85
2018-11	7.91	18.02	2019-11	7.61	16.02
2018-12	7.77	17.24	2019-12	6.91	15.18

2019-01	8.24	17.09	2020-01	6.84	14.86
2019-02	8.87	17.62	2020-02	6.11	14.86
2019-03	8.92	16.94			

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, अप्रैल 2018 में सौर सेल आयात मूल्य 11.96 रुपये प्रति वाट से घटकर फरवरी 2020 में प्रति वाट हो गया है। इसी अवधि के दौरान, माँड्यूल की आयात कीमतें प्रति वाट 23.26 रु. से 14.86 रुपये प्रति वाट से नीचे आ गई थीं।

(ग) मार्जिन तथा क्षति का खतरा

66. जांच की मौजूदगी का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, एक उचित बिक्री कीमत (एफएसपी) की गणना उत्पादन की लागत पर उपयुक्त तर्कसंगत लाभ पर विचार करने के बाद की गई है। उसके बाद क्षति के मार्जिन की गणना सोलर सैल और एफएसपी से आयातों के पहुंच मूल्य के अंतर के रूप में की गई है। जांच की अवधि की सबसे हाल की अवधि अर्थात् 1.4.19 से 30.9.19 के दौरान आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि आयातों की पहुंच कीमतों से घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की न केवल कटौती होना जारी है बल्कि वह उचित कीमत प्राप्त करने में घरेलू उद्योग को रोक भी रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की मालसूची में भी सबसे हाल की अवधि तीव्र वृद्धि देखी गई है। इस कारण से, यदि रक्षोपाय शुल्क को अब हटा लिया जाता है तब विचाराधीन उत्पाद के प्रयोग का बढ़ते हुए क्रम में विचाराधीन उत्पाद के आयातों को संबद्ध जांच की शुरुआत के समय प्राप्त स्तरों तक अपना लेंगे। इसके परिणामस्वरूप गंभीर क्षति जो घरेलू उद्योग को हो रही थी वह फिर से होगी क्योंकि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता का नकारात्मक होना जारी है और घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रगति प्रभावहीन हो जाएगी।

(ट) कारणात्मक संबंध

67. नियम 11(1) के अनुसार, यह निर्धारण करना अपेक्षित है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों और समान प्रतिस्पर्धी उत्पाद के घरेलू उद्योग को क्षति अथवा क्षति के खतरे के बीच कोई कारणात्मक संबंध है। इस संबंध में, कोरिया-डेयरी में डब्ल्यू टी ओ के पैनेल द्वारा टिप्पणी जो "कारण" का निर्धारण करने के लिए मूलभूत दृष्टिकोण दर्शाता है, को नोट कर लिया गया है। इस कारण से कारणात्मक संबंध का आकलन करने में मुझे वस्तुपरक और परिमाण योग्य प्रकृति के सभी संगत कारकों जिनका उद्योग की इस स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, मूल्यांकन करना पड़ता है। इसके अलावा, बड़े हुए आयातों को छोड़कर यदि अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो तब ऐसे कारकों द्वारा हुई किसी क्षति के लिए आयातों को जिम्मेदारी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
68. 2016-17 से सितंबर, 2019 की अवधि के लिए आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात अधिक स्तरों पर रहा है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद के आयात की कीमतों में भी बहुत अधिक गिरावट आई है। आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से बहुत कम बनी हुई है। रक्षोपाय शुल्क के बिना, आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होगी। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता वर्तमान में नकारात्मक है और उस पर उस स्थिति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जब विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क को हटा लिया जाएगा।
69. निम्नलिखित कारकों को नोट कर लिया गया है और उन पर यह सिद्ध करने में संगत के रूप में विचार किया गया है कि रक्षोपाय शुल्क को जारी नहीं रखने और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के जारी रहने और उसके फिर से होने के बीच कारणात्मक संबंध है।

क. भारत में विचाराधीन की घरेलू बाजार में आयातों की मात्रा बहुत अधिक रही है। 30 जुलाई 2018 से 25 प्रतिशत की दर से रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के साथ, 2018-19 में समग्र आयातों में कमी आई। हालांकि 30 जुलाई, 2019 तक 20 प्रतिशत तक रक्षोपाय शुल्क में कमी के साथ, आयातों में वृद्धि फिर से देखी गई है।

ख. आयातों का बाजार हिस्सा अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखा और आगे क्षति के विश्लेषण की अवधि के दौरान इस में थोड़ी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भी रक्षोपाय शुल्क के द्वारा दिए गए

संरक्षण के फलस्वरूप आंशिक रूप से वृद्धि हुई है। हालांकि अन्य घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा जो घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं था, कमी आई। यद्यपि, घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में रक्षोपाय शुल्कों को लगाए जाने के साथ सुधार आया है, क्षमता का उपयोग अभी भी भारत में विचाराधीन उत्पाद की भारी मांग पर विचार करते हुए आदर्श से कम है। इसके अलावा, 30 जुलाई, 2019 से शुल्कों में कमी के साथ, विचाराधीन उत्पाद के आयातों में फिर से वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप मालसूची के स्तरों में बहुत अधिक वृद्धि हुई।

- ग. मूल जांच में अंतिम जांच परिणामों में यह नोट किया गया था कि आयात की कीमतों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही थीं और उसमें हास हो रहा था। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमतों के साथ आयातों का पहुंच मूल्य की तुलना यह दर्शाती है कि आयातों की कीमतों के कारण अभी भी घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। इस कारण से यदि रक्षोपाय शुल्क को जारी नहीं रखा जाता है तब प्रयोक्ता आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद को फिर से अपनाएंगे जिसके फलस्वरूप कीमत हास पुनः होगा और घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त बाजार हिस्से को नुकसान होगा।
- घ. वर्तमान रक्षोपाय शुल्क लागू रहने के कारण बड़ी हुई कार्यक्षमता के कारण बिक्री की लागत में कमी आई है और उसके द्वारा घरेलू उद्योग को लाभप्रद होने की बड़ी हुई संभावना के बाद घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। यदि रक्षोपाय शुल्क का विस्तार नहीं किया जाता है तब परिणामी कीमत कटौती में कमी आएगी और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए सकारात्मक समायोजन निष्प्रभावी हो जाएंगे और यह वापस गंभीर क्षति की स्थिति तक पहुंच जाएगा।
- ड. यद्यपि पिछले वर्ष से इसमें सुधार आया है फिर भी घरेलू उद्योग की लाभप्रदता नकारात्मक ही है।
- च. हितबद्ध पक्षकारों ने किसी अन्य कारकों का उल्लेख नहीं किया है जिनके कारण भी घरेलू उद्योग को साथ-साथ क्षति हो रही हो।

70. अतः उपर्युक्त मानदंडों का व्यापक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को हो रही गंभीर क्षति संभवतः भविष्य में भी जारी रहेगी। यदि रक्षोपाय शुल्क का विस्तार नहीं किया जाता है और इस कारण से उसे जारी रखना आवश्यक है ताकि घरेलू उद्योग को आगे गंभीर क्षति का उपचार किया जा सके और उसे रोका जा सके।

(ठ) समायोजन योजना

- 71. मूल जांच के दौरान, घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित कदम उठाकर आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के विरुद्ध प्रतिस्पर्धी बनने के लिए एक समायोजन योजना प्रस्तुत की।
 - छ. यदि बेहतर नकदी प्रवाह को प्राप्त कर लिया जाता है, तब कच्चे माल की दीर्घावधि खरीद, दर और मात्रा।
 - ज. क्षमता का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग जिसके फलस्वरूप बेहतर परिवर्तन लागत प्राप्त हो।
 - झ. अर्ध निर्धारित और निर्धारित लागतों का बेहतर विभाजन।
 - ञ. उधार लेने की लागत को कम करने के लिए बेहतर क्रेडिट रेटिंग और ऋण की बेहतर सर्विसिंग।
 - ट. बैकवर्ड एकीकरण के प्रति प्रयास और समग्र पारि-प्रणाली का विकास करना।
 - ठ. प्रौद्योगिकी का विकास और आर एंड डी
- 72. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह आपत्ति उठाई है कि घरेलू उद्योग ने समायोजन योजना कार्यान्वित करने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है और यह कि उन्होंने मूल जांच के दौरान यह साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है जिसके कारण उन्होंने रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने की मांग की है।
- 73. इस संबंध में जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, घरेलू उद्योग की समायोजन योजना के प्रति उल्लेख किए गए कदमों का केन्द्र लागत में कमी को प्राप्त कर प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करना था। घरेलू उद्योग द्वारा लागत की समायोजन कटौती के प्रति उठाए गए कदमों के बारे में उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन संबंधित घरेलू उत्पादकों के रिकॉर्डों से किया गया है और यह देखा गया है कि घरेलू उत्पादकों ने अपनी कार्यक्षमताओं में सुधार

लाने के लिए अपने आरंभिक आवेदन में उनके द्वारा उल्लिखित कदमों को नहीं उठाया है यद्यपि, उन्हें अभी भी समायोजन योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे प्रगति करने की आवश्यकता है। उनके द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप यह नोट किया गया है कि समायोजन योजना के संबंध में डेढ़ वर्षों के भीतर, घरेलू उत्पादकों ने निर्धारित लागतों में 12.25 सेंट/वॉट के लक्ष्य की तुलना में सितंबर, 2019 तक 2.48 सेंट/वॉट की लागत में कटौती प्राप्त हुई है। प्राधिकरण आगे कहता है कि कच्चे माल की कीमतों को कम करने के लिए डीआई ने रसद को हवा से समुद्र में बदल दिया और बड़े आकार के वेफर्स का उपयोग करना भी शुरू कर दिया।

74. लागत में उपर्युक्त कटौती को कच्चे माल की लागत में कटौती, क्षमता के बेहतर उपयोग के कारण परिवर्तन लागतों में कटौती के फलस्वरूप किफायती उत्पादन को प्राप्त कर और कर्मचारियों की संख्या में कटौती के कारण निर्धारित लागत में कटौती और बड़े हुए उत्पादन के द्वारा आसान बनाया गया है।
75. इस कारण से यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने मूल समायोजन योजना के संबंध में जिसके द्वारा उल्लिखित प्रयास किए हैं और यह अपने आप को आयात प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिए सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है। हालांकि आयात की कीमतें तेजी से गिरना जारी है और घरेलू उद्योग की कीमतों में रक्षोपाय शुल्क को शामिल किए बिना कटौती हो रही है। इस कारण से घरेलू उद्योग से यह अपेक्षित है कि उसे विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण हुई अपने अस्थिर वित्तीय स्थिति पर विजय पाने के लिए अपने आप को एक साथ तैयार करने हेतु और अधिक समय दिया जाए।
76. घरेलू उत्पादकों ने उन कदमों का ब्यौरा देते हुए एक संशोधित समायोजन योजना प्रस्तुत की है जो इसमें आयात संबंधी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के उद्देश्य से आगे अपनी लागतों को कम करने के लिए उठाने की योजना बनाई है। संशोधित समायोजन योजना में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित कदम शामिल हैं।
 - कच्चे माल की कीमतों में आगे कटौती : बेहतर नकदी के प्रवाह के साथ, घरेलू उद्योग दीर्घावधि संविदा करने, दर में छूट और मात्रा में छूट के द्वारा आपूर्तिकर्ताओं के साथ कीमतों के बारे में आगे फिर से मोलभाव करने की स्थिति में हागा। कंपनी का उद्देश्य प्रमुख कच्चे माल अर्थात् वेफर्स का उत्पादन करने की सुविधा स्थापित करने की भी है।
 - परिवर्तन लागतों में आगे कटौती : घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि लागत में लक्ष्य कटौती अभी प्राप्त की जानी है और उत्पादन की मात्रा में आगे वृद्धि से घरेलू उद्योग को अगले पांच वर्षों में उसे प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और इसमें इस संबंध में एक संशोधित लक्ष्य प्रस्तुत किया है।
 - उत्पादन बढ़ाकर, निर्माण की प्रक्रिया को स्वचालित कर और प्रचालन संबंधी कार्यक्षमताओं को प्राप्त कर निर्धारित लागत में आगे कटौती।
 - संयंत्र और मशीनरी के पूर्ण उपयोग के द्वारा, ह्रास लागत में अगले कुछ वर्षों में कटौती होगी।
 - एस जी ए, वित्त और अन्य लागतों में कटौती।
77. घरेलू उद्योग ने अनुमान लगाया है कि इसकी समायोजन योजना अगले तीन वर्षों में पूरी कर ली जाएगी। संशोधित समायोजन योजनाओं को घरेलू उत्पादकों द्वारा उनके अलग-अलग प्रश्नावली के उत्तरों के साथ प्रस्तुत किया गया था। इस कारण से यह देखा गया है कि यदि शुल्कों को जारी नहीं रखा जाता है, तब आयातों के कारण भारत में अस्थिर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचेगी और वह समाप्त हो जाएगा। पूर्व के समायोजन योजना के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग अनुमानित लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाया है क्योंकि वे अपने प्रयासों के कारण मुख्य रूप से केवल निर्धारित लागतों पर लागत में कटौती को प्राप्त करने में सक्षम हुआ है। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग ने सकारात्मक समायोजन को दर्शाया है।

ड जनहित

78. कुछ पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाए रखने से कोई जनहित का कार्य पूरा नहीं होगा। इसके विपरीत रक्षोपाय शुल्क को लगाए जाने से जनहित को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचेगा क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के अनेक अंतिम प्रयोक्ता जैसे सोलर पावर डेवलपर अपने संयंत्रों को बंद कर सकते हैं। इस संबंध में, यह देखा गया है कि "जनहित" अभिव्यक्ति के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता

का हित शामिल नहीं है। इसका एक बहुत व्यापक अर्थ है, जिसमें व्यापक सामुदायिक हित को ध्यान में रखकर सामान्य सामाजिक कल्याण शामिल है। जबकि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप क्रेताओं के हाथ में आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद और अंतिम उपभोक्ता के हाथों में बिजली की मामूली रूप से बढ़ी हुई लागत हो सकती है अतः यह महत्वपूर्ण होगा कि रक्षोपाय शुल्क को लगाए जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए। रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य घरेलू उद्योग को बड़े हुए आयातों के द्वारा उत्पन्न प्रतिस्पर्धा की नई स्थिति का मुकाबला करने के लिए सकारात्मक समायोजन करने हेतु समय देना है। उस अवधि तक और उस सीमा तक जिस सीमा तक उसे समुचित माना गया है, रक्षोपाय शुल्क को लगाने से न केवल प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, उपभोक्ताओं के लिए कम होगा, बल्कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किए गए अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प और वह भी प्रतिस्पर्धी दरों पर दिया जा सगा। घरेलू उत्पादकों, जिन्होंने भारी निवेश के साथ संयंत्रों की स्थापना की है, काफी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बहुमूल्य योगदान देते हैं। रक्षोपाय शुल्क लगाने से घरेलू उत्पादक बड़े हुए आयातों के द्वारा उत्पन्न प्रतिस्पर्धा को देखते हुए फिर से पूर्व स्थिति में आने में सक्षम होंगे और इस कारण से वे विचाराधीन उत्पाद के क्रेताओं तथा अंतिम उपभोक्ताओं के दीर्घ अवधि हित में भी होगा।

79. माँड्यूल निर्माताओं की प्राथमिक चिंता संस्थापित सोलर सैल निर्माण क्षमता की तुलना में सोलर माँड्यूल का निर्माण करने के लिए उनकी संस्थापित क्षमता के बीच मांग और आपूर्ति में अंतर रही है जो आयात को आवश्यक बना देता है। हालांकि यह देखा गया है कि यह केवल अस्थायी स्थिति है, जहां इस अंतर को उच्चतर कीमत पर आयात किए गए सोलर सैलों के द्वारा तब तक पूरा किया जाएगा, जब तक घरेलू उत्पादक मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं कर लेते हैं। दूसरी ओर, वर्तमान वास्तविक स्थिति पर विचार करते हुए जहां घरेलू सैल निर्माताओं को अपने अस्तित्व के खतरे का सामना करना पड़ रहा है और न कि रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने के फलस्वरूप घरेलू सैल निर्माण आधार का पूर्ण रूप से क्षय हो जाएगा और सोलर माँड्यूल निर्माता माँड्यूल का निर्माण करने के लिए आयात किए गए सोलर सैल पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाएंगे। भारत में घरेलू सैल के निर्माण के प्रचालनों को पूर्ण रूप से बंद करने पर, माँड्यूल निर्माता निर्यातकों की दया पर रहेंगे जो बाद में कीमतों को तय करने की स्थिति में होंगे और केवल सोलर सैल निर्माण करने वाले माँड्यूल निर्माताओं की कीमतों को अप्रतिस्पर्धी बनाने के लिए वृद्धि कर सकते हैं। इसका सोलर माँड्यूल जैसे ईवीए शीट और सोलर ग्लास के लिए उपकरण के निर्माण में शामिल अन्य अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम उद्योगों पर नीचे क्रम तक प्रभाव पड़ेगा और भारत की सोलर उपकरण निर्माण क्षमताओं को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। वहीं दूसरी ओर रक्षोपाय शुल्क लगाने से घरेलू सैल निर्माताओं का बना रहना सुनिश्चित होगा, जो बाद में सैल की आपूर्ति करने के लिए माँड्यूल निर्माताओं को आपूर्तिकर्ताओं का एक व्यापक विकल्प उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, यद्यपि, सोलर सैल की खरीद की कीमतों में अस्थायी रूप से वृद्धि हो सकती है, फिर भी घरेलू स्तर पर उत्पादित सोलर सैल की लागत तब कम हो जाएगी जब सैल निर्माता प्रतिस्पर्धा के अनुरूप अपने आप को समायोजित करेंगे। बदले में इससे सोलर माँड्यूल की उत्पादन लागत में कमी आएगी और यह माँड्यूल निर्माताओं को उससे आयात किए गए माँड्यूल के साथ बेहतर तरीके से प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी जिससे वे स्वीकार्य तौर पर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग बैकवर्ड एकीकरण का प्रयास करते रहे हैं और कुछ प्रमुख आपूर्ति जैसे सोलर ग्लास, ईवीए शीट, बैड शीट आदि ने पहले ही भारत में उत्पादन की क्षमता में सुधार लाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में निवेश किया है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने सरकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद पर मूल सीमाशुल्क 20 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की घोषणा की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह घोषणा दर्शाती है कि विचाराधीन उत्पाद पर प्रशुल्क लगाना भी जनहित का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

80. इस कारण से, घरेलू उद्योग को संरक्षण देने के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाना व्यापक जनहित में है क्योंकि इसके फलस्वरूप रोजगार, पूंजी खर्च का विस्तार, आर एंड डी तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में वृद्धि होगी। कच्चे माल और उपभोग किए जाने वाले सामानों जैसे बेफर, पेस्ट, ईवीए, जंकशन बॉक्स, सोलर ग्लास के आपूर्तिकर्ताओं को भी नई इकाइयों को स्थापित किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरी ओर यदि रक्षोपाय शुल्क को संरक्षणात्मक रूप से लगाया जाना जारी नहीं रखा जाता है तब इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग समाप्त हो जाएगा, जो इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए और अधिक भयावह स्थिति होगी।

81. यह भी अनुरोध किया गया है कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से मांग और घरेलू आपूर्ति के अंतर, जिसके के कारण आयात करना जरूरी होता है, की वजह से भारत का 2022 तक 100 गीगावाट सोलर विद्युत उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि रक्षोपाय शुल्क के प्रशुलक उपायों की प्रकृति के हैं और न कि परिमाणात्मक प्रतिबंधों की प्रकृति के हैं। इस कारण से घरेलू मांग में कमी आयातों के द्वारा यद्यपि, रक्षोपाय शुल्क का भुगतान करने के बाद पूरा किया जा सकता है। रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सक्षम बनाना है। इस कारण से, घरेलू उद्योग को दिये गये संरक्षण से इसे अपनी कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के स्तर तक लाने में सहायता मिलेगी जो सोलर पावर डेवलपर और अंतिम उपभोक्ताओं के दीर्घावधि हित में होगा क्योंकि वे आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद पर एकमात्र निर्भर नहीं रहेंगे। इस कारण से यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाए रखना जनहित में है। घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत उचित ब्याज के साथ जब आयात के उतरा मूल्य के साथ तुलना में संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग के लिए मूल्य की चोट जारी है। इस क्षति को रोकने के लिए, मौजूदा रक्षोपाय शुल्कों को रक्षोपाय शुल्क के चालू प्रगामी उदारीकरण के साथ जारी रखते हुए कुछ और समय के लिए विस्तार किए जाने की आवश्यकता है।

ढ. विकासशील राष्ट्र

82. सीमाप्रशुलक अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख (1) के परंतुक में यह प्रावधान है कि रक्षोपाय शुल्क विकासशील देश से आने वाली वस्तु पर नहीं लगाया जाएगा क्योंकि आयातों में इसका हिस्सा उस वस्तु के कुल आयातों का 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है अथवा जहां वस्तु एक से अधिक विकासशील देश से उत्पादन किया गया हो, तब इस प्रकार के सभी विकासशील देशों से आयातों का सकल योग जिसमें प्रत्येक का 3 प्रतिशत से कम आयात का सामूहिक हिस्सा है, उस वस्तु के कुल आयातों का 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। इसके अलावा, दिनांक 5 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 19/2016-सीमाशुल्क (एन टी) में इस प्रावधान के उद्देश्य से विकासशील देशों का उल्लेख है। वर्तमान मामले में उपलब्ध आंकड़ों की उक्त अधिसूचना के साथ पठित इस कानून प्रावधान को लागू करने के बाद जांच परिणाम यह है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात चीन जन.गण., थाइलैंड और वियतनाम सहित एक से अधिक उल्लिखित विकासशील देश से हो रहा है। हालांकि भारत ने विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों के प्रतिशत के रूप में, चीन जन.गण., थाइलैंड और वियतनाम से अलग-अलग रूप में आयात 3 प्रतिशत से अधिक होता है, जबकि प्रत्येक अन्य विकासशील देश का हिस्सा अलग-अलग रूप में 3 प्रतिशत से कम है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने थाइलैंड से आयातों का अनुमान गलत तरीके से लगाया है क्योंकि क्षति की अवधि के दौरान यह 3 प्रतिशत से अधिक है जबकि वास्तव में यह बहुत कम है। इस संबंध में, यह भी तर्क दिया गया है कि किसी समीक्षा में, विकासशील राष्ट्र जिन्हें रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से बाहर किया गया था, को समीक्षा के अनुसरण में इसके क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है।
83. हितबद्ध पक्षकारों के कहने पर थाइलैंड से विचाराधीन उत्पाद के आयात संबंधी आंकड़ों का फिर से सत्यापन किया गया था और यह पाया गया है कि थाइलैंड से आयातों की मात्रा 2018-19 में और 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2019 तक 3 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा, मैं इस अनुरोध में यह पाता हूं कि नए विकासशील देशों को बिना किसी सही कारण के समीक्षा के अनुसरण में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि समीक्षा का उद्देश्य ही इस तथ्य का मूल्यांकन करना है कि क्या रक्षोपाय शुल्क घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति से रोकने अथवा उसका उपचार करने के लिए अपेक्षित है। इस कारण से, यदि आयातों की मात्रा में अन्य अन्य विकासशील देशों, जिन्हें मूल जांच के अनुसरण में शुल्क के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था, से वृद्धि हुई हो, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति को उस स्थिति में नहीं रोका जा सकता है अथवा इसका उपचार नहीं किया जा सकता है जब इन विकासशील देशों जिनका आरंभिक 3 प्रतिशत से आयात अधिक हुआ है, को इस शुल्क, जिसे जारी रखा जाना है, के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। इस कारण से ऐसी स्थिति में, शुल्क को जारी रखने में कमी केवल एक औपचारिकता होगी, क्योंकि यह इन नए स्रोतों, जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति उत्पन्न कर रहे हैं अथवा उसकी चुनौती दे रहे हैं, से आयातों के अंतरप्रवाह पर लागू नहीं होगा। मैंने फिनोल पर रक्षोपाय शुल्कों के दिनांक 11 दिसंबर, 2001 की समीक्षा में अंतिम जांच परिणामों को भी नोट किया है जिसमें मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर को समीक्षा के अनुसरण में शुल्क के क्षेत्र में शामिल किया गया था। यद्यपि, इन देशों को मूल शुल्क के समय शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, मैंने एसीटोन के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क की समीक्षा में

जिसमें साउथ अफ्रीका और सिंगापुर को समीक्षा के अनुसरण में रक्षोपाय शुल्क के क्षेत्र में शामिल किया गया था, यद्यपि उन्हें मूल शुल्क लगाए जाने के समय शुल्क के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था, दिनांक 4 फरवरी, 2002 के अंतिम जांच परिणामों में नोट भी किया है। तदनुसार, इन हितवद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे को स्वीकार नहीं किया जाता है।

84. आगे यह नोट किया जाता है कि विकासशील देशों जिसका अलग-अलग हिस्सा 3 प्रतिशत से कम है, का सामूहिक भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों का 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इस कारण से, चीन जन गण, थाइलैंड और वियतनाम को छोड़कर विकासशील देशों से होने वाले विचाराधीन उत्पाद के आयात की सिफारिश सीमा प्रशुलक अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख (1) के परंतुक के संबंध में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के अध्यधीन किए जाने के लिए सिफारिश नहीं की गई है।

ग. निष्कर्ष

85. उपर्युक्त जांच और विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि

- i. विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप 2018-19 में आयातों में गिरावट के बाद, 30 जुलाई, 2019 से रक्षोपाय शुल्क की दर में कमी के अनुसरण में 1 अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 की अवधि में आयातों में वृद्धि हुई है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों में जांच की समग्र अवधि की तुलना में कुल भारतीय घरेलू उत्पादन के सापेक्ष तथा स्वतंत्र रूप में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
- ii. घरेलू उद्योग को लगातार गंभीर क्षति हो रही है जिसे इसके कार्य निष्पादन के समग्र विचार विशेषकर इसका क्षमता उपयोग जो विचाराधीन उत्पाद की मांग पर विचार करते हुए कम है, माल भंडार के स्तरों में वृद्धि तथा नकारात्मक लाभप्रदता के आधार पर देखा गया है। यद्यपि, घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन और बिक्री में सुधार किया है और अपने घाटे को कम किया है फिर भी इसकी स्थिति अस्थिर बनी हुई है और यदि रक्षोपाय शुल्क को जारी नहीं रखा जाता है, तब इसे आगे और गंभीर क्षति हो सकती है।
- iii. आयात की कीमतें क्षति की अवधि अर्थात् 2016-17 से 2019-20 (वार्षिकीकृत) के दौरान गिरावट होना जारी रहा है। रक्षोपाय शुल्क के बिना आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है और इसके कारण यदि शुल्क को हटा लिया जाता है, तब घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होगी। इसके परिणामस्वरूप इस बात की पूरी संभावना है कि घरेलू उद्योग को रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के पूर्व हो रहा गंभीर कीमत न्यूनीकरण और ह्रास फिर से होगा और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर आगे और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- iv. सोलर पावर डेवलपर और अंतिम उपभोक्ता की लागत में विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप वृद्धि होगी। हालांकि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना जनहित में होगा क्योंकि यह देश में सौर उद्योग के निर्माण आधार के पूर्ण रूप से क्षय होने से रोकेगा जिसने बहुत अधिक मात्रा में निवेश किया है। यद्यपि, घरेलू उद्योग ने समायोजन योजना का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया है, परंतु अपनी समायोजन योजना को कार्यान्वित करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं जिसने अपने कार्य निष्पादन में सुधार किया है और इसके फलस्वरूप आगे आयातों की तुलना में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी और साथ ही दीर्घावधि में घरेलू उपभोक्ता को विचाराधीन उत्पाद की लागत में कमी आएगी।

त. सिफारिशें

86. विचाराधीन उत्पाद का भारत में आयात के कारण घरेलू उद्योग को न केवल गंभीर क्षति होना जारी रहा है बल्कि इसके कारण "विचाराधीन उत्पाद" के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होने का भी खतरा है और यह जनहित में होगा कि सीमा प्रशुलक (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन), नियमावली 1997 के नियम 12 के साथ पठित नियम 18 के संबंध में भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाए रखना जारी रखा जाए। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने चार वर्षों में क्रमशः 14.95%, 14.90%, 14.85% और 14.80% के रक्षोपाय शुल्क के प्रगामी उदारीकरण के साथ आगे चार वर्षों की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क को बढ़ाए जाने की मांग की है। इस बात को ध्यान में रखकर कि संरक्षण के दो वर्ष पहले ही दिए जा चुके हैं और घरेलू उद्योग ने अपनी स्थिति में सुधार किया है परंतु उसे समायोजित करने के लिए कुछ और समय की जरूरत है, एक अन्य वर्ष

की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क का विस्तार किया जाना समुचित होगा। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान, शुल्क की मौजूदा मात्रा को उस गति से उदारीकृत किया जाना जारी रखना होगा, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि घरेलू उद्योग द्वारा समायोजन को केवल एक वर्ष की अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए। तदनुसार, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, आगे सकारात्मक समायोजन को आसान बनाने के लिए रक्षोपाय शुल्क को घरेलू उद्योग का संरक्षण जारी रखना उपयुक्त माना जाता है। रक्षोपाय शुल्क का पालन करने की सिफारिश सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष 85414011 और 85414012 के अंतर्गत आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद पर 30.7.2020 से लगाए जाने के लिए की जाती है। इसमें उल्लिखित प्रशुल्क मर्दे सांकेतिक मात्र हैं और आयात की गई वस्तुओं का विवरण सिफारिश की गई रक्षोपाय शुल्क की प्रयोज्यता का निर्धारण करेगा।

वर्ष	सिफारिश किए गए रक्षोपाय शुल्क
प्रथम 6 माह	रक्षोपाय शुल्क @ 14.90% यथामूल्य की दर से
अगले 6 माह	रक्षोपाय शुल्क @ 14.50% यथामूल्य की दर से

87. चूंकि विकासशील देशों जिसे दिनांक 5 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 19/2016-सीमाशुल्क (एन टी) में सूचीबद्ध किया गया है और जिसमें चीन जन.गण., थाइलैंड और वियतनाम को शामिल नहीं किया गया है, से आयात अलग-अलग रूप में 3 प्रतिशत और सामूहिक रूप में 9 प्रतिशत से अधिक होता है, चीन जन.गण., थाइलैंड और वियतनाम को छोड़कर विकासशील देशों के मूल के विचाराधीन उत्पाद के आयात पर सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख (1) के परंतुक के संबंध में रक्षोपाय शुल्क नहीं लगेगा।

बिद्युत बिहारी स्वैन, महानिदेशक (रक्षोपाय)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2020

Case No. (SG) 01/2020

Subject : Final Findings of review investigation for continued imposition of Safeguard duty on imports of “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” into India- Proceedings under the Customs Tariff Act, 1975 and the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 - Reg.

F. No. 22/1/2020 - DGTR

(A) Introduction

1. An application dated 15 January 2020 was filed before me on 15 January 2020 under Rule 18 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter also referred to as the “Rules”) by the Indian Solar Manufacturers Association (ISMA) on behalf of three Indian producers, namely (i) M/s Mundra Solar PV Limited, Adani House, Meetha Khali 6 Road, Navrangpura, Ahmedabad-380009, Gujarat; (ii) M/s Jupiter Solar Power Limited, Village Katha, Post Office Baddi, Teh. Nalagarh, Dist. Solan, Himachal Pradesh-173205; and (iii) M/s Jupiter International Limited, Village Katha, Post Office Baddi, Teh. Nalagarh, Dist. Solan, Himachal Pradesh-173205, seeking continued imposition of the existing safeguard duty (hereinafter also referred to as the “Duty”) against imports of “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC”) into India.

2. The existing safeguard duty on the product under consideration was imposed pursuant to the final findings issued by the Director General (Safeguards) under Rule 11(1) of the Rules, and published in the Gazette of India (Extraordinary) on 16th July 2018 recommending levy of safeguard duty @ 25% *ad valorem* during the 1st year, @ 20% *ad valorem* during the next 6 months and @15% *ad valorem* during the next 6 months on imports of “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” into India for protection of the domestic industry from the serious injury caused by the increased imports of the PUC. Based on the said final findings and in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 8B of the Customs Tariff Act, 1975(51 of 1975) read with Rules 12 and 14 of the Rules, the Central Government vide Notification No.01/2018 - Customs (SG) dated 30th July, 2018 imposed on “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels”, falling under sub-heading number 8541.40.11 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, when imported into India, a safeguard duty at the rate of:

- (i) twenty-five per cent *ad valorem* minus anti-dumping duty payable, if any, when imported during the period from 30th July, 2018 to 29th July, 2019 (both days inclusive);
- (ii) twenty per cent *ad valorem* minus anti-dumping duty payable, if any, when imported during the period from 30th July, 2019 to 29th January, 2020 (both days inclusive); and
- (iii) fifteen per cent *ad valorem* minus anti-dumping duty payable, if any, when imported during the period from 30th January, 2020 to 29th July, 2020 (both days inclusive).

3. Further, the said notification exempted levy of safeguard duty on imports of the PUC from notified developing countries other than China and Malaysia under Clause (a) of sub-section (6) of Section 8B of Customs Tariff Act 1975,

4. The Customs Tariff Heading 8541 4011- Solar cells, whether or not assembled in modules is split into the following two headings, vide Section 117(b) of the Finance Act 2020 (No.12 of 2020) read with entry No.2 of Schedule III thereof w.e.f. 01.02.2020:

8541 4011- Solar Cells, not assembled

8541 4012- Solar Cells assembled in modules or made up into panels

5. Vide customs notification No. 1/2020-Customs (SG) dated 2 February 2020, the two new tariff headings mentioned hereinabove were substituted in the place of single tariff heading in the earlier customs notification No. 1/2018-Customs (SG) dated 30 July 2018.

6. Thus, the existing safeguard duty is applied on “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” classifiable under the Tariff Headings 85414011 and/or 85414012 of Chapter 85 of Schedule I of the Customs Tariff Act 1975. The Customs tariff classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the product under consideration as mentioned in the final findings dated 16th July 2018.

7. On the basis of the written application referred to in paragraph 1 above and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicants regarding evidence of serious injury and that the domestic industry is adjusting positively, the Director General initiated a review investigation, in accordance with Section 8B of the Act, read with Rule 18 of the Rules, for examining the need for continued imposition of safeguard duty on the PUC vide Notice of Initiation (NOI) No. F.No.22/1/2020-DGTR dated 3rd March 2020.

8. In accordance with Rule 18 read with sub-rules (2) and (3) of Rule 6 of the said Rules, a copy of the NOI dated 03.03.2020 and a copy of a Non-confidential Version (NCV) of the application dated 15.01.2020 filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government in the Ministry of Commerce & Industry, Ministry of Finance, Ministry of New and Renewable Energy, Ministry of Power, Ministry of MSME, Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution and the Governments of major exporting countries through their Embassies in India, and the interested parties mentioned in the said application. Further, a questionnaire seeking information from the interested parties as prescribed under Rule 6(4) of the Rules was forwarded to the known interested parties with a request to make their views known in writing within 30 days from the date of issue of the NOI.

9. In response to the NOI and oral hearing, either a request to consider as interested parties or submissions were received from the following parties:

1.	M/s Indian Solar Manufacturers Association
2.	M/s Jupiter Solar Power Limited
3.	M/s Jupiter International Limited
4.	M/s Mundra Solar PV Limited
5.	Indonesian Embassy
6.	Government of Malaysia
7.	China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME)
8.	M/s ACME Solar Holdings Limited
9.	M/s Solar Power Developers Association
10.	M/s Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.,
11.	M/s All India Solar Industries Association
12.	M/s Shapoorji Pallonji Infrastructure Capital Company Pvt. Ltd.
13.	M/s Azure Power India Private Limited
14.	Council on Energy, Environment and water
15.	M/s REC Solar Pvt Ltd, Singapore
16.	M/s Vikram Solar Ltd
17.	Taipei Economic and Cultural Centre
18.	M/s Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.
19.	M/s SB Energy Pvt. Ltd,
20.	M/s GRT Jewellers (India) Pvt. Ltd
21.	M/s Acme Cleantech Solutions Pvt. Ltd.
22.	M/s AMP Energy India Private Limited
23.	M/s Avaada Energy Private Limited.
24.	M/s Ayana Ananthpuramu Solar Private Ltd
25.	M/s Emmvee Photovoltaic Power Private Limited
26.	M/s Goldi Solar Private Ltd
27.	M/s TEPSOL Photovoltaic Power Ventures Pvt
28.	M/s North India Module Manufacturer Association (NIMMA)
29.	M/s Insolation Energy Pvt Ltd (On behalf of NIMMA)
30.	M/s Patanjali Renewable Energy Pvt Ltd
31.	M/s Renewsys India Pvt Ltd
32.	M/s Websol Energy System Ltd
33.	M/s Viraj Solar Maharashtra Pvt Ltd

10. The Authority hosted the list of interested parties on the DGTR's website.

11. To enable access of all non confidential version (NCV) submission by all interested parties, the Authority advised all interested parties exchange their NCV submissions with each other through email in view of the practical difficulties faced by them in accessing the public file due to Covid-19 crisis.

12. An oral hearing was held on 3rd July 2020. In terms of sub rule (6) of rule 6 of the Rules, all the interested parties who participated in the oral hearing were requested to file written submission of the views presented orally. Copy of written submissions filed by an interested party was made available to all the other interested parties as was advised in the oral hearing. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties.

13. The submissions made by all interested parties pursuant to the oral hearing or otherwise have been appropriately examined and addressed under the relevant paras. As many issues are repetitive, they have been collectively addressed at the relevant paras. Data submitted by the Domestic Industry has been verified through desk study to the extent considered necessary.

(B) Submissions made by interested parties

14. The submissions made by various interested parties are summarized below:

i) Governments of exporting countries

15. Governments of Indonesia, Malaysia and Taiwan made their views known to the DG(Safeguards).

16. In the written submission filed pursuant to the oral hearing, Indonesia contended that (a) increase of imports and unforeseen development also need to be looked into in a review (b) Indonesia was excluded from the application of safeguard measure in the original investigation as imports from Indonesia constituted less than 3% of total imports into India and should continue to be so under any subsequent review, and (c) current imports from Indonesia continues to be less than the de minimis level of 3% and accordingly no safeguard duty shall be imposed on imports from Indonesia.

17. In the written submissions filed pursuant to the public hearing, Government of Malaysia submitted that (a) the imports of product under consideration has drastically reduced post imposition of safeguard duty in July 2018 and Malaysia should be excluded as per Article 9 (1) of the Agreement on safeguard, and (b) as per Article 12(2) of the Agreement on safeguard, in the case of an extension of a measure, evidence that the domestic industry concerned is adjusting shall also be provided to the Committee on Safeguards. Malaysia also suggested to inform the interested party of the developments of domestic industry's adjustment plan after the imposition of safeguard measure.

18. Taiwan in its written submissions filed pursuant to the oral hearing raised the following issues:

- (i) Article 8 of the Agreement on safeguard gives right of suspension of substantially equivalent concessions or other obligations under GATT 1994 to exporting countries if duration of safeguard measures is more than 3 years.
- (ii) Information provided in the petition does not support the claim of the domestic industry regarding extension of safeguard measure for another 4 years period.
- (iii) Article 2.1 of the Agreement provides that for levy of safeguard measures, there should be an increase of imports, absolute or relative to domestic production. Total imports into India have decreased from 9,790 Mega Watts in 2017-18 to 8,754 Mega Watts in 2019-20 (A).
- (iv) Imports from Taiwan fell from 393 Mega Watts in 2017-18 to 24 Mega Watts in 2019-20. Taiwan's share in total imports is approximately 0.28% in 2019-20.
- (v) One of the constituents of domestic industry is situated in special economic zone. The Authority had clearly observed in the final findings of the original investigation that unit situated in special economic zone cannot be considered as part of domestic industry for the purpose of safeguard investigation. The standing of the applicants as domestic industry and claim of serious injury should be assessed based on the remaining two constituents of domestic industry only.
- (vi) Revised adjustment plan cannot be relied upon because domestic industry has not provided complete information regarding its fulfilment and compliance of adjustment plan submitted during original investigation. If safeguard duty imposition in the range of 25% to 15% has not allowed the domestic industry to implement its original adjustment plan, there is no certainty that the revised adjustment plan will be implemented when safeguard duty of less than 15% will be in force.
- (vii) The information provided in the petition of the domestic industry regarding market share, production, capacity, capacity utilisation, domestic sales etc. during the period of investigation shows substantial improvement. This indicates that domestic industry is not suffering any serious injury.

- (viii) According to the Union Budget of India for 2020-2021, we note that India has proposed to make the amendments in the first schedule to the Customs Tariff Act 1975, creating tariff item 8541.4011 for “Solar Cells, not assembled” and tariff item 8541.4012 for “Solar Cells assembled in modules or made up into panels” and that a tariff rate of 20% has been proposed to be effective from 2 February 2020. We concern that the tariffs on these products raised by India have surpassed India's zero bound commitment in the WTO.

ii) Exporters or trade or business associations from exporting countries

19. The following exporters and trade or business associations from the exporting countries filed submissions in this review:

- (i) REC Solar Pte Ltd ("REC Solar")
- (ii) Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co Ltd ("Canadian Solar")
- (iii) China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products ("CCCME").

20. Submissions in response to the initiation notice and oral hearing made by REC Solar:

- (i) As per Rule 18 of the Rules, provisions of Rules 5, 6, 7 and 11 apply mutatis mutandis to a review investigation. Accordingly, review application submitted by an applicant is to be substantiated by sufficient evidence regarding increased imports, serious injury or threat of serious injury, causal link between increased imports and alleged serious injury or threat of serious injury and a statement on the efforts being taken, or planned to be taken, or both, to make a positive adjustment to import competition. The initiation of the investigation does not comply with the requirements of under Rule 5.
- (ii) If the DI had not filed the questionnaire response along with the DI petition, this implies that the application examined by the Hon'ble DG did not include the adjustment plan. Thus, if the application for initiation of this present review investigation did not include the revised adjustment plan, thus the Hon'ble DG has not followed the requirement under Rule 5 of the Indian SG Rules.
- (iii) The applicants do not meet the criteria for being considered as 'domestic industry' on account of two factors - (a) JIL is not a 'producer' of the PUC as it merely carries out repurposing/ incremental job work. (b) The DI, as identified, is not representative of the major proportion of the total domestic production – with or without the inclusion of JIL within the scope of DI.
- (iv) Alpha product is designed under a Design Patent issued by Singapore as well as by governments in other jurisdictions including Europe. A Design application made by them in India is pending. Because of the use of patented design, the product - (i) uses proprietary advanced technology, is of superior quality, space efficient, and more environmental friendly, (ii) commands a higher price in the Indian market and (iii) is neither identical nor alike in all respects to the articles manufactured in India. Alpha product shall be excluded from the scope of the PUC as it is patented and such exclusion will be in line with the decision of the Indian authority in the Anti-Dumping duty investigation concerning imports of *Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel* from China PR, Japan, Korea, European Union, South Africa, Taiwan (Chinese Taipei), Thailand and USA dated 24 November 2009 where certain patented grades of stainless steel were excluded.
- (v) Rule 2(e) provides for two scenarios in which a product can be declared as a “like article”. WTO panels and appellate body in multiple cases have resorted to the test of ‘likeness’ such as *Japan - Alcoholic Beverages* and *Canada – Periodicals*. The WTO Appellate Body endorsed the basic approach set out in the 1970 Report of the Working Party on Border Tax Adjustment. As observed by the DG (SGD) in the final findings of safeguard investigation against import of Hot Rolled Coils/sheet/strips dated 08 December 2009, likeness of the products shall be assessed by considering physical characteristics, end use, manufacturing process and price relationship.

- (vi) Base year to determine any increase or decrease in import volumes in the present review investigation should not overlap with the Original Investigation. However, this has not been followed in the present case where 2016-17 has been taken as the base year for all data analyses and projections.
- (vii) Only six months import data is available for the year 2019-20. Such import data cannot be 'annualized' to construct import volume for the year 2019-20 because such annualization will not be an evidence of actual imports as required under the relevant provisions and as interpreted by WTO DSB.
- (viii) It would be insufficient to make an affirmative determination of increased imports based on only a minor increase in imports. Though the volume of imports has increased slightly during the period of investigation, the increase is not sharp, sudden or significant enough to cause serious injury as interpreted by WTO DSB Appellate Body in WT/DS-121 Argentina-Footwear (EC).
- (ix) Data clearly highlights that if import figures of March 2020 are considered then the import of the PUC has actually declined from 2018-19 to 2019-20 by 1% instead of increasing as claimed by DI on the basis of annualised figures
- (x) The injury in a safeguard investigation cannot be determined on a same footing as in an anti-dumping or a countervailing duty investigation and that it must be analyzed on a higher standard. The term "serious injury" is also defined in Article 4.1(a) of the Agreement on Safeguards. The DI has made significant improvements during the POI. There is increase in production, sales, market share, productivity etc. The respondent claims that DI has been able to increase its capacity utilization as well as production but has nowhere indicated that the imports are causing serious injury to the DI with respect to the sales of PUC in domestic market
- (xi) Article 4.2(b) of the AoS expressly states that injury caused to the DI by factors other than increased imports "shall not be attributed to increased imports". Any decline in domestic prices is attributable to the falling prices of PUC globally and not the imports of PUC into India. DI's performance, if any, is not attributable to increased imports. Some of the 'factors which demonstrate a break in the causal link between increased imports and alleged serious injury and threat thereof are demand-supply gap, inherent deficiency in Indian Solar Manufacturing Industry, insufficiency in showing increase in imports and absence of serious injury.
- (xii) The capacity utilization of the DI has increased from 44% in 2016-17 to 75% during 2019-20(A) which is an equivalent increase by 70%. Similarly, domestic production of the DI has increased from 100 indexed-MW points in 2016-17 to 171 indexed-MW points during 2019-20(A) which is an equivalent increase by 71%. The domestic sales by the DI have increased in volume from 100 indexed-MW in 2016-17 to 166 indexed-MW in 2019-20(A). It is incorrect to say that the domestic share has gone down considerably during the POI.
- (xiii) Market share of DI shows a sharp increase in the most recent period. It must be noted that the market share of the DI has increased from 60 Indexed-% points in 2018-19 to 124 Indexed-% points in 2019-20(A) which is an equivalent increase by 64% in a year whereas the market share of imports has actually seen a decline by 3 Indexed-% points during the same period.
- (xiv) DI should not include MSPL in calculating price undercutting. The undercutting provided in the petition is not accurate and should be re-calculated. The DA should direct the DI to refile revised data at the earliest for purpose of reasonable analysis in the present investigation.
- (xv) Price undercutting is calculated based on average prices charged by domestic producers including MSPL i.e. the SEZ unit. In the price undercutting calculations, SEZ units shall not be included. The price undercutting for solar cells has decreased from 55-65% range in 2016-17 to 0-10% range during the POI. Similarly, the price undercutting for solar module has decreased from 35-45% range in 2017-18 to 5-15% range during the POI.

- (xvi) Some of the 'factors which demonstrate a break in the causal link between increased imports and alleged serious injury and threat thereof are enlisted as follows
- a. Demand Supply gap
 - b. Inherent deficiency in Indian solar manufacturing industry
 - c. Insufficiency in showing increased imports
 - d. Absence of alleged serious injury
- (xvii) Rule 18 of the Indian SG Rules requires the DI to adjust positively before the Hon'ble DA can make a recommendation for continued imposition of the SG duty. DI is enjoying duty protection since July 2018 and has yet not made the requisite efforts to adjust positively in accordance with the adjustment plan. DI has not provided information on usage of PERC technology or Bi-facial technology projects, which was another step they intended to undertake while enjoying the duty protection. DI has not produced documentary evidence regarding positive adjustment. Further, the revised adjustment plan provided with the questionnaire response is vague and excessively confidential DI should have at least provided a non-confidential summary of the comparison between the adjustment plan provided during the original safeguard investigation and as provided in the present review investigation.
- (xviii) The DI has not adduced any evidence as to how continued imposition of safeguard duty on the PUC will not affect the consumers/ user industry and the user industry/consumer in India heavily relies on imports of PUC from other countries.
- (xix) Imposition of safeguard duty is not in public interest. Given the increasing demand of the PUC globally as well as in India, it is very likely that the user industry may not be able to procure the PUC from the DI in line with its requirements. In such circumstances, the user industry would have no other option but to import the PUC from overseas. As their projects cannot be closed due to the unavailability of the PUC in domestic market, such continuous imposition of duty would make imports financially unviable. This would be severely prejudicial to the interest of the user industry in India.
- (xx) continued imposition of duty will create trade barriers for imports which would lead to formation of monopoly by the DI. And it will result in damage to the downstream industries which collectively are large employers in the country. They have tremendous scope for further generating employment if this duty is removed. A concept note was issued by the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, dated 15 December 2017 wherein it stated the following: "The present maximum solar cell manufacturing capacity per year is only around 3 GW against an average requirement of 20 GW i.e. 15%. Balance capacities have to be procured from international market." Any increase in imports of PUC in India is attributable to the lack of domestic supply. The Indian solar manufacturers have been using obsolete technology and are highly insufficient to meet the domestic demand.
- (xxi) However, the Indian manufacturers lack an integrated production chain. This has resulted in inherent deficiencies rendering them uncompetitive against global companies.
- (xxii) DI has proposed to liberalize the duty at the meagre rate of 0.05% in a year which in itself shows that it is not willing to positively adjust. Given the oddity of the reduction such meagre liberalization is unheard of in any safeguard investigation. Even in the Final Findings of the Original Investigation the Hon'ble Authority has recommended 5% reductions in three stages.
- (xxiii) Indian Government's proposal to raise the Basic Customs Duty ('BCD') on the imports of the PUC by 20%.⁴⁸ This will be 5% higher than the current levy of 15% safeguard duty and thus is over and above the 14.95% duty that the DI has requested in review. In sum with the increase in BCD the DI is no longer in need of a safeguard duty to protect its interests. safeguard levy in addition to the increase in BCD will result in an irreversible negative impact on the overall user industry which is already facing supply shortages.
- (xxiv) During 2019-20, 94% of imports of PUC into India came from three countries - China PR -

75%, Thailand -10.2% and Vietnam -9.4%. DI has also argued that not only import of the PUC is coming into India in significant quantities from China PR, Thailand and Vietnam, the import price from Vietnam and Thailand has also decreased consistently throughout the POI. Where the DI is suffering from unfair trade practice, such as low-priced imports, the remedy lies under the anti-dumping provisions and not the safeguard provisions.

21. Submissions in response to the initiation notice and in its written submissions and oral hearing made by Canadian Solar:

- (i) Volume of Imports from Thailand are inflated in the petition. Imports from Thailand are not above 3% if import quantity as per the methodology determined by the domestic industry is taken into account for assessing volume of total imports and volume of imports from Thailand. They were less than three percent in the year 2016-17 and the year 2017-18 i.e. in the first two years of the period of investigation. No rule which provides that the Authority should rely on the last 18 months period in the period of investigation.
- (ii) Rule 18(1)(i) does not provide for imposition of safeguard duty afresh on countries that were not originally subject to safeguard duty. Accordingly, developing countries excluded from the scope of safeguard duty pursuant to the original investigation cannot be included pursuant to a review.
- (iii) Safeguard duty should normally not be extended in a review unless there are extraordinary circumstances requiring such as an extension.
- (iv) Safeguard duty should normally not be extended in a review unless there are extraordinary circumstances requiring such an extension. Extension of safeguard duty for another period will also result in suspension of substantially equivalent level of concessions and other obligations existing under GATT 1994 between India and exporting WTO member countries in accordance with Article 8 of the Agreement on Safeguards.
- (v) In the original investigation the Authority relied on the binding tariff concession of 0% basic customs duty on imports of the PUC pursuant to the IT Agreement ("ITA-I"). Tariff rate under HS code 8541 4011 and 8541 4012 has already been increased to 20% vide the Finance Act, 2020 with effect from 1st February 2020. The Government of India is now expected to announce its decision to impose this increase in customs duty rate on import of solar cells and modules. It should be clearly specified whether ITA-I restricts India's freedom of action and prevents it from raising customs duties on import of solar cells and modules. It is inconsistent with Article XIX of GATT to impose both safeguard duty and customs duty on the imports of PUC. In any case, to ensure that India does not communicate conflicting stance to WTO, both safeguard duty and customs duty should not be imposed. Authority should consider that if basic customs duty of 20% is imposed as contemplated under the First Schedule of Customs Tariff Act, domestic industry will get sufficient protection and there is no need for additional safeguard duty of 15%.
- (vi) Solar Cells and Solar Modules have different physical characteristics, different usage, different pricing and different production process and they should be treated separately for the purpose of determining standing of the domestic industry in the present safeguard review. Authority must assess whether production of each of the subject goods by the petitioners constitute a major proportion of the total Indian production as has been done by the authority in the antidumping investigations concerning (a) *Front Axle Beam and Steering Knuckles from China PR* and (b) *Penicillin – G and 6APA from China and Mexico*.
- (vii) Standing of solar cells and solar modules should be assessed separately. To increase their utility of solar cells, a number of individual PV cells are interconnected together in a sealed, weatherproof package called a module. There are several standalone producers of solar modules who are not producers of solar cells. Production of these module producers cannot be excluded from total domestic production. Total Indian production of both solar cells and solar modules should be taken into account to determine whether the share of domestic industry in total production constitute major proportion or not. If it is done so, it would clearly establish that the domestic industry does not have sufficient standing for

solar modules because the share of the petitioners in total module production in India is very less and would not amount to major proportion share .

- (viii) Trade Notice SG/TN/1/97 dated 6th September 1997 provides the format of application and the data to be provided in the application. However, petitioner companies have claimed complete confidentiality with regard to several economic parameters, which is relevant for assessment of serious injury and have not complied with the requirements of Annexure I of Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018 issued by the DGTR that provides guidelines for disclosure of information in confidential and non-confidential version of the petition. The domestic industry has also not shown any good cause for such excessive confidentiality in contravention of the Trade Notice. The claims of confidentiality by the petitioner over Appendix 10 of the petition shall be disallowed.
- (ix) In terms of Article 7.2 of the WTO Safeguards Agreement , Article 2.1 of the Agreement and Rule 18 of the Rules safeguard measures can be imposed or extended only if there is 'increase in imports' of the subject product. Only six months import data is available. Such import data cannot be 'annualized' to construct import volume for the year 2019-20 because such annualization will not be an evidence of actual imports as required under Article 2.1 of the WTO Safeguard Agreement, Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, and the Rule 11 of the Safeguard Rules. WTO Panel in *India- Certain Measures on Imports of Iron and Steel Products* noted that objective data for the full financial year is required for assessment of trend in comparison with previous two years.
- (x) In the Safeguard review of PX-13 OR 6PPD (Rubber Chemicals) into India and the Safeguard review of Phenol into India under, the DG safeguards examined whether there is increase in imports or not into India. Thus, there is no doubt that the requirement of increase in imports is applicable in safeguard review as well.
- (xi) In the present safeguard review, the DI should show that there is continued increase in imports in the subsequent years after 2017-18 i.e. 2018-2019 and the year 2019-2020. However, the import data shows that there is no increase in imports in this period. Increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough to cause or threaten to cause 'serious injury'.
- (xii) The increase in imports should not be viewed in comparison with the base year of 2016-17. As per the data shown in the petition, there is decline in imports in recent period if 2017-18 is considered as the base year.
- (xiii) imports from China PR have not increased during the period of application of safeguard duty during last two years despite gradual reduction of safeguard duty from 25% to 15%. Thus, the apprehension that if safeguard duty is further reduced to 0% after 29th July 2020, it will result in increase in imports from China PR is unfounded.
- (xiv) The petitioner companies cannot be treated as domestic industry in terms of Article 4.1(c) of the AoS and Section 8B(6)(b) of the Act, as their collective output does not constitute a major proportion of the total domestic production.
- (xv) Further, the Petition does not disclose the following:
 - (a) total production of the petitioner companies of cells and modules;
 - (b) total Indian production of cells and modules;
 - (c) Percentage share of petitioner companies in total Indian production in cells and modules;
 - (d) Percentage share of two petitioner companies having manufacturing units in DTA in total production of cells and modules (after excluding production of SEZ Units).
- (xvi) Domestic industry has not disclosed total Indian production and aggregate figure of its total production during the POI. The total Indian production cannot be confidential because the information does not pertain to the domestic industry specifically. In absence of disclosure of this information, no effective rejoinder submission can be made by the

other interested parties in response to the claim that the domestic industry had more than 30% share in total Indian production during the entire POI. If the petitioner companies are unwilling to disclose the information, Authority is requested to disregard such information in terms of Rule 7(3) of the Safeguard Rules.

- (xvii) Authority should verify whether the capacity of two petitioner companies located in DTA would constitute a 55-60% share in total Indian production during April 2019 to September 2019 as their combined capacity is only 390 MW.
- (xviii) Jupiter International Ltd. was not the petitioner company in the original investigation. The petition does not provide information regarding (i) reason for non-inclusion of Jupiter International Ltd. in the original investigation (ii) the reason for inclusion of Jupiter International Ltd in the present review investigation. (iii) Standalone capacity, production and sales of Jupiter International Ltd. during the period of investigation (iv) Date of commencement of production of subject goods by Jupiter International Ltd.
- (xix) Petitioners located in SEZ units should not be considered as part of domestic industry as their primary goal is to cater to the export market. The final findings dated 27 September 2012 of the DG Safeguards in the Electrical Insulators case, where WSI Industries (located in SEZ), was excluded from the scope of the domestic industry. SEZ unit cannot be included within the scope of the domestic industry as stated in the Manual of Operating Practices for antidumping cases issued by DGTR.
- (xx) If Mundra Solar PV Limited is excluded from the scope of the domestic industry, the non-injurious price of the domestic industry would reduce substantially.
- (xxi) The domestic industry is not adjusting positively. Indosolar Ltd. has become non-operational and is undergoing insolvency proceedings and ten more companies have also become non-operational during this period. The safeguard duty is not permitting the domestic industry to adjust positively and therefore there is no need for extension of safeguard duty.
- (xxii) Revised adjustment plan not provided in the petition but in the questionnaire response of each petitioner company and is treated as confidential. The petitioner companies have also not provided non-confidential summary of the same.
- (xxiii) Rule 17 of the Safeguard Rules provide for progressive liberalization of duty at regular intervals. Requirement of liberalization of safeguard duty at regular intervals is not a symbolic requirement and cannot be met by merely reducing safeguard duty by 0.05% at the end of each year. Request for such low liberalization of duty evidences that the safeguard duty is not required to be continued because it will not be useful to facilitate adjustment.
- (xxiv) Rule 18 of the Safeguard Rules requires that safeguard duty can be extended to prevent or remedy serious injury. The petitioner companies are not suffering serious injury or threat of serious injury. In terms of the decision of the Appellate Body in WT/DS 178- US – Lamb existence of serious injury or threat of serious injury cannot be easily assumed. The Authority should satisfy itself based on the evaluation of economic parameters of the domestic industry that the injury suffered by the domestic industry is ‘serious’ in nature.
- (xxv) Domestic producers who are experiencing decline in market share are not included as domestic industry in the application. Market share of petitioner companies has increased during the period of investigation. Market share of other Indian producers of subject goods has reduced substantially. Objective assessment of material injury cannot be made without examining performance of the other Indian producers who are experiencing decline in market share.
- (xxvi) From the data, it is evident that the capacity, sales and production of the domestic industry has significantly improved in the POI. It is clear that the domestic industry has faced no injury in terms of employees and productivity per day. Both parameters have witnessed a healthy increase. Therefore the domestic industry has not suffered injury at all, leave alone

injury in the nature of ‘overall impairment’ which can be categorized as serious injury.

- (xxvii) Price undercutting should be determined after adding safeguard duty. In any case price undercutting trend shows that there is no correlation between price undercutting by imports and the profit/loss experienced by the domestic industry. In 2016-17, the domestic industry was making profits. In the year 2017-18, price undercutting reduced by 41 indexed points from the base year, however, the domestic industry started incurring losses. In the year 2018-19, price undercutting was at the lowest for both cells and modules, however, the losses incurred by the domestic industry was the highest.
- (xxviii) The market share of domestic industry has increased by approximately 50% during the period of investigation. The market share of imports has remained stable and has only increased by 2% during the period of investigation.
- (xxix) The domestic industry’s reliance on Article 9.1 of the Agreement on Safeguards to contend that developing countries can be included within the scope of a levy pursuant to a review is incorrect since if exclusion of imports from developing countries were required to be reviewed periodically, Agreement on Safeguard would have provided review mechanism for such purpose. If developing countries are included within the ambit of the levy after two years of safeguard duty, an inconsistent practice would be created which would result in unpredictability.
- (xxx) The Phenol safeguard investigation does not support the contention of the Domestic industry as in the first review proceedings initiated on the said product, the SGD was not extended to other developing countries which were not included within the scope of the original levy. A third review investigation was conducted after the first review was over in order to assess whether the import of Phenol from other countries had increased.
- (xxxi) The domestic industry has wrongly equated imposition of safeguard duty with the survival of domestic industry. Other module producers in India namely (i) Patanjali Renewable Energy Private Limited and (ii) Goldi Solar Private Limited have specifically objected to the continuation of safeguard duty on import of solar cells. They have stated that the indigenous cell manufacturing is hardly 3 GW, which constitutes only 25% of the requirement of module manufacturers. Both companies have protested against extension of safeguard duties on imports of solar cells, since manufacturing of solar modules is dependent on imports. If claim of DI that reduction in imports is in public interest in general is accepted, then it would mean that safeguard duty should be imposed on all imports into India for which there is a domestic producer in India. The requirement of public interest is to be examined in the context of the PUC and not generally in relation to imports into India.
- (xxxii) Continuation of SGD will result in its imposition for a total period of six years. India has not imposed safeguard duty for a continuous period of six years on any product in last 25 years.

22. Submissions in response to the initiation notice and in its written submissions and oral hearing made by M/s CCCME:

- (i) Authority has considered only two companies namely Jupiter International Limited and Jupiter Solar Power Limited for the scope of the domestic industry and excluded Mundra Solar PV Limited (SEZ). However, no clarification has been provided with regard to activities of JIL and JSPL. JSPL, being only a job-worker manufacturing subject goods as per orders of JIL, cannot be considered as part of DI. This is a new development which had been hidden by the petitioners till the time of oral hearing.
- (ii) Request of petitioners to reconsider SEZ unit as part of DI is incorrect as Section 53 of SEZ Act 2005 provides that a special economic zone is deemed to be a territory outside the customs territory of India for the purpose of authorized operations. Further, Section 30(a) of the SEZ Act provides that any goods removed from SEZ to the DTA shall be chargeable to duties of customs including safeguard duties where applicable on such goods when imported which is a condition also applicable to EOUs. The petitioners located in SEZs and EOUs cannot be considered as domestic industry as they are at a separate commercial

position on account of the various incentives and benefits that accrue to them. Hence, SEZ units are not impacted by the conditions of competition in the domestic industry and accordingly, there is no reason for including SEZ units into the Domestic industry.

- (iii) Certain products which the Indian Domestic Industry has no or insufficient capability to produce, i.e. thin film products, mono-crystalline solar products and solar cells, should be excluded from the scope of subject goods.
- (iv) Solar cells are raw materials for modules. Several other materials and additional production processes are needed to manufacture modules from solar cells. Therefore, they are different products, which are needed by different types of clients. Considering these facts, solar modules should be excluded from scope of PUC.
- (v) The revised adjustment plans submitted in the questionnaire response by M/s Jupiter Solar Power Limited and M/s Jupiter International Limited, are insufficient and inappropriate. In Safeguard investigation concerning imports of Phthalic Anhydride (PAN), PX-13 OR 6PPD (Rubber Chemicals), Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of 400 Series, Not Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium into India, Flexible Slabstock Polyol (FSP), the DG refused to impose SGD when the DI failed to produce documentary and corroboratory proof regarding adjustment plan. The petitioner only claimed reduction of costs but did not provide any evidence about the steps they have undertaken to adjust and whether there is relationship between the steps they have undertaken and the reduction of cost. Even in the questionnaire response, the description of their adjustment is quite abstract.
- (vi) In the revised adjustment plan provided by DI, the cost of manufacturing has shown a downward trend. This has been fueled by the reducing prices of main raw material, namely silicon wafers internationally. Reduction in cost of production, due to reduction in raw material prices globally cannot be attributed to positive implementation of Adjustment Plan.
- (vii) Claim that adjustment plan is not necessary for the levy of safeguard duty is incorrect as Rule 5(2)(b) of the Customs Tariff which is mutatis mutandis applicable to safeguard reviews requires adjustment plan to be submitted.
- (viii) A safeguard measure may be adopted only if there is evidence of increased imports causing serious injury and such increase must have occurred as a consequence of unforeseen developments as per Article XIX:1(a) of GATT and as confirmed by the Appellate Body on Argentina -Footwear (EC). The Questionnaire Format for prospective applicants requires them to provide evidence regarding existence of unforeseen developments which has not been provided by the applicant. Reliance has been placed upon *US- Lamb* and Final Findings issued in case of *Hot Rolled Flat products of Stainless Steel of 304 grade into India from China PR (F.No. D-22011/06/2012)* wherein it was held that SGD could not be imposed on the absence of unforeseen developments.
- (ix) The reason for increase in imports from China PR is not any unforeseen development but the GOI's vision to promote renewable sources of energy, which results in an increase in the demand for solar cells and modules. The demand-supply gap will have to be filled by imports from China PR and other countries in the absence of adequate domestic supply. The DI only argued that levy of measures is unforeseen but ignored that causal relationship between such developments and increase in imports is also necessary. The Indian market is a free and demand-oriented market, so increase in imports is caused by increase in demand instead of levy of trade remedy measures by other countries. Excess capacities cannot be seen as unforeseen developments within the meaning of Article XIX of GATT. In line with India's commitments for reduction of CO2 emissions by 33-35% from 2005 levels, India targets achieving 100 GW of solar generation by 2022 and this cannot be considered as unforeseen either. Commitments under certain international agreement may be unforeseen, but the fact that certain international agreement may be signed and may cause influence and change to relevant market is indeed foreseen.

- (x) Purpose for which the petitioner requests a continuation of the duty is not to remedy the injury but to obtain unjustified trade protection through illegal means to maintain its monopoly or dominant position in the market. The domestic industry does not have enough capacity to meet Indian demand. Imports have to be made to meet the demand supply-gap. Negative effect of imposition of SGD will include: (1) trade relationship between India and other countries; (2) the various downstream industries and consumers in India; (3) the healthy development of the Solar Cell Industry, and will also adversely affect the Rural Electrification projects initiated by the Current Government on large scale. In the Final Findings on Methyl Acetoacetate, the DG safeguard did not recommend imposition of SGD as the Domestic Industry was not able to demonstrate that the imposition of SGD on said product was in public interest.
- (xi) Initially, the petitioner had filed an application for ADD in 2012 wherein DA recommended duty on the imports of Solar Cell. However, no ADD was levied pursuant to such recommendations since domestic solar capacity was insufficient to meet the government's ambitious targets for power generation from green energy sources. Later, in 2017, Petitioners again sought ADD but the investigation was later terminated on request of petitioners due to "unreasonable and unjustifiable grounds" put forward by the petitioners.
- (xii) The demand of huge costs associated with manufacturing cells is a great challenge to the Domestic Industry. According to one manufacturer, a 100 MW cell manufacturing facility calls for an investment of ₹800 million (\$10.53 million), excluding land and infrastructure costs. However, a 100 MW cell facility would not have the same economies of scale to compete with imported cell prices, especially Chinese cells. An optimum capacity of 500 MW is what would be profitable, for which investment about ₹4 billion (\$52.63 million) is required. Even if domestic manufacturers do decide to invest, there is no guarantee of demand as government policies change too often without much notice. When the DI's manufacturing capacity is insufficient to even fulfil demand of locally manufactured products required for projects under DCR category, it is vague/absurd to curb or impose duty on imports which will affect the entire industry.
- (xiii) No surge in imports of subject goods has been experienced in the recent past, either in absolute or relative term. However, the reason for the increase of imports in India from 2016 to POI is not the sudden surge of imports, but the growth of the Indian market demands following the development of downstream industry.
- (xiv) The sales of domestic industry are showing positive trend with significant growth. The market share of domestic Industry has increased drastically during the POI as compared to the base year 2016-17. Capacity remains unchanged during the injury period and period of investigation. However, production has increased sharply during 2019-20. The cost of sale has decreased. The profitability of the domestic industry has improved. Accordingly, capacity utilization has also increased during the POI when compared to the base year. Thus, there is no injury to the domestic industry from the imports from subject countries.
- (xv) Rule 5(2)(b) of the Rules states that the application shall be supported by a statement of efforts being taken or planned or both to make adjustment to import competition. Since current investigation was initiated on March 2020, hence the proposed adjustment plan for 2019-20 becomes infructuous. In essence, the DI wants a blanket extension of safeguard duty for four years but has no plans to improve its competitiveness post 2022.

iii) Importers, Domestic Producers and trade/business associations in India

23. The following importers and trade or business associations from India have filed submissions in this review:

- (i) Solar Power Developers Association ("SPDA")
- (ii) Shapoorji Pallonji Infrastructure Capital Co. Ltd ("Shapoorji")
- (iii) Vikram Solar Limited ("Vikram")
- (iv) Patanjali Renewable Energy Pvt Ltd ("Patanjali")

- (v) Goldi Solar Private Limited ("Goldi")
- (vi) RenewSys India Private Limited ("Renewsys")
- (vii) Websol Energy System Ltd. ("Websol")

24. SPDA has reiterated the submissions made by Canadian Solar Thailand during the course of the investigation and the same have not been stated again to avoid repetition. Only those arguments which have specifically been raised by SPDA and do not find mention in the submissions of Canadian Solar have been reproduced below:

- (i) MNRE had issued Order dated 02.01.2019 regarding Approved List of Models & Manufacturers (ALMM) for Solar PV cells & modules, providing for enlistment of models and manufacturers of solar PV cells and modules, complying with the BIS Standards in ALMM List-I (for solar PV modules) & ALMM List-II (for solar PV Cells). The list is scheduled to be published on 30th September 2020. Therefore, the DG is requested to examine whether the petitioner companies have adjusted positively to attain quality to ensure reliability and consistency and qualify to be included in this list.
- (ii) Imports from China PR have not increased during the period of application of safeguard duty despite gradual reduction of safeguard duty from 25% to 15%. Thus, the apprehension that reduction of safeguard duty to 0% after 29th July 2020, would result in increase in imports from China PR is unfounded.
- (iii) Furthermore, EU withdrew the antidumping and countervailing duties on solar cells and modules against China with effect from 3rd September 2018 and this has led to increase in exports from China to EU and India's share in China PR exports have declined proportionately from 29.6% to 7.3%. Thus, there is no requirement for China to increase its exports to India if safeguard duty is withdrawn.
- (iv) Indosolar Ltd. and ten other domestic producers of the PUC have become non-operational or are undergoing insolvency proceedings. Therefore, Domestic Industry is not adjusting positively so as to warrant extension.
- (v) Relying on decline in import price of the PUC into India during the 4 year POI is simplistic and misleading.
- (vi) The domestic industry cannot reasonably claim that all countries including developed countries such as EU countries, Taiwan, Singapore and other smaller developing countries such as Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, etc. are exporting PUC to India at cheap and unfair prices and are undercutting the price of domestic industry even though domestic industry has taken sufficient steps towards positive adjustment in last two years.

25. Submissions in response to the initiation notice and in its written submissions and oral hearing made by Shapoorji :

- (i) Review Applicants has failed to establish that the pre-conditions specified in Rule 18(2) have been satisfied so as to warrant continued imposition of Safeguard duty beyond the two-year period (from July 2018 to July 2020)
- (ii) The current review investigation should not be undertaken as a Writ Petition, filed by the Company, challenging the validity of the previous imposition of Safeguard duty on PUC is sub-judice before the Hon'ble Madras High Court.
- (iii) Review Applicants do not qualify as a 'domestic industry' in terms of Section 8B read with Rule 18 Safeguard Duty Rules and should not be permitted to file the review application for the continuation of the imposition of Safeguard duty on PUC. Review Applicants have a very small portion of the domestic installed capacity which disqualifies them from being considered as a DI and they cannot be permitted to file the review application
- (iv) There has not been any increase in the import of PUC. Assessment of whether there has been any increase in the imports or not should be done by analysing the import volumes during the years in which Safeguard duty is imposed viz 2018-19 and 2019-20 with the year immediately prior to the imposition of Safeguard duty viz. 2017-18 which would be

the last year considered in the Final Findings dated 16.07.2018. Comparing the import volumes with any year before such a year (2017-18) would imply that the Agreement, CTA or the Safeguard Rules envisage imposition of Safeguard duty till import becomes lower than the imports in the first year of the period under investigation of the original investigation – which is not the case. An assessment in imports in absolute terms and in relative terms (to the domestic sales) indicates that the same have not increased.

- (v) Any assessment of whether the DI is adjusting positively should necessarily take into account, the impact of Safeguard duty not just on solar cells but also on solar modules / panels which form part of the PUC and imports of which have been subject to Safeguard duty.
- (vi) There is no evidence to show that the DI is adjusting well to the imposition of Safeguard duty. In terms of the adjustment plan, the DI had provided future performance for the next 3 years as under:
 - i. long term procurement of raw material, rate and volume discounts if better cash flow is achieved.
 - ii. higher utilisation of capacity leading to better conversion cost;
 - iii. better apportionment of semi-fixed and fixed costs;
 - iv. better credit ratings would lower the cost of borrowing and better servicing of debt;
 - v. efforts towards backward integration and developing an entire eco-system;
 - vi. technology development and R&D.
- (vii) Review Applicants have merely shown that they have achieved costs reduction (of raw material, conversion costs, fixed costs). Apart from this, the Review Applicants have not given any data or made any claim to show that the DI has achieved the other performances (in the adjustment plant) or have taken appropriate steps to fulfil the same. DI cannot claim that it is adjusting positively to the imposition of Safeguard duty without providing information / data to show that appropriate steps have been taken to fulfil the aforesaid adjustment plan. In absence of such information / data, the claim of the Review Applicants is false and cannot be accepted.
- (viii) Essential economic figures of the DI and other domestic manufacturers of PUC are ambiguous and vague which has made appropriately responding to the Review Application difficult. It renders response an empty formality and is against the principles of natural justice. Economic data for the period prior to the imposition of Safeguard duty on PUC viz. period prior to 30th July 2018 has been wrongly taken into account in the Review Application. Aggregate Data should have been provided instead of indexed data.
- (ix) DI is not facing any serious injury which would warrant continued imposition of Safeguard duty. There has not been an absolute increase in imports. Even on relative terms, when the volume of imports are compared with the domestic sales it is seen that volume change in both import and domestic sales is based on the demand / consumption. Both volume and domestic sales dipped when there was a dip in consumption, however, in 2019-20 when consumption and demand was higher, domestic sales recuperated with a growth in sales of 101% than imports which saw only a 9.2 percent increment. After the imposition of Safeguard duty in 2018, market shares of domestic sales is on a rise with about 40.9% increase in market share from 2017-18 to 2019-20 for the DI, compared with only a 0.99 % increase in the market share for the same period for the imports. Domestic sales (in MW) clearly show that while there was dip in 2018-20 (due to reduction in consumption) the same sales level shot up again in 2019-20 with increment of 130.5 % from the previous year 2018-19. Therefore, imports do not seem to have an impact on the domestic sales which is on an upward trend. Except in the year 2018 -19 when the consumption /demand was low, production quantity and capacity utilisation has incrementally increased to cater to such a demand. This shows that imports have not had a negative impact on such indicators.

- (x) The fact that installed capacity has not been increased is not due to the imports, but for various other economic factors which puts the DI at a disadvantage.
- (xi) Profits and Losses figures show that in 2019-20 the domestic producers have drastically recuperated (upto an extent of 91.1 %) from the losses faced during the year 2018-19. This clearly shows that the imports do not adversely affect the domestic industry
- (xii) Data in relation to the certain other relevant economic factors such as inventory, numbers of employees and productivity per employee have also been compared. Reduction / Stagnation in the employee number is due to the fact that manufacturing of solar cells has over the years become automated due to technological advancement. High productivity per employee in the year 2019-20 is indicative of the positive growth of the domestic industry which have not suffered serious injury due to the imports.
- (xiii) Methodology for price undercutting (which is alleged to be the main source of injury) has not been provided (d) The combined installed capacity for Jupiter International and Jupiter Solar Power Ltd has been provided without providing individual installed capacities for each of the companies
- (xiv) The Review Applicants have determined a year wise non-injurious price (and basis that price underselling) point without so much as providing any methodology / basis for the same and that provided figures in indexed form – making the data in relation to the same vague, ambiguous and incomprehensible making it impossible for the Company to rebut the claim of the Review Applicant.
- (xv) Domestic producers have managed to substantially reduce the cost of the solar cells – and at the same time have been able to improve their overall financial health including reduce their losses. In such a scenario, where the domestic industry is financially improving at a time when the Review Applicant's are alleging price undercutting shows that lower landed value of imports while undoubtedly giving competition to the domestic producers do not cause serious injury to them. In any event, lower landed value of the imports is only one criteria which is adverse to the domestic industry and the same cannot be the sole basis for claiming serious injury.
- (xvi) Any injury, if at all, are due to economic which have nothing to do with import of the PUC which would persist even if Safeguard duty is continued to be imposed.
- (xvii) The imposition of Safeguard duty would do little to remove the underlying reasons for the DI being at a competitive disadvantage, and problems pertaining to demand and visibility would persist. While imposition of Safeguard duty would reduce the unit costs for Indian manufacturers and improve cash flows, effect of such a benefit would only be temporary. Some of the key factors which are responsible for the competitive disadvantage of the DI – clearly showing that injury, if at all, is caused due to such factors (and not due to surge in imports) have been provided herein under
 - a. Higher cost of finance:
 - b. Higher electricity prices
 - c. Lower economies of scale
 - d. Lack of vertical integration
 - e. Lack of increase in installed capacity
 - f. Under-utilisation of DI: In furtherance
 - g. PUC manufactured by the DI are not as bankable as the imported PUC
- (xviii) Continued imposition of Safeguard duty would hamper Public Interest. In this regard, the following may be taken into account:
 - i. It would lead to further erosion of imports of PUC (which forms an essential part of solar power projects), thereby making it impossible for India to achieve its Paris Convention target of installing 100GW of solar energy capacity.

- ii. Due to imposition of Safeguard duty, the cost of module increased, in turn, leading to increase in project cost and electricity tariff costs. This eventually led to delays in awarded projects and cancellation of tenders, especially as developers have expressed doubts about the viability of tariff caps recommended by the Ministry of New and Renewable Energy (“MNRE”).
- iii. Increase in tariff led to cancellation of nearly 5 GW of awarded project capacity, which was a setback to the Government’s goal of installing 100 GW of solar power capacity.
- iv. Project deployment viz. solar power projects is more labour intensive and provides for around 3.45 (utility) and 24.72 (rooftop) direct full-time equivalent jobs per MW. Cancellation / Delays in solar power projects led to curtailing of huge employment potential.
- v. Problems relating to recovery of additional Safeguard duty cost and cancellations of projects which led to uncertainty and hurt investor sentiment.
- vi. Imposition of Safeguard duty on imports would be in violation of Article 51(c) of the Constitution of India which requires a state to endeavour to foster respect for international law and treaty obligation.
- vii. Imposition of Safeguard duty has adversely impacted standalone module manufacturers which have faced an increase in raw material cost as they are largely dependent on imported solar cells.
- viii. Solar power developers instead of procuring domestically manufactured solar module manufactured out of domestically produced solar cells, structured their transaction in manner so as to procure the maximum amount of modules made from imported solar cells (which were cheaper and better in quality) when the Safeguard duty rate was at its lowest. The intended effect of Safeguard duty to improve the competitiveness of the domestic producers of solar cells was limited.
- ix. Chinese Government in 2018 decided to replace the system of providing subsidies and brought in a system of competitive bidding for the solar projects as a result of which the growth of solar projects would be limited in China. This has impacted the domestic solar cell manufacturers in China leading to a collapse in prices which have huge built out capacity largely dependent on the Chinese demand. Such prices are also reflected in the imports and are unlikely to reduce any further even if Safeguard duty is continued to be imposed – especially as it would be imposed only at a lower rate (than what was earlier imposed).
- x. This factor coupled with the factor that Safeguard duty has had a negative impact on the growth of the solar industry in general due to project cancellations / delays, increase in tariffs etc. would further dis-incentivize investment in the DI – consequently leading to an effect completely opposite of what was initially intended.
- (xix) DI has no intentions / ability to adjust positively is clear as they have proposed liberalisation of merely 0.05% at the end of each year, thereby enabling them to take maximum protection of the Safeguard duty for the a long duration of time.
- (xx) If the allegation of the DI is that dumping results in the injury to the DI and they should take recourse to a separate anti-dumping investigation. Having not done so, the DI cannot allege this as a ground under a Safeguard investigation.

26. Submissions in response to the initiation notice and in its written submissions and oral hearing made by M/s Vikram :

- (i) DG (Safeguards) should clarify that under the provisions of Section 30 of the SEZ Act read with Section 8B (6) of the Customs Tariff Act, 1975, any safeguard duty imposed on solar cells whether or not assembled in modules or panels would not be payable on clearance of solar cells and/or modules from SEZ units to DTA.

- (ii) If clearance from SEZ units to DTA is subject to levy of safeguard duty, SEZ units will be at a disadvantage vis-a-vis DTA units and the SEZ units will die an unnatural death and thousands of people will have to lose their jobs.
- (iii) This will also adversely affect the country's ability to produce indigenously manufactured cells and modules as the entire investment made by PV cell and module manufactures including that of VSL, which operates out of SEZ, will become redundant.
- (iv) Imposition of safeguard duty without settling interpretation issue between the provisions of Section 30 SEZ Act 2005 and Section 8B(6) of Customs Tariff Act or otherwise without exempting units set up in the SEZs would be counterproductive and defeat the very purpose of its imposition. Any imposition of safeguard duty without exempting units set up in the SEZs from safeguard duty will cause irreparable harm to SEZ units and thus will not accord the adequate safeguard protection to the domestic industry as a whole.

27. Submissions in response to the initiation notice and in its written submissions and oral hearing made by M/s Patanjali :

- (i) The Government should extend the imposition of safeguard duty for another 3-4 year but only on import of modules and not on cells.
- (ii) The Indigenous Cell manufacturing is hardly 3 GW (25% of Indigenous Module Manufacturing) so most module manufacturers have to import Chinese Cells after paying safeguard duty and this increases the cost of indigenous modules are costlier than the Chinese modules.
- (iii) Till India have extra cell manufacturing capacity to cater requirements of the module manufacturers, SGD should be discontinued on cells, so that the cost indigenous module could be reduced.

28. Submissions in response to the initiation notice and in its written submissions and oral hearing made by M/s Goldi :

- (i) The Government should extend the imposition of safeguard duty for another 3-4 year but only on import of modules and not on cells.
- (ii) Indian manufacturers are keen to substantially expand their manufacturing capacities with further investment into Cell Production. However, due to lower cell production capacity and high demand, maximum module manufacturers have to import the cells and needs to pay SGD and this could be increasing the cost of Indigenous Modules.
- (iii) Till India have sufficient capacity to cater domestic requirements of the module manufacturers, SGD should be discontinued on cells import, so that the cost of indigenous modules could be reduced.

29. Submissions in response to the initiation notice and in its written submissions and oral hearing made by M/s RenewSys and Websol:

- (i) There is no prohibition in law for SEZ units to be considered as domestic producers of an article for the purpose of constituting Domestic Industry within the meaning of Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff act, 1975.
- (ii) SEZ clearances to the DTA do not attract customs duties, since India has reduced its customs duties to 'nil' for the PUC pursuant to being a signatory to ITA:1. DTA clearances for the PUC by the producers based in the SEZ do not attract any customs duties. SEZ units are under an obligation to maintain positive Net Foreign Exchange (NFE). Since sale of the subject goods into the DTA are considered for the purpose of computing positive NFE, SEZ Units do not have any impediment in continuing to sell the same in the DTA and no compulsion to export either for the purpose of maintaining positive NFE.
- (iii) There is no embargo and in fact there is a specific provision which facilitates the sales in DTA by such SEZ units. Such DTA sales by the SEZ units compete in the domestic market with other manufacturers of the subject goods based out in the DTA. Therefore, these SEZ units are also domestic producers of the subject goods. The SEZ Units have

consistently been selling the subject goods in the DTA, that they are not subject to customs duties while clearing the subject goods into the DTA as the customs duties are 'nil' on the PUC.

- (iv) In view of the fact that no customs duties are leviable on DTA clearances, these SEZ units producing the subject goods are at par with the other domestic producers of the subject goods.
- (v) Finding of the Ld. DG Safeguards in the case of Unwrought Aluminium is both per incuriam and sub silentio. In this regard, the Hon'ble Supreme Court has categorically held in the case of State of U.P. & Anr. v. Synthetics and Chemicals Ltd. & Anr. [(1991) 4 SCC 139] that a decision on an issue which is per incuriam and sub-silentio is not a binding precedent and can be discarded from consideration when deciding a subsequent case.
- (vi) For the reasons stated above, the earlier final finding shall be reconsidered and SEZs shall be included as an integral part of the domestic industry and thus prevent supplies from SEZ to DTA from the levy of safeguard duty.

iv) Applicant domestic industry - Indian Solar Manufacturers Association ("Domestic Industry" or "DI")

30. Submissions in response to the initiation notice and in its written submissions and oral hearing made by domestic industry :

- (i) The product under consideration in the present investigation is 'Solar Cells whether or not assembled in modules or panels'. For practical use, Solar Cells are packaged and connected into an assembly and such an assembly of Solar Cells is referred to as a Solar Panel or Solar Module. The electrical connections are made to the Solar Cells in series to achieve desired output wattage and / or in parallel to provide a desired current capability. In view of Entry No.2(ii) of the Third Schedule to the Finance Act 2020, and the Customs notification No.1/2020-Customs (SG) dated 2 February 2020 existing safeguard measures' i.e. 15% duty is applicable on 'Solar Cells whether or not assembled in modules or panels' classifiable under Customs Tariff Headings 85414011 and 85414012. However, the tariff heading is indicative only and is in no way binding on the scope of the imported product under investigation. The description of the product alone must be dispositive for the purposes of imposition of safeguards measures.
- (ii) The PUC is being manufactured using either of the two major technologies: (1) Crystalline Silicon (c-Si) based Solar Cell technology, also known as Silicon Wafer based technology, and (2) Thin Film technology. The c-Si technology may use n-type and p-type Silicon, and also mono crystalline and multi crystalline Silicon materials. The Thin Film technology may use Amorphous Silicon, Cadmium Tellurium (CdTe) or Copper Indium Gallium Selenium as semi-conductor materials. Solar Cells based on both c-Si technology and Thin Film technology are imported into India.
- (iii) The applicants manufacture Solar Cells / modules / panels using only c-Si technology and not Thin Film technology. The products are covered under Attachment A, Section 1 of the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products, popularly known as Information Technology Agreement (ITA-1). Since India is a signatory to ITA-1, the imported products are exempt from basic customs duties. The relevant tariff heading identifies cells, modules and thin film modules as one product and the duty exemption is applicable to all the three types i.e. c-Si solar cells, c-Si solar modules/panels and Thin film modules/panels. The focus must be on the identification of the products, and their "like or directly competitive" relationship and not on the processes by which those products are produced while determining the scope of 'like article' as held by the Appellate Body In US – Safeguard Measures on Imports of Fresh, Chilled or Frozen Lamb Meat from New Zealand and Australia.
- (iv) In the absence of any material differences between the two types of Solar Cells, any attempt at drawing a distinction between c-Si technology products and thin film technology products would result in defining not "like or directly competitive product" but a *portion* of such like or directly competitive products. Such an approach is inconsistent

with determination of like or directly competitive product under the AoS and has also been reiterated by the WTO Panel's in Dominican Republic – Safeguard Measures.

- (v) There are no material differences between the two Solar Cells manufactured in terms of function or end use, since Solar Cells based on both c-Si and Thin Film technologies are used to generate electricity using the photovoltaic process. Accordingly, there being no basis for differentiating between the two types of Solar Cells for the determination of a “directly competitive/substitutable product” in relation to the imported products, the PUC has correctly been determined as “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels”.
- (vi) In the investigations conducted by EU and USA, thin films technology products were excluded from the scope of product under investigation. However, Canada included the same within the scope. The inclusion and/or exclusion of thin films from the scope of product under consideration is a case-by-case determination based on facts of each case. The facts surrounding the present case in India make it essential to include thin films also in the scope of product under investigation. Otherwise, the entire exercise may lead to circumvention of safeguard duties since the importers may simply switch to thin films to avoid any duties. “Thin Film Modules” are also imported under the same heading and are exempt from basic customs duty like solar cells/modules.
- (vii) In the Final Findings of the Designated Authority in the Final Findings of the first anti-dumping investigation, thin films were considered as like article with solar modules made from c-Si technology and included in the PUC for the following reasons which are also applicable to this review:
 - a. Difference in technology do not alter or impede the end uses of solar panels through either technology;
 - b. Even though the technology is different the principle adopted in both the technologies are similar i.e. photovoltaic process to convert sunlight into electricity;
 - c. Even though the basic raw materials differ, technical character of raw materials used under both the technologies have the qualities to suit photovoltaic technology;
 - d. Crystalline Solar cells are semiconductor p-n junction diodes which converts light into electricity. Similarly, thin film based solar cells are also semiconductor p-n junction diodes and convert light into electricity.
 - e. There is a direct competition between both the technologies as the products of both the technologies can produce power out of solar light and developers can chose either of the technologies for their power projects in the inception stage and thereafter simultaneously in independent lines.
 - f. Both goods are offered in module/panel form to the ultimate end user under both the technologies.
 - g. The cost/pricing is also decided based on factors such as Watt per unit, efficiency of the cell/modules and the competition in the market parlance between the crystalline and thin film products are also generally based on such factors under both the technology;
 - h. The Solar Cells of all technologies were classified under common Customs Classification tariff heading 8541 40 11 with common tariff heading. After the amendment w.e.f 01.02.2020 also, thin film modules are also covered under tariff heading 8541 40 12 which also covers modules with cells made of c-Si solar cells.
 - i. Imposition of safeguard duty on the product of one technology, which is functionally substitutable with the product of another technology would be futile, as the product having no duty can replace the other in the market.
 - j. Power Purchase Agreements between DISCOMS and Solar Power Developers do not differentiate between the technologies for setting up solar power plants.

- (viii) Despite the Tariff heading 85414011 being divided into Tariff heading 85414011 (Solar Cells, not assembled) and Tariff heading 85414012 (Solar Cells assembled in modules or made up into panels), cells and modules deserve to be treated as a single product. Solar cells and solar cells arranged into modules form a single product and fall under the scope of the PUC for the reason that solar modules are nothing but an assembly of Solar Cells that are packaged and connected into an assembly for practical use. In the finding of the USITC in the safeguard investigation on imports of solar cells into the US, a single domestic product consisting of all forms of CSPV Cells, whether or not partially or fully assembled into other products was considered. The USITC found that although CSPV modules are not "like" CSPV cells, they are "directly competitive" within meaning of safeguard statute. Since CSPV cells are the basic element of a CSPV module, both cells and modules share the same primary physical properties. The characteristics of CSPV cells that enable them to convert sunlight into electricity are not affected by the module assembly process but are an essential function of the module in CSPV solar systems; likewise, CSPV modules cannot sever their intended function of converting sunlight into electricity without the inclusion of CSPV cells. The processes used to manufacture CSPV modules from CSPV cells are technologically sophisticated, more labour intensive than manufacturing CSPV cells, and add value to the product, but they enhance rather than change the basic function of the CSPV cells, which is to convert sunlight into electricity. Both CSPV cells and CSPV modules are integrated into photovoltaic solar systems that convert sunlight into electricity for use in residential, commercial and utility applications. CSPV cells represent a substantial portion of the total cost of finished CSPV modules and prices of cells generally correlated with module prices during the POI. For these reasons, a single domestic product was defined which included both CSPV cells and CSPV modules.
- (ix) In the anti-dumping investigation under Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 on imports from China, Malaysia, Taiwan and USA, the Designated Authority had also considered Solar Cells and Modules to be a single product for almost identical reasons in the Final Findings dated 22.05.2014.
- (x) REC Solar has not been granted any patent in India and has failed to provide evidence that Indian purchasers cannot and do not use domestically produced goods for the end-uses for which they use REC's patented products. Many engineering products would have patents and they would still be subjected to trade remedy investigations because they satisfy the requirements of increased imports/dumping/subsidisation causing injury to the domestic industry in the importing country
- (xi) India has also subjected the patented products to trade remedy measures in several cases. In the Safeguard investigation concerning imports of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of 400 series cited (final findings dated 23rd March 2015) where In a similar situation, DG Safeguards has rejected the claim for exclusion of the product from the scope. In the Final Findings in Anti-dumping investigation concerning imports of Seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel), whether hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14'' OD, originating in or exported from China PR dated 9th December, 2016 the authority has held that patented goods and other sub category cannot be excluded from the scope of PUC as long as are technically and commercially substitutable with the domestic like goods and any such exclusion will lead to circumvention
- (xii) The Final Findings in Anti-Dumping duty investigation concerning imports of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel from China PR, Japan, Korea, European Union, South Africa, Taiwan (Chinese Taipei), Thailand and USA relied upon by REC Solar PTE Ltd is not applicable to the facts and circumstances of the present case for the simple reason that though a patent application has been made in India, the said patent has not yet been granted.

- (xiii) Besides submitting that the Alpha Product is of superior quality, space efficient, uses proprietary advanced technology and is environmentally friendly which allegedly leads to their product being priced higher than that of the Domestic Industry, it has not been the case of REC Solar PTE Ltd. that their product is not in direct competition with and not commercially substitutable by the domestic like product for the same end use. REC Solar PTE Ltd. has not provided any evidence which demonstrates that users have used their products for any use other than for generating electricity through photovoltaic effect.
- (xiv) In determining product scope, the focus should be on the like or directly competitive nature of the domestically produced article with that of the imported article. Solar cells of various types produced by different technologies vary in terms of efficiency, price, physical characteristics, like size and weight etc. These variations only lead to a trade off in price and efficiency. However, the final usage of the PUC produced by the Domestic industry and that which is imported remains the same i.e. to produce power through the photovoltaic effect.
- (xv) M/s CCCME have not produced any evidence to demonstrate that the PUC using these technologies which are not produced by the DTA units do not compete with the article produced by these units.
- (xvi) The collective production of the petitioners accounts for more than 50% of the total production of the PUC in India and as such, represent a major proportion of the total Indian production and therefore, constitute Domestic Industry of the like article in India.
- (xvii) In the original investigation, the DG held that producers located in SEZs cannot be considered as domestic producers. The Director General should revisit their decision of not considering SEZ unit as part of domestic industry for the following reasons:
 - a. Section 53 mandates that SEZs shall be considered to be outside the customs territory of India for a limited purpose i.e. for the purposes of undertaking the authorized operations. Though an SEZ is deemed to be outside the customs territory of India to the extent provided under the SEZ Act, it is very much a part and parcel of the territory of India and subject to its laws and regulations.
 - b. It is observed that 'import' under the SEZ Act means receiving goods or services by an SEZ Unit from a place outside India whereas 'export' means supplying goods from the DTA to an SEZ Unit. DTA clearance by SEZ units are not considered as 'import' into India or 'export' from an SEZ.
 - c. Though goods removed from an SEZ to the DTA are chargeable to customs duty as leviable on such goods when imported into India in view of Section 30, it is may be noted that the same is not considered as 'import' as held by the Hon'ble High Court of Allahabad in India Exports.
 - d. Clearances of goods from an SEZ to the DTA are also not considered to be 'exports'. Rather, DTA sales to SEZ units are considered to be 'exports' under the SEZ Act, 2005 for the purpose of making available benefits to the Special Economic Zone Unit/Developer just as in the case of actual exports such as duty drawback, DEPB benefits, etc. However, other liabilities that flow from actually exporting from DTA to a territory outside India such as levy of export duties are not attracted.
 - e. Except for specific exemptions and exclusions provided under SEZ Act, 2005, DTA sales by SEZs are subject to the same levies as that of goods produced in the DTA such as Central Sales Tax unlike in the case of imports. Therefore, units situated in SEZ cannot be considered to be situated outside India and continue to be part and parcel of India. Right to seek protection from the DG should also be made available to SEZ units as it is available to any other unit in India.
 - f. Sale of PUC from an SEZ to the DTA will not attract safeguard duty as is clear from a combined reading of Section 8B(2A) and Section 30 of the SEZ Act, 2005

- g. Section 9A pertaining to the levy of anti-dumping duty, Section 9 with respect to countervailing duty and Section 8B pertaining to the levy of safeguard duty all state, in no uncertain terms, that the same are applicable on imports of an article into India
- h. If an article is not imported into India, none of the aforesaid duties are payable. In this regard, though by a deeming provision, a legal fiction is created whereby SEZ's are considered to be outside the customs territory of India, there is no provision under any extant law in India which deems the clearance of goods manufactured in an SEZ to the DTA as an import.
- i. That clearance of goods manufactured in an SEZ to the DTA does not amount to import into the territory of India has been reiterated in a catena of judgments including *Essar Steel v. Union of India* [2010 GLH (1) 52], *India Exports v. State of U.P. & Ors* [(2012) 47 VST 126], *Tirupathi Udyog Limited rep. by its Manager-Administration Shri D.V. Saradhy v. Union of India (UOI) through the Secretary, Ministry of Finance and Ors.* [2011 (272) ELT 209(A.P.)].
- j. Without factum of import, there can be no levy of anti-dumping duty, countervailing duty or safeguard duty
- k. The mention of levy of anti-dumping duty and countervailing duty during DTA clearance mentioned in Section 30 has to mean duty payable on the value of the inputs (in the event that the inputs imported from specified countries attract anti-dumping duty or countervailing duty or safeguard duty) used on the finished product and not on the finished product itself.
- l. Same principle also applicable to safeguard duties levied against any like article that is also manufactured in an SEZ and cleared into the DTA. This is also evident from Section 8B(2A) of the Customs Tariff Act, 1975
- m. Section 30 of SEZ Act read with Section 8B(2A) of CTA make it clear that safeguard duty is only payable on inputs used in finished products and not finished product manufactured in the SEZ and cleared into the DTA..
- n. SEZ units cannot be barred from being considered as domestic producers of the like article or from being considered as part of the Domestic Industry. Under safeguard law, Clause (b) of sub-section (6) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 defines Domestic Industry
- o. DA has considered SEZ unit manufacturing the PUC as part of the Domestic Industry of the like article in the previous Anti-Dumping Investigation on imports of Solar Cells, whether or not assembled partially or fully in Modules or Panels or on glass or some other suitable substrates, originating in or exported from Malaysia, China PR, Chinese Taipei and USA in the Final Findings dated 22.05.2014. Thus, as far as anti-dumping proceedings are concerned, SEZ units producing the PUC are considered to be Domestic Industry of the like article under both Rule 2(b) of the AD Rules 1995 and Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
- p. In both Safeguard law as well as Anti-Dumping law, the provisions do not stipulate that only producers of a like article situated in the DTA shall be considered as Domestic Industry or for that matter, like article produced in an SEZ and cleared into the DTA for domestic consumption is not to be considered as domestic production of the like article. Producers of a like article in a SEZ are required to be considered as part of the Domestic Industry considered as producers of a like article situated in a SEZ do not suffer from any limitation or impediment in selling it in the domestic market of India.
- q. DTA clearances of goods by an SEZ are liable for payment of customs duty as leviable on them if imported. However, as noted in the Final Findings of the Designated Authority in the previous anti-dumping investigation, India's import tariff on the PUC which falls under Customs Tariff Item 85414011 of the Customs

Tariff Act, 1975 is 'Free' and therefore, no customs duty is leviable on DTA clearances by SEZ units manufacturing the same. SEZ units also have an obligation to maintain positive Net Foreign Exchange ("NFE") which, in view of the methodology for computation thereof as prescribed under Rule 53, imposes a further obligation on SEZ units to export the goods produced by them.

- r. As such, there is a limitation on the quantum of sales that can be made by an SEZ unit in the DTA for consumption in the domestic market. However, in the facts of the present case, DTA clearances by SEZ units manufacturing the PUC are also counted towards fulfillment of positive NFE in view of Rule 53(A)(I) of the SEZ Rules, 2006. There is no compulsion on the producers of the PUC that are based in SEZs to export the goods for the purpose of maintaining positive NFE and neither is there any restriction or limitation to sell the same in the DTA since positive NFE can be achieved through DTA sales. Further, since the tariff heading is 'free', no customs duty is payable on the PUC cleared from the SEZ either. This also makes it abundantly clear that the SEZ units are selling the subject goods in the domestic market without any restrictions and competing in the domestic market of the PUC
 - s. In the Safeguard Investigation concerning Imports of Saturated Fatty Alcohol, the Authority had considered M/s VVF Limited, a 100% EOUs, to be Domestic Industry. The Designated Authority has also regularly considered 100% EOUs to be eligible for inclusion into the scope of the Domestic Industry. For e.g., 100% EOUs have been considered to be part of the domestic industry in the antidumping investigations concerning (a) DPP Red 254 from China PR and Switzerland; (b) Vitamin-A Palmitate from China PR and Switzerland.
 - t. It is to be noted that similar to SEZs, 100% EOUs are also considered to be outside the DTA in as per Para 9.16 of the FTP 2015-20 (which is pari materia FTP 2009-14). Both 100% EOUs and SEZs are similarly situated as they are not considered to be in the DTA and their sales in the DTA are also contingent upon maintaining positive NFE. Therefore, tests that are applicable for gauging the eligibility of 100% EOUs for inclusion into the scope of Domestic Industry should also be applicable for testing the eligibility of SEZ units.
 - u. In the facts of the present case, it is seen that as the SEZ units can achieve positive NFE through domestic sales, there is no restriction on the quantity of sales and neither is there a compulsion to export. SEZ units having no restriction on the sale of like article in DTA are required to be considered as part of the Domestic Industry under section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act, 1975.
 - v. Therefore, DG shall consider the SEZ unit of M/s Mundra Solar PV Limited as part of the Domestic Industry manufacturing the PUC in India and consider its data for the purposes of the present investigation.
 - w. In the safeguard final findings concerning unwrought aluminum and electrical insulators, SEZ units were not considered to be part of the Domestic Industry for the reason that SEZ units were set up in SEZs for the purpose of export, that clearances by the SEZ unit in question was subject to customs duty and that supplying goods from the DTA to an SEZ Unit was considered as an export. This reasoning is incorrect and based on an erroneous understanding of the relevant legal provisions. These decisions are also per incuriam as they did not consider the binding decisions of Allahabad, Gujarat and Andhra Pradesh High Courts.
- (xviii) Assuming that SEZ units cannot be included within the scope of the Domestic Industry and that the scope of the Domestic Industry restricted to only DTA units following decision made in the original investigation, the two applicant DTA units i.e. Jupiter International Ltd ("JIL") and Jupiter Solar Power Ltd ("JSPL") account for a major proportion of the domestic production (after excluding SEZ units).
- (xix) There is no embargo in domestic producers who had not participated in the original investigation from participating in the sunset review as Domestic Industry. As per the

statutory definition under Section 8B(6)(b), the "domestic industry" means the producers as a whole of the like article or a directly competitive article in India or whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India. There is no restriction that only those domestic producers who had petitioned for imposition of measures during the original investigation have to be taken as domestic industry in a sunset review also.

- (xx) Interested parties are also unable to demonstrate that the rationale put forth by the Petitioners for including SEZs within the scope of Domestic Industry is incorrect and they have only relied upon previous Final Findings which have been distinguished and demonstrated by the Petitioners to be per incuriam i.e. in ignorance of settled law and statute. The reliance placed upon the DGTR manual of operating procedures cannot be of any assistance to the opposing interested parties as the same cannot overrule the binding precedents on this issue laid down by the Hon'ble High Courts.
- (xxi) Section 8B only states that the collective output of the like or directly competitive article of the domestic producers who participate in the investigation should constitute a major share of the total production of the said article to be considered as Domestic Industry. Even if MSPVL is not considered within the ambit of Domestic Industry, the combined production of JIL and JSPL in production of the like article in the DTA constitutes a major proportion.
- (xxii) Installed capacity of the subject goods is irrelevant for the purpose of determining standing of the Domestic Industry and the only relevant criterion is actual production.
- (xxiii) Solar modules produced from imported solar cells cannot be considered for the purpose of domestic production of the like article in India. Even solar modules produced from domestically produced solar cells cannot be taken into consideration for the purpose of calculating total domestic production of the subject goods as this would result in double counting of the total production of the like article. This is because domestically produced solar cells will first be accounted for at the time of production by the Solar Cell manufacturers and thereafter, again be counted at the time of arrangement into modules by the domestic module manufacturers. This would lead to counting the same solar cell twice for calculating total output of the PUC in India and is therefore, impermissible.
- (xxiv) Information regarding standalone capacity, production, sales of Jupiter International Ltd. during the POI, date of commencement of its production, exact nature of relationship between Jupiter Solar Power Ltd. and Jupiter International Ltd. and sales and/or purchase transactions of subject goods between these two entities have been provided to the Ld. DG Safeguards has been provided in the Petition and the Confidential version of the Domestic Producers Questionnaire Response filed by Jupiter Solar Power Ltd. and Jupiter International Ltd.
- (xxv) Para 17.12 in the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations of the DGTR states that as long as the applicants in the SSR account for a major portion of the total domestic production, the applicants need not be the same as that in the original investigation.
- (xxvi) Section 8B does not provide that the domestic producers seeking protection by way of safeguard measures should constitute a minimum percentage before they can be considered as a major share. Rather, the statute stipulates that they should account for a major share of the total production of the said article in India.
- (xxvii) Issue regarding what constitutes "a major share" came up before the Dispute Settlement Body of the WTO constituted under the Dispute Settlement Understanding in the case of China - Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Automobiles from the United States wherein it was held that applicants should constitute sufficiently important, serious and significant share of the domestic production for being considered as Domestic Industry.
- (xxviii) The abovesaid observations of the WTO Panel provide decisive guidance in view of the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in the case of Commissioner of Customs,

Bangalore v. G.M.Exports [(2016) 1 SCC 91] wherein it laid down the guidelines for construing and ascertaining the meaning of legislations which have been enacted pursuant to India's international obligations as a result of being a signatory to a multilateral agreement in the nature of the Agreement on Safeguards

- (xxix) Language used in Section 8B(6) of the Customs Tariff Act, 1975, which is the definition clause of Domestic Industry in the Indian legislation incorporating India's obligations under the WTO, also refers to 'a' major share rather than 'the' major share which clearly establishes the intent of the legislature to not restrict the domestic producers to a minimum of 50% of the total domestic production before they are eligible to be considered as Domestic Industry
- (xxx) The facts recorded in the impugned Final Findings with respect to the share in the domestic production of the Petitioners in the DTA considered for the purposes of the present investigation reveals that they accounted for no less than 30-35% of the total domestic production during the period of investigation considered in the present review and as much as 55-60% during the most recent period.
- (xxxi) Present Petitioners based in the DTA have been in existence for a sufficiently long period and have seen the ravages of increased importation which has caused serious injury and forced them to resort to emergency measures. Therefore, Applicants, whether including or excluding SEZ units, are liable to be considered as Domestic Industry of the like and directly competitive article in India as the percentage of production accounted for by them is sufficiently large to qualify as an important, serious or significant proportion of total production.
- (xxxii) JIL does not merely perform incremental job work but has produced the directly competitive article during the period of investigation. It has also produced the directly competitive article through JSPL on a job work basis. Therefore, the activities of JIL do not constitute merely incremental work.
- (xxxiii) Increase in imports is not a requirement in a sunset review. The fact that Rules 5, 6, 7 and 11 apply mutatis mutandis in a review has to be seen in the context of the purpose of review which is stated in both Section 8B(4) of the Customs Tariff Act, 1975 and Rule 18 of the Safeguard Rules. **As per Article 7.2 of the Agreement on Safeguards**, only the procedure for conducting review set out in Articles 2, 3, 4 and 5 will apply. Besides the procedural aspects in these provisions, the requirement of an increase in imports for the initial levy do not apply. Hon'ble Madras High Court has held in the case of *Saint Gobain India Private Limited v. Union of India, Ministry of Finance and Ors* that the agreement to which India is a signatory and in pursuance of which the relevant legislation in this regard has been introduced into the municipal law as well as the purpose of the legislation must be the guiding force while interpreting the Indian law
- (xxxiv) The measure in question came into force with effect from 30 July 2018. In order to assess the situation of the domestic industry post imposition, one has to compare it with the situation that prevailed pre-imposition. Only for the purposes of enabling comparison between pre and post imposition of measure, data for 2016-17 and 2017-18 have been presented.
- (xxxv) Domestic Industry has also procured DGCI&S data for the months of Oct 2019 to Feb 2020 and a non-confidential summary has been provided in the written submissions filed by the domestic industry pursuant to the oral hearing held on 3 July 2020 and the interested parties have got an opportunity of presenting rejoinders thereon.
- (xxxvi) The duties were put in place w.e.f. 30 July 2018. As a consequence of imposition of duties, import volume came down to 8,010 MW during 2018-19. But this decline in imports was very short-lived as imports have demonstrated an increasing trend again.
- (xxxvii) Assuming for that an increase in imports is necessary, from an examination of the three corresponding quarters for 2018-19 and 2019-20, it can be seen that imports have shot up in the 2019-20. Despite imposition of safeguard duty, import volumes of the subject goods have not gone back to earlier levels and are still coming into India at increased levels.

- (xxxviii) It is pertinent to note that while the volume of imports have gone up except the slight dip in volumes experienced pursuant to the levy of safeguard duty in 2018-19, imports prices of the PUC have been on a consistent decline. Despite the imposition of safeguard duty, import volumes of the subject goods have not gone back to earlier levels and are still coming into India at increased levels.
- (xxxix) In response to the imposition of safeguard duties, import prices have gone down further which has reduced the intended effect of the safeguard duty. This is palpable from the fact that the volume of imports have gone up with the sharp drop in import prices in 2019-20 coupled with the fact that the safeguard duty was reduced to 20% w.e.f 01.08.2019 and 15% w.e.f 02.01.2020. Import prices have reduced progressively on a month-by-month basis. Between April 2018 and February 2020, import prices of cell declined by 50% and module by 30%.
- (xl) Though import volumes from China PR reduced post imposition of safeguard duty, they continued to be the largest exporter of PUC to India.
- (xli) After EU withdrew the antidumping and countervailing duties on solar cells and modules against China with effect from 3rd September 2018, exports from China to EU has increased from 5.36% in 2017 to 25.7% in 2019 (1H) and India's share in China PR exports have declined proportionately from 29.6% to 7.3% which coincides with the imposition of SGD by India. This fact clearly demonstrates that the removal of duties by the EU has resulted in an increase of exports to it from China whereas imposition of duties by India has resulted in reduction of exports to it from China PR. If safeguard duty is removed on imports from China, China will start re-exporting the goods in increased quantities to India. Therefore, the contention of interested parties that there is no requirement for China to increase its exports to India is counter intuitive.
- (xlii) Exports of the PUC from China to Thailand and Vietnam have increased after imposition of the safeguard duty by India which is currently in force. Thereafter, a corresponding increase has been witnessed in imports of the PUC from Thailand and Vietnam into India.
- (xliii) Imports from Thailand and Vietnam now account for approximately 12.46% and 11.7% respectively amongst total imports of the PUC into India in the most recent period i.e. 2019-20 (April - September) whereas they accounted for only 0.26% and 0.70% prior to imposition of safeguard duty in 2017-18 despite total imports being higher. Levy of safeguard duty shall be extended to both Thailand and Vietnam since they have increased beyond the threshold requirement of 3% for developing countries.
- (xliv) Article 9.1 of the Agreement on Safeguards provides that safeguard measures shall not be applied against a product originating in a developing country Member 'as long as' its share of imports of the product concerned in the importing Member does not exceed 3%. The use of the phrase 'as long as' establishes embargo on application of safeguard measure shall be in force till such time the import volumes remain within the de minimis level of 3%. Once the de minimis level is crossed, there is no restriction for applying a safeguard measure.
- (xlv) Vide Final Findings in review dated 11th December, 2001 of safeguard measures on Phenol, Malaysia, South Africa and Singapore were included within the scope of the measure pursuant to the review though these countries were not included at the time of the original measure. Similarly, vide Final Findings dated 4th February, 2002 in review of safeguard duty on imports of Acetone, South Africa and Singapore were included within the scope of the safeguard duty pursuant to the review though they had not been included within the scope of the measure at the time of the original levy.
- (xlvi) In a review of safeguard measures conducted by EU on Steel product, developing countries which were excluded from the purview of the original levy were included within its ambit pursuant to the review of the measure. A second review investigation was also conducted by EU and developing countries which were excluded pursuant to the first review were included within its ambit. Therefore, other WTO members have also extended safeguard measures to developing countries pursuant to a review when these countries have exceeded

the de minimis threshold in the most recent period of the review.

- (xlvi) The determination of whether the share of Indonesia in total imports of the PUC may be determined as per DGC&S data for the most recent period which data is available and if the same is de minimis, then it is liable to be excluded.
- (xlvii) M/s Canadian Solar Thailand has compared the total quantity as given in DGC&S data which is an aggregate of different units of measurement. The aggregate total of all such units cannot give any meaningful indicator of the volume of imports. The different units of measurement must be converted into one single unit for the purposes of analysis. The most appropriate unit for the product concerned is wattage, which has been used by the authority in the original investigation also. upon conversion to wattage, imports from Thailand accounts for 12.46% during the most recent period.
- (xlviii) Very purpose of review is to evaluate whether the safeguard duty is required to prevent or remedy serious injury to the Domestic Industry. Therefore, if quantum of imports have increased from other developing countries which were not included within scope of measure pursuant to original investigation, serious injury to Domestic Industry cannot be prevented or remedied if these developing countries which have exceeded the 3% threshold are not included within the scope of the measure that is to be continued.
- (i) Confidentiality has been claimed with respect to data such as economic parameters i.e. production, sales, market share as well as adjustment plan which is business sensitive and confidential in conformity with Rule 7. Adequate non-confidential summary has been provided in lieu thereof to facilitate a reasonable understanding of information. Only where the information was not amenable for summarization has full confidentiality been claimed. The domestic industry has conformed with the requirements of Trade Notice SG/TN/1/97 dated 6th September 1997 and provided indexed figures regarding the relevant economic parameters. Petitioners have also provided complete information regarding its economic parameters in the confidential version as per the prescribed format provided in Trade Notice SG/TN/1/97 dated 6th September 1997.
- (ii) Though Trade Notice No.10 of 2018 is not applicable to safeguard proceedings, the petitioners have conformed with the requirements for making claims of confidentiality provided therein.
- (iii) JIL and JSPL are related entities as JSPL is a subsidiary company of JIL. Therefore, it can be said that there are two group of companies who have filed the present application namely, Jupiter and MSPVL. Therefore, if actual information is disclosed in line with the trade notice assuming that there are more than two domestic producers, then it will result in disclosure of confidential information to the other applicant group company. As a result, the very purpose of the confidentiality is defeated. The combined data for JIL and JSPL has been shared in the petition of the Domestic Industry in the portion where the performance of the Domestic Industry in the DTA has been provided.
- (iv) Petitioners have submitted all indexed figures relating to injury parameters in Section 5 of the application.
- (v) Furthermore, combined installed capacity of JSPL and JIL has been provided without their individual installed capacities for the reason that JSPL has produced the PUC for JIL during the most recent period on job work basis and therefore, their combined capacity becomes relevant rather than their individual capacities.
- (vi) There is no embargo on interested parties to procure DGC&S data on their own and make submissions on such data. The data was received only two days prior to the oral hearing and was sorted a day before the hearing so there was not adequate time to share the non-confidential summary. Summary of DGC&S data has been shared by the Domestic Industry in the written submissions. The Domestic Industry is barred from sharing the raw and unsorted DGC&S data in the public file as the same is confidential as per trade notice no.10 of 2018. Therefore, the interested parties have to procure the unsorted and raw DGC&S data on their own, the procedure for which is laid down in the aforesaid trade notice.

- (lvi) In the present investigation, there are 3 applicants only with one in the SEZ which was excluded in the previous investigation. Therefore, as the possibility existed that the SEZ unit shall be excluded, the data has been provided for both SEZ and DTA units combined as well as for the DTA units and SEZ units separately.
- (lvii) Since JSPL has produced only on job work basis, the actual production and other related data cannot be revealed as the actual data of JSPL and JIL can be ascertained on that basis. This data has not been revealed as the same is business sensitive information and prejudicial to the interests of the petitioners if revealed. A non-confidential summary has been provided by the Domestic Industry in conformity with Rule 7(2) in the form of a trend analysis of the Domestic Industry's performance parameters from the year 2016-17 onwards to facilitate a reasonable understanding of its performance before and after the investigation.
- (lviii) Neither Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975, nor the Rules made thereunder impose an obligation on the Ld. DG Safeguards to analyze whether increased imports were a result of unforeseen developments in a review investigation. Since unforeseen developments and the effect of obligations were already determined as causes which led to the increase in imports which consequently warranted the imposition of safeguard measures, it is not required that the same unforeseen developments and the effect of obligations which led to the increase in imports be re-examined in a review, nor is it likely or even possible for unforeseen development and the effect of obligations (which are not the same as those which were gauged during the original measure) to have led to an increase in imports in the intervening period after the imposition of the measure but prior to its review. During the original investigation, the Director General determined that increase in imports was directly responsible for the serious injury caused to the Domestic Industry of the like and directly competitive article in India.
- (lix) If the Domestic Industry has taken measures to adjust to import competition, the yardstick for gauging whether the safeguard duty should be continued or not should depend on an assessment of whether the economic situation of the Domestic Industry has improved to the extent that there is no threat of serious injury recurring to it despite continuing to face import competition.
- (lx) Of paramount importance is whether the PUC is still being imported in significant volumes, whether such significant volumes are undercutting the prices of the Domestic Industry sans the safeguard levy, whether the installed capacity with the Domestic Industry has not been fully utilized despite adequate demand in the market due to continued significant importation of the PUC, whether the Domestic Industry is able to sell the product in the market or whether its inability due to the influx of imports has led to an increase in inventories.
- (lxi) Only in the context of comparing the situation of the domestic industry post-imposition of measures with reference to a period prior to the imposition, data for the pre-imposition is being considered.
- (lxii) There is no requirement to provide a revised narrative of the Petition as there is no such prescription in law and secondly, the descriptive narrative provided for DTA units in the petitioners' applicant also provide the combined details of the units of the Domestic Industry based in the DTA.
- (lxiii) Share of the domestic industry in domestic production as a range has been provided by the Domestic Industry to all interested parties
- (lxiv) While the demand increased by 35% from 2016-17 to 2019-20 (A), imports maintained their dominant market share. The domestic industry also gained market share in the same period marginally by ***% which evidences that it is adjusting to the market in a positive direction. However, market share of other Indian producers has halved which evidences the fact that the Domestic Industry as a whole is still suffering from serious injury. Actual increase in market share of the Domestic Industry is only ***% which is negligible. The overall market share of all domestic producers in India has dropped from ***% in 2016-17 to ***% in April 19 – Sep 19.

- (lxv) The production and sales of the Domestic Industry has increased as a result of the protection of safeguard duties and due to implementation of its adjustment plan. However, the overall position of domestic producers is fragile as the sales of other domestic producers located in the DTA have dropped sharply.
- (lxvi) The improvement in capacity utilisation is a direct result of imposition of measures and due to the Domestic Industry being able to bring its cost of sales down through implementation of its adjustment plan. However, considering that protection of safeguard duty has been in force for the past two years and the massive demand of the PUC in India, the installed capacity of the Domestic Industry has remained underutilized due to competition from imports which are lowering in prices. The Domestic Industry has not been able to sell its entire production which has led to an increase in inventories. Without the protection of SGD, import prices would undercut the prices of the Domestic Industry and circumscribe its ability to sell its product. This would lead to increased inventories and idling of production facilities and gains made towards this end would be lost.
- (lxvii) The productivity per employee has improved substantially which indicates that the Domestic Industry has improved its efficiency as per its adjustment plan
- (lxviii) Profitability of the Domestic industry turned severely negative in 2018-19. However, with increased production and sales coupled with significant reduction in cost of sales, the Domestic Industry has been able to reduce its losses from 2018-19. However, profitability of the Domestic Industry remains negative and its situation remains fragile.
- (lxix) With respect to the contention by interested parties that profitability differs in 2017-18 shown in the current petition from that in the original investigation, the original investigation consisted of five applicants viz. (i) M/s Mundra Solar PV Limited, (ii) M/s Indosolar Limited, (iii) M/s Jupiter Solar Power Limited, (iv) M/s Websol Energy Systems Limited, and (v) M/s Helios Photo Voltaic Limited whereas in the present investigation, it consists of only (i) M/s Mundra Solar PV Limited, (ii) M/s Jupiter International Limited, and (iii) M/s Jupiter Solar Power Limited. Therefore, it is but obvious that the performance parameters including that of profitability would not be identical. Furthermore, the factum of profits during 2017-18 for the present applicant compared to those of the original investigation which showed negative profitability is not relevant as the impact on profitability as a result of serious injury caused by increased imports displays the same trend for both sets of applicants While profitability of the applicants in the original investigation decreased sharply from -22 in 2016-17 to -107 in 2017-18, that of the present applicants also witnessed a plunge from 100 to 22 though still barely profitable. Therefore, the data provided by the Domestic Industry is reliable as the incidence of the adverse impact of increased imports correlate for both sets of applicants.
- (lxx) Though inventory levels improved in 2018-19, the inventory levels have again witnessed a considerable jump in the most recent period despite the presence of adequate demand.
- (lxxi) Increase in imports at extremely cheap prices during April 19-Sept 19, especially from Vietnam and Thailand have circumscribed the ability of the Domestic Industry to sell its product in the domestic market which has led to the piling up of inventories.
- (lxxii) Without the inclusion of safeguard duty, the prices of imports continue to undercut the selling price of the Domestic Industry. Without safeguard duty, serious injury to Domestic Industry would occur to a much greater degree and improvement in position of Domestic Industry in relation to production, sales, productivity and profitability would be wiped out as users would increasingly switch back to cheaper imports.
- (lxxiii) In sunset reviews, prices of imports shall be examined sans safeguard duty to gauge whether serious injury is likely to recur due to price undercutting if safeguard duty is discontinued.
- (lxxiv) Safeguard duty is not applicable to imports from Thailand and Vietnam which account for approximately 24% of all imports into India during April 2019-Sept 2019. Furthermore, landed value of imports from Thailand and Vietnam are very low. With a substantial portion of the PUC being imported into India without the levy of safeguard duty, imports continue to suppress and depress the prices of the Domestic Industry which has to align its selling prices accordingly.

- (lxxv) As a consequence of price undercutting, the prices of the Domestic Industry were suppressed and depressed which led to downward revision of prices by the Domestic Industry.
- (lxxvi) Thereby, though the margin of price undercutting reduced as a result of the price depressing effects, the losses of the Domestic Industry mounted as it had to sell the PUC at unremunerative prices.
- (lxxvii) Applicants have latest state of the art production facilities and are capable of producing solar cells of latest technologies. In many cases, efficiency of domestically produced solar cells are significantly higher than imported solar cells.
- (lxxviii) Efficiency is not cause of injury. There is a market for domestically produced solar cells and domestic producers are able to sell their production. However, domestic producers have to compete with imported goods in terms of price. Since imports continue to enter Indian market at very low prices, domestic producers are seriously injured.
- (lxxix) Imported goods continue to undercut prices of the domestic industry during Apr-Sep 2019. Low percentage of price undercutting is only because domestic industry has to compete with imports by reducing its prices. Domestic producers are forced to match import prices. Otherwise, they will not get orders.
- (lxxx) Price underselling would be a more appropriate parameter of the extent of injury caused by imports. Import prices have consistently declined and are preventing the domestic industry from realising remunerative prices for the domestic like articles.
- (lxxxi) There are no other known causes for continued serious injury post imposition of safeguard measures.
- (lxxxii) As per the statutory prescription under Section 8B(4), it is not necessary for the Domestic Industry to continue to suffer from serious injury and it is sufficient for the Domestic Industry to show that it has taken measures to adjust to the serious injury suffered by it and upon demonstrating that such serious injury will recur.
- (lxxxiii) 2016-17 and 17-18 have been included for the reason that the performance of the Domestic Industry before and after the imposition of anti-dumping duty can be analyzed in order to facilitate an understanding of their condition before and after the imposition of SGD
- (lxxxiv) The interested parties cannot be allowed to approbate and reprobate at the same time i.e. first contend that the Domestic Industry is not adjusting positively to serious injury and in the same breath, also contend that the Domestic Industry is no longer suffering from serious injury as their economic condition has improved from that during the original investigation. Eleven domestic producers including Indosolar becoming non-operational without any other reason attributable to their closure is clear evidence of the fact that the presence of low priced imports have continued to cause serious injury to the Domestic Industry. Therefore, it is submitted that the contradictory submissions of the interested parties opposing the levy clearly establish that both serious injury due to imports still exists and that the Domestic Industry has adjusted positively to import competition as it has been able to reduce the extent of serious injury that was being suffered by it during the original investigation to a considerable degree.
- (lxxxv) The fact that production facilities of the Domestic Industry are yet to be fully utilized despite the demand supply gap establishes the fact that imports are preventing the Domestic Industry from selling the directly competitive article in the domestic market by undercutting their prices.
- (lxxxvi) No evidence has been provided to substantiate the claim that the PUC produced by the Domestic Industry is inferior or for that matter, that lenders have refused to finance projects which propose to use the domestically produced PUC for the reason that domestically produced cells are of inferior quality
- (lxxxvii) The applicants acknowledge improvements in some performance parameters post imposition but, the position of the domestic industry continues to be in a precarious and fragile condition financially. Though production, sales, capacity utilisation and market

share have increased, the profitability of the Domestic Industry continues to be negative due to continued price pressure from substantial quantities of imports coming into India without the levy of safeguard duty, etc

- (lxxxviii) Lack of vertical integration, increase in installed capacity and leveraging economies of scale which have been cited as factors causing injury to the Domestic Industry all form part of its adjustment plan and details of the same have also been provided in the Domestic Producers Questionnaire Response filed by the applicants.
- (lxxxix) Insofar as allegation regarding low utilization of capacity due to seasonal nature of tenders is concerned, the Domestic Industry has provided its data from 2016-17 to 2019-20 which shows that even over an extended duration of time, the Domestic Industry's capacity remains underutilized despite an exponential increase in demand. Therefore, any injury attributed to tenders being seasonal are controverted by the extended duration over which the performance of the Domestic Industry has been gauged.
- (xc) The various other factors causing injury to the DI that have been cited by M/s Shapoorji Pallonji are not backed by any factual data or evidence and are merely in the realm of surmises and conjecture. Neither the citation, nor the source has been provided to verify the basis of such claims.
- (xci) The domestic producers need more time to adjust to the market situation. These circumstances necessitate the continued imposition of the duties to enable the domestic industry to gain stability and establish itself in the market.
- (xcii) The Domestic Industry requires the protection of SGD in order to alleviate the pressure of low import prices and thereby achieve profitability to be able to implement their adjustment plan.
- (xciii) Imports cater to more than 90% of the demand and have adversely impacted the investments made by the domestic industry.
- (xciv) Article 5.1 does not impose an obligation to consider adjustment plans in the context of imposition of safeguard duty as observed in the report of the WTO Panel in Korea — Dairy. The purpose of levy of safeguard measures is to provide the Domestic Industry with adequate time to adjust to import competition and does not oblige the Domestic Industry to provide an adjustment plan in order to be eligible for protection of the levy.
- (xcv) Rather, the question of adjustment becomes relevant with respect to progressive liberalization of duty which has to be determined by the investigating authority based on an examination of the time required by the Domestic Industry to adjust to import competition.
- (xcvi) Since the very condition for levy of safeguard duty is to prevent or remedy serious injury to the Domestic Industry, evidence of the industry adjusting positively to import competition entails both an improvement in the condition of the Domestic industry as well as an examination of whether the intended effect of the adjustment plan proposed during the original investigation has been achieved to a reasonable extent. In this regard, intended effect of the adjustment plan proposed by the Petitioners during the original investigation was reduction in cost of sales to better compete with low priced imports.
- (xcvii) Petitioners planned to reduce their cost to become cost-competitive with exporters from outside India by taking up a number of steps which included (i) Renegotiation with existing suppliers of raw materials with view to reduce cost of raw material by entering into long term bulk contracts as may be required. (ii) Projects for backward integration by establishing plants for manufacture of wafers and ingots from basic raw material and help realise economics of scale. (iii) Taking up projects for forward integration by establishing facilities for manufacturing modules by those who only have facilities for making cells. (iv) Taking up projects, wherever feasible, for technically superior products using PERC technology or Bi-facial technology. (v) Reduction of cost of conversion primarily by ramping up utilisation of capacity, depending upon the quantum of safeguard duty imposed which would prompt the requisite changes in the market. (vi) Reduction of

financing cost as the cost of borrowing was substantial at the relevant point of time and had a significant impact on the return on capital employed.

- (xcviii) Within one and half years, the domestic producers have achieved a cost reduction of *** - *** cents/watt. The domestic industry achieved a weighted average cost reduction of *** cents/watt. These have been demonstrated in detail in the respective domestic producers questionnaire responses of the applicants.
- (xcix) It must be considered as evidence of the Domestic Industry adjusting. However, due to the continuing fall in prices of imports, the present review has been necessitated as the Domestic Industry has to achieve even more cost saving to be competitive again and to this end, a revised adjustment plan has been provided. Insofar as the constituents of the Domestic Industry having changed are concerned, it is submitted that the relevant criterion is whether the Domestic Industry of the like and directly competitive article is adjusting. Even if producers who had not participated during the original investigation partake in the review, it is sufficient to demonstrate that these domestic producers which are new are also adjusting positively as a result of the protection afforded by the safeguard duty.
- (c) The details of the adjustment plan are confidential in nature as it is business sensitive information and an adequate non-confidential summary thereof that allows for an adequate understanding of steps sought to be undertaken have been disclosed in Annexure 4 of the NCV domestic producers questionnaire response of the applicants.
- (ci) Claim of M/s Canadian Solar Thailand that petitioner companies have not claimed that they have made concrete efforts to meet the six step adjustment process is factually incorrect and contrary to the material on record inasmuch as each of the applicants have provided their revised adjustment plan alongwith the reduction achieved till September 2019 pursuant to the original investigation at Annexure 4 of their respective Domestic Producers Questionnaire Response.
- (cii) While domestic industry is positively adjusting itself to meet import competition, import prices have continued to decline steeply which is continuing to cause serious injury to the domestic industry. Therefore, the domestic industry needs more time to pull itself together to overcome its fragile financial situation caused by increasing imports.
- (ciii) A revised adjustment plan has been prepared and provided to the Director General by each petitioner company taking into account their own peculiar facts and cost structure.
- (civ) The adjustment plan is in line with the earlier one tendered during the original investigation but the cost reductions and other measures sought to be achieved have been revised in view of the further fall in import prices.
- (cv) Interested parties have failed to appreciate that safeguard duty was sought for a period of four years during the original investigation and had submitted the adjustment plan according to the said time line. Therefore, the fact that the revised adjustment plan is more or less in line with the earlier adjustment plan is only logical and should come as no surprise to these interested parties.
- (cvi) The present adjustment plan has clearly achieved substantial cost reductions whereas certain steps such as R&D to develop and adopt new technologies are yet to be achieved as the Domestic Industry is still suffering from losses due to a resurgence in imports at prices which have lowered further. Further steps towards an adjustment plan which has already been successful to a large extent in order to achieve additional cost savings is a viable plan.
- (cvii) With respect to the contention that the reduction in cost of sales is due to decline in prices of silicon wafers, the decrease in cost of sales was a result of lower cost savings achieved through the adjustment plan. Otherwise, the Domestic Industry would not have been able to reduce the gulf between imports prices and NSR of Domestic which existed before the imposition of SGD pursuant to the original investigation if the only determining factor for prices internationally was raw material price. In case raw material was the only determining factor for price, the difference between imports and the NSR would have remained the same pre and post levy of SGD.

- (cviii) Insolvency of Indosolar can be attributed to the fact that though the preliminary findings dated 05.01.2018 of the Director General in the original Final Findings recommended 70% provisional safeguard duty on a finding that critical circumstances exist for the levy thereof, due to a stay obtained from the Hon'ble Madras High Court in a frivolous litigation initiated by a solar power developer viz. M/s Shapoorji Pallonji resulted in a stay upon imposition of provisional duty till 16.04.2018. Thereafter, despite the recommendation to impose final SGD and the consequential notification levying the same, the levy could not be given effect to due to the stay dated obtained by M/s ACME Solar Holdings in WP 12817 of 2018 which led to issuance of Instruction No.12/2018 whereby it was decided not to insist on payment of safeguard duty at the time of clearance of the PUC till further orders of the Hon'ble Orissa High Court. Stay was finally vacated by the Hon'ble Supreme Court vide order dated 10.09.2018 in SLP (c) 24009-10 of 2018. Due to the prolonged delay in imposition of SGD despite the Director General already having determined under Rule 9 of the Safeguard Rules that critical circumstances existed where delay in the imposition of provisional duty would lead to damage which would be difficult to repair as far back as 05.01.2018, the SGD could not be levied due to frivolous litigation by members of the SPDA. Consequently, as no provisional safeguard duty could be imposed due to the stay on the preliminary findings, the inevitable outcome of the delay in the imposition of SGD was that M/s Indosolar continued to suffer from serious injury during the pendency of the original investigation and thereafter also which pushed it beyond the brink of being able to salvage its operations and implement its adjustment plan. Furthermore, serious injury suffered by other domestic producers before imposition of safeguard duty ultimately proved to be grievous and therefore, this only reinforces the fact that continuation of safeguard duty is required. Therefore, this fact clearly establishes that discontinuation of SGD measures, which have demonstrated their efficacy by an improvement of all economic parameters of the Domestic Industry, would damage the Domestic Industry again which would be difficult to recover from.
- (cix) Since India aims to generate 100 GW of solar power generation by 2022 for achieving India's commitments under the Paris Agreement which calls for reduction by 33-35% of CO2 emissions by the year 2022, the domestic industry have made significant investments in expanding installed capacity. However, the prevailing imports prices would result in the imported PUC capturing the entire domestic market and destroy the domestic industry in the process.
- (cx) The continuation of safeguard duties will provide an incentive for continuous investment, capex expansion and reduction in cost by achieving the economies of scale.
- (cxi) Continued imposition of safeguard duty is also in the larger public interest and non-levy of safeguard duty would be against the public interest of India because local manufacturing will cease to exist and Rs. 11,000 Crores investment will become insolvent and result in mass unemployment. Effect of continued imports on Domestic Industry is palpable from the closure of a number of domestic producers. Already existing skewed import dependence of Government of India will continue to inflate exponentially as India was China's top export destination to the extent of US\$ 4.1 billion in FY 2017-18 and imports from China declined to some extent only after the imposition of Safeguard Duty.
- (cxii) Considering that domestic cell manufacturers are facing an imminent threat to their existence, not continuing of safeguard duty shall result in complete erosion of the domestic cell manufacturing base and solar module manufacturers will become entirely dependent on imported solar cells for manufacturing modules. The fall in landed prices of solar cells arranged in modules has been much higher than that of only solar cells. Upon total winding up of domestic cell manufacturing operations in India, module manufacturers will be at the complete mercy of exporters who would then be in a position to dictate prices and can simply increase the prices of solar cells making module manufacturers uncompetitive as well. This will have a cascading effect on other upstream and downstream industries involved in the manufacture of equipment for solar modules such as EVA Sheets and solar glass and destroy India's solar equipment manufacturing capabilities entirely.

- (cxiii) Not protecting the Domestic Industry when it has been adjusting positively under the protective umbrella of safeguard duty would be against the Hon'ble Prime Minister's make in India campaign.
- (cxiv) Though detailed guidelines have been issued in this regard by the MNRE vide office memorandum dated 22.07.2019, the projects envisaged thereunder are yet to take off and any tangible benefits released as a consequence thereof. As the domestic producers have not yet benefitted from the KUSUM program, the protection of safeguard duty is required. Furthermore, Domestic Producers also intend to supply to entire domestic market. The imposition of safeguard measures will ensure that the Domestic Industry can supply to the entire domestic market at large, become competitive and not solely dependent on KUSUM program for its survival.
- (cxv) As India has made commitments under ITA-1, it is prevented from increased the BCD. As long as effective rate remains zero, fact that BCD has been increased to 20% is of no consequence. There is no embargo on both SGD and BCD being levied simultaneously.
- (cxvi) SGD is only a tariff measure and therefore, there is no embargo on meeting the demand supply deficit through imports. That imports of the PUC have not abated despite the levy of SGD which clearly evinces that demand supply gap is being met through imports. SGD only increases prices and does not prohibit importation unlike quantitative measures.
- (cxvii) Public interest does not cover only the immediate interests of users and consumers of the product in question. The long term public interest would be served only when Indian power sector is capable of meeting its capital equipment requirements from within and not dependent on imports.
- (cxviii) The purpose of SGD is to protect and remedy serious injury suffered by the Domestic Industry due to increased import competition. Whether a measure is in public interest has to be determined by considering the intent and purpose of the legislation under which the said determination is being made. If the SGD is capable of achieving the aforesaid objective, the levy must be considered as being in public interest.
- (cxix) With respect to the contention that technologically advanced solar cells such as PERC and Bi facial are only produced by MSPVL which is excluded, M/s MSPVL is liable to be considered as Domestic Industry. Variations of PUC produced by it are very much a result of technological capabilities of Domestic Industry. If only DTA units are considered, since JSPL and JIL were older units than MSPVL which started its production in 2017, further research and development and investing in capex for installing production facilities with newer technologies require a venture to be profitable. In the wake of increased import competition, the profitability of JIL and JSPL was severely impacted which prevented them from taking steps in this regard. Despite imposition of SGD and improvement in financial position, the Domestic Industry is yet to become profitable again and therefore, it has not been able to invest in R&D and acquire new technologies. However, Domestic Industry has taken concrete steps towards realizing its adjustment plan which has resulted in a large part of it being implemented. Once the Domestic Industry is able to become profitable again with the help of SGD, it will be able to invest further in this front. Therefore, protection of SGD is required to be extended as imports continue to undercut the prices of the Domestic Industry and continue to put immense pressure on the ability of the Domestic Industry to sell its production for a reasonable price.
- (cxx) Reliance upon Methyl Acetoacetate is misplaced as SGD was not found to be in public interest in said case as Domestic Industry had utilized its production facilities for manufacturing products other than PUC and claimed loss of market share as a result of import competition. Furthermore, it was found not to be in public interest as no documentary evidence had provided regarding impact on the downstream industry. price undercutting was also negative which would render imported goods much costlier than domestically produced PUC and create unfair market condition. Finally, no serious injury and threat or even a threat thereof was found to the Domestic industry. In present case, serious injury had already been determined pursuant to original investigation. However, CCCME has failed to appreciate that in the present case, the Domestic Industry has

provided evidence that the Central Government has taken steps to balance the interests of affected power developers with the Ministry of New and Renewable Energy having notified a pass-through facility vide Notification F. No. 283/3/2018-GRID SOLAR dated 02.04.2018 which provides a clarification on “change in law” clause of the agreements. Thereafter, the Ministry of Power has also issued directions to the CERC on 27.08.2018 for allowing pass through of safeguard duty paid on imported solar cells and modules. In pursuance thereof, certain Solar Power Developers have also been allowed pass through of the additional safeguard duty borne by them on the imported PUC and the evidence of the same was attached as Exhibit 389 in the written submission of the Petitioners. Therefore, Central Government has taken adequate steps to safeguard interests of solar power developers.

- (cxxi) Regarding impact on ultimate consumer, Domestic Industry had quantified impact of 95% safeguard duty on prices of power in their submissions during original investigation and same was also taken into consideration by Director General who determined that actual impact would be somewhere in between that suggested by Domestic Industry and that by opposing parties. Thereafter, DG had recommended 25% safeguard duty which was found to be in public interest after considering impact on ultimate consumer. In present case, SGD sought is much lower than original investigation.
- (cxxii) PUC produced by the Domestic Industry adheres to the applicable BIS norms. Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Components Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2017 prohibits manufacture, store for sale, sale or distribution of photovoltaic cells which do not conform to the Specified Standard. Had the product sold by applicants not conformed to applicable BIS norms, they would not have been able to manufacture, store or sell the PUC.
- (cxxiii) M/s SPDA and M/s Canadian Solar Thailand have themselves referred to the factum of closure of many domestic producers producing the directly competitive article in India. Therefore, the question of taking unfair advantage of trade remedial measures does not arise and a clear case is made out for their continuation.
- (cxxiv) Safeguard duties, which are interim measures, provide for the domestic industries to calibrate their position in their industry on being faced with international competition.
- (cxxv) Level of safeguard duty afforded pursuant to the original investigation did not provide full protection necessary for Domestic Industry to achieve desired objective of fully implementing adjustment plan. As the safeguard duty is already very low, level of liberalization sought is much lower so that Domestic Industry can achieve revised cost savings planned in the present review.
- (cxxvi) WTO Appellate Body Report in Ukraine – Definitive Safeguard Measures on Certain Passenger Cars cannot be relied upon to contend that liberalisation of duty is intended to have substantial reduction of duty at regular intervals as the Appellate Body only held that progressive liberalisation of the duty cannot be delayed and put off to a later date and the same has to be liberalized at regular intervals. Nowhere is it observed that extent of liberalization should be substantial, nor minimum extent of liberalization required at regular intervals.
- (cxxvii) The quantum of reduction and duration of levy depends on the extent necessary to facilitate positive adjustment of the Domestic Industry.
- (cxxviii) Exclusion of M/s MSPVL was not the reason for the downward revision of SGD to 25%. injury margin during original investigation was higher than amount of SGD recommended and can be verified from records of original investigation.

(C) EXAMINATION & FINDINGS OF DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)

31. Based on the (a) information presented in the petition by the domestic industry, additional information presented by various interested parties, various submissions made by the interested parties and other primary and secondary records available, and (b) verification of information and evidence presented by the interested parties to the extent considered necessary, I have examined the same and record my final finding as under:

a) Applicable legal provisions

32. The first proviso to Section 8B(4) of the Customs Tariff Act, 1975 provides that *if the Central Government is of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed, it may extend the period of such imposition. The second proviso states that in no case the safeguard duty shall continue to be imposed beyond a period of ten years from the date on which such duty was first imposed.*

33. Rule 18 of the Rules states as follows:

(1) The Director General shall, from time to time, review the need for continued imposition of the safeguard duty and shall, if he is satisfied, on the basis of information received to him, that -

- (i) safeguard duty is necessary to prevent or remedy serious injury and there is evidence that the industry is adjusting positively, it may recommend to the Central Government for the continued imposition of duty;*
- (ii) there is no justification for the continued imposition of such duty, recommend to the central Government for its withdrawal.*

Provided that where the period of imposition of safeguard duty exceeds three years the Director General shall review the situation not later than the mid-term of such imposition, and, if appropriate, recommend for withdrawal of such safeguard duty or for the increase of the liberalization of duty.

(2) Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding 8 months from the date of initiation of such review or within such extended period as the Central Government may allow.

(3) The provisions of rules 5, 6, 7 and 11 shall mutatis mutandis apply in the case of review.

34. Rule 4(5) of the Rules enjoins a duty on the Director General Safeguards *to review the need for continuance of safeguard duty.* A perusal of the above provisions shows that in a review, the Director General (Safeguards) is required to examine the evidence and to determine that -

- (a) it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed to prevent or remedy serious injury; and
- (b) that the domestic industry is positively adjusting i.e. whether the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof.

35. The investigation has been conducted in accordance with the said rules and the final findings are recorded through this notification.

b) The Product Under Consideration (PUC)

36. The product under consideration in the original investigation was defined as follows:

“Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” classifiable under Tariff Heading 8541 and Tariff Item 85414011 of the Customs Tariff Act, 1975. Solar Cells are also known as Photovoltaic Cells in the market parlance. Photovoltaic technology enables direct conversion of sunlight into electricity at the atomic level and Solar Cells are solid state electrical devices that convert sunlight directly into electricity by the photovoltaic effect. For practical use, Solar Cells are packaged and connected into an assembly and such an assembly of Solar Cells is referred to as a Solar Panel or Solar Module. The electrical connections are made to the Solar Cells in series to achieve desired output wattage and / or in parallel to provide a desired current capability.”

37. As noted earlier, the Customs Tariff Heading "8541 4011- Solar cells, whether or not assembled in modules" is split into the following two headings, vide Section 117(b) of the Finance Act 2020 (No.12 of 2020) read with entry No.2 of Schedule III thereof w.e.f. 01.02.2020:

8541 4011- Solar Cells, not assembled

8541 4012- Solar Cells assembled in modules or made up into panels

38. Vide customs notification No. 1/2020-Customs (SG) dated 2 February 2020, the two new tariff headings mentioned hereinabove were substituted in the place of single tariff heading in the earlier customs notification No. 1/2018-Customs (SG) dated 30 July 2018.

39. Thus, the existing safeguard duty is applied on “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” classifiable under the Tariff Headings 85414011 and/or 85414012 of Chapter 85 of Schedule I of the Customs Tariff Act 1975. The Customs tariff classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the product under consideration.

40. Various interested parties opposing the review have submitted that Solar Cells and Solar Modules can not be treated as the same and that the domestic industry does not possess Thin-film technology and “PERC” (Passivated Emitter Rear Cell) based technology, Bi-facial N-type solar cells, 5 and 6 bus bar High efficiency solar cells and mono crystalline technology and therefore, the PUC should be restricted to only such products for which the DI has production capability or has actually produced.

41. Further, REC Solar PTE Ltd. has claimed that their Alpha product has been awarded a design patent by Singapore and other territories including Europe and that its design application is also pending in India. REC Solar claims that their Alpha product (i) uses proprietary advanced technology, is of superior quality, space efficient, and more environmental friendly, (ii) commands a higher price in the Indian market and (iii) is neither identical nor alike in all respects to the articles manufactured in India. They seek exclusion of their Alpha product from the scope of the PUC as they hold certain design patents for it and have relied upon the observations made in Anti-Dumping duty investigation concerning imports of *Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel* from China PR, Japan, Korea, European Union, South Africa, Taiwan (Chinese Taipei), Thailand and USA dated 24 November 2009 for this purpose.

42. On carefully examining this aspect, I note that Solar cells of various types produced by different technologies vary in terms of efficiency, physical characteristics like size and weight etc., and price. These variations though lead to trade off in price and efficiency, the end-use of the PUC is only to produce power. Insofar as the reliance on the Final Findings in Anti-Dumping duty investigation concerning imports of *Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel* from China PR, Japan, Korea, European Union, South Africa, Taiwan (Chinese Taipei), Thailand and USA is concerned, I have noted that specific grades of the PUC which the Domestic Industry were not producing were excluded as these grades were required for specific end use applications which could not be substituted by the like article produced by the Domestic Industry. In the present case, besides submitting that the Alpha Product is of superior quality, space efficient, uses proprietary advanced technology and is more environmental friendly, it has not been the case of the interested party that their product is not in direct competition with and is not commercially substitutable by the domestic like product.

43. In the Final Findings dated 9th December, 2016 in the Anti-dumping investigation concerning imports of Seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel from China PR, the authority held that patented goods and other sub category cannot be excluded from the scope of PUC as long as they are technically and commercially substitutable with the domestic like goods and any such exclusion will lead to circumvention.

44. The Rules hold a domestic producer as “a producer of the like article or directly competitive article in India or a trade or business association, a majority of members of which produce or trade the like article or directly competitive article in India” and “like article” defined as “like article means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation.” The common and overlapping applications of the PUC i.e. conversion of sun light directly into electricity by the photovoltaic effect, establishes that imported and domestically produced subject goods are directly competitive. The variations in technology only lead to a trade off in price and efficiency. This, therefore, does not warrant any exclusion from the scope of PUC as stated in the initiation notification. Further, these issues were also dealt in the original finding and therefore I find no merit in the contention of the interested parties regarding exclusion of certain grades or variants of the PUC and uphold and confirm the scope of PUC as considered and mentioned in the original investigation.

45. Taking into account the change in the customs tariff headings, the PUC is defined as follows:

“Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” classifiable under Tariff Heading 854140 and Tariff Items 85414011 and 85414012 of the Customs Tariff Act, 1975. Solar Cells are also known as Photovoltaic Cells in the market parlance. Photovoltaic

technology enables direct conversion of sunlight into electricity at the atomic level and Solar Cells are solid state electrical devices that convert sunlight directly into electricity by the photovoltaic effect. For practical use, Solar Cells are packaged and connected into an assembly and such an assembly of Solar Cells is referred to as a Solar Panel or Solar Module. The electrical connections are made to the Solar Cells in series to achieve desired output wattage and / or in parallel to provide a desired current capability.

The Customs tariff classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the product under consideration”.

c) Scope and Standing of Domestic Industry (DI)

46. Clause (b) of sub-section (6) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 defines Domestic Industry (hereinafter also referred to as the "DI"), as follows:

‘(b) “Domestic industry” means the producers -

- i. as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or*
- ii. Whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India’*

47. As regards scope and standing of the DI, the original final findings dated 16.07.2018 and the initiation notice dated 03.03.2020 has already clarified that SEZ units are outside the scope of the DI. The scope of DI in the review is also limited to units in DTA.

48. The review application is filed by ISMA on behalf of (i) M/s Mundra Solar PV Limited, Adani House (SEZ); (ii) M/s Jupiter Solar Power Limited (DTA); (iii) M/s Jupiter International Limited (DTA). The DGTR in this case has limited the Domestic Industry only to 2 DTA units i.e. M/s Jupiter Solar Power Limited and M/s Jupiter International Limited in accordance with the original findings dated 16.7.2018. With regard to the production of JIL and JSPL, the Director General found the following:

- (i) JIL and JSPL are DTA units and belong to the same group. JSPL is a subsidiary of JIL.
- (ii) JSPL was an applicant in the original investigation. JSPL was producing on its own account during 2016-17 and 2017-18. JSPL also got solar cells produced by JIL on job work basis during 2016-17, 2017-18 and 2018-19. Since March 2019, JSPL did not produce on their own account but produced only on job work basis for JIL. JIL is producing on its own account and also getting the produced on job work basis through JSPL.
- (iii) Some interested parties have contended that JSPL has done only incremental job work. However, it is found that JSPL has carried out all production activities as it has produced solar cells from wafers supplied by JIL. It is also found that JIL has produced solar cells on its own account as well as got them produced by JSPL on job work basis.

The 2 DTA units account for a major share of total domestic production (more than 50%) in India of the PUC. For the purpose of computing the share, the production by SEZ Units has been excluded as stated above.

d) Period of Investigation

49. At the time of initiation, the period of investigation (POI) for the present investigation was considered as 1st April 2016- 31st March 2017, 1st April 2017- 31st March 2018, 1st April 2018- 31st March 2019 and 1st April 2019-30th September 2019. The said period was considered as long enough to take into consideration the market conditions and other factors that are relevant for ascertaining the need for continued imposition of Safeguard Duty.

e) Source of Information

50. At the time of initiation, the DI had provided transaction-wise import data for the PUC from Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S), Department of Commerce for the period 2014-15 to 2019-20 (up to September 2019) and the same was taken into consideration for analysis at the time of initiation. The DI has later provided DGCI&S import data up to February 2020. The Post-POI import data has also been considered from 1st October 2019 to 28th February 2020. The data provided by the applicant has been verified on the basis of data received from the DGCIS and desk study by referencing the certified financial records submitted by DI.

f) Confidentiality and information submitted

51. The DI have provided some information in their application on confidential basis and has requested that it be treated as confidential. The DI have also provided a non-confidential version (NCV) of their application, as required under Rule 7 of the said Rules read with Trade Notice dated 21.12.2009 issued by Director General (Safeguards) under File No. D-22011/75/2009. Further, the DI have submitted reasons justifying their claim of confidentiality of this information.

52. In terms of Rule 7 of the said Rules, the applicant may choose not to disclose information which is by nature confidential and provide a non-confidential summary thereof. The DI have submitted reasons for claiming confidentiality of the information and furnished a non-confidential summary of the information filed on confidential basis. Some of the interested parties have claimed that the guidelines for disclosure of information in confidential and non-confidential version of the petition in Annexure I of Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018 issued by the DGTR has not been observed by the DI while filing the petition.

53. The claims of the DI regarding confidentiality along with the reasons furnished for such claim have been considered in accordance with the requirements of Rule 7. The applicant has provided the NCV of the application as per the established-practice which was made available to all the interested parties

g) Nature and quantum of import

54. Some of the interested parties have claimed that Rule 5 of the Rules requires that for any initiation of investigation, the Director General must find an increase in imports. In particular, clause 5(3) requires that the Director General shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1) unless he examines the adequacy and accuracy of the evidence provided in the application and satisfies himself that there is sufficient evidence regarding increased imports. Since there have been no increase in imports, there is no basis to impose Safeguard Duty.

55. I observe that the criterion of increased imports would not be applicable in a review as the purpose of review, as per Rule 18, is to assess whether a continued imposition of Safeguard duty is necessary to prevent or remedy serious injury and there is evidence that the industry is adjusting positively.

56. The quantum of imports needs to be examined keeping in mind the impact of the safeguard measure already in force and whether the imports would continue to injure the domestic industry, if the safeguard measure was removed. In this regard, it is to be noted that even after imposition of safeguard duty, import volumes of the subject goods have not gone back to earlier levels but are still coming into India at increased levels. The actual imports in 2017-2018 were 9790 MW which remained at 8010 MW in 2018-19 and 8545 MW in 2019-20. (Annualized -Actual data considered till February 2020)

57. Imports were 6,375 MW in 2016-17 and it increased to 9,790 MW in 2017-18. The duties were put in place w.e.f. 30th July 2018. As a consequence of imposition of duties, import volume came down to 8,010 MW during 2018-19. But this decline in imports was short-lived as the import volume for the most recent period i.e. 2019-20 (Annualized- Actual data till September 2019) was 8,754 MW.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (A)	April 19 – Sep 19
Cells	MW	785	1,280	2,024	2,588	1,294
Modules	MW	5,590	8,510	5,986	6,167	3,083
Total Imports	MW	6,375	9,790	8,010	8,754	4,377
Trend	MW	100	154	126	137	

58. It is noted that even if the base year of the injury period is considered, imports have grown by 2379MW i.e. an increase of 37%. Furthermore, Imports of 4,377 MW made during first half of FY 2019-20 were lower than 4,917 MW imported during the corresponding period of FY 2017-18. While there was no safeguard duty during the first half of FY 2017-18, imports during the first half of FY 2019-20 were subjected to a Safeguard duty of 25% from 1st April to 29th July 2019. Therefore, the import volumes reduced by 1780MW in 2018-19. However, with the liberalization of safeguard duty to 20% w.e.f, 30th July 2019, imports have again demonstrated an upward trend and have increased by 744MW in 2019-20(A) i.e. an increase of 9%.

59. It is also relevant to note that increase has been witnessed in imports of the PUC from Thailand and Vietnam into India which now account for approximately 12.46% and 11.7% respectively amongst total imports of the PUC into India in the most recent period i.e. 2019-20 (April - September) whereas they accounted for only 0.26% and 0.70% respectively prior to imposition of safeguard duty in 2017-18 despite total imports being higher. Furthermore, the prices of imports from Thailand and Vietnam have also reduced drastically and are much lower than the prices of imports from China PR, which are also subject to safeguard duty @ 15% currently over the import price in Rs./watt as demonstrated below:

Row Labels	Unit	2017-18	2018-19	2019-20 (April - September)	2019-20(A)
CHINA PR	Rs./watt	21.76	17.49	15.58	15.58
THAILAND	Rs./watt	18.53	9.33	10.58	10.58
VIETNAM SOC REP	Rs./watt	10.59	12.87	11.13	11.13

60. In fact, import prices from Thailand and Vietnam have been undercutting prices of the Domestic Industry even after imposition of safeguard duty.

g) Unforeseen developments and the effect of obligations

61. Some of the interested parties opposing the review filed by DI have contended that in the case of a review also, a safeguard measure may be continued only if there is evidence of increased imports causing serious injury to domestic industry and such increase in imports must have occurred as a consequence of unforeseen developments as provided in Article XIX:1(a) of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). In this regard, it has been pointed out by these interested parties that no information regarding unforeseen developments or the effect of obligations has been filed by the DI at the time of making the application. In this regard, I observe that unforeseen development and the effect of obligations are necessary preconditions for imposition of Safeguard Duty at the time of the original measure only as is the observation that increase in imports is not a necessary criterion as the Rules require two issues i.e. whether the safeguard duty is necessary to prevent or remedy serious injury and there is evidence that the industry is adjusting positively to be examined. Therefore, neither is an increase in imports a necessary precondition for continuation for safeguard measures, nor is such increase in imports required to have been caused by unforeseen developments or the effect of obligations which are the requirements for justifying the imposition of the original measure only.

62. It is reiterated that in the determination made in the original Final Findings, it was observed that the increase in imports during the relevant injury period in the investigation was as a result of unforeseen developments and the effect of the obligations incurred by India under the GATT. I do not consider it is required to revisit the issue in the present review.

h) Serious injury and/or threat of serious injury

63. The next matter for determination is whether extension of safeguard duty is necessary and whether imports of the PUC have continued to cause serious injury to the DI of like or directly competitive products or to prevent or remedy serious injury which may result as a consequence of the discontinuation of duties. The examination of injury to the DI of the PUC includes examination of various parameters such as DI's sales; production; capacity utilization, market share vis-à-vis imports amongst others as stated below;

- (i) **Share of domestic market:** It can be seen from the table below that while the demand increased by 34% from 2016-17 to 2019-20 (A), imports maintained their dominant market share. The domestic industry also gained market share in the same period marginally by 1.1% evidencing that it is positively adjusting

Market Share in Demand	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (Annualized)	April 19 - Sep 19
Imports	% (Indexed)	100	101	105	102	102
Domestic sales by the DI	% (Indexed)	100	88	60	124	124
Domestic sales by other Indian producers	% (Indexed)	100	84	36	49	49
Demand/Consumption	MW (Indexed)	100	152	120	134	67

- (ii) **Production and Sales:** From the table below representing the production and sales of the Domestic Industry and total imports of the PUC, it is noted that though the production and sales of the Domestic Industry have increased as a result of the protection of safeguard duties and due to implementation of its adjustment plan, however, the overall position of domestic producers continues to be fragile as the sales of other domestic producers, other than SEZ, have dropped.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (A)	April 19 - Sep 19
Total imports	MW	6,375	9,790	8,010	8,754	4,377
Production of DI	MW (indexed)	100	129	64	170	85
Sales of DI	MW (indexed)	100	134	72	166	83
Sales of Other Indian Producers	MW (Indexed)	100	128	43	66	33

- (iii) **Capacity utilisation** The capacity utilisation of the DI increased from 44% in 2016- 17 to 75% in 2019-20 (A). However, considering that the protection of safeguard duty has been in force for the past two years and the massive demand of the PUC in India, the installed capacity of the Domestic Industry continues to remain underutilized due to competition from imports.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (A)	April 19-Sept. 19
Installed Capacity	MW (Indexed)	100	100	100	100	50
Production of DI	MW (Indexed)	100	129	64	170	85
Capacity Utilisation	%	44%	57%	28%	75%	75%

- (iv) **Employment and Productivity:** The employment generated by the DI has dropped during the injury analysis period.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (A)	April 19-Sept. 19
No. of employees	No. (Indexed)	100	96	69	69	69
Productivity per employee	MW (Indexed)	100	135	94	249	125

(v) However, the productivity per employee has improved substantially which indicates that the Domestic Industry has improved its performance as per its adjustment plan.

(vi) **Profit / Loss:** It can be seen that the profitability of the Domestic industry turned negative in 2018-19. However, with increased production and sales coupled with reduction in cost of sales, the Domestic Industry has been able to reduce its losses from 2018-19. However, it is noted that the profitability of the Domestic Industry remains negative and its situation remains fragile.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (A)	April 19-Sept. 19
Profit/ Loss	Rs./Watt (Indexed)	100	22	(204)	(18)	(18)
Domestic Sales Price	Rs./Watt (Indexed)	100	78	40	37	37
Cost of sales	Rs./Watt (Indexed)	100	90	95	49	49

(vii) **Inventory:** Though inventory levels improved in 2018-19, they have sharply increased in the most recent period i.e. in 2019-20(A) as indicated in the table below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (A)	April 19-Sept. 19
Inventory	MW (Indexed)	100	120	11	272	141

(viii) **Price Undercutting:** It can be seen that without the inclusion of safeguard duty, the prices of imports continue to undercut the selling price of the Domestic Industry and cause serious injury to it .

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	April 19-Sep 19
Landed Value of Imports					
Solar Cells	Rs./Watt	15.42	13.68	8.95	8.76
Solar Modules	Rs./Watt	29.20	22.56	19.10	16.80
Net Sales Realisation of DI					
Solar Cells	Rs./Watt (Indexed)	100	78	39	37
Solar Modules	Rs./Watt (Indexed)		100	61	57
Price Undercutting					
Solar Cells	Rs./Watt (Indexed)	100	59	6	4
Solar Modules	Rs./Watt (Indexed)		100	4	15

Price Undercutting (%)					
Solar Cells	% Range	55-65	35-45	5-15	0-10
Solar Modules	% Range		35-45	0-10	5-15

Some interested parties have raised an objection with respect to the price undercutting analysis stating that the price undercutting should be analyzed after addition of safeguard duty into the landed value of the PUC. In this regard, it is noted that this being a review to examine the extension of safeguard duty to prevent recurrence of injury the impact of imports without Safeguard Duty needs to be evaluated.

i) Post POI trend

64. During the first three quarters of 2019-20, imports have increased by 33% compared to the first three quarters of 2018-19. Further, the increase in import volume was also coupled with a decline in import prices. The value and per unit price of imports during the period of investigation including the post-POI period is tabulated below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	Apr-Sep 2019	Apr-19 to Feb-20	2019-20 (Annualised)
Cells	Rs. in Lacs	121,126	175,202	181,155	113,301	207,785	226,675
Cells	Rs./watt	15.42	13.68	8.95	8.76	7.91	7.91
Modules	Rs. in Lacs	1,632,107	1,920,223	1,143,368	517,875	849,750	927,000
Modules	Rs./Watt	29.2	22.56	19.1	16.8	16.32	16.32
Total	Rs. in lac	1,753,233	2,095,425	1,324,523	631,176	1,057,535	1,153,675
Total	Rs./watt	31.29	34.10	27.50	21.40	16.54	14.42

65. The weighted average import price per watt has declined from Rs.27.5 during 20-16-17 to Rs.13.5 during 2019-20. The monthly trend of import prices show a further decline during the last few months as shown in the table below:

	Cells	Modules		Cells	Modules
FY2018-19	8.95	19.10	FY2019-20	7.91	16.32
2018-04	12.08	22.40	2019-04	8.61	17.36
2018-05	11.96	23.26	2019-05	8.92	16.00
2018-06	9.73	22.61	2019-06	9.04	16.29
2018-07	8.50	21.83	2019-07	9.03	15.97
2018-08	8.26	20.93	2019-08	8.70	17.76
2018-09	8.06	20.02	2019-09	8.25	16.82
2018-10	8.07	19.75	2019-10	8.30	15.85
2018-11	7.91	18.02	2019-11	7.61	16.02
2018-12	7.77	17.24	2019-12	6.91	15.18
2019-01	8.24	17.09	2020-01	6.84	14.86
2019-02	8.87	17.62	2020-02	6.11	14.86
2019-03	8.92	16.94			

As may be seen from the table above, solar cell import prices have come down from Rs.11.96 per watt in April 2018 to Rs.6.11 per watt in February 2020. During the same period, import prices of modules came down from Rs.23.26 per watt to Rs.14.86 per watt.

j) Margin and Threat of Injury

66. For the purpose of evaluating existence of injury, a Fair selling price (FSP) has been computed by considering an appropriate reasonable return on the Cost of Production. The margin of injury has thereafter been computed as difference of landed value of imports of Solar cells and the FSP. An analysis of the data during the most recent period i.e 1.4.19 to 30.9.19 of POI indicates that the landed prices of imports continue not only to undercut the Net Sales Realization (NSR) of the Domestic Industry but also are preventing the DI to realise a fair price. Furthermore, the inventories of the Domestic Industry have also witnessed a sharp rise in the most recent period. Therefore, if the safeguard duty is removed now, the users of the PUC will increasingly switch back to imports of PUC to levels received at the time of initiation of subject investigation. Consequently, the serious injury that was being suffered by the Domestic Industry would recur as the profitability of the Domestic Industry continues to be negative and the progress made by DI would be nullified.

k) Causal link

67. As per Rule 11(1), it is required to determine whether a causal link exists between imports of the PUC and the serious injury or threat thereof to the Domestic Industry of the like competitive product. In this regard, the observations by the WTO Panel in Korea-Dairy which sets forth the basic approach for determining “causation” has been noted. Therefore, in performing the causal link assessment, I am obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if factors other than increased imports have caused injury to the Domestic Industry, any injury caused by such factors should not be attributed to imports.

68. The analysis of data for the period 2016-17 to Sept 2019 indicates that imports of the PUC have remained at significant levels. Furthermore, the import prices of the PUC have also come down drastically. The prices of imports continue to be below the net sales realisation of the Domestic Industry. Without safeguard duty, imports would undercut the prices of the Domestic Industry. The profitability of the Domestic Industry is currently negative and would be adversely affected if safeguard duty on the PUC is removed.

69. The following factors are noted and have been considered as relevant in establishing that a causal link exists between the discontinuation of safeguard duties and continuation and recurrence of serious injury to the Domestic Industry:

- a. The volume of imports in the domestic market of the PUC in India has remained significant. With the imposition of safeguard duty @25% w.e.f. 30th July, 2018, overall imports reduced in 2018-19. However, with the reduction in safeguard duty to 20% from July 30th 2019, imports have again witnessed an increase.
- b. The market share of imports has maintained its dominant position further increasing slightly during the injury analysis period. The market share of the Domestic Industry also increased marginally as a result of protection afforded by safeguard duty. However, market share of other domestic producers not forming part of the Domestic Industry reduced. Though production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry has improved with the imposition of safeguard duties, the capacity utilization is still less than ideal considering the massive demand of the PUC in India. Furthermore, with the reduction of duty w.e.f. 30th July, 2019, imports of the PUC have increased again which has resulted in substantial increase in inventory levels.
- c. In the Final Findings in the original investigation, it was noted that import prices were suppressing and depressing the prices of the Domestic Industry. A comparison of the landed value of imports with the net selling prices of DI indicates that the prices of imports are still undercutting that of the Domestic Industry. Therefore, if safeguard duty is discontinued, users will switch back to the imported PUC which would lead to recurrence of price suppression and the market share gained by the Domestic Industry would be lost.

- d. Due to the current safeguard duty being in place, increased efficiency has reduced the cost of sales thereby enabling the Domestic Industry to reduce losses with a increased likelihood of being profitable. In case the safeguard duty is not extended, the resultant price undercutting would erode and nullify the positive adjustment made by the DI, pushing it back to the situation of serious injury.
- e. The profitability of the DI continues to be negative though it has improved from previous year.
- f. The interested parties have not pointed out any other factors which are also causing injury to the Domestic Industry at the same time;

70. Therefore the afore stated comprehensive evaluation of parameters demonstrates that serious injury being caused to the DI is likely to continue in future if the safeguard duty is not extended and the same is therefore necessary to extend safeguard duty to prevent further serious injury to the Domestic Industry.

l) Adjustment plan

71. During the original investigation, the Domestic Industry presented an adjustment plan for becoming competitive against the imported PUC in the form of steps such as:

- a. long term procurement of raw material, rate and volume discounts if better cash flow is achieved;
- b. higher utilisation of capacity leading to better conversion cost;
- c. better apportionment of semi-fixed and fixed costs;
- d. better credit ratings for lowering the cost of borrowing and better servicing of debt;
- e. efforts towards backward integration and developing an entire eco-system;
- f. technology development and R&D.

72. Some of the interested parties have raised an objection that the Domestic Industry has not provided any evidence regarding having implemented the adjustment plan that they had furnished during the original investigation which is why they have asked for continuation of the safeguard duty.

73. In this regard, as noted above, the focus of the steps narrated towards the adjustment plan of the Domestic Industry was on gaining competitiveness by achieving cost reduction. The information provided by the Domestic Industry with respect to the steps taken towards adjustment reduction of cost have been verified from the records of the respective domestic producers and it is observed that the domestic producers have taken steps enumerated by them in their initial application for improving their efficiencies though they still need to make further progress to attain the targets fixed in the adjustment plan. As a result of the efforts made by them, it has been noted that within one and half years in terms of the adjustment plan, the domestic producers have achieved a cost reduction of 2.48 cents/watt till September 2019 as against a target of 12.25 cents/watt in fixed costs. The Authority further notes that for reducing the raw material prices the DI changed logistics from air to sea and also started using larger size wafers.

74. The abovesaid cost reductions have been facilitated by reduction in raw material costs, achieving economies of scale as a result of reduction in conversion costs due to better utilisation of capacity and reduction in fixed cost due to reduction in number of employees and increased production.

75. Therefore, it has been observed that the domestic industry has made the efforts enumerated by it with respect to original adjustment plan, and is positively adjusting itself to meet import competition. However, import prices have continued to decline steeply and are undercutting the prices of the Domestic Industry without inclusion of safeguard duty. Therefore, the domestic industry is required to be given more time to pull itself together to overcome its fragile financial situation caused by imports of the PUC.

76. The domestic producers have presented a revised adjustment plan detailing the steps it has planned to take to reduce its costs further in order to meet import competition. The revised adjustment plan includes the following steps proposed by the Domestic Industry:

- Further reduction in raw material costs: With better cash flow, DI will be in position to further re-negotiate prices with suppliers by entering long term contract, rate discount and volume discount. The company also intends to establish facilities to produce the major raw material i.e. wafers.
- Further reduction in Conversion Costs: The Domestic Industry has stated that the target reduction in cost is yet to be achieved and a further increase in production quantity will help the Domestic Industry to achieve the same in the next few years and has provided a revised target in this regard.
- Further reduction in fixed cost by increasing production, automation of manufacturing process and achieving operational efficiencies.
- By full utilization of plant and machinery, the depreciation cost will be reduced in the next few years
- Reduction in SGA, Finance and other costs.

77. The Domestic Industry has projected that its adjustment plan will be completed in the next three years. The revised adjustment plans were submitted by the domestic producers along with their respective questionnaire responses. Therefore, it is observed that if the duties are not continued, imports would cause further injury and wipe out the fragile domestic industry in India. On the earlier adjustment plan it is noted that domestic industry has not been able to achieve the projected target as they have been able to achieve cost reduction mainly on fixed costs only due to their efforts. Nevertheless, the domestic industry has evidenced positive adjustment.

m) Public Interest

78. Some of the parties have argued that continued imposition of safeguard duty on imports of PUC would not serve any public interest. On the contrary imposition of safeguard duty would severely prejudice the public interest as a number of end users of the PUC such as solar power developers may close down. In this regard, it is observed that the expression 'public interest' does not cover in its ambit consumer interest alone. It is a much wider term, which covers in its ambit the general social welfare taking into account the larger community interest. While the imposition of safeguard duty may result in increased cost of the imported PUC in the hand of buyers and a slightly increased cost of power at the hands of the end user, it is important to keep in mind the objective of imposition of safeguard duty. The purpose of imposition of safeguard duty is to provide time to the domestic industry to make positive adjustment to meet with the new situation of competition offered by the increased imports. The imposition of safeguard duty, for the period and to the extent considered adequate, would, therefore not only minimize the adverse effect, if any, for the customers but also give them a wider choice to source their requirements, and at competitive prices. The domestic producers who have set up plants with huge investments provide employment to a large number of people and make valuable contribution to the national economy. Imposition of safeguard duty may enable the domestic producers to survive in the face of competition offered by the increased imports, will, therefore, also be in the long-term interest of the buyers of the PUC as well as end users.

79. The primary concern of module manufacturers has been the demand supply gap between their installed capacity to manufacture solar modules in comparison to installed solar cell manufacturing capacity which necessitates imports. However, it is observed that this is only a temporary situation where the gap will have to be filled by imported solar cells at a higher price till the domestic manufacturers ramp up their capacity to meet the demand. On the other hand, considering the current factual situation where domestic cell manufacturers are facing threat to their existence, not continuing the safeguard duty shall result in complete erosion of the domestic cell manufacturing base and solar module manufacturers will become entirely dependent on imported solar cells for manufacturing modules. Upon total winding up of domestic cell manufacturing operations in India, module manufacturers will be at the complete mercy of exporters who would then be in a position to dictate prices and can simply increase the prices of solar cells making module manufacturers uncompetitive as well. This will have a cascading effect on other upstream and downstream industries involved in the manufacture of equipment for solar modules such as EVA Sheets and solar glass and destroy India's solar equipment manufacturing capabilities entirely.

On the other hand, levy of safeguard duty will ensure the subsistence of domestic cell manufacturers which will then provide a wider choice of suppliers to module manufacturers to source cells from. Furthermore, though the prices of procurement of solar cells may increase temporarily, the cost of domestically produced solar cells shall come down once the cell manufacturers adjust to the competition. In turn, this will bring down the cost of production of solar modules and help module manufacturers compete better with imported modules from which they are admittedly facing tough competition. It is noted that the Domestic Industry has been attempting at backward integration and certain key supplies such as solar glass, EVA Sheet, back sheet, etc. have already made significant investments for improving production capacity in India. Some interested parties have drawn attention to the announcement by the Government on increasing basic custom duty on PUC to 20%. This announcement indicates that tariff application on PUC is also an important aspect of public interest.

80. Therefore, levy of safeguard duties to protect the Domestic Industry is in the larger public interest as it will lead to increase in employment, capex expansion, R&D and Foreign Direct Investment (FDI). Suppliers of raw materials and consumable such as wafers, paste, EVA, junction box, solar glass, will also be encouraged to establish new units. On the other hand, if the protective levy of safeguard duty is not continued, it will lead to the extinction of the Domestic Industry which would be a much more disastrous situation for the economy of the country.

81. It has also been submitted that imposition of safeguard duty will adversely affect India's target to achieve 100GW of solar power generation by 2022 due to the demand and domestic supply gap which necessitates imports. In this regard, it is noted that safeguard duties are only in the nature of tariff measures and not quantitative restrictions. Therefore, the shortfall in the domestic demand can be met by imports, albeit after paying safeguard duty. The objective of safeguard duty is to enable the domestic producers to become internationally competitive. Therefore, protection accorded to the Domestic Industry will help to lower its cost to the level of international prices which will be in the long-term interest of solar power developers and end users as they will not be solely reliant on the imported PUC. It is, therefore, observed that continued imposition of safeguard duty on the PUC is in Public interest. The cost of production of the domestic industry with a reasonable interest when compared with landed value of imports indicates continued price injury to the Domestic Industry. To prevent this injury the existing Safeguard needs to be extended for some more time continuing with ongoing progressive liberalisation of Safeguard duty.

n) Developing nations

82. Proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975 provides that Safeguard Duty shall not be imposed on article originating from a developing country so long as its share of imports does not exceed 3% of the total imports of that article or, where the article is originating from more than one developing country, then, so long as the aggregate of the imports from all such developing countries, each with less than 3% import share taken together, does not exceed 9% of the total imports of that article. Further, Notification No.19/2016-Custom (NT), dated 5th February, 2016 specifies the developing countries for the purposes of this provision. Upon applying this legal provision read with the said notification to the available data in the present case, the finding is that import of the PUC is originating from more than one specified developing country including China PR, Thailand and Vietnam. However, as a percentage of the total imports of the PUC into India, the imports from China PR, Thailand and Vietnam individually account for more than 3% while the share of every other developing country is individually less than 3%. Some of the interested parties have contended that the Domestic Industry has incorrectly projected imports from Thailand as more than 3% during the injury period whereas it is much less. In this regard, it has also been contended that in a review, developing nations which were excluded from the application of the safeguard measure cannot be included within its scope pursuant to a review.

83. At the instance of the interested parties, the import data of the PUC from Thailand was reverified and it has been found that the quantum of imports from Thailand exceeds 3% in 2018-19 and from 1st April, 2019 to 30th September, 2019. Furthermore, I find the submission that new developing countries cannot be included pursuant to a review to be without any merit since the very purpose of the review is to evaluate whether the safeguard duty is required to prevent or remedy serious injury to the Domestic Industry. Therefore, if the quantum of imports have increased from

other developing countries which were not included within the scope of the measure pursuant to the original investigation, serious injury to the Domestic Industry cannot be prevented or remedied if these developing countries which have exceeded the 3% threshold are not included within the scope of the measure that is to be continued. Therefore in such a situation, the continuation of the measure will be reduced to an empty formality as it would not be applicable to influx of imports from these new sources which continue to cause or threaten serious injury to the Domestic Industry. I have also noted the Final Findings in review dated 11th December, 2001 of safeguard measures on Phenol wherein Malaysia, South Africa and Singapore were included within the scope of the measure pursuant to the review though these countries were not included at the time of the original measure. Furthermore, I have also noted the Final Findings dated 4th February, 2002 in review of safeguard duty on imports of Acetone in which South Africa and Singapore were included within the scope of the safeguard duty pursuant to the review though they had not been included within the scope of the measure at the time of the original levy. Accordingly, this issue raised by the interested parties is not accepted.

84. It is further noted that the collective share of the developing countries whose individual share is less than 3% does not exceed 9% of the total imports of the PUC into India. Therefore, the import of the PUC originating from developing countries except China PR, Thailand and Vietnam, are not recommended to be subjected to levy of Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975.

o) Conclusions

85. On the basis of the above examination and analysis, it is concluded that:

- i. After a decline in imports in 2018-19 as a consequence of the imposition of safeguard duty on the PUC, imports have increased for the period between 1st April 2019 to September 2019 pursuant to reduction in rate of safeguard duty from July 30th, 2019. There has been a significant increase in imports of the PUC in absolute terms as well as in relation to total Indian domestic production over the entire POI;
- ii. The domestic industry is continuing to suffer serious injury which is evidenced from an overall consideration of its performance, particularly on the basis of its capacity utilization which is sub-par considering the demand of the PUC, increasing levels of inventory and negative profitability. Though the Domestic Industry has improved its production and sales and reduced its losses, its position continues to be fragile and would relapse into further serious injury if the safeguard duty is discontinued;
- iii. Import prices have continued to decline over the injury period i.e. 2016-2017 to 2019-2020 (A). Without safeguard duty, import prices are below the selling price of the Domestic Industry and would undercut the prices of the Domestic Industry if removed. Consequently, there is every likelihood that the severe price suppression and depression being suffered by the Domestic Industry before the imposition of safeguard duty would recur and the profitability of the Domestic Industry will get further adversely impacted;
- iv. The cost on the Solar Power Developers and the ultimate consumer will increase as a result of safeguard duty on the PUC. However, imposition of safeguard duty would be in public interest because it will prevent complete erosion of manufacturing base of solar industry in the country which has made substantial investments. The Domestic Industry has though not fully adhered to the adjustment plan but have made serious efforts to implement its adjustment plan which has improved their performance and will further lead to its increased competitiveness vis-à-vis imports and also lower cost of the PUC to the domestic consumer in the long run.

p) Recommendations

86. The imports of 'PUC' into India, have not only continued to cause serious injury to the Domestic Industry but also threaten to cause serious injury to the domestic producers of "PUC" and it will be in the public interest to continue the imposition of safeguard duty on imports of the PUC into India in terms of Rule 18 read with Rule 12 of the Customs Tariff (Identification And Assessment of Safeguard Duty) Rules'97. It is noted that the domestic industry has sought extension of the Safeguard duty further for a

period of four years with progressive liberation of Safeguard duty to 14.95%, 14.90%, 14.85% and 14.80% in the four years respectively. Keeping in view that 2 years of protection has already been provided and DI has improved its position but needs some more time to adjust, extension of Safeguard for a period of another one year would be adequate. Further during this period, the existing quantum of duty would continue to be liberalised at a pace so as to ensure that adjustment by DI is attained within the span of one year only. Accordingly, the safeguard duty as indicated below is considered appropriate to continue protection to the domestic industry to facilitate further positive adjustment. Following safeguard duty is recommended to be imposed w.e.f. 30.7.2020 on PUC imported under sub-heading 85414011 and 85414012 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975. The Tariff Items mentioned herein are indicative only and the description of the imported goods will determine the applicability of the recommended Safeguard Duty.

Year	Safeguard duty recommended
First 6 Months	Safeguard duty @ 14.90% ad valorem
Next 6 Months	Safeguard duty @ 14.50% ad valorem

87. As the imports from developing nations, as listed in Notification No.19/2016- custom(NT) dated 5th February,2016, except China PR, Thailand and Vietnam do not exceed 3% individually and 9% collectively, the import of product under consideration originating from developing nations except China PR, Thailand and Vietnam will not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B (1) of the Customs Tariff Act, 1975.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Director General (Safeguard)